रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-78 REGISTERED NO. D. (D./N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 29, 1985/आषाढ 8, 1907
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 1985/ASADHA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1984

का. आ. 2858:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सर होरमसजी नौरोजी मोदी (हांगकांग वाले) तथा श्रीमति मानक बाई मोदी धर्मार्थ ट्रस्ट" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6072/फ़ा. सं. 197/256/83-आ. क. (नि.-I]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
INCOME TAX

New Delhi, the 13th December, 1984

S.O. 2858.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Hormusji Nowroji Mody (of Hong Kong) and Lady Manekbai Mody Charity Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6072/F. No. 197/256/83-IT(AI)]

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1985

आयकर

का. आ. 2859:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "कृष्णामूर्ति फ़ाऊंडेशन इंडिया, मद्रास" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6165/फ़ा. सं. 197-ए/151/82-आ. क. (नि.I)]

New Delhi, the 1st March, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2859.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Krishnamurti Foundation India, Madras" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6165/F. No. 197-A/151/82-IT(A)]

आयकर

का. आ. 2860:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "दि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एण्ड कल्चरल हेरीटेज" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6166/फा. सं. 197/26/85-आ. क. (नि-I)]

पी. सक्सेना, उप सचिव

INCOME-TAX

S.O. 2860.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Indian National Trust for Art and Cultural Heritage" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985 86 to 1987-88.

[No. 6166/F. No. 197/26/85-IT(AI)]

P. SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1985

आयकर

का. आ. 2861:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सेवा मंदिर, उदयपुर" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6170/फा. सं. 197-ए/255/82-आ. क. (नि.I)]

New Delhi, the 18th March, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2861.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Seva Mandir, Udaipur" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6170/F. No. 197-A/255/82-IT(AI)]

आयकर

का. आ. 2862: —आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ "सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट" को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6171/फा. सं. 197-ए/105/82-आ.क (नि-I)]

INCOME-TAX

S.O. 2862.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Dorobji Tata Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6171/F. No. 197-A/105/82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1985

(आयकर)

का. आ. 2863 :—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "पीपुल्स एक्सन फार डिवलेपमेंट (इंडिया) महाराष्ट्र स्टेट कमेटी" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6182/फा. सं. 197-ए/113/82-आ.का. (नि-I)]

New Delhi, the 2nd April, 1985

INCOME-TAX

SO. 2863.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Peoples Action for Development (India) Maharashtra State Committee" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6182/F. No. 197-A/113/82-IT(AI)]

आयकर

का. आ. 2864:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "मोबाइल क्रेशेज फार वर्किंग मदर्स चिल्ड्रन" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6183/फा. सं 197-ए/92/82-आ.क. (नि. I)]

INCOME-TAX

S.O. 2864.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (44 of 1961), the Central Government hereby notifies "Mobile Creches for Working Mothers Children" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6183/F. No. 197-A/92/82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1985

आयकर

का. आ. 2865:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "जमशेदजी टाटा ट्रस्ट" को निर्धारण वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के अंत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 6188/फा सं 197/194/78- आ.क. (नि -I)]

New Delhi, the 10th April, 1985

INCOME-TAX

S.O 2865.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Jamsetji Tata Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 and 1985-86

[No. 6188/F. No. 197/194/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1985

आयकर

का आ 2866—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "सर होर्मुसजी नारौजी मोदी (आफ हागकाग) एंड लेडी मानकबाई मोदी चेरिटी ट्रस्ट" को कर निर्धारण वर्ष 1984–85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[स 6198 (फा सं 197/256/83-आ. क नि-1)]

New Delhi, the 18th April, 1985

INCOME-TAX

S O 2866—In exercise of the power conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sir Hormusji Nowroji Mody (of Hong Kong) and Lady Manekbai Mody Charity Trust' for the purpose of the said section for the period covered by the assessment year 1984-85

[No 6198(F No 197/256/83-ITAI)]

नई दिल्ली, 31 मई, 1985

आयकर

का आ. 2867.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "सोसाइटी आफ दि हैल्पर्स ऑफ मेरी, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6240 (फा सं. 197/54/85-आ. क नि-1)]

आर के तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 31st May, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2867—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of the Helpers of Mary, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88

[No 6240(F No. 197/54/85-ITAI)]

R. K TEWARI, Under Secy

नई दिल्ली 23 मई, 1985

आयकर

का. आ 2868—इस कार्यालय की दिनांक 7-3-1980 की अधिसूचना स 2630 (फा. सं. 203/99/80-आ क नि II) के सिलसिले मे, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की धारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

(i) यह कि मॉडल इस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियो का पृथक् लेखा रखेगा।

(ii) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसधान सबधी क्रियाकलापो की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सबंध मे प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप मे प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(iii) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखो की तथा अपनी परिसंपत्तिया, देनदारिया दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों मे से प्रत्येक की एक-एक प्रति सबधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(iv) यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करेगा। अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

मॉडल इस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, बी. सी. रोड, जम्मू 180001।

यह अधिसूचना 1-4-1983 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[स. 6231 (फा. स 203/57/85-आ.क. नि. II]

गिरीश दवे, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 1985

INCOME-TAX

S O. 2868—In continuation of this Office Notification No. 3206 (F No. 203/99/80-ITA II) dated 7th March, 1980, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 (Thirty five/one/three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Model Institute of Education & Research will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research

(ii) That the said institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April, each year.

(iii) That the said institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said institute will apply to C.B.D.T., Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Application received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Model Institute of Education & Research, B.C. Road, Jammu-180001.

This notification is effective for a period from 1st April, 1983 to 31st March, 1986.

[No. 6231 (F. No. 203/57/85-ITA. II)]

GIRISH DAVE, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 1985

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का. आ. 2869.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के अधिकारी श्री जे. दत्ता को, जो पिछले दिनों तकनीकी अध्ययन ग्रुप, नई दिल्ली में अध्यक्ष के रूप में तैनात थे, 30 मई 1985 के अपराह्न से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-19011/28/79-प्रशा-I]

New Delhi, the 30th May, 1985

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 2869.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No.54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri J. Datta, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise), and formerly posted as Chairman, Technical Study Group, New Delhi, as Member of the Central Board of Excise and Customs with effect from the afternoon of the 30th May, 1985 and until further orders.

[F.No.A.19011/28/79-Ad.I]

का. आ. 2870.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड (कारबा का संव्यवहार का विनियमन नियमावली) 1964 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारी श्री जे. दत्ता को, जिन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य तैनात किया गया है, 30 मई, 1985 के अपराह्न से अगला आदेश होने तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-19011/28/79-प्रशा. 1]

S.O. 2870.—In exercise of the powers conferred by Rule 3 of the Central Board of Excise & Customs (Regulation of Transaction of Business) Rule, 1964, the Central Government hereby appoints Shri J. Dutta, an officer of the Indian Customs & Central Excise Service and posted as Member, Central Board of Excise & Customs, as Chairman, Central Board of Excise & Customs with effect from the afternoon of the 30th May, 1985 and until further orders.

[F.No.A.19011/28/79-Ad.I]

नई दिल्ली, 4 जून, 1985

का. आ. 2871.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री एल. एम. प्रसाद को, जो पिछले दिनों आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल-II, कलकत्ता, के रूप में तैनात थे, 1 जून, 1985 (पूर्वाह्न) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. ए-19011/2/85-प्रशा. 1]
जे. एम. त्रेहन, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 1985

S.O. 2871.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Board of Revenue Act, 1963(No.54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri L.M. Prasad, an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) and formerly posted as commissioner of Income-tax, West Bengal-II, Calcutta, as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from 1st June, 1985 (FN).

[F.No.A.19011/2/85-Ad.I]

J. M. TREHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जून, 1985

स्टाम्प

का. आ. 2872.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 फरवरी, 1985 की अधिसूचना सं. 8/85-स्टाम्प फा. सं. 33/1/85-वि.क. का. आ. सं. 850, का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में, स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनार्थ उस सारणी के स्तंभ (2) में तद्नुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा को भारतीय

मुद्रा में संपरिवर्तित करने के लिए; विनिमय की दर निर्धारित करती है :—

सारणी

क्र.सं.	विदेशी मुद्रा	100 रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की विनिमय दर
1	2	3
1.	आस्ट्रियन शिलिंग	173.9
2.	आस्ट्रेलियन डालर	11.320
3.	बेल्जियम फ्रैंक	498.5
4.	कनाडियन डालर	10.950
5.	डेनिश क्रोनर	88.65
6.	डुत्शे मार्क	24.75
7.	डच गिल्डर	27.88
8.	फ्रैंच फ्रैंक	75.60
9.	हांगकांग डालर	62.50
10.	इतालवी लीरा	158.37
11.	जापानी येन	2011
12.	मलेशियन डालर	20.17
13.	नार्वेजियन क्रोनर	71.40
14.	पौंड स्टर्लिंग	6.4460
15.	स्वीडिस क्रोनर	71.55
16.	स्विस फ्रैंक	20.90
17.	अमरीकी डालर	8.015
18.	सिंगापुर डालर	17 690

[सं. 25/85/स्टाम्प-फ़ा. सं. 33/1/85-वि. क.]

भगवान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 10th June, 1985

STAMPS

S.O 2872.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 8/85-Stamps F. No. 33/1/85-ST S.O. 850, dated, the 8th February, 1985, the Central Government hereby prescribes in column (3) of the Table below the rate of exchange for the conversion of the foreign currencies specified in the corresponding entry in column (2) thereof into the currency of India for the purposes of calculating stamp duty.

TABLE

S. No.	Foreign currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100
1	2	3
1.	Austrian Schillings	173.9
2.	Australian Dollars	11.320
3.	Belgian Francs	498.5
4.	Canadian Dollars	10.950
5.	Danish Kroners	88.65
6.	Deutsche Marks	24.75
7.	Dutch Guilders	27.88
8.	French Francs	75.60
9.	Hong Kong Dollars	62.50
10.	Italian Lire	158.37
11.	Japanese Yen	2011
12.	Malaysian Dollars	20.17
13.	Norwegian Kroners	71.40
14.	Pound Sterling	6.4460
15.	Swedish Kroners	71.55
16	Swiss Francs	20.90
17.	U S A Dollars	8.015
18.	Singapore Dollars	17.690

[No. 25/85/Stamps—F. No. 33/1/85-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली 5 जून, 1985

का. आ. 2873.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 21क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निम्नलिखित व्यक्तियों को 15 जून, 1985 से भारतीय स्टेट बैंक के बम्बई स्थानीय मंडल का सदस्य नामित करती है :

बम्बई स्थानीय मंडल

1. श्री रामभाऊ एन. कोल्हे,
   49, रामकृष्ण नगर,
   खामला रोड, नागपुर-440015
2. श्री अनिलकुमार वर्जूजी तुमाने,
   नई शुक्रवाडी, राष्ट्रीय विद्यालय के पास,
   नागपुर (महाराष्ट्र राज्य)

[संख्या एफ़. 8/16/84-बी. ओ.-1]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 5th June, 1985

S.O. 2873.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 21, read with sub-section (1) of section 21A of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby nominates the following persons to be member of the Bombay Local Board of the State Bank of India with effect from 15 June, 1985.

BOMBAY LOCAL BOARD

1. Shri Rambhau N. Kolhe,
   49, Ramkrishna Nagar,
   Khamla Road,
   Nagpur-440015.
2. Shri Anil kumar Varluji Tumane,
   New Shukrawari,
   near Rashtriya Vidyalaya,
   Nagpur (M. S.)

[No. F. 8/16/84-B.O.I]

S. S. Hasurkar, Director

नई दिल्ली, 10 जून, 1985

का. आ. 2874 .—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफ़ारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध 25 मार्च, 1986 तक बैंक आफ़ तमिलनाडु लिमिटेड, तिरूनेलवेली पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका संबंध बैंक द्वारा धारित तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले के चेरानमहादेवी गांव (पहले जिसका नाम सेरमादेवी गाँव था) में कुल 19 सेंट की अचल संपत्ति अर्थात् नंजा लैंड सर्वे संख्या 200-7, 8 और 10-ई-1 से है।

[संख्या 15/8/84-बी. ओ.-III]

New Delhi, the 10th June, 1985

S.O. 2874.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply upto the 25th March, 1986 to the Bank of Tamilnadu Ltd., Tirunelveli, in respect of the immovable property, viz. Nanja Lands having survey Nos. 200-7, 8, and 10-E-1 measuring in all 19 cents held by it at Cheranmahadevi Village, Tirunelveli district, Tamilnadu (formerly known as Sermadevi Village).

[No. 15/8/84-B.O. III]

का. आ. 2875 .—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफ़ारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में फ़ार्म "क" के साथ संलग्न टिप्पणी (च) में उपबंध करूर वैश्य बैंक लि. पर जहां तक उसका संबंध 31 दिसंबर, 1984 को उसके तुलन पत्रों से है, लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/1/85-बी०ओ०-III]

S.O. 2875.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the form 'A' in the Third Schedule to the said Act, shall not apply to the Kapur Vysya Bank Limited in respect of their balance sheet as at the 31st December, 1984.

[No. 15/1/85-B.O. III]

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

का. आ. 2876 .—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफ़ारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख, की उपधारा (1) और (2) के उपबंध गणेश बैंक आफ़ कुरुंडवाड लि. कुरुंडवाड पर 19 जून, 1985 से 18 सितम्बर, 1985 तक की तीन महीने की अवधि के वास्ते या जब तक उस बैंक के लए नियमित रूप से पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती इन दो में से जो भा पहले हो, लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/25/84-बी.ओ.-II]

New Delhi, the 12th June, 1985

S.O. 2876.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10-B of the said Act, shall not apply to the Ganesh Bank of Kurundwad Limited, Kurundwad, for a further period of three months from 19th June, 1985 to 18 September, 1985 or till the appointment of a regular whole-time Chairman and Chief Executive Officer for that bank, which is earlier.

[No. 15/25/84-B.O. III]

का. आ. 2877 .—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफ़ारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के वास्ते सेंट्रल बैंक आफ़ इंडिया, बंबई पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जिस तक उनका संबंध गिरवीदार (प्लेजी) के रूप में, मैसर्स स्टार आफ गुजरात टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड अहमदाबाद की प्रदत्त शेयर पूंजी मे उसकी 30 प्रतिशत से अतिरिक्त शेयर धारिता से है।

[संख्या 15/2/85-बी. ओ. III]

S.O. 2877.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act, shall not apply to Central Bank of India, Bombay for a period of two years from the date of notification, insofar as they relate to its holding of shares in excess 30 per cent of the paid up share of M/s. Star of Gujarat Textile Mills Ltd., Ahmedabad, as pledgee.

[No. 15/2/85-B.O. III]

नई दिल्ली, 13 जून, 1985

का. आ. 2878 .—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफ़ारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख की उपधारा (1) और (2) के उपबंध काशीनाथ सेठ बैंक लिमिटेड शाहजहांपुर पर 2 जून, 1985 से पहली सितंबर, 1985 तक की तीन महीने की अवधि के वास्ते या जब तक उस बैंक के लिये नियमित रूप से पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, इन में से जो भी पहले हो लागू नहीं होंगे।

[संख्या 15/3/85-बी. ओ.-III]

एम. के. एम. कुट्टि, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 1985

S.O. 2878.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949, the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10-B of the said Act, shall not apply to the Kashi Nath Seth Bank Ltd., Shahjahanpur, for a period of three months from 2nd June, 1985 to 1st September, 1985 or till the appointment of a regular wholetime Chairman and Chief Executive Officer for that Bank, whichever is earlier.

[No. 15/3/85-B.O. III]
M. K. M. KUTTY, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय : मध्य प्रदेश

इन्दौर, 30 अप्रैल, 1985

अधिसूचना संख्या—1/85

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

का. आ. 2879.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 1/81 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 28-2-1981 नीचे वर्णित सीमा तक संशोधित की जाती है :—

1. अधिसूचना संख्या 1/81 के.उ.शु. दिनांक 28-2-1981 के पृष्ठ 9 पर, नियम 173 एल तथा 173 एम के सामने स्तंभ 2, 3 व 4 की वर्तमान प्रविष्टियां हटाई जाती हैं तथा बदले में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाती हैं :—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली	प्रत्यायोजित शक्ति का स्वरूप	अधिकारी जिसे प्रत्यायोजित	सीमा
1	2	3	4
173एल तथा 173 एम	(1) माल के भंडारण में छूट संबंधी शक्ति	अपर समाहर्ता/उपसमाहर्ता	
	(2) माल की वापिसी के लिए अवधि बढ़ाने संबंधी शक्ति	उपसमाहर्ता	
	(3) नियम 173 एल और 173 एम के अंतर्गत समाहर्ता की शक्तियां	समाहर्ता सहायक	

2. अधिसूचना संख्या 1/81 के. उ. शु. दिनांक 28-2-1981 के पृष्ठ संख्या 11 पर, नियम 192 के सामने स्तंभ 3 में "विप्रेषित अधिसूचना में उल्लेखित अधिकारी" की वर्तमान प्रविष्टि के बाद अन्यथा सहायक समाहर्ता जोड़ें।

3. अधिसूचना संख्या 1/81 दिनांक 28-2-81 की अन्य बातें अप्रभावी रहेंगी।

[प. सं. IV(16) 8-38/के. उ.शु./भाग-II
शिवन के० धर, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE : MADHYA PRADESH

Indore, the 30th April, 1985

NOTIFICATION No. 1/85

CENTRAL EXCISES

S.O. 2879.—In exercise of the powers vested in me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944 Notification No. 1/81-CE dated 28-2-1981 is modified to the extent mentioned hereunder :—

1. At page No. 9 of the Notification No. 1/81-CE dated 28-2-1981 the existing entries in Cols. 2, 3 and 4 against Rule 173L and 173M are deleted and substituted by following entries :—

Central Excise Rules	Nature of power delegated	Officer to whom delegated	Limitation
1	2	3	4
173L and 173M	(i) Power to relax storage of goods,	Addl. Collector/ Deputy Collector	
	(ii) Power to extend the period for return of goods;	Deputy Collector	
	(iii) Collector's other powers under Rule 173L & 173M only.	Assistant Collector	

2 At page No. 11 of the Notification No. 1/81-CE, dated 28-2-1981 against Rule 192 in Col. 3 after the existing entry "officer mentioned in remission notification" add otherwise Assistant Collector.

3. Other contents of Notification No. 1/81 dated 28-2-81 remain unaffected.

[C. No. IV(16) 8-3/81/CX/Pt. 1]
S.K. DHAR, Collector

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 29 जून, 1985

अधिसूचना

सं. 201/85—सीमाशुल्क

का. आ. 2880—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 50), की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य के खमाम जिले में न्यू इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एरिया खमाम को शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम बनाने के प्रयोजन लिय भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. 473/271/85—सी. शु. 7]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 29th June, 1985

NOTIFICATION

No. 201/85-CUSTOMS

S.O. 2880.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares New Industrial Development Area of Khammam of Khammam District in the State of Andhra Pradesh to be a Warehousing station for the purposes of setting up hundred per cent export-oriented undertakings.

[F. No. 473/271/85-CUS.VII]

सं. 202/85-सीमाशुल्क

का. आ. 2881—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में कागल ग्राम को शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम बनाने के प्रयोजन के लिये भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. 473/267/85-सीमाशुल्क-7]

No. 202/85-CUSTOMS

S.O. 2881.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Kagal in Kolhapur District in the State of Maharashtra to be a warehousing station for the purposes of setting up hundred per cent export-oriented undertakings.

[F. No. 473/267/85-CUS. VII]

सं 203/85—सीमाशुल्क

का. आ. 2882:—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू और काश्मीर राज्य के जम्मू जिले में बाड़ी ब्राह्मण को शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम बनाने के प्रयोजन के लिये भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. 473/323/85-सी. शु.-7]

सुनील कुमार, अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

NO. 203/85-CUSTOMS

S.O. 2882.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Bari Brahamana in Jammu District in the State of Jammu and Kashmir to be a warehousing station for the purposes of setting up of hundred per cent export-oriented undertakings.

[F. No 473/323/85-CUS.VII]

SUNIL KUMAR, Under Secy.,
Central Board of Excise and Customs

कुदाल जांच आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

का० आ० 2883 :—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 8 और जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5 के उपनियम 8 के अधीन तथा इस आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुदाल जांच आयोग—गांधी शान्ति प्रतिष्ठान एवं अन्य संगठनों के बारे में—(जिसे बाद में आयोग कहा गया है), जिसे अधिनियम की धारा 3 के अधीन भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 83 (अ) दिनांक 17 फरवरी, 1982 के अधीन गठित किया गया, 26 जुलाई, 1982 के आदेश संख्या का. आ. 2908 द्वारा प्रक्रिया विनियमन सम्बन्धी आदेशों में इस प्रकार संशोधन करता है :—

"कार्यालय का समय" से सम्बन्धित पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

4. कार्यालय का समय :—आयोग का कार्यालय केंद्रीय सरकार द्वारा मनाई जाने वाली छुट्टियों के अलावा सभी अन्य दिनों को 9.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक तथा 1.30 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक खुला रहेगा। तथापि, किसी भी कार्य दिवस में पार्टियों तथा जनता के साथ कार्य-संचालन का समय 9.30 पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक होगा। (1.00 बजे अपराह्न से 1.30 बजे अपराह्न-भोजन-अन्तराल छोड़कर)।

यह अधिसूचना आयोग के कार्यालय के लिए 3-6-85 से और आयोग के कोर्ट के लिए 12-6-85 से प्रभावी होगी।

आयोग के आदेश से।

[संख्या 22/10/85-प्रशा.]

डी. वाई. मनव्वर, सचिव

KUDAL COMMISSION OF INQUIRY

ORDER

New Delhi, the 12th June, 1985

S.O. 2883.—In exercise of the powers conferred on it by Section 8 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) and sub-rule 8 of Rule 5 of the Commissions of Inquiry (Central) Rules, 1972 and all other powers enabling it, the Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other organisations constituted under Section 3 of the Act by the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 83(E), dated the 17th February, 1982 (hereinafter referred to as the Commission) hereby makes the following amendment in its Order No. S.O. 2908 dated 26th July, 1982 (relating to Regulation of Procedure) namely :—

Existing para 4 relating to Hours of working shall be substituted as follows :—

4 Hours of working.—The office of the Commission shall be open between 9.00 A.M. to 1.00 P.M. and 1.30 P.M. to 5.00 P.M. of all days other than holidays and closed days observed by the Central Government. However, the hours during which business may be transacted with the parties and the public shall be between 9.30 A.M. and 4.00 P.M. (excluding the lunch interval from 1.00 P.M. to 1.30 P.M.) on any working day.

This Notification shall take effect from 3rd June, 1985 insofar as the Commission's office is concerned and from 12th June, 1985 insofar as it relates to the Commission's Court.

By Order of the Commission.

[No. 22/10/85-Admn.]

D. Y. MANAWWAR, Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जून, 1985

का. आ. 2884 :—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर-10 में विनिर्मित डीजल इंजिनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड को, जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, बम्बई हाउस, 24 होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई-400023 में है, 16 मई, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का. आ. 1476, तारीख 16 मई, 1981 के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

[फाइल सं. 5(4)/80-ईआई एंड ईपी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 29th June, 1985

S.O. 2884.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1985 M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, having their registered office at Bombay House, 24, Homi Mody Street, Bombay-400023, as the agency for inspection of diesel engines manufactured at M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, Jamshedpur-10, prior to export subject to the conditions notified vide S.O. 1476 dated 16th May, 1981.

[F. No. 5(4)/80-EI&EP]

का. आ. 2885.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, पिम्परी, पूणे-411018 में विनिर्मित डीजल इंजिनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, को जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, बम्बई हाउस, 24 होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई-400023 में है 16 मई, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का. आ. 1477, तारीख 16 मई, 1981 के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

[फाइल सं. 5(4)/80-ईआई एंड ईपी]

S.O. 2885.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1985 M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, having their registered office Bombay House, 24, Homi Mody Street, Bombay-400023 the agency, for inspection of diesel engines manufactured M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, mpri, Pune-411018 prior to export, subject to the conditions notified vide S.O. 1477 dated 16th May, 1981.

[F. No. 5(4)/80-EI&EP]

का. आ. 2886.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी यंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 2) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, मैसर्स मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, सूर रोड, अदुगोदी, बैंगलूर-560030 में विनिर्मित डीजल इंजिन के पुर्जों और संघटकों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड को, जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होसूर रोड़, अदुगोदी, बैंगलूर-560030 में है, 16 मई, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का. आ. 1478, तारीख 16 मई, 1981 के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

[फ़ाइल सं. 5(4)/80-ईआई एंड ईपी]

S.O. 2886.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1985 M/s. Motor Industries Company Limited, having their registered office at Hosur Road, Adugodi, Bangalore-560030, as the agency, for inspection of diesel engine spares and components, manufactured at M/s. Motor Industries Company Limited, Hosur Road, Adugodi, Bangalore-560030, prior to export, subject to the conditions notified vide S.O. 1478 dated 16th May, 1981.

[F. No. 5(4)/80-EI&EP]

का. आ. 2887.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स किरलोस्कर क्यूमिनस लिमिटेड, कोथरड, पूणे-411029 में विनिर्मित डीजल इंजिनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स किरलोस्कर क्यूमिनस लिमिटेड को जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय कोथरड, पूणे-411029 में स्थित है 16 मई, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का. आ. 1480, तारीख 16 मई, 1981 के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

[फ़ाइल सं. 5(4)/80-ईआई एंड ईपी]

S.O. 2887.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1985 M/s. Kirloskar Cummins Limited, having their registered office at Kothrud, Pune-411029, as the agency, for inspection of diesel engines manufactured at M/s. Kirloskar Cummins Limited, Kothrud, Pune-411029, prior to export subject to conditions notified vide S.O. 1480 dated 16th May, 1981.

[F. No. 5(4)/80-EI&EP]

का. आ. 2888.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर-10 में विनिर्मित आटोमोबाइल के पुर्जों, संघटकों और उप साधनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड को, जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, बम्बई हाउस, 24 होमी-मोदी स्ट्रीट, बम्बई-400023 में है, 16 मई, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का. आ. 1481, ता 16 मई, 1981

के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप में मान्यता देता है।

[फाइल स. 5(3)/80-ईआई एंड ईपी]

S.O. 2888.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1985 M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, having their registered office at Bombay House, 24, Homi Mody Street, Bombay-400023, as agency, for inspection of automobile spares, components and accessories manufactured at M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, Jamshedpur-10 prior to export subject to the conditions notified vide S.O. 1481 dated 16th May, 1981.

[F. No. 5(3)/80-EI&EP]

का : आ. 2889.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, पिम्परी, पुणे-411018 में विनिर्मित आटोमोबाइल के पुर्जों, संघटकों और उप-साधनों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड को जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बम्बई हाउस, 24 होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई-400023 में स्थित है, 16 मई, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का. आ. 1482, तारीख 16 मई, 1981 के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

[फाइल सं. 5(3)/80-ईआई एड ईपी]

S.O. 2889.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1985 M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited having their registered office at Bombay House, 24, Homi Mody Street, Bombay-400023, as the agency, for inspection of the automobile spares, components and accessories, manufactured at M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Limited, Pimpri, Pune-411018, prior to export, subject to the conditions notified vide S.O. 1482 dated 16th May, 1981.

[F.No.5(3)/80-EI&EP]

का. आ. 2890.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, हौसूर रोड, अडुगोदी, बैंगलूर-560030 में विनिर्मित ओटोमोबाइल के लिए, स्पार्क प्लगों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड को, जिनका राजेस्ट्रीकृत कार्यालय हौसूर रोड, अडुगोदी, बैंगलूर-560030 में है, 16 मई, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए 'का आ. 1483, तारीख 16 मई, 1981, के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप में मान्यता देती है।

[फाइल सं. 5(3)/80-ईआई एंड ईपी]

S.O. 2890.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1985, M/s. Motor Industries Company Limited, having their registered office at Hosur Road, Adugodi, Bangalore-560030, at the agency for inspection of spark plugs for automobiles manufactured at M/s. Motor Industries Company Limited, Hosur Road, Adugodi, Bangalore-560030, prior to export subject to the conditions notified vide S.O. 1483 dated 16th May, 1981.

[F. No. 5(3)/80-EI&EP]

का. आ. 2891.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सुन्दरम् फास्टनर्स लिमिटेड, पैडी मद्रास-600050 में विनिर्मित कीलकों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स सुन्दरम् फास्टनर्स लिमिटेड को, जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 37, माउंट रोड मद्रास-600006 में स्थित है, 16 मई, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए का. आ. 1492, तारीख 16 मई, 1981 के अनुसार अधिसूचित शर्तों के अधीन रहते हुए, अभिकरण के रूप मे मान्यता देता है।

[फाइल सं. 5(9)/80-ईआई एंड ईपी]

S.O. 2891.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 16th May, 1985 M/s. Sundram Fasteners Limited, having their registered office at 37, Mount Road, Madras-500006, as the agency, for inspection of fasteners, manufactured at M/s. Sundram Fasteners Limited, Padi, Madras-600050, prior to export subject to the conditions notified vide S.O. 1492 dated 16th May, 1981.

[F. No. 5(9)/80-EI&EP]

का. आ. 2892.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स दिल्ली टेस्ट हाऊस 9/7 शक्ति नगर, नई दिल्ली-110007 पर स्थित शाखा को भी इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार खनिज तथा अयस्कों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में 5 अप्रैल, 1985 से एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है।

अनुसूची

1. फ़ैरोमैंग्नीज, स्लेग सहित फ़ैरोमैंग्नीज,
2. 'बाक्साइड, कैलसिड सहित',
3. मैंगनीज डायक्साइड,
4. कायनाइट,

5. सिलीमेनाइट
6. जिंक अयस्क, जिंक कान्सेन्ट्रेस सहित,
7. मैंगनसाइड,
8. बैराइटिस,
9. लाल आक्साइड
10. पीला गैरिक,
11. स्टेटाइट,
12. फ़ैल्डसपार

[फा. सं. 5/10/83-ईआई एण्ड ईपी]
सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 29th June, 1985

S.O. 2892.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of one year with effect from 5th April, 1985 M/s. Delhi Test House, 9/7, Shakti Nagar, New Delhi-110007, as an Agency for the inspection of mineral Ores specified in Schedule annexed hereto prior to export.

SCHEDULE

1. Ferromanganese, including ferromanganese slag.
2. Bauxite, including calcined bauxite.
3. Manganese Dioxide.
4. Kyanite
5. Sillimanite.
6. Zinc Ores, including zinc concentrates.
7. Magnesite, including dead burnt and calcined magnesite.
8. Barytes.
9. Red Oxide.
10. Yellow Ochre.
11. Steatite.
12. Feldspar.

[F. No. 5/10/83-EI&EP]
C. B. BUKRETI, Jt. Director

नई दिल्ली 29 जून, 1985

आदेश

का०आ० 2893—केन्द्रीय सरकार को, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जूता और जूते के संघटकों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन रखा जाये;

और केन्द्रीय सरकार के उक्त प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाये है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त उपनियम के अनुसरण में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2384 तारीख 17 जुलाई, 1967 तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2128 तारीख 19 जून, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिये प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है ।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजना चाहे तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, ग्यारहवां फ्लोर, प्रगति टावर, 26 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि जूता और जूतों के संघटक निर्यात के पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे ।

(2) इस आदेश के उपाबन्ध में दिये गये जूता और जूता संघटकों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो जूते के ऐसे संघटकों को निर्यात से पूर्व लागू किया जायेगा ;

(3) निम्नलिखित को जूते और जूते के संघटकों के लिये मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना :—

(1) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों को और

(2) विदेशी क्रेता द्वारा अनुमोदित किये गये नमूने (नमूनों) सहित निर्यातकर्ता द्वारा लिखे गये संविदात्मक विनिर्देशों/तकनीकी विनिर्देशों को ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे जूते और जूतों के संघटकों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके प्रत्येक परेषण के साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अधिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि जूते और जूतों के संघटकों का परेषण निर्यात योग्य है ।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं के भू-मार्ग, समुद्र मार्ग या वायु मार्ग द्वारा जूते और जूते के संघटकों के वास्तविक व्यापार नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होंगी, परन्तु यह तब तक ऐसे नमूनों को निःशुल्क निर्यात किये जाने के लिये अनुज्ञा दी जाती है ।

3. इस आदेश में :—

(1) "जूता" से विभिन्न प्रकार की सामग्री या चमड़े कैनवस, रबड़, टैक्सटाइल लकड़ी और संश्लिष्ट जैसे सामग्री के संयोजन से पांव की संरक्षा करने और पहनावे के रूप में काम आने के

लिये सैंडिल, जूते या बूट के रूप में बने किसी भी रूप का जूता अभिप्रेत है । इनके अन्तर्गत शिशुओं, बालकों, महिलाओं और पुरुषों के उपयोग के लिये अभिप्रेत पैदल सैर वाला जूता सायं काल पहनने (ड्रैस) वाला जूता, विशिष्ट अवसरों पर उपयोग वाला जूता, क्रीड़ा जूता, व्यावसायिक जूता, विकलांग और शल्य-जूते भी होंगे ।

(2) "जूता संघटक" से ऐसा कोई भी निर्मित या अर्धनिर्मित संघटक अभिप्रेत है जो जूते के विनिर्माण में उपयोग के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री या चमड़े, कैनवस रबड़ टैक्सटाइल लकड़ी या संश्लिष्ट जैसे सामग्री के संयोजन से बना है।

उपाबंध

अधिसूचना सं० का० आ० 2385, तारीख 17 जुलाई, 1967 को अधिक्रांत करते हुए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्र और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाये जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जूता और जूता संघटकों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1985 है (2), ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है ।

(ग) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) (1) "जता" से विभिन्न प्रकार की सामग्री या चमड़े, केन्वस, रबड़, टैक्सटाइल लकड़ी और संश्लिष्ट जैसी सामग्री के संयोजन से पाँव की संरक्षा करने और पहनावे के रूप में काम आने के लिये सैंडिल, जूते या बूट के रूप में किसी भी रूप का जूता अभिप्रेत है । इनके अन्तर्गत शिशुओं, बालकों, महिलाओं और पुरुषों के उपयोग के लिये अभिप्रेत पैदल सैर वाला जूता, सायकाल पहनने (ड्रैस) वाला जूता, विशिष्ट अवसरों पर उपयोग वाला जूता, क्रीड़ा जूता, व्यावसायिक जूता, विकलांग और शल्य-जूते भी होंगे ।

(2) "जूता संघटक" से ऐसा कोई भी निर्मित या अर्ध-निर्मित संघटक अभिप्रेत है जो जूते के विनिर्माण में उपयोग के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री या चमड़े, केन्वस, रबड़, टैक्सटाइल, लकड़ी या संश्लिष्ट जैसे सामग्री के संयोजन से बना है ।

(ङ) "प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण" (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्र०क्वा०नि० भी कहा गया है) से ऐसी क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली अभिप्रेत है जिसके द्वारा विनिर्माण एकक यह सुनिश्चित करता है कि जूता और जूता के संघटक, सामग्री तथा संघटकों के क्रय, विनिर्माण, निरीक्षण, परिरक्षण और पैकिंग के विभिन्न स्तरों पर नियंत्रणों का प्रयोग करके, मानक विनिर्देशों के अनुरूप करने के लिये परिषद् द्वारा अधिकथित रीति से विनिर्मित या बनाये जाते हैं ;

(च) "परेषणवार निरीक्षण" से परिषद् द्वारा अधिकथित रीति से अभिकरण द्वारा निरीक्षण और परीक्षा करके यह अवधारित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है कि निर्यात के लिये अभिप्रेत जूते और जूतों के संघटकों का कोई परेषण मानक विनिर्देशों का अनुपालन करता है या नहीं ;

(छ) "अनुमोदित एकक" से अभिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसा विनिर्माण एकक अभिप्रेत है, जो प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण की अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(ज) "कालिक निरीक्षण" ऐसे अनुमोदित एकक में अभिकरण के अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा अन्तरालों पर एकक में प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये किया गया निरीक्षण अभिप्रेत है; और

(झ) "मौके पर जांच" से परिषद् द्वारा अधिकथित रीति से किसी निर्यात परेषण का मानक विनिर्देशों से उसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिये अभिकरण द्वारा निरीक्षण अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :—

(1) निर्यात के लिये आशयित जूते और जूते के संघटकों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जायेगा कि वह अधिनियम की धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

क उपनियम 2 के अनुसार किसी अनुमोदित एकक द्वारा प्रयुक्त प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण के आधार पर ।

ख परेषणवार या निरीक्षण के आधार पर ।

या

ग दोनों द्वारा ।

(2) प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण

(i) कोई ऐसा विनिर्माण एकक, जो उसके द्वारा विनिर्मित जूता और जूता के संघटक निर्यात करने का इच्छुक है और जिसके पास यथोचित प्रसंस्करण नियंत्रण है प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने के अपने आशय को सूचना देते हुए अभिकरण को आवेदन करेगा।

(ii) अभिकरण, एकक द्वारा प्रयोग किये गये प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण की यथोयोग्यता का निर्धारण करने की व्यवस्था करेगा और यदि उसका समाधान हो जाये तो , अभिकरण एकक को अनुमोदित एकक घोषित करेगा ।

(iii) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिये कि अनुमोदित एकक द्वारा आवश्यक प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण बनाये रखा गया है, अभिकरण कालिक निरीक्षण और मौके पर जांच करेगा ।

(iv) किन्तु प्रसंस्करण क्वालिटी नियंत्रण के अधीन प्राप्त एकक का अनुमोदन अभिकरण द्वारा इस संबंध में परिषद् द्वारा अधिकथित मार्गों के अनुसार कम से कम सात दिन की सूचना देने के पश्चात् वापस लिया जा सकेगा ।

(v) कोई ऐसा एकक जिसका अनुमोदन वापस ले लिया गया है, कमियों को दूर करने के पश्चात् अभिकरण को नये अनुमोदन के लिये नया आवेदन देगा ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—

(i) जूते और जूते के संघटकों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातिकर्ता, निरीक्षण के लिये अभिकरण को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना लिखित में परेषण के भेजने के कम से कम चार दिन पहले प्रस्तुत करेगा जिससे कि अभिकरण नियम तीन और परिषद् द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार परेषण का निरीक्षण कर सके ।

(2) अभिकरण, अपना यह समाधान हो जाने पर कि परेषण मानक विनिर्देशों और अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है, सूचना प्राप्त होने के चार दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करेगा, परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं हुआ है, तो वह चार दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके कारणों सहित लिखित रूप में प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा ।

(3) प्रमाणीकरण के पश्चात्, अभिकरण भण्डारकरण में, अभिग्रहण में या पत्तन पर परेषण का पुनः निर्धारण करेगा । परेषण अपेक्षाओं के अनुरूप न पाये जाने की दशा में मूलतः जारी किया गया प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

5. निरीक्षण का स्थान :—

इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण

(क) विनिर्माण एकक के परिसर में,

या

(ख) उस परिसर में जहां माल निरीक्षण के लिये प्रस्थापित किया गया है, परन्तु यह तब जब कि इस प्रयोजन के लिये वहां पर्याप्त सुविधायें विद्यमान हों ।

या

(ग) लदान पत्तन पर, किया जायेगा ।

6. निरीक्षण फीस :—

इन नियमों के अधीन न्यूनतम बीस रुपये के अधीन रहते हुए, निरीक्षण के लिये प्रस्थापित प्रत्येक परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल के प्रत्येक एक सौ रुपये या उसके भाग के लिये पचास पैसे की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में अभिकरण को संदत्त की जायेगी ।

7. अपील :—

(1) नियम 4 के उप नियम 2 के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त विशेषज्ञों के एक पैनल को, जिसमें पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे , अपील कर सकेगा ।

(2) पैनल की गण पूर्ति तीन होगी ।

(3) पैनल द्वारा अपील, उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जायेगी ।

[फाइल सं० 6(3)/84-ई आई एण्ड ई पी]

एस०एन० हरिहरन, निदेशक

New Delhi, the 29th June, 1985

ORDER

S.O. 2893.—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, the footwear and footwear components shall be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2384 dated 17th July, 1967 and Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2128 dated 19 June 1976,

the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of publication of this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, 11th floor, Pragati Tower, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

(1) To notify that footwear and footwear components shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Footwear and footwear Components (Quality Control and Inspection) Rules, 1985 as set out in Annexure to this Order, as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Footwear Components prior to export;

(3) To recognise—

(i) National or international Standards; and

(ii) Contractual Specifications/Technical specifications written down by the exporter, alongwith sample(s) approved by the foreign buyer.

—as the standard specification for such Footwear and Footwear Components.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of such footwear and footwear Components unless every consignment thereof is accompanied by a certificate issued by any one of the Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the consignment of Footwear and Footwear Components are exportworthy.

2. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide trade samples of footwear and footwear components to the prospective buyers, provided such samples are allowed to be exported free of cost.

3. In this order;

(i) "Footwear" means any form of footwear made of various kinds of materials or combination of materials such as leather, canvas, rubber, textile, wood and synthetics, to protect the fact and to serve as a costume, in the form of sandal, shoe or boot. These shall include walking shoes, dress shoes, occasional footwear, sports footwear, occupational footwear, orthopaedid and surgical footwear meant for the use of babies, children, ladies or gents.

(ii) "Footwear Components" means any fabricated or semi-fabricated components made of various kinds of materials or combination of materials such as leather, canvas, rubber, textiles, wood and synthetics for use in the manufacture of footwear.

ANNEXURE

Draft rules proposed to be made under Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), in supersession of the notification S.O. No. 2385 dated 17th July 1967.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Footwear and Footwear Components (Quality Control and Inspection) Rules, 1985 (2) These shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Council" means the Export Inspection Council;

(c) "Agency" means any one of the Export Inspection Agencies established under Section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras.

(d) (i) "Footwear" means any form of footwear made of various kinds of materials or combination of materials such as leather, canvas, rubber, textiles, wood and synthetics, to protect the foot and to serve as a costume, in the form of sandal, shoe or boot. These shall include walking shoes, dress shoes, occasional footwear, sports footwear, occupational footwear, rthopaedic and surgical footwear meant for the use of babies, children, ladies or gents.

(ii) "Footwear Components" means any fabricated or semi-fabricated component made of various kinds of materials or combination of materials such as leather canvas, rubber, textiles, wood and synthetics for use in the manufacture of footwear.

(e) "In-process Quality Control" (hereinafter also referred to as IPQC) means a system of quality control by which a manufacturing unit ensures that Footwear and Footwear Components are manufactured or fabricated to conform to the standard specifications by exercising controls at different stages of purchase of materials and components, manufacture, inspection, preservation and packing, in a manner as laid down by the Council);

(f) "Consignmentwise Inspection" means the process of determining whether a consignmet of Footwear and Footwear Component meant for export complies with the standard specifications, by inspection and testing by the Agency in a manner as laid down by the Council;

(g) "Approved Unit" means a manufacturing unit approved by the Agency as having satisfied the requirements of IPQC.

(h) "Periodic Visit" means a visit made by office(s) of the Agency to the approved unit at intervals to ensure compliance of the requirements of IPQC in the unit; and

(i) "Spot-check" means an inspection by the Agency of an export consignment to ensure its conformity to the standard specifications in a manner as laid down by the Council.

3. Basis of Inspection.—(1) Inspection of footwear and footwear components intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Act ;

(a) On the basis of In-process Quality Control exercised by an approved unit in accordance with sub-rule (2)

or

(b) on the basis of Consignmentwise Inspection.

or

(c) by both

(2) In-process Quality Control.—(i) Any manufacturing unit intending to export footwear and footwear components manufactured by it and having adequate IPQC shall apply to the Agency initiating therein its intention to seek approval under IPQC.

(ii) The Agency shall then arrange to assess adequacy of IPQC exercised by the unit and if satisfied, the agency shall declare the unit as an approved unit.

(iii) For the purpose of satisfying itself that necessary IPQC is continued to be maintained by the approved unit, the agency shall carry out periodic visits and spot checks.

(iv) The approval accorded to the unit under IPQC may, however, be withdrawn by the Agency, as per norms, laid down in this regard by the Council, after giving a notice of minimum period of seven days.

(v) A unit, whose approval has been withdrawn, may after rectifying the deficiencies, make fresh application to the Agency for fresh approval.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of footwear and footwear components shall submit an intimation for inspection, in writing, to the agency of his intention so to do, not less than four days prior to the despatch of the consignment, to enable the agency to carry out inspection of the consignment as per rule 3 and the procedure laid down by the Council.

(2) The agency, on satisfying itself that the consignment conforms to the standard specifications and requirements of the Act, shall issue an Inspection Certificate for Export within four days of receipt of the intimation, provided that where the agency is not so satisfied, it shall, within the said period of four days, refuse, in writing to issue the certificate along with the reasons therefor.

(3) Subsequent to certificaion, the agency may re-assess the consignment in storage, in transit or at the part. In the event of the consignment being found not conforming to the requirements, the certificate originally issued shall be withdrawn.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out,

(a) at the premises of the manufacturing unit,

or

(b) at the premises at which the goods are offered for inspection, provided adequate facilities for the purpose exist therein, or

(c) at the port of shipment.

6. Inspection Fee.—A fee at the rate of fifty paise for every one hundred rupees or fraction thereof of the f.o.b. value of each consignment offered for inspection subject to a minimum of Rs. twenty shall be paid by the exporter to the Agency is inspection fee, under these rules.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (2) of rule 4, may within ten days of the receipt of communication of such refusal by him prefer an appeal to a Panel of Experts as may be appointed for the purpose, by the Central Government, consisting of non-officials of at least two-thirds of the total membership of the Panel.

(2) The quorum for the Panel shall be three.

(3) The appeal shall be disposed of by the Panel within fifteen days of its receipt.

[File No. 6(3)/84-EI&EP]
N. S. HARIHARAN, Director

आदेश

[का. आ. 2894.—केन्द्रीय सरकार, की निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि कयर मैटिंग्स का पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव बनाए है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम 2 की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अत : अब केन्द्रीय सरकार भारत के विदेश व्यापार मंत्रालय को कयर मैटिंग्स से संबंधित अधिसूचना सं. का.आ. 1386 तारीख 3 जून, 1972 को और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की कयर मैटिंग्स से संबंधित पुनरीक्षित प्रस्तावों का समावेश करने वाली अधिसूचना सं. का. आ. 1425 तारीख 10 अप्रैल, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है उक्त प्रस्तावों को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद, प्रगति टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

1. (1) अधिसूचित करना कि कयर मैटिंग्स निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाएगा ;

(2) इस आदेश के उपाबंध में दिए गए कयर मैटिंग्स के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1985 के प्ररूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी-नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे कयर मैटिंग्स को लागू होगा ;

(3) निम्नलिखित को मान्यता देना:—

(क) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मानकों तथा भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानकों को ;

(ख) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं को पूरा करते हुए उत्पाद के अधीन संविदात्मक विनिर्देशों को ; और

(ग) उन विनिर्देशों को जो ऊपर खण्ड (क) और (ख) के अंतर्गत नहीं आते हैं किन्तु निर्यातकर्ता द्वारा कयर मैटिंग्स के लिए संविदात्मक विनिर्देशों के रूप में घोषित ऐसे मानकों का परीक्षण और अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे कयर मैटिंग्स के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिकरणों में से किसी एक के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि कयर मैटिंग्स उप पैरा (3) के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्यात योग्य है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा कयर मैटिंग्स के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका मूल्य किसी भी प्रकार के प्रति नमूना 250 प्रतिशत रुपये से अधिक नहीं होगा।

3. इस आदेश में "कयर मैटिंग्स" से बिजली करघा और हथकरघे पर निर्मित कयर मैटिंग्स अभिप्रेत है, जिसमें —

( ) कयर मैटिंग्स मैट्स ;

(ii) कयर मैटिंग्स के गलीचे ;

(iii) कयर मुरजोक ;

(iv) कयर के कालीन (अलप्पी कालीन) ;

(v) कयर मैटिंग्स के कोई अन्य प्रकार सम्मिलित है ;

अनुसूची

कयर मैटिंग्स के लिए विनिर्देश:—

1. सामान्य अपेक्षाएं :

1.1 क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार कयर मैटिंग्स विरंजित या अविरंजित कयर धागे से विनिर्मित किया जाएगा। धारा 2 प्लाई का होगा ।

1.2 कयर मैटिंग्स मजबुत और समान रूप से बुना जाएगा ।

1.3 कयर मैटिंग्स सादी; रंगी हुई या स्टैंसिल की हुई होगी या उनमें डिजाइन बनें हुए होंगे।

1.4 क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार कयर मैटिंग्स के गलीचे या मैटिंग्स मैटस बनाए जा सकते हैं । ऐसी दशा में मैटिंग्स मैट्स या गलीचों के कटे हुए किनारों को या तो उचित "सूती धागे से सिला जाएगा या जुट रेक्सिन या चमड़े की पट्टी (सादी, रंगीनया अलंकृत) से बांधा जाएगा या उसके किनारे दोहरे किए जाएंगे और मैटिंग्स मैट्स या गलीचों के अन्दर अन्त-ग्रथित किए जाएंगे या किनारों पर रबड़ या सरेस लगाया जाएगा या रबड़/रबड़ फाइबर का अस्तरण लगाया जाएगा।

1.5 कयर मैटिंग्स के साथ लवण या अन्य बाह्य पदार्थ नही लादे जाएंगे।

2. विशेष आपेक्षाएं :

2.1 विशेष क्वालिटी संख्या की कयर मैटिंग्स अनुसूची में दिए गए उसके लिए विशेष क्वालिटी संख्या की अपेक्षाओं को पूरा करेगी या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बनाएं गए और इस आदेश के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देश के अनुसार होगी।

2.2 संरचना : विशेष क्वालिटी संख्या की कयर मैटिंग्स अनुसूची में दिए गए उस क्वालिटी संख्या के संरचनात्मक विवरण के अनुरूप होगी या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बनाए गए और इस आदेश के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार होगी ।

2.3 सिरे तथा गांठे :

कयर मैटिंग्स के बाने सिरों की न्यूनतम संख्या तथा प्रति डेसीमीटर गांठों की संख्या अनुसूची में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार होगी या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बनाए गए और इस आदेश के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार होगी ।

2.4 भार : प्रतिवर्ग मीटर भार वह होगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बनाएं गए और इस आदेश के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार होगा।

2.5 विमाएं :

कयर मैटिंग्स की विमाएं क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

2.6 सिरों, गांठों, भार तथा विमाओं के संबंध में अनुज्ञेय सहायता अनुसूची में दी गई हैं अनुसार होंगी।

पैकिंग :

3.1 कयर मैटिंग्स की पैकिंग क्रेता और विक्रेता के बीच हुए करार के अनुसार होगी। पैकिंग कम से कम 217 ग्राम प्रति मीटर (7 औंसप्रति गज) वाले नए हैसियन में लपेटे जाएगें।

3.2 प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां लिखी होंगी अर्थात्:—

(क) अधिसूचित क्वालिटी संख्यांक और ब्राण्ड का नाम;

(ख) आकार ;

(ग) पैकेज में टुकड़ों की संख्या ;

(घ) निर्यातकर्ता विदेशी क्रेता का कोड नाम, यदि कोई हो ;

(ङ) पैकेज की क्रम संख्या ;

(च) कुल भार ;

(छ) पोत लदान चिह्न ।

हथकरघा मैटिंग्स-टू ट्रेडल की सादी बुनाई

(क) सामान्य विशेषताएं :—प्रत्येक बाना धागा बाने धागे के ऊपर तथा नीचे से बारी-बारी निकाला जाएगा अर्थात् जब आधे सिरे ऊपर की ओर होंगे तो समान सिरे नीचे की ओर होंगे और इसका उल्टा होगा। मैटिंग्स के दोनों ओर एक जैसा प्रदर्शन करेंगे और अतः मैटिंग्स दोनों तरफ से प्रयोग की जा सकती है ।

(ख) संरचनात्मक विवरण :—

क्वालिटी सं.	ताना			बाना			
	सूत की क्वालिटी	लगभग स्कोरेज	सिरे/डे. मी. न्यूनतम	सूत की क्वालिटी	लगभग स्कोरेज	न्यूनतम गांठें/डे. मी.	भार कि. ग्राम 2 मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
एम 2 ए1	एंजेंगो	15	33	वाइकोम/बीच	..	11	1.50
एम2 ए2	एंजेंगो	14	31	वाइकोम/बीच	..	11	1.55
एम2 ए3	एंजेंगो	13	29	वाइकोम/बीच	..	10	1.62
एम ए4	एंजेंगो	12	27	वाइकोम/बीच	..	9	1.70
एम2 आर1	आर्टरी	15	33	वाइकोम/बीच	..	11	1.42
एम2 आर2	आर्टरी	14	31	वाइकोम/बीच	..	11	1.47
एम2 आर3	आर्टरी	13	29	वाइकोम/बीच	..	10	1.55
एम2 आर4	आर्टरी	12	27	वाइकोम/बीच	..	9	1.62
एम2 बी1	वाइकोम	15	33	कालीकट/बीच	..	9	1.35
एम2 बी2	वाइकोम	14	30	कालीकट/बीच	..	9	1.42
एम2 बी3	वाइकोम	12	27	कालीकट/बीच	..	9	1.52
एम2 बी०	बीच	11	20	बीच/कठोर बिना भिगोया	..	9	1.18
एम2 बी1	बीच	11	22	बीच/कठोर बिना भिगोया	..	9	1.30
एम2 बी2	बीच	9	20	बीच/कठोर बिना भिगोया	..	9	1.40
एस2 एम1	एंजेंगो	17	39	वाइको	..	12	1.40
एस2 एम2	आर्टरी	14	31	एलोई	..	11	1.50
एस2 एम3	वाइकोम	11	22	वाइकोम/बीच	..	9	1.25
एस2 एम4	एंजेंगो	13	19	वाइकोम	..	10	1.40
एस2 एम5	बेपोर	7	15	बीच	..	7	2.10
एम2 एम6	अष्टमुडी	9	18	वाइकोम	..	9	1.90
एस2 एम7 (2×1)	बेपोर	6	14	बेपोर	..	5	2.65
एस2 एम8	क्वीलैंडी	8	20	वाइकोम	..	7	2.10
एम2 एम9	क्वीलैंडी	9	18	क्वीलैंडी	..	7	2.10
एम2 एम 10 (2×1)	वाइकोम थीम	..	36	वाइकोम थीम	..	12	1.10

टू-ट्रेडल की टोकरी बुनाई

(क) सामान्य विशेषताएं :—टू-ट्रेडल सादी बुनाई जैसी ही किन्तु कवर धागे के दो या अधिक धागे ताना अनुसार तथा बाना अनुसार एक साथ बुने जाएंगे इससे वस्तु में धारी या चैक (टाइल) का डिजाइन बन जाता है। मैटिंग दोनों तरफ से प्रयोग की जा सकती है ।

(ख) संरचनात्मक विवरण :—(3×3, 3×2, 2×2 1×2)

1	2	3	4	5	6	7	8
एम 2 बीए1	एंजेंगो	15	30	एंजेंगो/आर्टरी	..	17	1.72
एम2 बीए2	एंजेंगो	14	28	एंजेंगो/आर्टरी	..	17	1.80
एम2 बीए3	एंजेंगो	13	26	एंजेंगो/आर्टरी	..	16	1.82
एम2 बीए4	एंजेंगो	15	30	वाइकोम	..	17	1.62
एम2 बीए5	एंजेंगो	14	28	वाईकोम	..	17	1.68
एम2 बीए6	एंजेंगो	13	26	वाइकोम	..	16	1.72
एम2 बीआर1	आर्टरी	15	30	आर्टरी	..	17	1.68
एम2 बीआर2	आर्टरी	14	28	आर्टरी	..	17	1.72
एम2 बीआर3	आर्टरी	13	26	आर्टरी	..	16	1.80

1	2	3	4	5	6	7	8
एम2 बीआर4	आर्टरी	15	30	वाइकोम	..	1'7	1.58
एम2 बीआर5	आर्टरी	14	28	वाइकोम	..	17	1.62
एम2 बीआर6	आर्टरी	13	26	वाइकोम	..	16	1.68
एम2 बीवी1	वाइकोम	14	28	वाइकोम	..	16	1.47
एम2 बीवी2	वाइकोम	13	26	वाइकोम	..	16	1.52
एम2 बीवी3	वाइकोम	12	24	वाइकोम	..	15	1.58
एम2 बीबी1	बीच	10	20	बीच	..	15	1.38
एम2 बीएम1	एंजेंगो	16	34	एंजेंगो	..	17	1.62
एस2 बीएम2	अस्टमुडी	10	23	वाइकोम	..	14	2.30
एस2 बीएम3	एंजेंगो एम	12	25	एंजेंगो एम	..	12	2.62
एस2 बीएम4	एंजेंगो	16	32	अति उत्तम एलोई	..	21	1.75
एस2 बीएम5	एंजेंगो (4 × 4 बुनाई)	14	28	एंजेंगो	..	24	2.15
एम2 बीएम7	क्वरलैंडी (4 × 4)	10	20	क्वीलैंडी	..	15	2.80
एस2 बीएम8 (8 × 8)	क्वीलैंडी	8	20	क्वीलैंडी	..	20	3.10
एस2 बीएम9 (4 × 4)	रस्सी बांधना	6	11	रस्सी बांधना	..	9	3.60
एस2 बीएम10	बैपोर	7	16	बैपोर	..	8	3.00

जालीदार चटाइयां :—

(क) सामान्य विशेषताएं :—इस मैटिंग की बुनाई टू-ट्रेडल बुनाई की तरह होगी इस अन्तर के साथ की ताने तथा ताने की लड़ियों को कुछ दूरी पर इस व्यवस्था में रखा जाएगा कि जाली बन जाए ।

(ख) सरचनात्मक विवरण :—

1	2	3	4	5	6	7	8
एच 2 एम1	एंजेंगो	14	9	वाइकोम	..	8	0.650
एच2 एम2	एंजेंगो	19	8	बीच	..	7	0.700
एच2 एम3	आर्टरी	15	*14	आर्टरी	..	14	0.875
एच 2एम4	एंजेंगो	12	**19	आर्टरी	..	11	1.400
एच2 एम5	वाइकोम	13	9	वाइकोम	..	8	0.740
एच2 एम6	वाइकोम	12	46	वाइकोम	..	40	0.400
	(साधारण)		प्रति मी.	(साधारण)		प्रति मी.	

*ताने को जोड़ो में व्यवस्थित किया गया है; जोड़े की प्रत्येक लड़ी दूसरी के साथ विकल्प रूप से बुनी गई है।

**ताने को तीन लड़ियो के समूह में व्यवस्थित किया गया है; जोड़े का प्रत्येक समूह पार्श्वस्थ के साथ विकल्प रूप से बुना गया है।

तीन-ट्रेडल की बुनाई :—

(क) सामान्य विशेषताएं :—यह बुनाई टू-ट्रेडल की अपेक्षा मोटी तथा अच्छी बिछावट/मैटिंग के लिए अपनाई गई है। इस प्रकार की बुनाई तिरछा या लहरदार डिजाइन प्रस्तुत करती है। टिवल लाइने फैब्रिक के केवल एक ओर बनाई जाएगी। अंतः मैटिंग दोनों ओर से प्रयोग नहीं की जा सकती।

(ख) सरचनात्मक विवरण :—

1	2	3	4	5	6	7	8
एम3 ए1	एंजेंगो	16	35	वाइकोम/बीच	..	11	1.58
एम 3 ए2	एंजेंगो	15	33	वाइकोम/बीच	..	11	1.62
एम3 ए3	एंजेंगो	14	31	वाइकोम/बीच	..	11	1.68
एम3 ए4	एंजेंगो	13	29	वाइकोम/बीच	..	10	1.75
एम3 ए5	एंजेंगो	12	27	वाइकोम/बीच	..	10	1.82
एम3 आर1	आर्टरी	16	35	वाइकोम/बीच	..	11	1.50
एम3 आर2	आर्टरी	15	33	वाइकोम/बीच	..	11	1.55
एम3 आर3	आर्टरी	14	31	वाइकोम/बीच	..	11	1.60
एम3 आर4	आर्टरी	13	29	वाइकोम/बीच	..	10	1.68
एम3 आर5	आर्टरी	12	27	वाइकोम/बीच	..	10	1.75
एम3 सी1	अष्टमुडी	1	24	वाइकोम/बीच	..	9	2.08
एम3 सी1	वाइकोम	14	31	वाइकोम/बीच	..	10	1.40
एम3 बी2	वाइकोम	13	29	वाइकोम/बीच	..	9	1.45

1	2	3	4	5	6	7	8
एम3 बी3	वाईकोम	12	27	वाइकोम/बीच	..	9	1.52
एम3 बी1	बीच	10	22	बीच/कठोर बिना भिगोया	..	9	1.40
एस3 एम1	एंजेंगो	15	33	अलपाट	..	12	2.00
एस3 एम2	एंजेंगो	16	40	वाइकोम/अलपाट	..	11	2.00
एम3 एम3	वाइकोम	11	24	वाइकोम	..	10	1.70
एस3 एम4	एंजेंगो	15	31	वाइकोम/बीच	..	11	1.52
एस3 एम5	एंजेंगो	14	34	वाइकोम	..	11	1.88
एस3 एम6	एजेंगो	11	27	अष्टमुडी	..	9	2.96
एम3 एम7	एंजेंगो	15	37	वाइकोम	..	11	1.80
एम3 एम8	एंजेंगो	14	31	एजेंगो/आर्टरी	..	13	1.67
एस3 एम9	एजेंगो	13					
	एजेंगो	17	36	एंजेंगो	..	19	1.90

चार ट्रेडल की बुनाई :—

(क) सामान्य विशेषताएं :— यह देखने में अधिक सुन्दर है और दोनों तरफ से प्रयोग में लाई जा सकती है और नहीं भी लाई जा सकती है। यह बुनाई ट्विल, डायमण्ड आदि जैसे नमूनों के प्रयोगों में उच्च क्वालिटी की मैटिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है।

(ख) संरचनात्मक विवरण :—

1	2	3	4	5	6	7	8
एम4 ए1	एंजेंगो	15	33	वाइकोम	..	13	1.70
एम4 ए2	एंजेंगो	14	31	वाइकोम	..	13	1.75
एम4 ए3	एंजेंगो	13	29	वाइकोम	..	13	1.82
एम4 ए4	एंजेंगो	12	27	वाइकोम	..	13	1.90
एम4 आर1	आर्टरी	15	33	वाइकोम	..	13	1.62
एम4 आर2	आर्टरी	14	31	वाइकोम	..	13	1.68
एम4 आर3	आर्टरी	13	29	वाइकोम	..	13	1.75
एम4 आर4	आर्टरी	12	27	वाइकोम	..	13	1.82
एम4 बी1	वाइकोम	14	31	वाइकोम	..	12	1.47
एम4 बी2	वाइकोम	13	29	वाइकोम	..	12	1.55
एम4 बी3	वाइकोम	12	27	वाइकोम	..	12	1.62
एस4 एम1	एंजेंगो	16	36	वाइकोम	..	17	1.50
एस4 एम2	एंजेंगो	15	33	एंजेंगो	..	17	1.75
एस4 एम3	आर्टरी	14	31	आर्टरी	..	14	1.75
एस4 एम4	एजेंगो	13	32	वाइकोम	..	15	2.13
एस4 एम5	एजेंगो	14	33	वाइकोम	..	14	2.20
एम4 एम6	एजेंगो तथा सीसल	14	31	सीसल	..	18	1.78
एम4 एम7	एजेंगो तथा एलोई	14	31	एलोई	..	18	1.87
एस4 एम8	एंजेंगो	16	33	अलापाट	..	12	2.00
एम4 एम9	एंजेंगो	13	29	एंजेंगो	..	15	1.80
एस4 एम10	एजेंगो	16	35	एंजेंगो	..	12	1.75
एस4 एम11	एजेंगो	14	31	एंजेंगो/आर्टरी	..	14	1.82
एस4 एम12	ढीली आर्टरी	..	8	साधारण आर्टरी	..	14	2.55
	सख्त आर्टरी	15	23	अतिरिक्त आर्टरी/ 4 प्लाई रोल	..	7	
एस4 एम13	बैपोर	6	14	बैपोर			
एस4 एम14	1. बैपोर/क्वीलैंडो	8	13		..	7	2.80
	2. आर्टरी	14	13	आर्टरी	..	9	2.60
एस4 एम15	क्वीलैंड	8	11				
	एंजेंगो	13	11	एंजेंगो	..	11	1.95
एस4 एम16	एलोई	10	20	क्वीलैंडो	..	9	2.40
एस4 एम17	क्वीलैंडी	9	20	क्वीलैंडी	..	9	2.62
एम4 एम18	क्वीलैंडी	10	16	क्वीलैंड	..	14	2.55
एस4 एम19	क्वीलैंडी	19	11	एजेंगो	..	18	1.96
एम4 एम20	ढीली एंजेंगो	15	9	साधारण एंजेंगो	..	11	(टोकरी बुनाई)
	सख्त एंजेंगो	14	19	अतिरिक्त क्वीलैंडी	..	11	2.20
एस4 एम21	एजेंगो	11	24	एंजेंगो एम	..	18	3.10
एस4 एम22	वाइकोम पतला	20	40	वाइकोम	..	17	1.35

विशेष रीड मैंटिंग : —

(क) सामान्य विशेषताएं : —इस प्रकार की मैंटिंग यह दर्शाती है कि तानों की लड़ियों के जोड़े के साथ-साथ काम करते हुए क्लोजर रीडस पर बुने जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि तानों का विवरण एक साथ बिना एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है।

(ख) संरचनात्मक विवरण : —

1	2	3	4	5	6	7	8
एस आर 4 एम 1	आर्टरी	15	26	वाइकोम	..	18	1.40
एस आर 4 एम 2	एंजेंगो	14	29	आर्टरी	..	16	1.75
एस आर 4 एम 3	आर्टरी	13	26	वाइकोम	..	16	1.68

बहु शाफ्ट कयर मैटिंग

(क) सामान्य विशेषताएं : —इस प्रकार की मैंटिंग में सामान्यतः डिजाईन होते हैं जिसमें चार शेफ्ट बुनाई से अधिक की अपेक्षा होती है। करघे पर बुनी हुई अधिक सुन्दर डिजाइनों की, डोबी तथा जेकरय रोडिंग तकनीकियों से तैयार मैंटिंग भी इस श्रेणी के अन्तर्गत लाई गई हैं।

(ख) संरचनात्मक विवरण : —

1	2	3	4	5	6	7	8
एस. एम 1	एंजेंगो	12	30	वाइकोम	..	14	2.00
एस. एम 2	एंजेंगो	14	26	एंजेंगो	..	18	2.00
एस. एम 3	एंजेंगो	16	35	एंजेंगो/एलोई/सीसल	..	12	1.70
एस. एम 4	क्वीलैंडी	8	20	क्वीलैंडी	..	15	3.20
एस. एम 5	एंजेंगो पी. ओ. ब्लीच किया हुआ	15	21	वाइकोम	..	26	1.32
एस. एम 6	क्वीलैंडी	9	20	क्वीलैंडी	..	8	2.62
एस. एम 7	क्वीलैंडी	9	20	क्वीलैंडी	..	18	4.00

(ख) बिजली करघे से बनी मैंटिंग का संरचनात्मक विवरण : —

(क) सामान्य विशेषताएं : —मैंटिंग दो शाफ्ट, तीन शाफ्ट, चार शाफ्ट तथा बहु शाफ्ट बुनाई से मैंटिंग बिजली करघे से भी उत्पादित की जाती है। यह हैण्डलूम मैंटिंग के मुकाबले अधिक घनी होगी।

(ख) संरचनात्मक विवरण : —

दो ट्रेडल बुनाई डिजाइन : —

1	2	3	4	5	6	7	8
पी 2 ए 1	एंजेंगो	13	28	वाइकोम	..	13	1.70
पी 2 ए 2	क्वीलैंडी/अष्टमुडी	10	22	वाइकोम	..	10	2.00
पी 2 ए 3	क्वीलैंडी/अष्टमुडी	9	16	वाइकोम	..	7	1.80
पी 2 ए 4	क्वीलैंडी (1 × 2)	9	21	वाइकोम	..	17	2.40
पी 2 ए 5	एंजेंगो	12/16	26	आर्टरी/वाइकोम	..	13	1.80
पी 2 ए 6	एंजेंगो	15/16	42	एंजेंगो	..	11	1.70
2- ट्रेडल टोकरी बुनाई :-							
पी 2 बी ए 1	एंजेंगो	12	30	वाइकोम		16	2.00
पी 2 बी ए 2	एंजेंगो	14	32	एंजेंगो/आर्टरी	..	18	2.20
पी 2 बी ए 3	एंजेंगो	14	28	एजेंगो/आर्टरी	..	16	2.00
पी 2 बी ए 4	एंजेंगो	13	28	एंजगो/आर्टरी/ (ढीला बल)	..	14	1.80
पी 2 बी ए 5	एंजेंगो	16	32	एंजेंगो	..	22	2.00
पी 2 बी ए 6	एंजेंगो	15	32	एंजेंगो	..	21	1.80
पी 2 बी ए 7	क्वीलैंडी	9	10	एंजेंगो	..	16	2.10
पी 2 बी ए 8	एंजेंगो	15	36	एंजेंगो	16	18	1.80
ती ट्रेडल बुनाई : —							
पी 3 ए 1	एंजेंगो	13	28	वाइकोम	..	14	1.80
पी 3 ए 2	एंजेंगो (दो प्लाई एलोई पतला) (लड़ियों की बराबर संख्या)	18	42	एंजेंगो	18	24	1.85

1	2	3	4	5	6	7	8
चार ट्रेडल की बुनाई : —							
पी 4 ए 1	एंजेंगो	15	30	वाइकोम	.	16	1.95
पी 4 ए 2	एंजेंगो	14	32	वाइकोम/आर्टरी	..	17	2.20
पी 4 ए 3	एंजेंगो	14	28	वाइकोम/आर्टरी	.	16	2.00
पी 4 ए 4	एंजेंगो मैगादन के 2/3, सीसत, 1/3 लड़ियां	13	26	वाइकोम	..	17	1.96
पी 4 ए 5	एंजेंगो एम या मैगादन के 2/3 लड़ियां सीसत 1/3 लड़ियां	13	25	वाइकोम	..	16	1.80
ए 4 ए 6	एंजेंगो एम	13	26	वाइकोम	.	12	2.20
पी 4 ए 7	एंजेंगो	12	28	वाइकोम	..	14	1.80
पी 4 ए 8	एंजेंगो	16	32	एंजेंगो	..	22	2.00
पी 4 ए 9	एंजेंगो	15	32	एंजेंगो	..	21	1 80
पी 4 ए 10	एंजेंगो एम	12	27	वाइकोम	..	14	2.20
पी 4 ए 11	क्वीलैंडी	9	10	एंजेंगो	..	16	2.10
पी 4 ए 12	एंजेंगो	11	28	आर्टरी/वाइकोम	..	15	2 10
पी 4 ए 13	एंजेंगो	13	11	आर्टरी	..	13	2.10
	क्वीलैंडी	9	11				
बहुणापट बुनाई : —							
पी० ए 1	एंजेंगो	15	32	वाइकोम	..	18	2.20
पी० ए 2	एंजेंगो	15	32	वाइकोम	..	13	2.10

कयर मुर्जोक : —

(क) सामान्य विशेषताएं : —ताने धागों को पूर्ण रूप से छिपाते हुए पूर्ण रूप से फेब्रिक के दोनों तरफ कयर भुर्जाक तथा कयर कालीन (अलप्पी कालीन) प्रमुख थी। रंग वाने धागे को प्रयोग करते हुए डिजाइन बुने जाते हैं। फेब्रिक में ताने धागों की संख्या तुलनात्मक रूप से बाना से कम है।

(ख) संरचनात्मक विवरण : —

1	2	3	4	5	6	7	8
बी एम ए एल	एलोई पतला	16	10	अलपाट	14	45	2.15
बी एल ए आर	एलोई पतला	16	10	आर्टरी	14	45	2.05
बी एम ए एन	एलोई पतला	16	10	एंजेंगो	15	47	1 90
बी एम वी एन	वाइकोम	14	10	एंजेंगो	15	38	2.05
बी एम वी एल	वाइकोम	14.	10	अलपाट	12	38	2.05
बी एम वी आर	वाइकोम	14	10	आर्टरी	13	42	1.90
बी एम जे एल/(बी एम ए बी)	जूट	5 प्लाई	10	अलपाट	12	40	2.35
बी एम ए एल 1	एलोई पतला	16	10	वाइकोम	14	52	2.35
एस एम एन क्यू	एंजेंगो	14	15	क्वीलैंडी	9	28	2.70
बी सी एस क्यू 10	क्वीलैंडी		12/एफटी	क्वीलैंडी	..	45/50	3.20
बी एम बी पी	वाइकोम	13/14	5	रस्सी बाधना	5/6	15/16	3.95
कयर कालीन (अलप्पी कालीन)							
बी सी एस आर	वाइकोम	14	12*	आर्टरी	16	57	2.35
बी सी एस आर 1	वाइकोम	14	12*	आर्टरी	14	52	2.45
बी सी एस आर 2	वाइकोम	14	12*	वाइकोम	13	50	2.15
बी सी एस डी	छः दोहरी लड़ियां *बीच	7/8	6	अष्टमुडी	8/9	29/30	3.05
सजावटी गुंथे हुए कालीन							

क्वालिटी संख्या	सूत की क्वालिटी	गुथे हुए	भार
1	2	3	4
पी बी आर ए	एंजेंगो	तीन प्लाई कयर के गुथा हुआ। प्रत्येक प्लाई कयर तंतु की दो प्लाई की तीन (3) लड़ियों से बनाई गई है।	1-90 (1.90)
एफ बी क्यू-1	क्वीलैंडी	तीन प्लाई कयर से गुथा हुआ। प्रत्येक प्लाई दो प्लाई कयर तंतु की दो लड़ियों से बनाई गई।	

कयर मैटिंग के पीछे रबड़ पेस्ट किया हुआ : —

क्वालिटी की सं.	सूत की क्वालिटी	लगभग स्कोरेज	नीचे दिए गए लड़ियों की सं. प्रति डे. मी.	अस्तरण सामग्री	बांधने की सामग्री तथा प्रसंस्करण
आर एम वाई-1	बैंगोर	8	13	हैसियत कम से कम 8 और क्वालिटी	वर्कनाइजिक अंश और बिना धब्बे वाले एंटी ओक्सीडेंट सहित रबड़ लेटेक्स।
आर एम वाई-2	बैंगोर	8	12	सूती कवेज	वर्कनाइजिक अंश और बिना धब्बे वाले एंटी ओक्सीडेंट सहित रबड़ लेटेक्स।
*आर एम क्यू-1	क्वीलैंडी	10	16	हैसियत कम से कम 8 औस क्वालिटी	वर्कनाइजिक अंश और बिना धब्बे वाले एंटी ऑक्सीडेंट सहित रबड़-टेक्स।
आर एम क्यू-2	क्वीलैंडी	10	16	क्राफ्ट कागज पर चिकनाई सूती जाली।	वर्कनाइजिक अंश और बिना धब्बे वाले एंटी ऑक्सीडेंट सहित रबड़ लेटेक्स।
आर एम ए-1	एंजेंगो	16	27	हैसियत कम से कम 10 औस क्वालिटी	वर्कनाइजिक अंश और बिना धब्बे वाले एंटी ऑक्सीडेंट सहित रबड़ लेटेक्स।
आर एम क्यू बी-1	क्वीलैंडी समानांतर तथा बिना पीछे की तरफ गेप के 10 स्कोरेज 5 प्लाई में गूंथकर बनाए गए।			हैसियत 10 औस क्वालिटी	वर्कनाइजिक अंश और बिना धब्बे एंटी ऑक्सीडेंट 3.50 कि.ग्राम प्रति मीटर वर्ग दबाव पर लेटेक्स के हैसियत के पीछे रबड़ सहित साफ तरह से गोटा लगाते हुए।

*यह प्रकार वर्गाकार टाइलों की तरह बनाया जाता है जो कि इस अवस्था में एक साथ सी जाती है कि कालीन आकार बन सके। प्रत्येक टाइल के धागे की बनावट में क्रास प्रभाव देने के लिए वर्गाकार टाईलों को एक प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है।

रबड़ का अन्तरण लगा हुआ मैटिंग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एस 2 बी आर वी 1	आर्टरी	16	25	वाइकोम	—	12	1.29	ताने में दो लड़ियां केन्द्र में हटाई गई।
एच एफ क्यू 1	फ्रेम मैटिंग क्वीलैंडी	9	16	क्वीलैंडी	—	16	2.70	

रिबड़ मैटिंग :—

(क) सामान्य विशेषताएं :—संरचना में मैटिंग वो ट्रेडन बुनाई की है किन्तु प्रदर्शित रिबड़ का प्रभाव सतह पर पड़ता है। ये सामान्य सादी बुनी मैटिंग की अपेक्षाकृत भारी तथा घनी होती है :

(ख) संरचनात्मक विवरण :—

क्वालिटी सं०	ताना				बाना						
	ढीला		कठोर		अनुपात मिरे						
	धागे की क्वालिटी	लगभग स्कोरेज	धागे की क्वालिटी	लगभग	ढीले	सख्त	ढीले	सख्त	धागे की क्वालिटी	न्यूनतम गांठें डे.मी.	भार कि.ग्राम मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एस के 1	एंजेंगो	15	एंजेंगो	17	2	1	20	10	आर्टरी	20	2.35
एस के 2	वाइकोम	12	सीसल	—	2	1	20	10	वाइकोम	16	2.40
एस के 3	वाइकोम	11	वाइकोम	13	1	2	9	18	वाइकोम	20	2.44
एस के 4	आर्टरी	13	वाइकोम	13	2	1	16	8	अच्छा बिना भिगोया हुआ	10	3.62
एस के 5	एंजेंगो	14	वाइकोम	13	2	1	18	9	वाइकोम	20	3.35
एस के 6	वाइकोम	12	वाइकोम	12	1	1	11	11	वाइकोम/बीच	24	2.30
एस के 7	वाइकोम	11	वाइकोम	13	1	2	8	16	वाइकोम	16	1.83
एस के 8	आरटरी	18	वाइकोम	14	2	1	16	8	वाइकोम	16	2.14
एस के 9	अष्टमुड़ी	8	वाइकोम	12	1	2	8	16	वाइकोम	20	3.05
एस के 10	आरटरी	12	वाइकोम	13	1	2	9	18	वाइकोम	20	2.45
एस के 11	आरटरी	15	वाइकोम	14	1	2	9	18	वाइकोम	20	2.10
एस के 12	आरटरी	14	आरटरी	16	1	2	13	13	वाइकोम	18	2.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एस के 13	वाइकोम	13	वाइकोम	13	2	1	14	7	वाइकोम	23	3.20
एस के 14	एंजेंगो	15	एंजेंगो	16	2	1	22	11	वाइकोम	23	2.80
एस के 15	एंजेंगो	14	सीसल	600 एम कि. ग्राम रनेजा	2	1	18	9	आरटरी	18	2.80
एस के 16	एंजेंगो	14	एंजेंगो	15	1	1	11	14	सीसल/वाइकोम	18	2.25
एस के 17	एंजेंगो	13	एंजेंगो	14	1	1	14	14	वाइकोम	16	2.44
एस के 18	वाइकोम	12	एंजेंगो	14	2	1	20	10	एंजेंगो	18	3'00
एस के 19	एंजेंगो	15	एंजेंगो	16	1	2	9	18	एंजेंगो	22	2.20
एस के 20	वाइकोम	14	वाइकोम	14	2	1	18	9	वाइकोम	22	2.40
एस के 21	एंजेंगो	13	एंजेंगो	13	2	1	18	9	आरटरी	16	2.55
एस के 22	वाइकोम	14	एंजेंगो	15	2	1	20	10	एंजेंगो	18	2.50
एस के 23	एंजेंगो	13	आरटरी	13	1	1	11	11	वाइकोम	22	2.70
एस के 24	वाइकोम	14	एंजेंगो	15	2	1	18	9	क्वीलैंडी	16	3.10
एस के 25	क्वीलैंडी	9	एंजेंगो	14	2	1	14	7	बेपोर	10	4.10
एस के 26	एंजेंगो	13	एंजेंगो	13	2	1	18	9	क्वीलैंडी	16	3.20
एस के 27	एंजेंगो	15	एंजेंगो	17	2	1	20	10	वाइकोम	22	2.20
बिजली, करघे के विभिन्न रिबेड मैटिंग:—											
पी के एम 1	मंगावन	12	मंगावन के	13	1	1	10	10	वाइकोम	14	2.00
पी के एम 2	एंजेंगो एम	13	एंजेंगो एम	14	1	1	13	13	वाइकोम	13	2.10
पी के एम 3	एंजेंगो एम	14	एंजेंगो	15	2	1	18	9	एंजेंगो/आरटरी	16	2.10
पी के एम 4	मंगावन के	12	मंगावन के	13	1	1	12	12	आरटरी	13	1.80
पी के एम 5	एंजेंगो	13	एंजेंगो	14	1	1	15	15	बोच	16	2.20
पी के एम 6	एंजेंगो	14	सीसल	600 मी. कि.	2	1	18	9	सीसल	18	2.30
पी के एम 7	वाइकोम	12	सीसल	600 मी.कि.	2	1	18	9	वाइकोम	18	2.40
पी के एम 8	एंजेंगो	16	सीसल		2	1	22	11	सीसल	18	2.00
पी के एम 9	एंजेंगो	13	एंजेंगो	12	2	1	18	9	आरटरी	18	2.90
पी के एम 10	एंजेंगो	15	एंजेंगो	17	2	1	22	11	आरटरी	18	2.10
पी के एम 11	एंजेंगो	15	एलोई पतला	—	2	1	22	11	एलोई पतला	19	2.00
पी के एम 12	एंजेंगो	18	एलोई पतला	—	1	1	22	22	एलोई/पतला	36	1.65
पी के एम 13	एंजेंगोएम	12	2 प्लाई सीसल	330 एम/कि.	2	1	20	10	सीसल 330एम/ कि. ग्राम.	20	3.20
पी के एम 14	एंजेंगो	18	5 प्लाईजूट	—	1	1	22	22	3 प्लाई जूट	36	1.85

'कयर मैटिंग, कयर मैटिंग के गलीचों, कयर मैटिंग की चटाईयों, कयर मुर्जोकि और कयर कालीनों (अलप्पी कालीनों) के लिए अनुज्ञेय सहिष्णुता ।

1. विमाए :— जब तक कि विक्रेता और विक्रेता के बीच विशेष रूप से अन्यथा करार न हो, विमाओं में निम्नलिखित सहयताएं अनुज्ञात की जाएंगी :—

(1) कयर मैटिंग :—

लम्बाई ± 1. प्रतिशत न्यूनतम शून्य

चौड़ाई 180 सें०मी० तक ± 13 मि०मी
180 सें०मी० से अधिक ± 25 मि०मी०

(2) कयर मैटिंग गलीचे तथा कयर मुर्जोक :—

लम्बाई ± 13 मि०मी०

चौड़ाई 180 सें०मी० तक ± 13 मि०मी०
180 सें०मी० से अधिक ± मि०मी०

(3) कयर मैटिंग चटाईयां :—

कयर कालीन (अलप्पी कालीन) :—

लम्बाई 13 मि०मी०

चौड़ाई 13 मि०मी०

2. ताना :—प्रत्येक डेसीमीटर चैन के किनारों की संख्या अनुसूची में विनिर्दिष्ट या विशेषों के पैनल द्वारा बनाए गए और इस आदेश के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार होगी । तथापि निम्नलिखित सहयताएं अनुज्ञात की जा सकती है ।

(i) कोयर मैटिंग :—
कोयर मैटिंग 2 लड़ियां प्रति डेसीमीटर
गलीचे तथा
मैटिंग मैट्स

1 लड़ी प्रति डेसीमीटर

चिपकाई हुई कोयर मेटिंग :— 1 लड़ी प्रति डेसीमीटर

III बाना :— प्रति डेसीमीटर गांठों की संख्या अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी या विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बनाए गए और इस आदेश के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार होगी। तथापि चौड़ाई 108" (274 सें०मी० तक तथा चौड़ाई 108" (274 सें०मी० से अधिक प्रति डेसीमी०) 2 गांठों वाले गांठे कोयर मैटिंग और मैटिंग गलीचों तथा कोयर मैटिंग मैट्स के मामलों में 5 प्रतिशत की सहायता अनुज्ञात की जा सकती है। बिजली करघे से बनी मैट्स के लिए विशेष रूप से 5 प्रतिशत।

IV. भार—प्रति वर्ग मीटर भार अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा या विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बनाए गए और इस आदेश के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार होगा। भार में ±7.5 प्रतिशत की सहिष्णुता अनुज्ञात की जा सकती है।

सजावटी गुथे हुए कालीनों की सहिष्णुता ±5 प्रतिशत हो सकती है।

V. स्कोरेज :— प्रयुक्त धागे का स्कोरेज अनुसूची में दिए गए के अनुसार होगा या विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित स्कोरेज के लिए मूल्यों के अनुसार होगा। तथापि स्कोरेज के मूल्यों पर प्लस या माइनस (±) सहायता अनुज्ञात की जा सकती।

परिशिष्ट

कोयर मैटिंग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1972 को अधिक्रांत करते हुए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयर मैटिंग निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "कोयर मैटिंग" से बिजली करघा और हथकरघा पर विनिर्मित कयर मैटिंग अभिप्रेत है और उसमें निम्नलिखित भी है;

(i) कोयर मैटिंग की चटाईयां;

(ii) कोयर मैटिंग के गलीचे;

(iii) कोयर मुर्जोंकं;

(iv) कोयर के कालीन (अलप्पी कालीन);

(v) कोयर मैटिंग के अन्य प्रकार।

3. निरीक्षण का आधार :— निर्यात के लिए आशयित कोयर मैटिंग का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि कोयर मैटिंग अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मान्यताप्राप्त विनिर्देश कहा गया है) के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :— (1) कोयर मैटिंग का निर्यात करने का इच्छुक कोई निर्यातकर्ता ऐसा करने के आशय की सूचना विहित प्रारुप में लिखित रूप में निर्यात निरीक्षण अभिकरण के निकटतम कार्यालय को देगा।

(2) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना पोतलदान की आशयित तारीख से कम से कम बहत्तर घंटे पहले दी जाएगी।

(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार कोयर मैटिंग के परेषण का इस दृष्टि से निरीक्षण करेगा कि क्या वह मान्यताप्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है और निर्यातकर्ता अभिकरण को सभी सुविधाएं देगा जिससे वह ऐसा निरीक्षण कर सके।

(4) अपना यह समाधान कर लेने पर कि कोयर मैटिंग का परेषण मान्यप्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं की के अनुरूप है, अभिकरण नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन संसूचना और परेषण के विवरण प्राप्त होने पर 3 दिन के भीतर निर्यातकर्ता को यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है और निर्यात योग्य है:

परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं हो पाता है वहां वह उक्त तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा।

5. निरीक्षण का स्थान :— इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण या तो —

(क) उस परिसर पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता के कोयर मैटिंग का परेषण निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया है, परन्तु यह तब जब कि बशर्ते कि वहां इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों या,

(ख) ऐसे अन्य स्थान पर किया जाएगा, जो इस प्रयोजन के लिए अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

6. अपील :— नियम 4 के अधीन प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित अपील पैनल, जिसमें कम से कम तीन व्यक्ति होंगे को अपील कर सकेगा ।

7. निरीक्षण फीस :— इन नियमों के अधीन कयर मैटिंग और कयर मैट्स के निरीक्षण के लिए फीस निम्नलिखित दरों से निरीक्षण फीस के रुप में दी जाएगी ।

(क) कयर मैटिंग : 2.5 मीटर और उससे कम चौड़ाई वाले कयर मैटिंग के लिए प्रति परेषण कम से कम 10 रुपए के अधीन रहते हुए एक रुपया प्रति पैकेट/रोल

कयर मैटिंग के गलीचे, कयर के कालीन, और कयर मुर्जोक । : 2.5 मीटर उससे कम चौड़ाई वाले कयर मैटिंग गलीचों, कयर के कालीनों और कयर मुर्जोक के लिए परेषण कम से कम 10 रुपए, के अधीन रहते हुए एक रुपया प्रति पैकेट/रोल ।

(2) कयर मैटिंग : 2.5 मीटर के अधिक चौड़ाई वाले कयर मैटिंग के लिए प्रति परेषण कम से कम 30 रुपये के अधीन रहते हुए तीन रुपये प्रति पैकेट/रोल

(3) कयर मैटिंग के गलीचे, कयर के कालीन और कयर मुर्जोक 2.5 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले कयर मैटिंग के गलीचों, कयर के कालीनों और कयर के मुर्जोक के लिए प्रति परेषण कम से कम 30 रुपए के अधीन रहते हुए तीन रुपए प्रीत पैकेट/रोल ।

(ख) कयर मैटिंग/मैट्स : प्रति परेषण कम से कम 6 रुपए के अधीन रहते हुए 0.60 रूपए प्रति पैकेट ।

[फाइल सं० 6(2)/83-ई आईएण्डईपी)
एन० एस० हरिहरन, निदेशक

ORDER

S.O. 2894.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export Trade of India that Coir Mattings shall be subject to quality control and inspection; and whereas the Central Government has formulated the following proposals for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade Nos. S.O. 1386 dated the 3rd June, 1972 relating to Coir Mattings, and the notification of Government of India, in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1425, dated 10th April, 1982, covering revised proposals relating to Coir Mattings, except in respect of things done or omitted to be done, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within 45 days of the date of publication in this order in the official Gazette to the Export Inspection Council, Pragati Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008.

PROPOSALS

1. (1) To notify that Coir Mattings shall be subject to qualify control and inspection prior to export ;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Coir Mattings (Inspection) Rules, 1985, set out in Annexure to this Order, as the type of quality control and inspection which shall be applied to such Coir Mattings prior to export;

(3) to recognise—

(a) national and international standards and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council of India ;

(b) Contractual specifications subject to the products complying with the minimum of the characteristics specified in the Schedule to the Order and

(c) the specification which do not fall under clauses (a) and (b) above but are approved by a panel of experts appointed by the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such standards declared by the exporter as contractual specifications for Coir Mattings.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of Coir Matting unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the Coir Mattings conform to the specifications recognised under sub-paragraph (3) and are exportworthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by sea land or air of samples of Coir Mattings to prospective buyers, the value of which does not exceed Rs. 250/- per sample of any type.

3. In this Order, 'Coir Mattings' means Coir Mattings manufactured on powerloom as well as handloom and includes.—

(i) Coir Mattings mats;
(ii) Coir mattings rugs;
(iii) Coir mourzouks ;
(iv) Coir carpets (Alleppey Carpets);
(v) Any other type of coir mattings.

SCHEDULE

SPECIFICATION FOR COIR MATTINGS

1. General requirements :

1.1 The Coir Mattings shall be manufactured from bleached or unbleached coir yarn as agreed to between the buyer and the seller. The yarn shall be of two ply.

1.2 The Coir Matings shall be firmly and evenly woven.

1.3 The Coir Mattings shall be plain, dyed or stencilled or may have designs woven into them.

1.4 The Coir Mattings may be made into rugs or matting mats as agreed to between the buyer and the seller. In such cases, the cut ends of the matting mats or rugs shall either be stitched with suitable cotton thread or bound with jute, rexin or leather webbing (plain, coloured or fancy) or ends doubled back and interlaced in the body of the matting mats or rugs or rubberedged or glued edged or with rubber/rubro fibre-backed.

1.5 The Coir Matting shall not be loaded with salt or other extraneous matter.

2. Specific requirements :

2.1 The Coir Mattings or a particular quality number shall comply with the requirements for that quality number as

given in the Schedule or be in accordance with the specifications formulated by the Panel of Experts appointed for the purpose, and recognised under this Order.

2.2 Constructions.—The Coir Mattings of a particular quality number shall conform to the constructional details for that quality number as given in the schedule or be in accordance with the specifications formulated by the Panel of Experts appointed for the purpose, and recognised under this Order.

2.3 Ends and picks.—The Minimum number of warp ends and the number of picks per docimeter of coir mattings shall be in accordance with the requirements given in the schedule or be in accordance with the specifications formulated by the Panel of Experts appointed for the purpose; and recognised under this Order.

2.4 Weight.—The weight for sq. mt. shall be as specified in the Schedule or be in accordance with the specifications formulated by the Panel of Experts appointed for the purpose, and recognised under this Order.

2.5 Dimentions.—The dimensions of coir mattings shall be as specified in the export contract as agreed to between the buyer and the seller.

2.6 Permissible tolerances in respect of ends, picks, weight and dimension shall be as given in the Schedule.

3. Packing :

3.1 The Coir Mattings shall be packed as agreed to between the buyer and the seller. The packages shall be wrapped with new bessian of minimum 217 gram per meter (7 oz a yard).

3.2 Each package shall be marked with the following particulars namely :—

(a) notified quality number and brand name ;

(b) size ;

(c) number of pieces in the package ;

(d) code/name of the exporter/foreign buyer, if any ;

(e) serial number of packages ;

(f) gross weight ;

(g) shipping marks ;

HANDLOOM MATTING—TWO TREADLE PLAIN WEAVE

a. General Characteristics : Each weft thread is passed alternatively over and under successive warp thread, that is when odd ends are up even ends are down and vice versa. Both sides of the matting present the same appearance, and the matting is. therefore reversible.

b. CONSTRUCTIONAL DETAILS :

Quality number	WRAP			WEFT			Wt. kg/M
	Quality of Yarn	Approx. scorage	ends/dm. Min.	Quality of Yarn	Approx. scorage	picks per dm. Min.	
1	2	3	4	5	6	7	8
M2A1	Anjengo	15	33	Vycome/Beach	..	11	1.50
M2A2	Anjengo	14	31	Vycome/Beach	..	11	1.55
M2A3	Anjengo	13	29	Vycome/Beach	..	10	1.62
A2A4	Anjengo	12	27	Vycome/Beach	..	9	1.70
M2R1	Aratory	15	33	Vycome/Beach	..	11	1.42
M2R2	Aratory	41	31	Vycome/Beach	..	11	1.47
M2R3	Aratory	13	29	Vycome/Beach		10	1.55
M2R4	Aratory	12	27	Vycome/Beach	..	9	1 62
M2V1	Vycome	15	33	Calicut/Beach	..	9	1.35
M2V2	Vycome	14	30	Calicut/Beach	..	9	1.42
M2V3	Vycome	12	27	Calicut/Beach	..	9	1.52
M2B0	Beach	11	20	Beach/Hard Unsoa Ked.	..	9	1.18
M2B1	Beach	11	22	Beach/Hard Unsoaked	..	9	1.30
M2B2	Beach	9	20	Beach/Hard Unsoaked		9	1.40
S2M1	Anjengo	17	39	Vycome	..	12	1.40
S2M2	Aratory	14	31	Aloe		11	1.50
S2M3	Vycome	11	22	Vycome/Beach	..	9	1.25
S2M4	Anjengo	13	19	Vycome	..	10	1.40
S2M5	Beypore	7	15	Beach	..	7	2.10
S2M6	Ashtamudi	9	18	Vycome	..	9	1.90
S2M7(2×1)	Beypore	6	14	Beypore	..	5	2.65
S2M8	Quilandy	8	20	Vycome	..	7	2.10
S2M9	Quilandy	9	18	Quilandy	..	7	2.10
S2M10 (2×1)	Vycome Thin	—	36	Vycome thin	..	12	2.10

TWO TREADLE BASKET WEAVE

(a) General Characteristics : Same as two treadle plain weave, but two or more threads of coir yarn work together both warp wise and weft wise. This enables productions of stripe and check (Tile) patterns. Matting is reversible.

(b) Constructional Details : (3×3, 3×2, 2×2, 1×2)

1	2	3	4	5	6	7	8
M2BA1	Anjengo	15	30	Anjengo/Aratory	..	17	1.72
M2BA2	Anjengo	14	28	Anjengo/Aratory	..	17	1.80

1	2	3	4	5	6	7	8
M2BA3	Anjengo	13	26	Anjengo/Aratory	..	16	1.82
M2BA4	Anjengo	15	30	Vycome	..	17	1.62
M2BA5	Anjengo	14	28	Vycome	..	17	1.68
M2BA6	Anjengo	13	26	Vycome	..	16	1.72
M2BR1	Aratory	15	30	Aratory	..	17	1.68
M2BR2	Aratory	14	28	Aratory	..	17	1.72
M2BR3	Aratory	13	26	Aratory	..	16	1.80
M2BR4	Aratory	15	30	Vycome	..	17	1.58
M2BR5	Aratory	14	28	Vycome	.	17	1.62
M2BR6	Aratory	13	26	Vycome	..	16	1.68
M2BV1	Vycome	14	28	Vycome	..	16	1.47
M2BV2	Vycome	13	26	Vycome	..	16	1.52
M2BV3	Vycome	12	24	Vycome	..	15	1.58
M2BB1	Beach	10	20	Beach	..	15	1.38
S2BM1	Anjengo	16	34	Anjengo	..	17	1.62
S2BM2	Ashtamudi	10	23	Vycome	..	14	2.30
S2BM3	Anjengo M	12	25	Anjengo M	.	12	2.62
S2BM4	Anjengo	16	32	Superfine Aloe	..	21	1.75
S2BM5	Anjengo (4×4) weave)	14	28	Anjengo	..	24	2.15
S2BM7	Quilandy (4×4)	10	20	Quilandy	..	15	2.80
S2BM8 (8×8)	Quilandy	8	20	Quilandy	..	20	3.10
S2BM9 (4×4)	Roping	6	11	Roping	..	9	3.60
S2MB10	Beypore	7	16	Beypore	..	8	3.00

MESH MATTINGS

(a) General Characteristics : The weave of this matting is same as two treadle, with the difference that the warp and weft stards are positioned at a distance to provide Mcash effect.

(b) Constructional Details :

1	2	3	4	5	6	7	8
H2M1	Anjengo	14	9	Vycome	..	8	0.650
H2M2	Beach	9	8	Beach	.	7	0.700
H2M3	Aratory	15	*14	Aratory	..	14	0.875
H2M4	Anjengo	12	**19	Aractory	..	11	1.400
H2M5	Vycome	13	9	Vycome	..	8	0.740
H2M6	Vycome (Common)	12	46	Vycome (Common)	..	40	0.400
			per Mtr.			Per Mtr.	

* WARP is arranged in pairs; each starand of the pair is woven alternately with the other.

** WARP is arranged in groups of 3 strands; each group of the pair is woven alternately with the adjacent one.

THREE TREADLE WEAVE :

(a) General Characteristics : This weave is employed to obtain a thicker and betterlooking/matting than the two Treadle. This type of weave produces a diagonal or a wavy effect. The Twill lines are formed on the fabric on one side only. Hence the matting is non-reversible.

(b) Constructional Details :

1	2	3	4	5	6	7	8
M3A1	Anjengo	16	35	Vycome/Beach	..	11	1.58
M3A2	Anjengo	15	33	Vycome/Beach	..	11	1.62
M3A3	Anjengo	14	31	Vycome/Beach	..	11	1.68
M3A4	Anjengo	13	29	Vycome/Beach	..	10	1.75
M3A5	Anjengo	12	27	Vycome/Beach	..	10	1.82
M3R1	Aratory	16	35	Vycome/Beach	..	11	1.50
M3R2	Aratory	15	33	Vycome/Beach	..	11	1.55
M3R3	Aratory	14	31	Vycome/Beach	..	11	1.60
M3R4	Aratory	13	29	Vycome/Beach	..	10	1.68
M3R5	Aratory	12	27	Vycome/Beach	..	10	1.75
M3C1	Ashtamudi	1	24	Vycome/Beach	..	9	2.08
M3V1	Vycome	14	31	Vycome/Beach	..	10	1.40
M3V2	Vycome	13	29	Vycome/Beach	..	9	1.45
M3V3	Vycome	12	27	Vycome/Beach	..	9	1.52

1	2	3	4		6	7	8
M3B1	Beach	10	22	Beach/Hard Unsoaked	..	9	1.40
S3M1	Anjengo	15	33	Alapat	..	12	2.00
S3M2	Anjengo	16	40	Vycome/Alapat	..	11	2.00
S3M3	Vycome	11	24	Vycome	..	10	1.70
S3M4	Anjengo	15	31	Vycome/Beach	..	11	1.52
S3M5	Anjengo	14	34	Vycome	..	11	1.88
S3M6	Anjengo	11	27	Ashtamadi	..	9	2.96
S3M7	Anjengo	15	37	Vycome	..	11	1.80
S3M8	Anjengo	14	31	Anjengo/Aratory	..	13	1.67
S3M9	Anjengo	13	36	Anjengo	..	19	1.90
	Anjengo	17					

FOUR TREADLE WEAVE :

(a) General Characteristics : This is more ornate in appearance and can be either reverisible or non-reverisble. This weave is used for production of superior quality mattings in a variety of patterns such as Twill, Diamond, Etc.

(b) Constructional details :

1	2	3	4	5	6	7	8
M4A1	Anjengo	15	33	Vycome	..	13	1.70
M4A2	Anjengo	14	31	Vycome	..	13	1.75
M4A3	Anjengo	13	29	Vycome	..	13	1.82
M4A4	Anjengo	12	27	Vycome	..	13	1.90
M4R1	Aratory	15	33	Vycome	..	13	1.62
M4R2	Aratory	14	31	Vycome	..	13	1.68
M4R3	Aratory	13	29	Vycome	..	13	1.75
M4R4	Aratory	12	27	Vycome	..	13	1.82
M4V1	Vycome	14	31	Vycome	..	12	1.47
M4V2	Vycome	13	29	Vycome	..	12	1.55
M4V3	Vycome	12	27	Vycome	..	12	1.62
S4M1	Anjengo	16	36	Vycome	..	17	1.50
S4M2	Anjengo	15.	33	Anjengo	..	17	1.75
S4M3	Aratory	14	31	Aratory	..	14	1.75
S4M4	Anjengo	13	32	Vycome	..	15	2.13
S4M5	Anjengo	14	33	Vycome	..	14	2.20
S4M6	Anjengo & Sisal	14	31	Sisal	..	18	1.78
S4M7	Anjengo & Aloe	14	31	Aloe	.	18	1.87
S4M8	Anjengo	14	33	Alapat	..	12	2.00
S4M9	Anjengo	16					
	Anjengo	13	29	Anjengo	..	15	1.80
S4M10	Anjengo	16	35	Anjengo	..	12	1.75
S4M11	Anjengo	14	31	Anjengo/Aratory	..	14	1.82
S1M12	Slack-Aratory		8	Ordy. Aratory	..	14	2.55
	Tight Aratory	15	23	Extra Aratory 4 ply role		7	
S4M13	Beypore	6	14	Bypore	..	7	2.80
S4M14	1. Beypore/Quilandy/	8	13				
	2. Aratory	14	13	Aratory	..	9	2.60
S4M15	Quilandy/	8	11				
	Anjengo	13	11	Anjengo	..	11	1.95
S4M16	Aloe	10	20	Quilandy	..	9	2.40
S4M17	Quilandy	9	20	Quilandy		9	2.62
S4M18	Quilandy	10	16	Quilandy	..	14	2.55
S4M19	Quilandy	9	11	Anjengo	..	18	1.96
S4M20	Slack, Anjengo	15	5	Extra : Anjengo	..	11	(Basket weave)
	Tight : Anjengo	14	19	Extra : Quilandy	..	11	2.20
S4M21	Anjengo	11	24	Anjengo M	..	18	3.10
S4M22	Vycome Thin	20	40	Vycome	..	17	1.35

SPECIAL REED MATTINGS :

(a) General Characteristics : This type of matting exhibits warp strands in pairs working to gether is woven on closer reeds to ensure distribution of warp uniformly without over-lapping.

(b) Constructional details :

1	2	3	4	5	6	7	8
SR4M1	Aratory	15	26	Vycome	..	18	1.40
SR4M2	Anjengo	14	29	Aratory	..	16	1.75
SR4M3	Aratory	13	26	Vycome	..	16	1.68

MULTI SHAFT COIR MATTING

(a) General Characteristics : These mattings generally incorporate designs which require more than four shaft weave. Mattings with more elaborate patterns woven on looms mounted with Dobby & Jacquard shedding machanisms are also brought under this category.

(b) Constructional details :

1	2	3	4	5	6	7	8
S0M1	Anjengo	12	30	Vycome	..	14	2.00
S0M2	Anjengo	14	26	Anjengo	..	18	2.00
S0M3	Anjengo	16	35	Anjengo/Aloe/Sisal	..	12	1.70
S0M4	Quilandy	8	20	Quilandy	..	15	3.20
S0M5	Anjengo P.O. Bleached	15	21	Vycome	..	26	1.32
S0M6	Quilandy	9	20	Quiladny	..	8	2.62
S0M7	Quilandy	9	20	Quilandy	..	18	4.00

B. Constructional details of Powerloom Mattings:

(a) General Characteristics : Mattings in two shift, thsee shift, four shift, and Multishaft weaves are produced on powesloom also. They are comparatively denser than the HandloomMattings. :

(b) Constructional details :

TWO TREADLE PLAIN WEAVE :

1	2	3	4	5	6	7	8
P2A1	Anjengo	13	28	Vycome	..	13	1.70
P2A2	Quilandy/Ashtamudi	10	22	Vycome	..	10	2.00
P2A3	Quilandy/Ashtamudi	9	16	Vycome	.	7	1.80
P2A4	Quilandy (1 × 2)	9	21	Vycome	..	17	2.40
P2A5	Anjengo	2	26	Aratory/Vycome	..	13	1.80
P2A6	Anjengo	15/16	42	Anjengo	..	11	1.76
2. Treadle Basket Weave							
P2BA1	Anjengo	12	30	Vycome	.	16	2.00
P2BA2	Anjengo	14	32	Anjengo/Aratory	18	18	2.20
P3BA3	Anjengo	14	28	Anjengo/Aratory	16	16	2.00
P2BA4	Anjengo	13	28	Anjengo/Aratory (loose twist)	.	14	1.80
P2BA5	Anjengo	16	32	Anjengo	.	22	2.00
P2BA6	Anjengo	15	32	Anjengo	.	21	1.80
P2BA7	Quilandy	9	10	Anjengo	..	16	2.10
P2BA8	Anjengo	15	36	Anjengo	16	18	1.80
3. Treadle Weave							
P3A1	Anjengo	13	28	Vycome	..	14	1.80
P3A2	Anjengo (2 Ply Aloe Thin (equal no. of strands)	18	42	Anjengo	18	24	1.85
4. Tradle Weave :							
P4A1	Anjengo	13	30	Vycome	.	16	1.95
P4A2	Anjengo	14	32	Vycome/Aratory	..	17	2.20
P4A3	Anjengo	14	28	Vycome/Aratory	..	16	2.00
P4A4	Anjengo Mangadan K 2/3 Sisal 1/3 Starands.	13	26	Vycome	..	17	1.96
P4A5	Ang. M or Mangadan K 2/3 Strands Sisal 1/3 Strands	13	25	Vycome	..	16	1.80
P4A6	Anjengo M	13	29	Vycome	..	12	2.20
P4A7	Anjengo	12	28	Vycome	..	14	1.80
P4A8	Anjengo	16	32	Anjengo	.	22	2.00
P4A9	Anjengo	15	32	Anjengo	.	21	1.80
P4A10	Anjengo M	12	27	Vycome	..	14	2.20
P4A11	Quilandy	9	10	Anjengo	..	16	2.10
P41A12	Anjengo	11	28	Aratory/Vycome	..	15	2.10
P4A13	Anjengo	13	11	Aratory	..	13	2.10
	Quilandy	9	11				
Multi shaft weave							
POA1	Anjengo	15	32	Vycome	..	18	2.20
POA2	Anjengo	15	32	Vycome	..	13	2.10

COIR MOURZOUKS :

(a) General Characteristics : In coir Mourzouks and Coir Carpets (Alleppey Carpets) were predominates or both sides of the fabric concealing the warp threads completely. The disigns are woven by using coloured weft threads. The number of warp thereads in the fabric are comparatively lesser than the weft.

(b) Constructional details :

1	2	3	4	5	6	7	8
BMAL	Aloe Thin	16	10	Alapat	14	45	2.15
BMAR	Aloe Thin	16	10	Aratory	14	45	2.05
BMAN	Aloe Thin	16	10	Anjengo	15	47	1.90
BMVN	Vycome	14	10	Anjengo	13	38	2.05
BMVL	Vycome	14	10	Alapat	12	38	2.05
BMVR	Vycome	14	10	Aratory	13	42	1.90
BMJL (VMAV)	Jute	5 Ply	10	Alapat	12	40	2.35

1	2	3	4	5	6	7	8
BMAL,1	Aloo Thin	16	10	Vycome	14	52	2.35
SMNQ	Anjengo	14	5	Quilandy	9	28	2.70
SCSQ10	Quilandy		12 Ft	Quilandy	..	45/50	5.20
BMVP	Vycome	13/14	5	Roping	5/6	15/16	3.95
	Coir Carpets (Alleppey Carpets)						
BCSR	Vycome	14	12*	Aratory	16	57	2.35
BCSR1	Vycome	14	12*	Aratory	14	52	2.45
BCSR2	Vycome	14	12*	Vycome	13	50	2.15
BSD	Beach	7/8	6	A Shtamudy	8/9	29/30	3.05

*Six double steands.

Fancy Braided Carpets :

Quality number	Quality of Yarn	Braid	Weight
1	2	3	4
PBRA-1	Anjengo	3 Ply Coir Braid each ply is formed by laying 3 strands of 2 ply Coir Yarn.	1—90(1.90)
FBQ-1	Quilandy	3 Ply Coir Braid each ply is formed by laying 2 strands of 2 ply Coir Yarn.	

RUBBER BACKED PASTED COIR MATTINGS :

Quality number	Quality of yarn	Approx. scorage	No. of strands laid per dm. min.	Backing material	Binding Material & processing
1	2	3	4	5	6
RMY-1	Beypore	8	13	Hessian-Minimum 8 oz. quality	Rubber latex containing vulcanising ingredients and non-staining antioxidants.
*RMY-2	Beypore	8	12	Cotton guaze	-do-
RMQ-1	Quilandy	10	16	Hessian Min. 8 oz. quality	-do-
RMQ-2	Quilandy	10	16	Cotton guaze pasted on kraft paper	-do-
RMA-1	Anjengo	16	27	Hessian-Min 10 oz. quality	-do-
RMQB-1	Quilandy 10 scorage made into 5 ply braid, laid parallely and without gap.			Hessian 10 oz. quality rubber backed.	Clearly laid braid bounded with rubber backed hessian using latex containing vulcanizing ingredients and non-straining antioxidants, hot pressed Kg. 3.50 per M^2

* This variety is made as sq. tiles which are stitched togehter in juxraposition to be made into rug sizes. The sq. tiles are so arranged to give a cross-effect in the lay of the yarn tile.

RUBBER PACKING MATTINGS

1	2	3	4	5	6	7	8
S2RB1	Aratory	16	25	Vycome	..	12	1.29 2 strands in the warp omitted in the centre.
	FRAME MATTING						
HFQ1	Quilandy	9	16	Quilandy	..	16	2.70

RIBBED MATTINGS :

(a) General Characteristics : Mattings are Two Treadle weave in construction, but exhibit ribbed effect on the surface. They are comparatively heavier and denser than the ordinary plain weave Mattings.

(b) Constructional details :

Quality No.	WARP				Ratio ends		WEFT				
	Slack Quality of yarn	App. Sec.	Thight Quality of yarn	App. Sec.	Slack	Tight	Slack	Tight	Quality of yarn	Picks min. dm	Wt. Kgs. M^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK1	Anjengo	15	Anjengo	17	2	1	20	10	Aratory	20	2.35
SK2	Vycome	12	Sisal	..	2	1	20	10	Vycome	16	2.40
SK3	Vycome	11	Vycome	13	1	2	9	18	Vycome	20	2.44
SK4	Aratory	13	Vycome	13	2	1	16	8	Finae unsoaked	10	3.62
SK5	Anjengo	14	Vycome	13	2	1	18	9	Vycome	20	3.35
SK6	Vycome	12	Vycome	12	1	1	11	11	Vycome/Beach	24	2.30
SK7	Vycome	11	Vycome	13	1	2	8	16	Vycome	16	1.83
SK8	Aratory	18	Vycome	14	2	1	16	8	Vycome	16	2.14
SK9	Ashtamudy	8	Vycome	12	1	2	8	16	Vycome	20	3.05
SK10	Aratory	12	Vycome	13	1	2	9	18	Vycome	20	2.45
SK11	Aratory	15	Vycome	14	1	2	9	18	Vycome	20	2.10
SK12	Aratory	14	Aratory	16	1	1	13	13	Vycome	18	2.25
SK13	Vycome	13	Vycome	13	2	1	14	7	Vycome	23	3.20
SK14	Anjengo	15	Anjengo	16	2	1	22	11	Vycome	23	2.80
SK15	Anjengo	14	Sisal	600 M kg runnage	2	1	18	9	Aratory	18	2.80
SK16	Anjengo	14	Anjengo	15	1	1	14	14	Sisal/Vycome	18	2.25
SK17	Anjengo	13	Anjengo	14	1	1	14	14	Vycome	16	2.44
SK18	Vycome	12	Anjengo	14	2	1	20	10	Anjengo	18	3.00
SK19	Anjengo	15	Angengo	16	1	2	9	18	Anjengo	22	2.20
SK20	Vycome	14	Vycome	14	2	1	18	9	Vycome	22	2.40
SK21	Anjengo	13	Anjengo	13	2	1	18	9	Aratory	16	2.55
SK22	Vycome	14	Anjengo	15	2	1	20	10	Anjengo	18	2.50
SK23	Anjengo	13	Aratory	13	1	1	11	11	Vycome	22	2.70
SK24	Vycome	14	Anjengo	15	2	1	18	9	Quilandy	16	3.10
SK25	Quilandy	9	Anjengo	14	2	1	14	7	Beypore	10	4.10
SK26	Anjengo	13	Anjengo	13	2	1	18	9	Quilandy	16	3.20
SK27	Anjengo	15	Anjengo	17	2	1	20	10	Vycome	22	2.20
	Powerloom Varieties of ribbed mattings :										
PKMK1	Mangadan K	12	Mangadank	13	1	1	10	10	Vycome	14	2.00
PKM2	Anjengo M	13	Anjengo	14	1	1	13	13	Vycome	13	2.10
PKM3	Anjengo M	14	Anjengo	15	2	1	18	9	Anjengo/ Aratory	16	2.10
PKM4	Mangadan K	12	Mangadan K	13	1	1	12	12	Aratory	13	1.80
PKM5	Anjengo	13	Anjengo	14	1	1	15	15	Beach	16	2.20
PKM6	Anjengo	14	Sisal	600M/ Kg	2	1	18	9	Sisal	18	2.30
PKM7	Vycome	12	Sisal	600M/ Kg.	2	1	18	9	Vycome	18	2.40
PKM8	Anjengo	16	Sisal		2	1	22	11	Sisal	18	2.00
PKM9	Anjengo	13	Anjengo	12	2	1	18	9	Aratory	18	2.90
PKM10	Anjengo	15	Anjengo	17	2	1	22	11	Aratory	18	2.10
PKM11	Anjengo	15	Thin Aloe	..	2	1	22	11	Thin Aloe	18	2.00
PKM12	Anjengo	18	Thin Aloe	..	1	1	22	22	Thin Aloe	36	1.85
PKM13	Anjengo M	12	2 ply sisal	330 M/kg	2	1	20	10	Sisal 330 M/kg	20	3.20
PKM14	Angengo	18	5 ply jute	1	1	1	22	22	3 ply jute	36	1.85

Tolerances permitted for coir mattings, coir matting rugs, coir matting, masts, coir mourzouks and coir carpets (Alleppey Carpets)

1. Dimensions :

Unless specifically agreed otherwise between the buyer and the seller, the following tolerances in dimensions shall be allowed.

(i) Coir mattings :	
Length	—+1% minus nil.
Width	—upto 180 cm, ±13 mm.
	—above 180 cm ±25 mm.
(ii) Coir mattings rugs and Coir mourzouks :	
Length	—±13 mm.
	—±upto 180 cm+13 mm.
	—+above 180 cm+25 mm.
(iii) Coir matting mats.	
Coir carpets (Alleppey Carpets)	
Length	—±13 mm.
	—±13 mm.

II Warp

The no. of chain ends per dm. shall be as specified in the schedule or be in accordance with the specifications formulated by the panel of experts and recognised under this order. The following tolerances may however be allowed—

(i) Coir mattings.	
Coir matting Rugs.	
and coir mattings mats	+2 strands per dm.
	—1 strand per dm.
Pasted coir matting	—1 strand per dm.

III Weft

The no. of picks per dm. shall be as specified in the schedule or be in accordance with the specifications formulated by the panel of experts and recognised under this order. A minus tolerance of 5% may however be allowed in the case of Coirmating coir matting rugs, and coir matting mats upto a width of 108" (274 cms) and for width over 108" (274 cms) 2 picks per D.M. Spl. treader for powerloom matting picks 5%.

IV. Weight :

The weight per sq. m. shall be as specified in the Schedule or in accodance with the specifications formulated by the panel of experts and recognised under this order. A tolerances of $\pm 7.5\%$ in the weight may be allowed.
-5%

Fancy Braided Carpets may have a tolerance of ±5%

V. Scorages :

The scorage of the yarn used shall be as given in the Schedule or in accordance with the values for scorage approved by the panel of experts. A tolerance of plus or minus 1 may however be allowed on the values of the scorages.

ANNEXURE

(Draft rules proposed to be made, in supersession of the Export of Coir Mattings (Inspection) Rules, 1972 under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Export of Coir Mattings (Inspection) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the Export Inspection Agencies recognised under section 7 of the Act;

(c) "Coir Mattings" means Coir Mattings manufactured on powerloom as well as handloom and includes;

(i) Coir matting mats;

(ii) Coir matting rugs;

(iii) Coir mourzouks;

(iv) Coir Carpets (Alleppey Carpets);

(v) any other type of Coir Mattings.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Coir Mattings intended for export shall be carried out with a view to seeing that the Coir Mattings conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act (hereinafter referred to as the recognised specifications).

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export Coir Mattings shall give an intimation in writing in the prescribed form of his intention so to do to the nearest office of the Export Inspection Agency.

(2) Every intimation for this purpose shall be given not less than seventy-two hours before the expected date of shipment.

(3) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the Agency shall inspect the consignment of Coir Mattings in accordance with the instructions issued by the Export Inspection Council from time to time in this behalf with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications, and the exporter shall provide all necessary facilities to the Agency to enable it to carry out such inspection.

(4) After satisfying itself that the consignment of Coir Mattings conforms to the recognised specifications, the Agency shall within 3 days of the receipt of the intimation and the particulars of the consignment under sub-rule (1) issue a certificate to the exporter declaring that the consignment is in conformity with the recognised specifications and is exportworthy:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within that said period of 3 days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons thereof.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either :

(a) at the premises at which the consignments of Coir Mattings are offered by the exporter for inspection,

provided adequate facilities for the purpose exist therein ; or

(b) such other place as may be specified by the Agency for the purpose.

6. Appeal.—Any person aggrieved by the refusal to issue a certificate under rule 4 may, within ten days of receipt of the communication of such refusal, prefer an appeal to such appellate panel consisting of not less than three persons as may be constituted by the Central Government for the purpose.

7. Inspection fee.—A fee at the following rates shall be paid as inspection fee for the inspection of Coir Mattings and Coir Matting Mats under the rules.

(a) (i)	Coir Mattings :	Rs. 1/-per packet/roll subject to a minimum of Rs. 10/- per consignment for the Coir mattings of 2.5 metres and below in width.
	Coir matting rugs Coir Carpets and Coir mourzouks.	Rs. 1/- per packet/roll subject to a min. of Rs. 10/- per consignment for the coir matting rugs, coir carpets and coir mourzouks of 2.5 metres and below in width
(ii)	Coir mattings :	Rs. 3/- per packet /roll subject to a min. of Rs. 30/- per consignment for the coir mattings above 2.5 metres in width.
(iii)	Coir matting rugs, Coir carpets and Coir mourzouks.	Rs. 3/- per packet/roll subject to a min. of Rs. 30 /- per consignment for the coir matting rugs, coir carpets and coir mourzouks above 2.5 matres in width.
(b)	Coir matting mats.	Rs. 0.60 per packet subject to a minmum of Rs. 6/- percon signment.

[No. 6(2)/83-EI&EP]
N.S. HARIHARAN, Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 14 जून, 1985

आदेश

का. आ. 2895:—मैसर्स मारुति उद्योग लि., 6ठी मंजिल, हंसालय, नई दिल्ली को स्वतंत्र विदेश मुद्रा के अन्तर्गत एक ट्राईवेक्टर मीटर के आयात के लिए 18,700/- रु. (अट्ठारह हजार सात सौ रुपए मात्र) का आयात लाइसेंस सं. 1/सी. जी./2040556 दिनांक 23-9-83 दिया गया था।

फर्म ने उल्लिखित लाइसेंस की सीमा शुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाईसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमा शुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराई गई थी। अतः इस प्रकार सीमा शुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. लाइसेंसधारी ने अपने तर्क के समर्थन में स्टाम्प पेपर पर सार्वजनिक नोटरी दिल्ली के समक्ष साक्ष्य देते हुए एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं इस प्रकार तदनुसार संतुष्ट हूं कि फर्म आयात लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति सं. 1/सीजी/2040556 दिनांक 23-9-83 खो गई है। यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(गग) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मारुति उद्योग को जारी किया गया ऊपर उल्लिखित मूल सीमा शुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति सं. 1/सीजी/2040556 दिनांक 23-9-83 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि पार्टी को सीमा शुल्क/विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं. सी.जी.-II/23/83-84/276]
पाल बेक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

New Delhi, the 14th June, 1985

ORDER

S.O. 2895.—M/s. Maruti Udyog Ltd., 6th Floor Hansalaya New Delhi were granted an Import Licence No. 1/CG/2040556 dated 23-9-83 for Rs. 18,700 (rupees eighteen thousand and seven hundred only) for import of 1 No. Trivenctor Meter under Free Foreign Exchange.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs/Exchange Control purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes and Exchange Control copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs and Exchange Control purposes copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Customs/Ex. Control purposes copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs/Ex. Control purposes copy of import licence No. 1/CG/2040556 dated 23-9-83 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs/Ex. Control purposes copy No. 1/CG/2040556 dated 23-9-83 issued to M/s. Maruti Udyog Ltd. is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs/Exchange Control purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. CG. II/23/83-84/276]
PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
For Chief Controller of Imports & Exports

(बी. एल. अनुभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1985

आदेश

का. आ. 2896:—डा. वी. एस. रेड्डी, 27 विजय राघव रोड़, टी नगर, मद्रास को मर्सिडिस बेंज 300 डी कार का आयात करने के लिए 2,71,000/- रुपए मात्र का एक सीमा शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/0489815 दिनांक 25-3-85 दिया गया था। आवेदक ने ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट खो गया है। आगे यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क निकासी परमिट

किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क निकासी परमिट का मूल्य बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया ।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने उपयुक्त न्यायिक प्राधिकारी के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । मैं, तदनुसार, सन्तुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/0489815, दिनांक 25-3-85 आवेदक से खो गया है । समय-समय पर यथा संशोधन आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(गग) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, डा. वी. एस. रेड्डी को जारी किया गया उपर्युक्त मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/0489815, दिनांक 25-3-85 एतद्-द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है ।

[फाइल सं. ए/आर/154/84-85/बीएल एस/876]

एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

(B. L. Section)

New Delhi, the 11th June, 1985

ORDER

S.O. 2896.—Dr. V. S. Reddy, 27 Vijayaraghava Rao, T. Nagar, Madras was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/0489815 dt. 25-3-85 for Rs. 2,71,000 only for import of Mercedes Benz 300 D Car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been lost/misplaced. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of her contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/0489815 dt. 25-3-85 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dt. 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/0489815 dt. 25-3-85 issued to Dr. V. S. Reddy is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[F. No. A/R-154/84-85/BI S/876]

N. S KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports.

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1985

आदेश

का. आ 2897. :—केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए साबुन और अपमार्जक के विनिर्माण मे लग हुए अनुसूचित उद्योग विकास परिषद् के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है :—

साबुन और अपमार्जक उद्योग विकास परिषद्

1. श्री ए. बी. गोदरेज, निदेशक,
मैसर्स गोदरेज साबुन,
मुबई । —अध्यक्ष

2 श्री संतोष कुमार, अवैतनिक सचिव,
फैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ
स्माल स्केल सोप एंड डिटर्जेंट
मैन्युफैक्चरर्स आफ इंडिया, ए-13,
वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली । —सदस्य

3. श्री पी. आर. मलहन, निदेशक,
डी. सी. (एस. एस. आई.), नई दिल्ली । —सदस्य

4. श्री पी. एम. सिन्हा, निदेशक,
मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, मुम्बई —सदस्य

5. श्री वी. जयप्पा, प्रबंध-निदेशक,
कर्नाटक सोप और डिटर्जेंट, बंगलौर । —सदस्य

6. श्री जे. एस. शेरगिल
मार्कफैड आयल,
राजपुरा, पंजाब । —सदस्य

7. श्री एन .पी. सिह, महाप्रबंधक (खाद्य),
मैसर्स टाटा आयल मिल्स लिमिटेड,
मुम्बई हाउस, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई । —सदस्य

8. श्री सी. एस. शाह, अध्यक्ष,
ए.एस.ई. स्वास्तिक,
हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्राडक्ट,
मुंबई । —सदस्य

9. डा. एस. गांगुली, अध्यक्ष
इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड,
बड़ौदा । —सदस्य

10. श्री जी. रामा रायुडू,
प्रबंधक निदेशक,
मैसर्स जयलक्ष्मी मिल्स,
गुंटूर । —सदस्य

11. श्री सुधीर जालान,
मैसर्स एशियाटिक सोप कम्पनी,
8, बी बी डी बाग,
कलकत्ता । —सदस्य

12. श्री किशोर माड़ीवाला, निदेशक,
मुंबई आयल इन्डस्ट्रीज, मुंबई । —सदस्य

13. श्री के. के. पटेल, निदेशक,
मैसर्स निरमा प्राइवेट लिमिटेड,
4, सुरेन्द्र मंगलदास प्रिमिसैस,
अहमदाबाद-15 । —सदस्य

14. राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा का प्रतिनिधि, पंडारा रोड़, नई दिल्ली। —सदस्य
15. तेल उद्योग और व्यापार के केन्द्रीय संगठन, अन्ना भवन, तीसरी मंजिल, देवजी रत्नसी मार्ग, मुंबई-400009 का एक प्रतिनिधि —सदस्य
16. गुजरात साबुन उत्पादन महामंडल, अहमदाबाद का एक प्रतिनिधि। —सदस्य
17. खादी और ग्रामोद्योग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि। —सदस्य
18. भारतीय मानक संस्थान का एक प्रतिनिधि —सदस्य
19. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि —सदस्य
20. डी० जी० (एच० एस०) का एक प्रतिनिधि —सदस्य
21. श्रम मंत्रालय के परामर्श से श्रम यूनियन का एक प्रतिनिधि —सदस्य
22. नागरिक पूर्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि —सदस्य
23. हिन्दुस्तान वेजिटेबिल आयल कारपोरेशन का एक प्रतिनिधि। —सदस्य
24. आयल टैक्नोलाजिस्ट एसोसिएशन आफ इंडिया का एक प्रतिनिधि —सदस्य
25. औद्योगिक सलाहकार, साबुन और अपमार्जन (तकनीकी विकास महानिदेशालय), नई दिल्ली। —सदस्य-सचिव

[फा. सं 14(3)/85-डीपीआर/ईजीजी]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Deptt. of Industrial Development)

New Delhi, the 1st June, 1985

ORDER

S O 2897.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints for a priod of twe years with effect from the date of publication in the Official Gazette of this order the following persons to be members of the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture of Soaps and Detergents :—

Development Council for Soap and Detergents Industries.

1. Shri A B. Godrej, Director, M/s. Godrej Soap Bombay. — Chairman
2. Shri Santosh Kumar, Honorary Secretary, Federation of Association of Small Scale Soap & Detergent Manufacturers of India, A-13, Wazirpur Industrial Area Delhi. — Member
3. Shri P.R. Malhan, Director, DC(SSI), New Delhi. — Member
4. Shri P.M. Sinha, Director, M/s. Hindustan Lever Limitd, Bombay. — Member
5. Shri V. Jayappa, Managing Director, Karnataka Soaps and Detergents, Bangalore. — Member
6. Shri J.S. Shergill, MARKFED Oil, Rajpura, Punjab. — Member
7. Shri N.P. Singh, General Manager (Foods), M/s. Tata Oil Mills Ltd., Bombay House, Homi Mody Street, Bombay. — Member
8. Shri C.S. Shah, President ASE Swastik Household & Industrial Products, Bombay. — Member
9. Dr. S. Ganguli, Chairman, Indian Petro-Chemicals Ltd, Baroda. — Member
10. Shri G. Rama Rayudu, Managing Director, M/s. Jaylaxmi Mills, Guntur. — Member
11. Shri Sudhir Jalan, M/s Asiatic Soap Co, 8, BBD Bag, Calcutta. — Member
12. Shri Kishore Mariwalla Director, Bombay Oil Industries, Bombay. — Member
13. Mr. K.K Patel, Director, M/s. Nirma Pvt. Ltd. 4 Surendra Mangaldas Premises, Ahmedabad-15. — Member
14. A representative of National Consumers' Front, Pandara Road, New Delhi. — Member
15. A representative from Central Organisation for Oil Industry & Trade, Anna Bhavan, 3rd Floor, Devji Rattansey Marg, Bombay-400007. — Member
16. A representative from Gujarat, Sabun Utapadak Mahamandal, Ahmedabad. — Member
17. A representative of Khadi & Village Industries, New Delhi. — Member
18. A representative from ISI — Member
19. A representative from Planning Commission. — Member
20. A representative from DG(HS) — Member

21.	A representative from Labour Union in Consultation with Ministry of Labour.	Member
22	A representative from Ministry of Civil Supplies.	Member
23.	A representative from Hindustan Vegetable Oil Corpn.	Member
24.	A representative from Oil Technologists Association of India.	Member
25.	Industrial Adviser, Soaps and Detergents, D.G.T.D., New Delhi.	Member-Secy.

[F. No. 14(3)/85-DPR/EGG]
A.P. SARWAN, Jt. Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 1985

शुद्धिपत्र

का. आ. 2898 :—भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक जनवरी, 26, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. 2819 दिनांक 27 दिसम्बर, 1984 में पृष्ठ 277 पर तालिका में :

(1) कालम 2 में क्रम संख्या 7 पर शब्द "प्रभा-देवी रोड" के बाद प्रकाशित रोड न पढ़ा जाए।

[संख्या आर-25015/82/84-ओ. आर.-आई.]

टी. एन. परमेश्वरन, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 30th May, 1985

CORRIGENDA

S.O. 2898.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) No. S.O. 281 dated the 27th December, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 26th January, 1985 at page 277, in the Table :—

(i) against serial No. 1 and 2, in column 2, for "Administrative" read "Administration";

(ii) against serial No. 4 in column 2, for "Post Office" substituted "," and omit "," appearing after the word "District";

(iii) against serial No. 5, in column 2, omit "," occuring after the words "Post Office";

(iv) against serial No. 7 in column 2, omit "Rd" occurring after the word "Prabhadevi"

[No. R-25015/82/84-OR-I]

T. N. PARAMESWARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जून, 1985

का. आ. 2899 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं० 3266 तारीख 8-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जोटाणा से सोभासण सी. टी. एफ. तक पाइपलाईन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात, जिला एवं-तालुका—महेसाना

गांव	ब्लोक नं.	हेक्टर	आर.	सें.
1	2	3	4	5
जगुदन	682	0	06	50
	684	0	01	50
	685	0	04	50
	688	0	03	50
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	690	0	04	50
	692	0	02	50
	693	0	05	00
	694	0	02	40
	718	0	06	25
	708	0	00	20
	कार्ट ट्रेक	0	00	15
	710	0	01	25
	711	0	07	25
	कार्ट ट्रेक	0	00	15
	860	0	16	25
	859	0	06	00
	901	0	00	50
	902	0	07	95
	916	0	05	25
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	931	0	03	25
	930	0	02	95
	919/पी	0	05	00
	911	0	00	25
	994	0	02	95
	995	0	01	75
	996	0	02	00
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	990	0	00	45
	991	0	03	75
	987	0	06	80
	988	0	00	15
	986	0	03	20
	985	0	02	50
	1068/1	0	03	20
	1071	0	01	85
	1072	0	01	80
	1973	0	01	70
	1074	0	01	85

[सं. ओ०-12016/104/84ओ एन.जी.डी.-4]

New Delhi, the 7th June, 1985

S.O. 2899.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3266 dated 18-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Govoernment directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Jotana to Sobhasan CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Jagudan	682	0	06	50
	684	0	01	50
	685	0	04	50
	688	0	03	50
	Cart Track	0	00	25
	690	0	04	50
	692	0	02	50
	693	0	05	00
	694	0	02	40
	718	0	06	25
	708	0	00	20
	Cart Track	0	00	15
	710	0	01	25
	711	0	07	25
	Cart Track	0	00	15
	860	0	16	25
	859	0	06	00
	901	0	00	50
	902	0	07	95
	916	0	05	25
	Cart Track	0	00	25
	931	0	03	25
	930	0	02	95
	919/P	0	05	00
	911	0	00	25
	994	0	02	95
	995	0	01	75
	996	0	02	00
	Cart Track	0	00	25
	990	0	00	45
	991	0	03	75
	987	0	06	80
	988	0	00	15
	986	0	03	20
	985	0	02	50
	1068/1	0	03	20
	1071	0	01	85
	1072	0	01	80
	1073	0	01	70
	1074	0	01	85

[No. O-12016/104/84-ONG-D4]

का.आ. 2900.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन० के० सी० एफ० से एन०के०जी०जी०एस०-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन के० सी एफ से एन के जी जी एस-1 तक पाइपलाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—बिरमगाम

गांव	सर्वे नं	हे	ए.आर ई.	सें.
तेलावी	16	0	12	00
	11	0	07	90
	12	0	13	10
	43	0	67	20
	48	0	72	96
	185	0	16	00
	219/1	0	09	00
	218/1	0	08	40
	217	0	18	50
	216	0	06	70
	215	0	10	80
	212/2	0	06	36
	212/3	0	05	88
	212/1	0	03	00
	209/6	0	10	20
	209/7	0	18	75
	209/10	0	15	00
	209/11	0	13	36

[सं. ओ-12016/67/85-ओ एन जी.-डी- 4]

S.O. 2900.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from NKCF to NK GGS I in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authortiy, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKCF to NK GGS I.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Telavi	16	0	12	00
	11	0	07	90
	12	0	13	10
	43	0	67	20
	48	0	72	96
	185	0	16	00
	219/1	0	09	00
	218/1	0	08	40
	217	0	18	50
	216	0	06	70
	215	0	10	80
	212/2	0	06	36
	212/3	0	05	88
	212/1	0	03	00
	209/6	0	10	20
	209/7	0	18	75
	209/10	0	15	00
	209/11	0	13	36

[No. O-12016/67/85-ONG-D4]

का०आ० 2901:—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जे०एन०ए०सी० से जोटाणा जी० जी०एस० 1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

अनुसूची

जे एन. ए. सी. से जोटाना जी. जी. एस 1 तक पाईपलाईन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात, जिला व तालुका—मेहसाना

गाव	सं.नं.	हे०	ए आर ई	सें.
जोटाणा	1490	0	11	40
	1493	0	09	96
	1494	0	08	40

[सं. ओ-12016/68/85-ओ.एन.जी.-डी-4]

S.O. 2901.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from JNAC to Jotana GGS I in Gujarat State pipeline shoold be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexe dhereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferrd by sub-section (1) of the Section 3 of th Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Compatent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an onjection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from JNAC to Jotana GGS I.

Stat—Gujarat, District & Taluka—Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Jotana	1490	0	11	40
	1493	0	09	96
	1494	0	08	40

[No. O-12016/68/85-ONG-D4]

का. आ. 2902—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन. के. इ. जे. से एन. के. सी.टी.एफ. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन. के. ई. जे. से एन. के. सी. टी. एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात; जिला—मेहसाणा तालुका कड़ी

गांव	स.नं.	हे.	एआरई.	सें.
चालासण	117	0	00	96
	116	0	06	84
	115	0	06	36
	114/3	0	12	00
	85	0	04	56
	86/2	0	01	08
	89	0	07	44
	90	0	11	04
	91/2	0	12	84
	91/4	0	04	32
	93	0	08	10

[सं. ओ-12016 / 69 / 85-ओ.एन जी-डी-4]

S.O. 2902.—Whereas it appears to the Central Government that it is neccssary in the public interest that for the transport of petroleum from NKEJ to NKCTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKEJ to NK CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Chalasan	117	0	00	96
	116	0	06	84
	115	0	06	36
	114/3	0	12	00
	85	0	04	56
	86/2	0	01	08
	89	0	07	44
	90	0	11	04
	91/2	0	12	84
	91/4	0	04	32
	93	0	08	40

[No. O-12016/69/85-ONG-D4]

नई दिल्ली, 10 जून, 1985

का. आ. 2903.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे अेनोड बेड से वायर बेड तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पाईप लाइन अेनोड बेड वायर बेड तक

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाणा तालुका, कालोल

गांव	ब्लोक नं.	हे.	एआरई	सें.
छत्राल	360	0	02	00
	361	0	03	20

[सं. ओ-12016 / 70 /85ओ.एन. जी.-डी-4]

New Delhi the 10th May, 1985

S.O. 2903.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Anode Bed to Wire Bed in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline unde the land to the Competent Arthority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Anode Bed & Wire Bed

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Chhatral	360	—	02	00
	361	—	02	20

[No. O-12016/70/85-ONG-D-4]

का. आ. 2904 —यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में अेनोड बेड और वायर बेड से सी.पी. स्टेशन तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

पाईपलाईन अनोड बेड से वायर बेड सी पी. स्टेशन तक

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—वीरमगम

गांव	सर्वे नं.	हें.	आर.	सें
तेलावी	209/9	0	02	35

[सं. O-12016/71/85-ओ.एन.जी.-डी-4]

S.O. 2904.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Anode Bed and Wire Bed to CP Station in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Anode Bed and Wire Bed C.P. Station

Stato : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Telavi	209/9	0	02	35

[No. O-12016/71/85-ONG-D4]

का॰आ॰ 2905.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. ए. ए. ए. से एस. एस. सी. टी. एफ हेडर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. एन. ए. ए. से एस. एस. सी. टी. एफ. हेडर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए है

राज्य गुजरात	जिला व तालुका		मेहसाना	
गांव	सर्वे नं.	है	आर.	सें.
संथाल	598	0	09	00
	597	0	13	50
	577	0	03	70

[सं. O-12016/72/85-ओ.एन.जी.-डी.-4]

S.O. 2905.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAA to S.S. CTF Header in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acuire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNAA to S.S. CTF Header

State : Gujarat District & Taluka : Mehsara

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Santhal	598	0	09	00
	597	0	13	50
	577	0	03	70

[No. O-12016/72/85-ONG-D-4]

का. आ. 2906.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन० के० 150 से एन० के० 151 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन. के. 150 से एन. के. 151 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य —गुजरात जिला व तालुका —मेहसाना

गांव	सं. नं.	हे.	एआरई	सें.
1	2	3	4	5
धानपुरा	285	0	06	24
	324	0	03	48
	323	0	05	28
	322	0	06	84
	316	0	02	88
	319	0	12	36
	318	0	02	04
	कार्ट ट्रैक	0	00	72

[सं. O-12016/66/85 ओ. एन. जी.- डी-4]

S.O. 2906.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from NK-150 to NK 151 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NK 150 to NK 151

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen tiare
Dhanpura	285	0	06	24
	324	0	03	48
	323	0	05	28
	322	0	06	84
	316	0	02	88
	319	0	12	36
	318	0	02	04
	Cart track	0	00	72

[No. O-12016/66/85-ONG-D4]

का. आ. 2907.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 291 (O-12016/2/85-ONG D-4) तारीख 26-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बम्बई के क्षेत्राचरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाश की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

पाईप लाईन पाली देवद गाव से तालुका पनवेल, जिला -रायगढ़, महाराष्ट्र

गाव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल
			हेक्टर-ऐयर
पाली देवद	21 का भाग	—	00-30
	22	—	00-02
	23	—	00-18
	24	—	00-23

[सं.O-12016/2/85-ओ. एन. जी.-डी-4]

S.O 2907.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 291 (o-12016/2/85-ONG D4) dated 26-1-85 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline passing through village Pali-Devad.

Taluka : Panvel Dist. Raigad, Maharashtra

Village		Survey No./ Gut No.	Hissa No.	Area	
				H	R
Pali-Devad	21	Part	—		00-30
"	22	"	—		00-02
"	23	"	—		00-18
"	24	"	—		00-23

[No. O-12016/2/85-ONG-D4]

नई दिल्ली, 11 जून, 1985

का. आ. 2908.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस.एन.ए.यू. से एस.एस. सी. टी एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. एन. ए. यू. से एस. एस. सी. टी. एफ तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला व तालुका : मेहसाना

गाँव	सर्वे न.	हे.	आरे.	से.
सथाल	588	00	14	40
	586	0	16	45

[सं O-12016/73/85-ओ. एन. जी.-डी-4]

S.O. 2908.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAU to SSCTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acuire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNAU to S.S. CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Santhal	588	0	14	40
	586	0	16	45

[No. O-12016/73/85-ONG-D4

का. आ. 2909.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 4578 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों

के गया था अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा का प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस. बी. ए. ए. से. सोबासाण—44 तक पाइपलाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला व तालुका—मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं	हे.	एआई.	सेंटीयर
जगुदण	412	0	06	25
	325	0	01	00
	कार्ट ट्रैक	0	00	90
	413	0	06	10

[सं. O-12016/130/84-ओ. एन. जी-डी4]

S.O. 2909.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4578 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from SBAA to SOB-44

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No	Hectare	Are	Centiare
Jagudan	412	0	06	25
	325	0	01	00
	Cart track	0	0p	90
	413	0	06	10

[No. O-12016/130/84-ONG-D4]

नई दिल्ली 14 जून 1985

का. आ. 2910—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. बी. ए. से एस. एस. सी. टी. एफ. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड़ बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस. एन. बी. ए. से एस. एस. सी. टी. एफ. तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—तालुका—मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हे	आरे.	सेंटीयर
कसलपुरा	806	0	10	92
	808	0	09	93
	809	0	11	40
	813	0	01	08
	कार्टट्रेक	0	03	00
	857	0	03	48

[सं. O-12016/74/85-ओ. एन. जी.-डी-4]

New Delhi, the 14th June, 1985

S.O. 2910.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNBA to S.S. CTF in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNBA to S.S. CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Kasalpura	806	0	10	92
	808	0	09	92
	809	0	11	40
	813	0	01	08
	Cart track	0	03	00
	857	0	03	48

[No. O-12016/74/85-ONG-D4]

का.आ. 2911.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस०एन०जे० से एस० एन०ई० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप-लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस.एन.जे. से ऐन.ऐन.ई. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला व तालुका—मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर	सेंटीयर
जोटाना	1281	0	00	60
	1323	0	08	60
	1324	0	07	50
	1326	0	07	50
	1341	0	02	90
	1325	0	03	60

[सं. O-12016/75/85 ओ. एन. जी.-डी-4]

S.O. 2911.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNJ to SNE in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission. Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNJ to SNE

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Jotana	1281	0	00	60
	1323	0	08	60
	1324	0	07	50
	1326	0	07	50
	1341	0	02	90
	1325	0	03	60

[No. O-12016/75/85-ONG-D4]

का. आ. 2912.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन०के०डी०बी० से एन०के०जी०जी०एस० II तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन.के.डी.बी. से एन.के.जी.जी.एस. II तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं.	हे.	आरे	सेंटीयर
बाल रासन	28	0	06	96
	कार्ट ट्रैक	0	00	60
	436/3	0	18	42
	437/1	0	05	04
	437/3	0	05	20

1	2	3	4	5
	438/3	0	05	88
	438/2	0	07	56
	420/2	0	05	64
	420/3	0	09	36
	420/4	0	00	50
	420/1	0	05	64
	416	0	00	50
	415/5	0	04	56
	412/पी	0	06	84
	415/1	0	05	04
	415/2	0	00	96
	413/पी	0	07	44
	413/पी	0	03	84
	413/पी	0	00	96
	413/पी	0	06	60
	421/1	0	02	64
	421/2	0	02	52
	421/3	0	02	28
	421/4	0	06	12

[सं O-12016/76/85-ओ एन जी-डी 4]

S.O. 2912 —Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from from NKDV to NK GGS II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission,

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from NKDV to NK GGS-II

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bilsasan	28	0	06	96
	Cart track	0	00	60
	436/3	0	18	42
	437/1	0	05	04
	437/3	0	05	20
	438/3	0	05	88
	438/2	0	07	56
	420/2	0	05	64
	420/3	0	09	36
	420/4	0	00	50
	420/1	0	05	64
	416	0	00	50
	415/5	0	04	56
	412/P	0	06	84
	415/1	0	05	04
	415/2	0	00	96
	413/P	0	07	44
	413/P	0	03	84
	413/P	0	00	96
	413/P	0	06	60
	421/1	0	02	64
	421/2	0	02	52
	421/3	0	02	28
	421/4	0	06	12

[No. O-12016/76/85-ONG-D4]

का. आ. 2913.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐस बी डी आर. से सी. टी ऐफ. सोभासन तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस बी डी आर से सी टी एफ सोभासन तक पाईपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला व तालुका—मेहसाना

गाँव	ब्लाक नं.	हे.	आरे.	सेंटीयर
हेबुवा	250	0	52	80
	263	0	03	48
	280	0	37	08
	कार्ट ट्रैक	0	01	80
	54	0	07	80
	55	0	03	96
	56	0	01	68
	71	0	08	16
	70	0	07	50
	69	0	00	72
	67	0	03	84
	289	0	08	28
	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]

[सं O-12016/77/85 ओ एन जी-डी 4]

S.O. 2913.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SBDR to CTF Cob in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Pipeline from SBDR to CTF. SOB.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hebuva	250	0	52	80
	263	0	03	48
	280	0	37	08
	Cart track	0	01	80
	54	0	07	80
	55	0	03	96
	56	0	01	68
	71	0	08	16
	70	0	07	50
	69	0	00	72
	67	0	03	84
	289	0	08	28
	65	0	06	96

[No. O-12016/77/85-ONG-D4]

का.आ. 2914.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य जे० एन० एन० से जे० एन० ए० जी० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतय: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

जे एन०एन. से जे० एन० ए० जी० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—व तालुका—मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हे०	आर	से०
माकनज	822	0	01	44
	820	0	07	92
	820	0	03	84
	962	0	06	60
	962	0	05	16
	899	0	00	72
	964	0	08	04
	960	0	09	84

[सं० O-12016/78/85-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 2914.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from JNN to JNAG in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from JNN to JNAG

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Maknaj	822	0	01	44
	820	0	07	92
	820	0	03	84
	962	0	06	60
	962	0	05	16
	899	0	00	72
	964	0	08	04
	960	0	09	84

[No O-12016/78/85-ONG-D4]

का०आ० 2915.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस०एन०ए०ए० से एस० एस०टी०एफ० सी०ओ० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एस० एन० ए० ए० से एस. एस० सी० टी० एफ० हेडर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य:—गुजरात जिला. व तालुका:—मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हे०	आर०	सें०
कसल पुरा	858	0	03	60
	857	0	08	90
	809	0	15	70
	808	0	16	60
	805	0	12	70

[सं०O-12016/79-85—ओएनजी—डी-4]
पी० के० राजगोपालन, डेस्क आफिसर

S.O. 2915.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNAA to S.S. CTF Header in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNAA to S.S. CTF Header

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Ce n-tiare
Kasalpura	858	0	03	60
	857	0	08	90
	809	0	15	70
	808	0	16	60
	805	0	12	70

[No. O-12016/79/85-ONG-D4]
P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 10 जून, 1985

का. आ. 2916 :—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 4 अगस्त, 1981 की अधिसूचना के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित नैगमिक प्राधिकरणों के अधिकारियों को, जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के रैंक के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों के संबंध में, जो कि उनकी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे ।

सारणी

अधिकारी का पद नाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1. उप निदेशक (संपदा एवं भवन) प्रशासन निदेशालय, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून-248003	उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों ।
2. उपनिदेशक (पी एंड ए) क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, मकरपुरा रोड़ बड़ौदा-390009	गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों ।

1	2
3 उपनिदेशक (पी एंड ए), अहमदाबाद परियोजना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अहमदाबाद-380005	गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
4. उपनिदेशक (पी एंड ए) अंकलेश्वर परियोजना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अंकलेश्वर-393010	गुजरात राज्य के बड़ौच जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
5. उपनिदेशक, मेहसाना परियोजना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, मेहसाना गुजरात राज्य	गुजरात राज्य के मेहसाना जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उस के स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
6. संयुक्त निदेशक, कैम्बे, परियोजना, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कैम्बे।	गुजरात राज्य के खेरा जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
7. उपनिदेशक, त्रिपुरा परियोजना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, अगरतला-799001.	त्रिपुरा राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हो।
8. उपनिदेशक (पी एंड ए), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, पूर्वी क्षेत्र जोरहाट	असम राज्य में शिवसागर जोरहाट जिले में शिवसागर गोलाघाट जोरहाट सरुपत्थर बोरहोला लखवा में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इस के द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाय इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।
9 उप निदेशक (पी एंड ए) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, काच्छार परियोजना सिलचर	असम राज्य के काच्छार जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ओर से उसके स्थान या इसके द्वारा पट्टे पर या अधिग्रहण की हो सिवाए इस प्रकार के जो अन्य सम्पदा अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हों।

[फाइल सं. ओ-11023/1/85-ओ.एन.जी/डी-3]

सी. बी. भावे, उप सचिव

New Delhi, the 10th June, 1985

S.O. 2916:—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants Act, 1971 (40 of 1971), and in suppersession of the Notification dated 4th August, 1981 of the erstwhile Ministry of Petroluem, Chemicals & Fertilizers (Department of Petroleum, the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in Column 1 of the Table below, being Officers of the corporate authority, equivalent in rank to a gazetted officer of Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties emposed on Estate Officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction, in respect of the premises specified in column 2 of the said Table :—

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdistion
(1)	(2)
1. Deputy Director (Estate and Housing), Directorate of Administration, Oil & Natural Gas Commission, DEHRADUN-248003.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or a on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the District Dehradun, Uttar Pradesh, except such of them as are under the administrative control of the other Estate Officers.
2. Deputy Director (P&A), Regional Office, Western, Region, Oil & Natural	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of

(1)	(2)
Gas Commission, Makarpura Road, BARODA-390009.	the Oil & Natural Gas Commission, in the District of Baroda, Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
3. Deputy Director (P&A), Ahmedabad Project, Oil & Natural Gas Commission Ahmedabad-380005.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission, in the District of Ahmedabad, Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
4. Deputy Director (P&A), Ankleshwar Project, Oil & Natural Gas Commission, Ankleshwar 393010.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned, by or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Baroach, Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
5. Deputy Director, Mehsana Project, Oil & Natural Gas Commission, Mehsana Gujarat State	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Mehsana, Gujarat State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
6. Joint Director, Cambay Project, Oil & Natural Gas Commission, Cambay.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Oil & Natural Gas Commission in the district of Khera, Gujara State, except such of them as are under the administrative control of other Estate Officers.
7. Deputy Director, Tripura Project, Oil & Natural Gas Commission, Agartala-799001.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned by, or on behalf o the Oil & Natural Gas Commission in the State of Tripura, except such of them as under the administrative control of other Estate Officers.
8. Deputy Director (P&A), Oil & Natural Gas Commission, Eastern Region, Nazira.	Premises belonging to, or tken on lease or requisitioned by, or on behalf of Oil & Natural Gas Commission in Sibsagar Golaghat, Jorthat, Sarapathar, Borhalla Lakwa in district of Sibsagar Jorhat in Assam State, other than those under the administrative control of other Estate Officers.
9. Deputy Director (P&A), Oil & Natural Gas Commission, Cachar Project, Silchar.	Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned, by or on behalf of Oil & Natural Gas Commission in district Cachar in Assam State, other than those under the Administrative control of other Estate Officers.

[File No O-11023/1/85-ONG/D-III]

C.B. BHAVE, Dy. Secy

नई दिल्ली, 18 जून 1985

का. आ. 2917.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 4547, तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य- गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—कालोल

गांव	ब्लाक नं०	हे०	आर	मी०
राधनपुर	16	0	16	00

[सं० O-14016/449/84-जी पी]

New Delhi, the 18th June, 1985

S.O. 2917.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4547 dated 10-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira : Bareilly . Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Ra 'hanpur	16	0	16	00

[No O-14016/449/84-G.P.]

का आ. 2918—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं 3754 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ,

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—अंकलेश्वर

गांव	सर्वे नं०	हे०	ए आर ई मे०
नौगामा	261	0	11 25
	190	0	22 05
	189	0	05 60
	191	0	31 15
	186	0	05 72
	185	0	35 10
	184	0	27 90
	19	0	31 20
	20	0	23 28
	17	0	01 98
	21	0	17 16
	26	0	01 50
	22	0	50 89
	24	0	00 18
	23	0	07 13
	कोटार	0	10 80
	61	0	34 85
	62	0	52 10
	70	0	10 66
	63	0	95 25

[सं० O-14016/100/84-जी०पी०]

S.O. 2918.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 3754 dated 6-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira : Bareilly . Jagdishpur

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Zagadiya

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Naugama	261	0	11	25
	190	0	22	05
	189	0	05	60
	191	0	31	15
	186	0	05	72
	185	0	35	10
	184	0	27	90
	19	0	31	20
	20	0	23	28
	17	0	01	98
	21	0	17	16
	26	0	01	50
	22	0	50	89

1	2	3	4	5
	74	0	01	18
	73	0	07	13
	Kotn		10	80
	61	0	31	85
	62	0	52	40
	71	0	10	66
	63	0	95	25

[No. O-14016/310/84-G.P.]

का. आ. 2919.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4075 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा से बरेली से जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगाना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	अलीपुर	1	0 15	
				3	0 10	
				4	0 90	
				8	0 03	
				9	1 93	
				10	0 05	

1	2	3	4	5	6	7
			75		0 44	
			76		0 04	
			77		0 66	

[सं० O-14016/314/84-जी० पी०]

S.O. 2919.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4075 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hajira - Barelly - Jagdishpur Project

Distt	Tahasil	Par-gana.	Village	Plot No.	Area in acers	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Ali pur	1	0-15	
				3	0-10	
				4	0-90	
				8	0-03	
				9	1-93	
				10	0-05	
				75	1-44	
				76	0-04	
				77	0-66	

[No. O-14016/314/84 G.P.]

का. आ. 2920.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4536 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—देवगढ़ बारीया

गांव	सर्वे नं०	हे०	आर	मी०
चेनपुर	28	0	26	00
	29	0	18	00
	कोटार	0	04	00

[सं० O-14016/138/84-ओ पी]

S.O. 2920.- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4536 dated 10-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira : Bareilly : Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Devgadh Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Cherpur	28	0	26	00
	29	0	18	00
	Kotar	0	04	00

[No. O-14016/438/84 G P.]

का०आ० 2921.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 4117/तारीख 1/12/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—पिपलबे तहसील—राजगढ़ जिला—राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	437/15	0.180
2.	437/5	0.360
3.	465	0.114

1	2	3
4	464	0.012
5.	470	0.005
6	462	0.120
7.	467	0.020
8.	483	0.126
9	468	0.055
10.	469	0.300
11.	472	0.540
12	484/2	0.180
13	471	0.025
14	466	0.005
15	463	0.051
16.	391/1	0.500
कुल योग. क्षेत्रफल		2.893

[स.O-14016/334/84-जीपी]

S.O. 2921.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4117 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has, under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the secton 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe line Project

Village : Pipalabe Tehsil : Rajagarh Distt. : Rajagarh

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
(1)	(2)	(3)
1.	437/15	0.180
2.	437/5	0.360
3.	465	0.114
4.	464	0.012
5.	470	0.005
6.	462	0.120
7.	467	0.020
8.	483	0.126
9.	468	0.055
10.	469	0.300
11.	472	0.540
12.	484/2	0.480
13.	471	0.025
14.	466	0.005
15.	463	0.051
16.	391/1	0.500
	TOTAL : AREA	2.893

[No. O-14016/334/84-G.P.]

का. आ. स. 2922.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 4094 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : दुनावना तहसील : बड़नगर जिला : उज्जैन राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	265	0.030
2.	269	0.042
3	270	0.508
4	271	0.272
5	272	0.084
कुल योग. क्षेत्रफल		0.936

[स. O-14016/543/84-जी.पी.]

S.O. 2922.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4094 dated 1-1-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government, vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

HBJ Gas Pipe line Project

Village : Dunalji Tehsil : Badnagar Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
(1)	(2)	(a)
1.	265	0 030
2.	269	0.042
3.	270	0.508
4.	271	0.272
5.	272	0.084
	TOTAL AREA	0 936

[No. O-14016/243/84-G.P.]

का.आ. 2923.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. नं. 4275 तारीख 8-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच बी जे गैस पाईप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : हरनावदा तहसील : बड़नगर जिला उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	76/4	0 052
2	83	0.397
3.	10	0 167
4	79	0 648
5	78	0.366
6	72	0.010
7	71	0.449
8	69	0.124
9	70	0.564
10.	53	0 032
11.	22	0.669
12.	19	0 836
13.	18	0 136
14	17/1/2	0 166
15	17/1/3	0 115
16	17/1/4	0 251
17	139	0 073
18	17/3/2	0 240
19	17/3/1	0.083
20	27/2	0 198
21	124	0 031
22	35	0.314
23	34/1	0 341
24.	29/2	0 125
25	34/2	0 251
26	30	0.585
27.	136	0 793
28	137	0.407
29	138	0.427
30.	14	0 020
	कुल योग—क्षेत्रफल	8 871

[सं० O-14016/361/84—जी पी]

S.O. 2923.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4275 dated 8-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe line Project

Village : Har .veda Tehsil : Badnagar Distt. : Ujjain

S No	Survey No	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
(1)	(2)	(3)
1.	76/4	0 052
2.	83	0.397
3	10	0.167
4.	79	0.648
5.	78	0.366
6.	72	0.010
7.	71	0.449
8.	69	0.124
9.	70	0.564
10.	53	0.032
11.	22	0.669
12.	19	0.836
13.	18	0.136
14.	17/1/2	0.166
15.	17/1/3	0.115
16.	17/1/4	0.251
17.	139	0.073
18.	17/3/2	0.240
19.	17/3/1	0 083
20.	27/2	0.198
21.	124	0.031
22.	35	0.314
23.	34/1	0.341
24.	29/2	0.125
25.	34/2	0.251
26.	30	0.585
27.	136	0.793
28.	137	0.408
29	138	0.427
30.	14	0.020
TOTAL : AREA		98.871

[No. -14016/361/84-G.P.]

का.आ. 2924:—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4115, तारीख 1-12-1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच० बी. जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम . मिण्डका तहसील बड़नगर · जिला– उज्जैन राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र 4	खसरा न. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	2	0 251
2.	4/1	0.052
3.	14	0.010
4	15	0.470
5	16	0.627
6.	22	0.523
7	19/1	0.052
8.	19/2	0 031
9	20	0 251
10	23	0.010
कुल योग :– क्षेत्रफल		2 277

[सं O–14016/332/84–जी पी]

S.O. 2924.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4115 dated 1-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe line Project

Village : Mindki Tehsil : Badnagar Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
(1)	(2)	(3)
1.	2	0.251
2.	4/1	0.052
3.	14	0 010
4.	15	0 470
5.	16	0.627
6.	22	0 523
7.	19/1	0.052
8.	19/2	0.031
9.	20	0.251
10.	23	0.010
	TOTAL AREA	,, 2.277

[No. O-14016/332/84-G.P.]

का०आ० 2925.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 4404 तारीख 15-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों के बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : मुंगार खेड़ी तहसील : बड़नगर (जिला— उज्जैन राज्य : मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	1	0.145
2.	64	0.230
3.	72	0 281
4	71	0 345
5.	70/2	0.116
6.	70/1	0.209
7	63	0.366
8.	58	0.177
9.	9/1/2	0.185
10	18/2	0.021
11.	9/1/3	0.042
12.	14	0.477
13.	16/2	0.449
14	18/1	0.676
15	19/2	0.063
16	19/3	0.439
17	19/4	0.424
18.	19/5	0.220
19.	57	0 052
20.	19/1	0.126
कुल योग : क्षेत्रफल		5.043

[सं. O-14016/ 369/84-जीपी]

S.O. 2925.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4404 dated 15-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby, declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe-line Project

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired For R.O.U. in Hectare.
1	2	3
1.	1	0.145
2.	64	0.230
3.	72	0.281
4.	71	0.345
5.	70/2	0 116
6.	70/1	0.209
7.	63	0.366
8.	58	0.177
9.	9/1/2	0.185
10.	18/2	0.021
11.	9/1/3	0.042
12.	14	0.477
13.	16/2	0.449
14.	18/1	0.676
15.	19/2	0 063
16.	19/3	0 439
17.	19/4	0.424
18.	19/5	0.220
19.	57	0.052
20.	19/1	0.126
	TOTAL AREA	5.043

[No. O—14016/369/84-G.P.]

का.आ. 2926.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4405 तारीख 15-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम उड़सिगा तहसील बड़नगर जिला— उज्जैन राज्य (मध्य— प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	250/1	0.294
2.	256	0.230
3.	258	0.062
4.	514	0.199
5.	508	0.010
6.	509	0.147
7.	513	0.292
8.	515 (मी)	0.732
9.	523/1	0.157
10.	523/2	0.031
11.	260	0.345
12.	524/4	0.374
13.	544	0.145
14.	545/1	0.209
15.	546	0.084
16.	259	0.010
18.	561	0.042
18	510	0.177
19.	511	
20.	562	0.136
21.	563	0.084
22.	512	0.042
23.	564	0.052
24.	565	0.136
कुल योग :— क्षेत्रफल		3.990

[सं. O—14016/370/84—जी पी]

S.O. 2926.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4405 dated 15-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe-line Project

Village : Udsinga Tehsil : Badnagar Distt. : Ujjain

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hecture
1	2	3
1.	250/1	0.294
2.	256	0.230
3.	258	0 062
4.	514	0 199
5.	503	0.010
6.	509	0.147
7.	513	0.292
8.	515 M.	0.732
9.	523/1	0.157
10.	523/2	0.031
11.	260	0.345
12.	524/4	0.374
13.	544	0.145
14.	545/1	0.209
15.	546	0.084
16.	259	0.010
17.	561	0.042
18.	510	0 177
19.	511	
20.	562	0.136
21.	563	0.084
22.	512	0.042
23.	564	0 052
24.	565	0.136
	TOTAL AREA	3.990

[No. O-14016/370/84-G.P.]

का. आ. 2927.- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3915 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम टिकोल तहसील नलखेड़ा जिला– शाजापुर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	374	0.052
2.	376	0.167
3.	379	0.052
4.	316	0.167
5.	317	0.010
6.	377	0.136
7.	378	0.021
8.	315/2	0.136
9.	314	0.105
10.	384	0.021
11.	1240	0.010
12.	313	0.167
13	1634/5/1+1649/5/1	0.084
14.	1156/3	0.021
15.	1157/2	0.261
16.	1159/3	0.021
17.	1634/5/2/+1649/5/2	0.084
18.	1155	0.334
19.	1177	0.125
20.	1180	0.105
21.	1208	0 314
22	1209	0.125
23.	1181/1124	0.261
24.	1179	0.010
25.	1626 1626/1818	0.240
26.	1181	0.010
27.	1207	0.021

1	2	3
28.	1182	0 251
29.	1232मी.	0.115
30.	1238	0.031
31.	1295	0 261
32.	1233	0.031
33.	1235	0.449
34.	1291/2	0.178
35.	1639/1	0.157
36.	1291/2	0.209
37.	1291/3	0.178
38.	1292/1	0.042
39.	1297	0.105
40.	1294	0.042
41.	1296	0.125
42.	1638/13	0.031
43.	1638/5	0.178
44.	1638/7	0.094
45.	1638/6	0.178
46.	1638/8	0.094
47.	1634/2	0.157
	1649/2	
48.	1634/3	0.125
	1649/3	
49.	1634/4	0.125
	1649/4	
50.	1633/21+634/6+1649/6	0.042
51.	1623/1	0.031
52.	1624/1	0.053
53.	1623/2	0.157
54.	1624/2	0.010
55.	1623/1817	0.010
56.	1632 मी.	0.470
57.	1631	0.042
	1632 मी.	
58.	1628	0.125
59.	1489	0.010
60.	1598 मी.	0.010
61.	1596	0.209
62.	1595/2	0.314
63.	1591	0.219
64.	315/1	0.010
65.	375	0.031
66.	385	0.010
67.	1634/1	0.209
	1638/9	
	1649/1	
68.	1634/7	0.188
69.	1633/1	0.010
70.	1629	0.042
71.	1231	0.010
72.	1625	0.010
73.	1597	0.073
74.	1593	0.021
75.	1594	0.010
	कुल योग क्षेत्रफल :-	8.542

[सं. ओ० 14016- 253/ 84- जीपी]

S.O. 2927.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 3915 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe-line Project

Village : Tikon Tehsil : Nalikheda Distt. : Shajapur

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired For R.O.U. in Hectares
1	2	3
1.	374	0.052
2.	376	0.167
3.	379	0 052
4.	316	0.167
5.	317	0.010
6.	377	0 136
7.	378	0.021
8.	315/2	0.136
9.	314	0.105
10.	384	0.021
11.	1240	0.010
12.	313	0.167
13.	1634/5/1	
	1649/5/1	0.084
14.	1156/2	0.021
15.	1157/2	0.261
16.	1159/3	0.021
17.	1634/5/2+ 1649/5/2	0.084
18.	1155	0.334
19.	1177	0.125
20.	1180	0.105
21.	1208	0.314
22.	1209	0.125
23.	1181/1124	0.261
24.	1179	0 010
25.	1626	0.240
	1626/1818	
26.	1181	0.010
27.	1207	0.021
28.	1182	0.251
29.	1232 M.	0.115
30.	1238	0.031
31.	1295	0.261

1	2	3
32.	1233	0 031
33	1235	0 449
34	1291/1	0 178
35	1639/1	0 157
36.	1291/2	0 209
37.	1291/3	0 178
38.	1292/1	0 042
39	1297	0 105
40	1294	0 042
41	1296	0.125
42	1638/13	0 031
43.	1638/5	0 178
44.	1638/7	0 094
45.	1638/6	0 178
46	1638/8	0 094
47	1634/2	0 157
	1649/2	
48	1634/3	0 125
	1649/3	
49	1634/4	0 125
	1649/4	
50	1633/2+1634/6+1649/6	0 042
51	1623/1	0 031
52	1624/1	0 053
53	1623/2	0 157
54	1624/2	0 010
55.	1623/1817	0 010
56.	1623 M	0 470
57.	1631	0 042
	1632 M	
58.	1628	0 125
59	1489	0 010
60.	1598 M	0 010
61.	1596	0 209
62	1595/2	0 314
63	1591	0 219
64.	315/1	0 010
65	375	0 031
66.	385	0 010
67	1634/1	0 209
	1638/9	
	1649/1	
68.	1634/7	0 188
69.	1633/1	0 010
70.	1629	0 042
71.	1231	0 010
72	1625	0 010
73.	1597	0 073
74	1593	0 021
75.	1594	0 010
	TOTAL AREA	8 542

[No. O—14016/253/84-G P]

का. आ. 2928.—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का आ स. 4088 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों का बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच बी जे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम कल्याणपुरा तहसील बड़नगर जिला– उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क	खसरा न 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स मे)
1	2	3
1	51	0 303
2	52	0 272
3	53	0 449
4	183/1	0 042
5	54	0 125
6	66	0 293
7	68	0 105
8	69	0 073
9	81	0 314
10	84	0 240
11	179	0 021
12	85	0 794
13	86	0 543
14	182	0 679
15	176	0 010
16	177	0 209
17	178	0.271
18	185	0 010
19	41	0.052
20	57	1 233
21	58	0 052
22	59	0.021
23	91	0 188
	योग कुल क्षेत्रफल :–	6 299

[सं ओ० 14016/336/84–जीपी]

S O. 2928.— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O 4048 dated 11-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd, free from all encumbrances

HBJ Gas Pipeline Project

Village Kalyan Pura Tehsil Badnager Distt : Ujjain

SCHEDULE

S No	Survey No	Area to be Acquired for R O U In Hectare
1	51	0 303
2	52	0 272
3	53	0 449
4	183/1	0 042
5	54	0 125
6	66	0 293
7	68	0 105
8.	69	0 073
9	81	0 314
10	84	0 240
11.	179	0 021
12.	85	0 794
13.	86	0 543
14.	182	0 679
15.	176	0 010
16.	177	0 209
17.	178	0 271
18.	185	0 010
19	41	0 052
20	57	1 233
21	58	0 052
22	59	0 021
23	91	0 188
	Total Area	6 299

[No O 14016/336/84-G P]

का आ 2929—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि म उपयोग के अधिकार का अर्जन, अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का आ स 4492 तारीख 22-12-84 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो म उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच बी जे गैस पाइपलाइन प्राजेक्ट

ग्राम खुरचन्या चंद्रभान तहसील महिदपुर जिला– उज्जैन राज्य (म प्रदेश)

अनुसूची

अनु क	खसरा न 1	उपयोग अधिकार अर्जन क्षेत्र (हैक्टर्स म)
1	2	3
1	265/1	0 271
2	265/2	0 312
3	267	0 016
4	268/1	0 739
	कुल योग क्षेत्रफल –	1 338

[स O-14016/380/84-जीपी]

S O 2929—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O 4492 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from all encumbrances

HBJ Gas Pipe Line Poject

Village Khurchanya Chandre Bhan Tehsil Mahidpur Dist. Ujjain

SCHEDULE

S No	Survey No	Area to be Acquired for R O U in Hectare
1.	265/1	0 271
2	265/2	0 312
3	267	0 016
4	268/1	0 739
	Total Area	1 338

[No O-14016/380/84-G P

का. आ. 2930 --यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 4128 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम बमानिया तहसील राजगढ़ जिला– राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	503	0.031
2.	504	0.480
3.	501	0.030
4.	505	0.025
5.	500	0.165
6	499	0.240
7.	491	0.105
8.	490 मेसे	0.120
9.	492	0.050
10.	489	0.441
11.	487	0.005
12.	488	0.052
13.	467	0.052
14	453	0.108
15.	454	0.074
16.	446	0.020
17.	445	0.400
18.	444	0.300
19.	442	0.270
20.	440	0.240
21.	441	0.005
22.	439	0.026
23.	498	0.005
24.	493	0.005
कुल योग --क्षेत्रफल		3.249

[सं. O-14016/354/84-जी पी]

S.O. 2930.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4128 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Bananiya Tehsil Rajgarh Distt. Rajgarh

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	503	0.031
2.	504	0.480
3.	501	0.030
4.	505	0.025
5.	500	0.165
6.	499	0.240
7.	491	0.105
8.	490	0.120
9.	492	0.050
10	489	0.441
11.	487	0.005
12.	488	0.052
13.	467	0.052
14.	453	0.108
15.	454	0.074
16.	446	0.020
17.	445	0.400
18.	444	0.300
19.	442	0.270
20.	440	0.240
21.	441	0.005
22.	439	0.026
23.	498	0.005
24.	493	0.005
	Total Area	3.249

[No. O-14016/354/84-GP]

का. आ. 2931.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 131 तारीख 12-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम चांदन गाव तहसील आगर जिला–शाजापुर राज्य (मध्य प्रदेश

अनुसूची

अनु क्र	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	671	0 010
2	982	0.010
3.	979	0 157
4	963/1	0 105
5	981	0 251
6.	978	0.157
7	976/1	0 314
8	972	0 031
9	973	0 282
10	938	0 188
11	939	0.105
12.	934	0 021
13.	936	0.052
14	937	0 010
15.	935	0 010
योग कुल क्षेत्रफल :–		1.703

[सं. ओ०–14016/524/84– जी पी]

S.O. 2931.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 131 dated 12-10-85 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Chandan Gaon Tehsil Agar Distt. Shajapur

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectare
1.	671	0.010
2.	982	0.010
3	979	0 157
4	963/1	0.105
5	981	0.251
6.	978	0 157
7.	976/1	0.314
8.	972	0.031
9.	973	0.282
10.	938	0.188
11.	939	0.105
12.	934	0.021
13.	936	0.052
14.	937	0.010
15.	935	0.010
Total Area		1.703

[No.O-14016/524/84—GP]

का. आ. 2932.—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 124 तारीख 12–1–85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : सिहारी तहसील : चाचोड़ा जिला : गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	391	0.245
2.	393	0.010
3.	394	0.323
4.	395	0.201
5.	396	0.149
6.	397	0.149
7.	398	0.343
8	403	0.314
9.	402	0.175
10.	406	0.214
11.	404	0.105
12.	405	0.107
योग कुल क्षेत्रफल :-		2.335

[सं. O-14016/517/84-जी पी]

S.O. 2932.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 124 dated 12-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Sihari Tehsil : Chacoda Distt. Guna

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectare
1.	391	0.245
2.	393	0.010
3.	394	0.323
4.	395	0.201
5.	396	0.149
6.	397	0.149
7.	398	0.343
8.	403	0.314
9.	402	0.175
10.	406	0.214
11.	404	0.105
12.	405	0.107
	Total Area	2.335

[No. O-14016/517/84-GP]

का. आ. 2933.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3934 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : नैत्याखेड़ी तहसील : चाचोड़ा जिला- गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	38/4	0.052
2.	38/5	0.125
3.	38/6	1.272
4.	38/9	1.296
5.	23	0.052
6.	19	0.502
7.	18	0.617
8.	1	0.094
9.	2	0.073
10.	3	0.063
11.	5	0.063
12.	15/2 ब	0 021
13	34	0 052
14.	96	0.167
15	97/1	0.261
16.	97/2	0.147
17.	98	0.105
18.	95	0.021
19.	80	0.428
20.	6	0.366
21.	7	0.021
22.	9	0.251
23.	16/1/3	0.199
24.	16/1/2	0.021
25.	17	0.564
योग कुल क्षेत्रफल		5.833

[सं. O-14016/277/84-जीपी]

S.O. 2933.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3934 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Netya Khedi Tehsil Chachoda Distt. Guna

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectare
1.	38/4	0.052
2.	38/5	0.125
3.	38/6	0.272
4.	38/9	1.296
5.	23	0.052
6.	19	0 502
7.	18	0.617
8.	1	0.094
9.	2	0.073
10.	3	0.063
11.	5	0.063
12.	15/2 B	0.021
13.	34	0.052
14.	96	0.167
15.	97/1	0.261
16.	97/2	0.147
17.	98	0.105
18.	95	0.021
19.	80	0.428
20.	6	0.366
21.	7	0.021
22.	9	0.251
23.	16/1/3	0.199
24.	16/1/2	0.021
25.	17	0.564
	Total Area	5.833

[No. O-14016/277/84—GP]

का. आ. 2934—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 134 तारीख 12-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम इटखेड़ी कला तहसील चाचोड़ा जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु०क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	138	0.266
2.	141	0.350
3.	140	0 031
4.	142	0.317
5.	145	0.369
6.	147	0.209
7.	148	0.532
8.	153	0.021
योग कुल क्षेत्रफल		2.095

[सं०O-14016/527/84--जी०पी०]

S.O. 2934.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 134 dated 12-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Entkhedi Kala Tehsil Chachoda Distt. Guna

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectares
1	2	3
1.	138	0.266
2.	141	0.350
3.	140	0.031
4.	142	0.317
5.	145	0.369
6.	147	0.209
7.	148	0.532
8.	153	0.021
	Total Area	2.095

[No.O-14016/527/84G P]

का. आ. 2935—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3937 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने को विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम बर्जनपुरा तहसील चाचोड़ा जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु. क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	2	0 073
2.	77/1 मं.	0.325
3.	77/1 मं.	0.105
4.	77/1 मा.	0.105
5.	77/1 मं.	0.136
6.	77/1 मो.	0.416
7.	75/1	0.063
8.	73	0 126
9.	69/2	0.460
10.	68	0.010
11	.65	0.261
12.	64	0.084
13	66/367	0 042
14.	63	0.345
15.	66/368/2	0.021
16.	60	0.272

1	2	3
17.	58	0.230
18.	54	0.126
19.	53	0.209
20.	55	0.031
21.	52	0.146
22.	50	0.073
23.	6/2	0.220
24.	9	0.126
25.	10	0.418
26.	12	0.010
27.	13	0.178
28.	4	0.093
29.	3	0.116
30.	49	0.010
31.	61	0.010
32.	74	0.021
योग कुल क्षेत्रफल:—		4.851

[स. O--14016/280/84 -जे.पी.]

S.O. 2935.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3937 dated 24-11-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intent on to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Beijanipura Tehsil Chachoda Distt. Guna

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R. O. U. in Hecture
1	2	3
1.		0.073
2.	77/1 M.	3.325
3.	77/1 M.	0.105
4.	77/1 M.	0.105
5.	77/1 M.	0.136
6.	77/1 M.	0.416
7.	75/1	0.063
8.	73	0.126
9.	69/2	0.460
10.	68	0.010
11.	65	0.261
12.	64	0.084
13.	66/367	0.042
14.	63	0.345
15.	66/368/2	0.021
16.	60	0.272
17.	58	0.230
18.	54	0.126
19.	53	0.209
20.	55	0.031
21.	52	0.136
22.	50	0.073
23.	8/2	0.220
24.	9	0.126
25.	10	0.418
26.	12	0.010
27.	13	0.178
28.	4	0.093
29.	3	0.116
30.	49	0.010
31.	61	0.010
32.	74	0.021
Total Area :		m 4.851

[No. O-14016/280/84-GP]

का. आ. 2936 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 133 तारीख 12-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : अल्ली खेड़ा तहसील : चाचोड़ा जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु. क्र.	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	7/1	0.320
2.	7/2	0.260
3.	12	0.214
4.	13	0.145
5.	46/3	0.784
6.	59	0.240
7.	60	0.418
8.	110	1.727
9.	130	0.400
10.	132	0.314
11.	138	0.375
12.	137	0.185
13.	147	0.100
14.	146	0.120
15.	144	0.140
16.	143	0.105
17.	142	0.120
18.	141	0.120
	योग कुल क्षेत्रफल :	6.087

[सं. O-14016/526/84-ज.प.]

S.O. 2936.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 133 dated 12-1-85 under sub-section (1) of Secion 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Alli Khedi Tehsil Chachoda Distt. Guna

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired fo R. O. U. in Hectare
1.	7/1	0.320
2.	7/2	0.260
3.	12	0.214
4.	13	0.145
5.	46/3	0.784
6.	59	0.240
7.	60	0.418
8.	110	1.727
9.	130	0.400
10.	132	0.314
11.	138	0.375
12.	137	0.185
13.	147	0.100
14.	146	0.120
15.	144	0.140
16.	143	0.105
17.	142	0.120
18.	141	0.120
	Total Area	6.087

[No. O-14016/526/84-GP]

का. आ. 2937.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3918 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

एच०-बी०-जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम चारणापुरा : तहसील चाचोडा जिला-गुना : राज्य (म. प्र.)

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	107/1	0.042
2.	76/3	0.165
3.	78/3	0.261
4.	79	0.230
5.	88	0.261
6.	85/1 मं.	0.188
7.	42/1	0 031
8.	32/1	0.021
9.	34/1	0.345
10.	27	0.240
11.	26/3	0.031
12.	22	0.325
13.	23	0.073
14.	117/1	0.042
	योग : कुल क्षेत्रफल	2 255

[सं. O-14016/256/84-जी पी]

S.O. 2937.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3918 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Charanpura Tehsil Chachoda Dist. Guna

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectares
1.	107/1	0.042
2.	76/3	0.165
3.	78/3	0.261
4.	79	0.230
5.	88	0.261
6.	85/1 M.	0.188
7.	42/1	0.031
8.	32/1	0.021
9.	34/1	0.345
10.	27	0.240
11.	26/3	0.031
12.	22	0.325
13.	23	0.073
14.	117/1	0.042
	Total Area :	2 255

[No. O-14016/256/84-GP]

का. आ. 2938.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4278 तारीख 8-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच० पे० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम हिरण खेड़ी . तहसील राजगढ़ : जिला–राजगढ़ : राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र०	खसरा नं. 6	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	659/1	1.985
2.	659/2	0.025
3.	621	0.005
4.	622	0.480
5.	623	0.253
6.	626	0.038
7.	629	0.038
8.	630	0.063
9.	631	0.013
10.	635	0.379
11.	636	0.114
12.	568	0.430
13.	542	0.026
14.	529	0.278
15.	539	0.015
16.	537	0.101
17.	538	0.228
18.	518	0.350
19.	521	0.038
20.	516/1	0.759
21.	515	0.063
22.	500	0.076
23.	499	0.076
24.	455	0.400
25.	497	0.101
26.	488	0.063
27.	487	0.013
28.	470	0.126
29.	469	0.253
30.	467	0.051
31.	468/1	0.126
32.	563	0.025
33.	569	0.228
34.	456	0.025
35.	457	0.005
36.	458	0.568
37.	462	0.013
38.	498	0.005
39.	640	0.010
	कुल क्षेत्रफल योग :–	7.845

[सं० O-14016/364/84-जी पी]

S.O. 2938.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4278 dated 8-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Hiran Khedi Tehsil Rajgarh Distt. Rajgarh

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectares
1.	659/1	1.985
2.	659/2	0.025
3.	621	0.005
4.	622	0.480
5.	623	0.253
6.	626	0.038
7.	629	0.038
8.	630	0.063
9.	631	0.013
10.	635	0.379
11.	636	0.114
12.	568	0.430
13.	542	0.026
14.	529	0.278
15.	539	0 015
16.	537	0.101
17.	538	0.228
18.	518	0.350
19.	521	0.038
20.	516/1	0.759
21.	515	0.063
22.	500	0.076
23.	499	0.076
24.	455	0.400
25.	497	0.101
26.	488	0.063
27.	487	0.013
28.	470	0.126
29.	469	0.253
30.	467	0 051
31.	468/1	0.126
32.	563	0 025
33.	569	0.228
34.	456	0 025
35.	457	0 005
36.	458	0.568
37.	462	0.013
38.	498	0 005
39.	640	0.010
	Total Area :	7.845

[No. O-14016/364/84-GP]

का.आ. 2939 —यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 137, तारीख 12-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम चेनपुरिया	तहसील-राजगढ़	जिला-राजगढ़	राज्य (मध्य प्रदेश)
क्रम सं०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)	
1.	15	0 090	
2.	17	0 126	
3	97	0 405	
4	96	0.080	
5	98	0 253	
6.	93	0 026	
7	101	0 052	
8	92	0 145	
9	82/1	0 026	
	योग कुल क्षेत्रफल	— 1.203	

[सं. O-14016/530/84-जी पी]

S.O. 2939.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 137 dated 12-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Chanpuriya Tehsil Rajgarh Distt. Rajgarh

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectares
1.	15	0.090
2.	17	0.126
3.	97	0.405
4.	96	0 080
5.	98	0.253
6.	93	0.026
7.	101	0 052
8.	92	0.145
9.	82/1	0.026
	Total Area :	1.203

[No O-14016/530/84-GP]

का.आ. 2940.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3783 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजिरा-बरेली--जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
जालौन	जालौन	जालौन	दौलतपुर	476	0-02	
				480	0-70	
				481	0-23	
				474	0-01	
				473	0-06	
				461	1-00	
				460	0-04	
				457	0-02	
				456	0-16	
				455	0-70	
				462	0-10	
				434	0 02	
				451	0-03	
				448	0-02	
				447	0-01	
				449	0-02	
				450	0-75	
				355	0-06	
				356	1-44	
				453	0 02	
				352	0-03	

[सं. O-14016/174/84-ज प]

S.O. 2940.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3783 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipel ne;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line From, Hajira—Bareilly-Jagdishpur Project

District	Tahasil	Pargana,	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Daulatpur	476	0-02	
				480	0-70	
				481	0-23	
				474	0-01	
				473	0-06	
				461	1-00	
				460	0-04	
				457	0-02	
				456	0-16	
				455	0-70	
				462	0-10	
				434	0-02	
				451	0—03	
				448	0—02	
				447	0—01	
				449	0—02	
				450	0-75	
				355	0-06	
				356	1-44	
				453	0-02	
				352	0-03	

[No. O-14016/174/84-GP]

का.आ. 2941—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 4564 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ,

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य--गुजरात जिला--पंचमहल तालुका : दाहोद

1	2	3	4	5
गमला	40	0	24	64
	391/1	0	14	70
	39/2	0	09	75

1	2	3	4	5
गमला—(जारी)	42/1	0	10	90
	46	0	08	64
	47/3	0	41	52
	50	0	05	00
	53/1	0	02	50
	53/3	0	22	90
	53/2	0	02	64
	53/4	0	11	38
	52/1	0	24	60
	52/2	0	09	87
	86/1	0	24	36
	87	0	13	20
	88	0	21	90
	90/5	0	02	10
	93	0	15	32
	127/1	0	41	60
	127/7	0	03	45
	132/1	0	01	24
	134/1	0	05	98
	134/2	0	15	62
	135/3	0	24	30
	135/5	0	08	54
	135/6	0	09	80
	123/1	0	16	76
	123/4	0	12	93
	121/1	0	02	32
	121/7	0	13	52
	121/7	0	12	54
	121/8	0	12	12
	121/3	0	09	28
	121/5	0	14	64
	120/1	0	04	20
	120/2	0	15	00
	120/3	0	08	23
	121/12	0	17	25
	121/13	0	18	20
	117/1	0	22	88
	117/2	0	03	85
	117/3	0	18	45
	146	0	18	00
	147/1	0	08	10

[सं. O-14016/467/84-ज. प]

S.O 2941.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4564 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of layng pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	
Gamla	40	0	24	64
	39/1	0	14	70
	39/2	0	09	75
	42/1	0	10	90
	46	0	08	64
	47/3	0	41	52
	50	0	05	00
	53/1	0	02	50
	53/3	0	22	90
	53/2	0	02	64
	53/4	0	11	38
	52/1	0	24	60
	52/2	0	09	87
	86/1	0	24	36
	87	0	13	20
	88	0	21	90
	90/5	0	02	10
	93	0	15	32
	127/1	0	41	60
	127/2	0	03	45
	132/1	0	01	25
	134/1	0	05	98
	134/2	0	15	62
	135/3	0	24	30
	135/5	0	08	54
	135/6	0	09	80
	123/1	0	16	76
	123/2	0	12	93
	121/1	0	02	32
	121/2	0	13	53
	121/7	0	12	54
	121/8	0	12	12
	121/3	0	09	28
	121/5	0	14	64
	120/1	0	04	20
	120/2	0	15	00
	120/3	0	08	23
	121/12	0	17	25
	121/13	0	18	20
	117/1	0	22	88
	117/2	0	03	85
	117/3	0	18	45
	146	0	18	00
	147/1	0	08	10

[No. O-14016/467/84-GP]

का.आ. 2942.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 4676 तारीख 14-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—देवगढ़ बारिया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेंटियर
शेरपुरा	168	0	46	00
	181/1/ई	0	00	50
	181/1/बी	0	01	40
	181/1/सी	0	22	00
	181/1/डी	0	07	00
	184	0	21	50
	182	0	04	00
	185	0	21	04
	186	0	10	00
	186	0	27	00
	187	0	14	00
	197	0	15	00
	199	0	23	00
	198	0	12	48
	19/3	0	08	00
	18	0	40	80
	17/1	0	17	00
	26/1	0	00	80
	26/3	0	09	00
	31	0	28	80
	30/3	0	16	64
	30/2	0	01	60
	29	0	25	00
	41/3	0	14	00
	41/4	0	04	00
	41/5	0	00	80
	41/6	0	09	00
	42/2	0	10	00
	40/1	0	12	00
शेरपुरा—(जारी)	40/2	0	03	00
	39/2	0	11	00
	37	0	16	00
	38/6	0	10	00
	38/5	0	03	00
	64/1	0	18	00
	64/2	0	04	00
	81/5	0	11	00
	81/6	0	10	00
	81/3	0	11	00
	80	0	03	00
	79/2	0	20	00
	76	0	14	00
	78	0	01	00
	77	0	20	00
	88/6	0	09	00
	88/7	0	06	00
	88/5	0	01	00
	88/8	0	25	00
	89	0	30	00
	92	0	30	00

[सं O-14016/ 492/84-जा.पी.]

S.O. 2942.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4676 dated 14-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Devgadh Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sherpura	168	0	46	00
	181/1/E	0	00	50
	181/1/B	0	01	40
	181/1/C	0	22	00
	181/1/D	0	07	00
	184	0	21	50

1	2	3	4	5
	182	0	04	00
	185	0	21	00
	186	0	10	00
	188	0	27	00
	187	0	14	00
	197	0	15	00
	199	0	23	00
	198	0	12	40
	19/3	0	08	00
	18	0	40	00
	17/1	0	17	00
	26/1	0	08	00
	26/3	0	09	00
	31	0	28	80
	30/3	0	16	64
	30/2	0	01	60
	29	0	25	00
	41/3	0	14	00
	41/4	0	04	00
	41/5	0	00	80
	41/6	0	09	00
	42/2	0	10	00
	40/1	0	12	00
	40/2	0	03	00
	39/2	0	11	00
	37	0	16	00
	38/6	0	10	00
	38/5	0	03	00
	64/1	0	18	00
	64/2	0	04	00
	81/5	0	11	00
	81/6	0	10	00
	81/3	0	11	00
	80	0	03	00
	79/2	0	20	00
	76	0	14	00
	78	0	01	00
	77	0	20	00
	88/6	0	09	00
	88/7	0	00	00
	88/5	0	01	00
	88/8	0	2·	00
	89	0	30	00
	92	0	30	00

[No. O-14016/492/84-GP]

का. आ. 2943 यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4569 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजनों के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : लुनावाड़ा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
पटवाण	64/1	1	75	92
	41	0	22	00
	69/1	0	16	84
	67	0	01	00
	69/2	0	21	84
	65/1	0	15	44
	66	0	52	22
	67/2	0	00	70
	62	0	67	40
	76/1	0	00	50

[सं. O-14016/472/84-जी पी]

S.O. 2943.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4569 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District Panchmahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Patvan	64/P	1	75	92
	91	0	22	00
	69/1	0	16	84
	68	0	01	00
	69/2	0	21	84
	65/1	0	10	44
	66	0	52	22
	67/2	0	00	70
	62	0	67	40
	76/1	0	00	50

[No. O-14016/472/84-GP]

का. आ. 2944:— यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4058 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	चक. गठ/	90	0-5-10	
				91	0-9-0	
				92	0-0-6	
				93	0-0-13	
				95	1-16-0	
				100	0-3-9	
				101	0-0-7	
				102	0-4-5	
				128	0-1-19	
				130	0-18-10	
				131	0-8-5	
				133	0-10-16	
				138	0-5-10	
				139	0-1-0	
				184/2	0-16-15	
				207	0-11-18	
				208	0-0-17	
				238	0-1-19	
				239/2	0-3-16	
				240	0-3-2	
				241	0-3-16	
				242	0-15-5	
				244	1-1-18	
				253	0-2-0	
				255	0-18-0	
				256	0-6-0	
				257	0-6-5	
				259	0-2-15	
				260	0-7-10	
				318	0-9-0	
				319	0-5-5	
				320	0-5-0	
				321	0-8-0	
				322	0-5-10	
				323	0-9-0	
				371	0-5-10	
				101/-	0-1-0	
				446		
				176	0-16-15	
				245	0-0-5	
				324	0-0-10	
				325	0-0-5	
				317	0-0-5	

[सं. O-14016/296/84-जी]

S.O. 2944.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4058 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Lands) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Barielly-Jagdeshpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot. No.	Area Required	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Unnau	Purva	Purva	Chandi-gadhi	90	0-5-10	
				91	0-9-0	
				92	0-0-13	
				95	1-16-0	
				100	0-3-9	
				101	0-0-7	
				102	0-4-5	
				128	0-1-19	
				130	0-18-10	
				131	0-8-5	
				133	0-10-16	
				138	0-5-10	
				139	0-1-0	
				184/2	0-16-15	
				207	0-11-18	
				208	0-0-17	
				238	0-1-19	
				239/2	0-3-16	
				240	0-3-2	
				241	0-3-16	
				242	0-15-5	
				244	1-1-18	
				253	0-2-0	
				255	0-18-0	
				256	0-6-0	
				257	0-6-5	
				259	0-2-15	
				260	0-7-10	
				318	0-9-0	
				319	0-5-5	
				320	0-5-0	
				321	0-8-0	
				322	0-5-10	
				323/2	0-9-0	
				371	0-5-10	
				101/446	0-1-0	
				176	0-16-15	
				245	0-0-5	
				324	0-0-10	

[No. O-14016/296/84-GP]

का.आ. 2945. अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4545 तारीख 10.12.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—दाहोद

गांव	सर्वे न.	हेक्टर	आर	सेंटीयर
कटवारा	80/1	0	34	00
	88/1	0	54	00
	87	0	16	00
	86/पी	0	50	00
	85/2	0	06	00
	83/पी	0	26	00
	83/पी	0	08	00
	83/पी	0	15	00
	169/1	0	12	00
	168	0	16	00
	172/1	0	08	00
	173	0	17	00
	166	0	16	00
	174/1	0	03	00
	174/2	0	32	00
	187/1	0	38	00
	186	0	04	00
	188	1	18	00

[सं. O-14016/447/84-जी.पी.]

S.O. 2945.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4545 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Katvara	80/1	0	34	00
	88/1	0	54	00
	87	0	16	00
	86/P	0	50	00
	85/2	0	06	00
	83/P	0	26	00
	83/P	0	08	00
	83/P	0	15	00
	169/1	0	12	00
	168	0	16	00
	172/1	0	08	00
	173	0	17	00
	166	0	16	00
	174/1	0	03	00
	174/2	0	32	00
	187/1	0	38	00
	186	0	04	00
	188	1	18	00

[No. O-14016/447/84-GP]

का. आ. 2946.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4566 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
टिम्बा	31	0	39	87
	29	0	59	16
	28/1/पी	0	00	90
	कोटर	0	22	86
	11/1	0	00	64
	12/2	0	06	39
	12	0	30	56
	12/1	0	12	92
	13/3/पी	0	17	00
	13/2/पी	0	14	40
	13/1	0	09	00
	13/4	0	01	86
	14	0	12	40
	15	0	12	18
	15	0	04	56
	16	0	64	35
	कोटर	0	18	48
	18	0	41	68
	19/1	0	02	55
	7/पी	1	99	97
	51/5	0	07	82
	53/1	0	09	45
	53/2	0	43	69
	56/1/पी	0	63	44
	56/2/पी	0	26	35
	57	0	57	00
	2	0	72	90
	3/1	0	22	00
	3/2	0	18	90
	3/3	0	19	35
	4/1	0	26	88
	5	0	07	72
	6/1	0	06	72
	6/9	0	16	00
	6/2	0	20	64
	6/3	0	10	00
	6/4	0	12	18
	6/5	0	88	00

[सं. O-14016/469/84-जीपी]

S.O. 2946.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4566 dated 10-12-84. under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas he Competent Authority has under Sub-Sec-

tion (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Timba	31	0	39	87
	29	0	59	16
	28/1/P	0	00	90
	Kotar	0	22	86
	11/1	0	00	64
	12/2	0	06	39
	12	0	30	56
	12/1	0	12	92
	13/3/P	0	17	00
	13/2/P	0	14	40
	13/1	0	09	00
	13/4	0	01	86
	14	0	12	40
	15	0	12	18
	15	0	04	56
	16	0	64	35
	Kotar	0	18	48
	18	0	41	68
	19/1	0	02	55
	7/P	1	99	97
	51/5	0	07	82
	53/1	0	09	45
	53/2	0	43	69
	56/1/P	0	63	44
	56/2/P	0	26	35
	57	0	57	00
	2	0	72	90
	3/1	0	22	00
	3/2	0	18	90
	3/3	0	19	35
	4/1	0	26	88
	5	0	07	72
	6/1	0	06	72
	6/9	0	16	00
	6/2	0	20	64
	6/3	0	10	00
	6/4	0	12	18
	6/5	0	88	00

[No. O-14016/469/84-GP]

का. आ. 2947.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं. 4488 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : लिमखेड़ा

गाव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
घुटिया	29	0	13	00
	30	0	48	00
	38पै।	1	92	00

[सं. O—14016/376/84—ज प]

S.O. 2947.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4488 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And Further Whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ghutiya	29	0	13	00
	30	0	48	00
	38/P	1	92	00

[No. O-14016/376/84-GP]

का. आ. 2948.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2794 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	एकों	12	0 12	
				13	0 01	
				14	0 10	
				15	0 01	
				16	0 06	
				63	0 37	
				64	0 26	
				65	0 01	
				66	0 22	
				67	0 28	
				68	0 13	
				69	0 15	
				70	0 50	
				71	0 01	
				73	0 66	
				74	0 01	
				75	0 72	
				76	1 89	
				77	0 01	
				78	1 04	
				79	0 45	
				80	0 01	
				492	0 88	
				493	0 01	
				494	0 01	
				497	0 78	
				498	0 32	
				499	0 27	
				500	0 06	
				520	0 02	
				521	0 02	
				524	1 05	
				529	0 01	

[सं. O-14016/186/84-ज. पी]

S.O. 2948.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2794 dated 27-10-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Akon	12	0–12	
				13	0–01	
				14	0–10	
				15	0–01	
				16	0–06	
				63	0–37	
				64	0–26	
				65	0–01	
				66	0–22	
				67	0–28	
				68	0–13	
				69	0–15	
				70	0–50	
				71	0–01	
				73	0–66	
				74	0–01	
				75	0–72	
				76	1–89	
				77	0–01	
				78	1–04	

1	2	3	4	5	6	7
J l.un			Ak ı ı	79	0–45	
				80	0–01	
				492	0–88	
				493	0–01	
				494	0–01	
				497	0–78	
				498	0–32	
				499	0–27	
				500	0–06	
				520	0–02	
				521	0–02	
				524	1–05	
				529	0–01	

[No O-14016/186/84-GP]

का. आ. 2949.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2717 तारीख 25-8-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा		विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महराजगंज	इन्हौना	पन्हौना	2691	0–4–0	
				2692	0–10–16	
				2193	0–3–4	
				2694	1–0–4	
				2703	0–3–4	
				2704	0–6–8	
				2705	0–5–0	
				2706	0–10–14	
				2707	0–2–10	
				2708	0–0–12	
				2715	0–3–18	
				2718	0–6–0	
				2719	0–5–19	
				2720	0–3–4	
				2721	0–10–0	
				2722	0–0–1	
				2723	0–3–12	
				2782	0–14–8	
				2783	0–17–0	
				2787	0–2–0	
				2791	0–4–0	
				2792	0–3–5	
				2793	0–4–0	
				2794	0–13–0	
				2795	0–7–0	
				2799	0–1–15	
				2800	0–6–0	
				2801	0–6–0	
				2802	0–2–5	
				2803	0–0–1	
				2706	0–10–14	

[सं० O-14016/95/84-जी पी]

S.O 2949.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2717 dated 25-8-84 under sub-section (1) of, section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power confened by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Barielly—Jagdieshpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Rai Barielly	Maha-raiganj	Enhona	Panhona	2691	0–4–0	
				2692	0–10–16	
				2193	0–3–4	
				2694	1–0–4	
				2703	0–3–4	
				2704	0–6–8	
				2705	0–5–0	

1	2	3	4	5	6	7
				2706	0-10-14	
				2707	0-2-'0	
				2708	0-0-12	
				2715	0-3-18	
				2718	0-6-0	
				2719	0-5-19	
				2720	0-3-4	
				2721	0 10-0	
				2722	0-0-1	
				2723	0-3-12	
				2782	0-14 8	
				2783	0-17-0	
				2787	0-2-0	
				2791	0-4-0	
				2792	0-3-5	
				2793	0-4 0	
				2794	0-13-0	
				2795	0-7 0	
				2799	0 1 15	
				2800	0 6-0	
				2801	0-6-0	
				2802	0-2-5	
				2803	0-0-3	

[No. O-14016/95/84-GP]

का आ 2950 —यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ म 2717 तारीख 25-8-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की सा तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्राजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम		लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
राय बरेली	महराजगंज	सेमरोता	भइयापुर			
				19	0-9-0	
				20	0-1-10	
				22	0-4-5	
				28	0-10-15	
				29	1-4-0	
				30	0-2-15	
				31	0-3-5	
				33	1-19-0	
				38	0-15-0	
				39	0-4-15	
				40	1-3-15	
				41	0-4-0	
				46	0-8-0	
				49	0-10-10	
				52	0-1-0	
				76	0-2-10	
				77	1-7-0	

[सं० O-14016/95/84-जीपी]

S.O 2950.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O 2717 dated 25 8-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rai-Barielly	Maharaj-ganj	Samro-ta	Bhaia-yapur	19	0-9-0	
				20	0-1-10	
				22	0-4-5	

1	2	3	4	5	6	7
				28	0 10-15	
				29	1-4-0	
				30	0-2-15	
				31	0-3-5	
				33	1-19-0	
				38	0-15-0	
				39	0 4 15	
				40	1-3-15	
				41	0 4 0	
				46	0 8-0	
				49	0-10-10	
				52	0-1-0	
				76	0-2-10	
				77	1-7-0	

[No O 14016/95/84-GP]

का आ 2951--यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि म उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का आ स तारीख 3717/25-8-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयाग के अधिकार का पाइप लाइनो को बिछान के लिए अर्जित करन का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) क अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करन के पश्चात् इस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची म विनिर्दिष्ट भूमिया म उपयाग का अधिकार अर्जित करन का विनिश्चय किया है।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना म सलग्न अनुसूची म विनिर्दिष्ट उक्त भूमिया म उपयाग का अधिकार पाइप लाइन बिछान क प्रयाजन क लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियो म उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार म निहित होन के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि म सभी बाधाओ स मुक्त रूप म घोषणा क प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा-बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्राजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	सर्वे न०	अर्जित किया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महराजगंज	बछरावं	गैन			
				494	0-13-1	
				195	0-1-15	
				198	0-0-16	
				197	0 2-10	
				192	0-12-12	
				191	0-1-15	
				199	0 1-15	
				190	1-9-0	
				188	0-17-4	
				183	0-11-8	
				212	0-1-4	
				213	0-13-12	
				175	0-19-1	
				174	0-1-15	
				226	0-0-15	
				173	0-11-16	
				171	1-2-4	
				172	0-1-16	
				170	0-10-4	
				169	0- 1-4	
				243	0-2-14	
				104	0 0-10	
				76	0-7-4	
				168	0-10-14	
				166	0-1-4	
				165	0-12-12	
				163	0-5-10	
				105	0-12-13	
				107	0-0-10	
				108	0-11-15	
				120	0-15-0	
				121	0-8-10	
				129	0-14-10	
				128	0-5-0	
				127	0-0-15	
				133	0-1-5	
				132	0-8-5	
				131	0-0-8	
				196	0-0-15	
				205	0-3-0	
				203	0-2-5	
				184	0-1-4	
				164	0-2-0	
				146	0-2-0	
				216	0-1-4	
				75	0-4-0	
				119	0-0-15	
				116	0-0-10	
				167	0-0-10	
				162	0-0-18	
				114	0-0-5	
				269	0-0-10	
				94	0-1-0	

[स० O-14016/95/84-ज प.]

S O 2951—Whereas it appears to the Central Government of India in the Ministry of Petroleum S O 2717 dated 25 8 84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now therefore in exercise of the power conferred by sub section (I) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rai-Bareilly	Maha-rajganj	Bachh-rawana	Rain	494	0-13-4	
				195	0-1-15	
				198	0-0-16	
				197	0-2-10	
				192	0-12-12	
				191	0-1-15	
				199	0-1-15	
				190	1-9-0	
				188	0-17-4	
				183	0-11-8	
				212	0-1-4	
				213	0-13-12	
				175	0-19-4	
				174	0-1-15	
				226	0-0-15	
				173	0-11-16	
				171	1-2-4	
				172	0-1-16	
				170	0-10-4	
				169	0-1-4	
				243	0-2-14	
				104	0-0-10	
				76	0-7-4	
				168	0-10-14	
				166	0-1-4	
				165	0-12-12	
				163	0-5-10	
				105	0-12-13	
				107	0-0-10	
				108	0-11-15	
				120	0-15-0	
				121	0-8-10	
				129	0-14-10	
				128	0-5-0	
				127	0-0-15	
				133	0-1-5	
				132	0-8-5	
				131	0-0-8	
				196	0-0-15	
				205	0-3-0	
				203	0-2-5	
				184	0-1-4	
				164	0-2-0	
				146	0-2-0	
				216	0 1 4	
				75	0-4-0	
				119	0-0-15	
				116	0-0-10	
				167	0-0-10	
				162	0-0-18	
				114	0-0-5	
				269	0-0-10	
				94	0-1-0	

[No. O-14016/95/84-GP]

का. आ. 2952—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं० 4121 तारीख 1.12.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम कुडी वे तहसील राजगढ़ जिला : राजगढ़ राज्य. (मध्य प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	6/1	0 131
2.	6/2	0.013
3	6/3	0 132
4	6/4	0 132
5.	6/5	0 132
6	6/6	0 192
7	5	0 544
8	4/1	0.228
9.	4/2	0.042
10.	12	0.018
11.	21	0.744
12.	22	0.025
कुल योग.—क्षेत्रफल		2.333

[सं. O-14016/334/84-जी पी.]

S.O. 2952.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4121 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after Considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power confered by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Kundli-Bc, Tehsil : Rajgarh Dist : Rajgarh

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U In Hectare
1.	6/1	0.131
2.	6/2	0.013
3.	6/3	0.132
4.	6/4	0 132
5.	6/5	0 132
6	6/6	0.192
7.	5	0.544
8	4/1	0.228
9.	4/2	0.042
10.	12	0 018
11.	21	0.744
12	22	0 025
	Total Area	2 333

[No. O-14016/339/84-GP]

का. आ. 2953.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. 126 तारीख 12-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।]

एच बी. जे. गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम . रानीपुरा तहसील राजगढ़ जिला . राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्रम	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	3	0 680
2.	4/1	1.000
3.	7/2	0 540
4.	7/1	0.025
5	12/1	0.036
6.	10	0.076
7.	4/2	0.026
8.	11	0.150
9.	14	0.190
10.	19	0.130
11.	20	0.005
12.	21	0.120
13	24	0.120
14.	25	0.120
15.	36	0.030
16.	35/1	0.300
17.	6/3	0.005
18.	6/1	0.400
19.	8/1	0 005
20.	9	0.020
21.	35/2	0.005
	योग . कुल क्षेत्रफल	3.983

[स. G-14016/519/84-जी. पी.]

S.O. 2953.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 126 dated 12-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Ranipura Tehsil : Rajgarh Distt : Rajgarh

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	3	0.680
2.	4/1	1.000
3.	7/2	0.540
4.	7/1	0.025
5.	12/1	0.036
6.	10	0.076
7.	4/2	0.026
8.	11	0.150
9.	14	0.196
10	19	0.130
11	20	0.005
12.	21	0.120
13.	24	0.120
14.	25	0.120
15.	36	0.030
16	35/1	0.300
17.	6/3	0.005
18.	6/1	0.400
19	8/1	0.005
20.	9	0.023
21.	35/2	0.005
Total Area		3.983

[No. O-14016/519/84-GP]

का.आ. 2954 :—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4532 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीसपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य :—गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : दहोद

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
चढ़वाना	371/5	0	34	00
	371/4	0	11	00
	371/3	0	17	00
	371/2	0	04	00
	373/2	0	11	00
	373/3	0	25	00
	373/4	0	03	00
	358	0	20	00
	359/2	0	34	00
	371/1	0	12	00

[सं. O-14016/434/84-जी पी]

S.O. 2954.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4532 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Chadhvana	371/5	0	34	00
	371/4	0	11	00
	371/3	0	17	00
	371/2	0	04	00
	373/2	0	11	00
	373/3	0	25	00
	373/4	0	03	00
	358	0	20	00
	359/2	0	34	00
	371/1	0	12	00

[No. O-14016/434/84-GP]

का. आ. 1955.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 का (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4565 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला पंचमहल तालुका हालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
गडोई	139	3	58	00
	145	0	39	00
	146	0	22	00
	136	0	30	00
	135	0	62	00
	131	0	26	00
	132	0	28	00
	88	0	18	00
	89	0	54	00
	90	0	01	00
	93	0	25	00
	96	0	50	00
	98	0	68	00

[सं O-14016/468/84-जीपी]

S.O. 2955.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4565 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No	Hectare	Are	Centare
Gadoi	139	3	58	00
	145	0	39	00
	146	0	22	00
	136	0	30	00
	135	0	62	00
	131	0	26	00
	132	0	28	00
	88	0	18	00
	89	0	54	00
	90	0	01	00
	93	0	25	00
	96	0	50	00
	98	0	68	00

[N . O-14016/468/84-GP]

का०आ० 2956.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4129 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि., में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्राजेक्ट

ग्राम सावन खेड़ा तहसील राजगढ़ जिला-राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	44	0.075
2.	45	0.075
3.	46	0.065
4.	47	0.253
5.	41	0.010
कुल योग क्षेत्रफल		0.478

[म.O- 14016/355/84- जी पी]

S.O. 2956.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4129 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication in this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Sawankheda Tehsil :Rajagarh Distt. : Rajagarh

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
*1.	44	0.075
2.	45	0.075
3.	46	0.065
4.	47	0.253
5.	41	0.010
Total Area		0 478

[No. 14016/355/84– GP]

का. आ. 2957.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 129 तारीख 12-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने का प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में. घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम: गुराड़िया तहसील: राजगढ़ जिला: राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	1	0.228
2.	2	0 048
	कुल योग क्षेत्रफल	0.376

[सं. O-14016/522/84-जी. पी]

S.O. 2957.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 129 dated 12-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Guradiya Tehsil : Rajgarh Distt : Rajgarh

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectre
1.	1	0.228
2.	2	0.048
Total Area		0.376

[No. O—14016/522/84- GP]

का. आ. 2958—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3925 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों, को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

347 GI/85—12

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

एच. बी. जे. पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम: पोलास तहसील: चाचोड़ा जिला: गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं	उपयोग का अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	54	0.637
2.	55	0.094
3.	57	0.199
4	60	0.105
5.	62	0.010
6.	63	0.460
7.	76	0.105
8.	73/81	0.031
	योग—कुल क्षेत्रफल	1.631

[सं. O-14016/263/84— जी पी]

S.O. 2958.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3925 Dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And Whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And Further whereas the Central Government has, after Considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd, free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Polas Tehsil : Chachoda Distt. : Guna

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	54	0.637
2.	55	0.094
3.	57	0.199
4.	60	0.105
5.	62	0.010
6.	63	0.460
7.	76	0.105
8.	73/81	0.031
	Total Area	1.631

[No. O-14016/263/84-GP]

का०आ० 2959.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 4276 तारीख 8-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाइन प्रोजक्ट

ग्राम: मालपुरा तहसील: बड़नगर जिला-उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स)
1	2	3
1.	235	0.052
2.	237/3	0.366
3.	237/1	0.166
4.	239/1/1	0.518
5	240	0.021
6.	239/1/2/4	0.146
7.	239/1/2/3	0.146
8.	239/1/2/2	0 146
9.	239/1/2/1	0.179
10.	239/2	0.166
11	239/3	0.314
12.	239/4	0.157
13.	239/5	0.209
14.	190	0.397
15.	189	0.314
16.	188	0.314
17.	239/9	0.031
18.	239/10	0.021
19.	236	0.031
20	229	0.052
21.	237/2	0.010
कुल योग :—क्षेत्रफल		3.756

[सं. O-14016/362/84-जीपी]

S.O. 2959.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4276 dated 8-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Malpura Tehsil : Badnagar Distt : Ujjain

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	235	0.052
2.	237/3	0.366
3.	237/1	0.166
4.	239/1/1	0.518
5	240	0.021
6.	239/1/2/4	0.146
7.	239/1/2/3	0.146
8.	239/1/2/2	0.146
9.	239/1/2/1	0.179
10.	239/2	0.166
11.	239/3	0.314
12.	239/4	0.157
13.	239/5	0.209
14.	190	0.397
15	189	0.314
16.	188	0.314
17.	239/9	0.031
18.	239/10	0.021
19.	236	0.031
20.	229	0.052
21.	237/2	0.010
	Total Area :	3.756

[No. O-14016/362/84—GP]

का. आ. 2960:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3914 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम गुजरिया तहसील नलखेड़ा जिला-शाजापुर राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्रफल (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	12	0.105
2	13	0.010
3.	20	0.010
4.	32	0.366
5.	34/1	0.031
6	35/1	0.240
7	66/4	0.125
8.	65/2	0.021
9.	22	0.219
10.	34/2	0.010
11.	35/3	0.042
12.	66/3	0.366
13.	77	0.042
14.	23	0.052
15.	31	0.219
16.	10/2	0.084
17.	9	0.397
18.	21	0.021
19.	30	0.209
20.	76	0.282
21.	72	0.073
22.	74	0.167
23.	29	0.010
24.	75	0.042
25.	78/1	0.063
26.	86	0.209
योग :—कुल क्षेत्रफल		3.415

[सं. O-14016/252/84-जीपी]

S.O. 2960.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3914 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Gujariya Tehsil : Nalkheda Distt : Shajapur

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	12	0.105
2.	13	0.010
3.	20	0.010
4.	32	0.366
5.	34/1	0.031
6.	35/1	0.240
7.	66/4	0 125
8.	65/2	0.021
9.	22	0.219
10.	34/2	0.010
11.	35/3	0.042
12.	67/3	0.366
13.	77	0.042
14.	23	0.052
15.	31	0.219
16.	10/2	0.084
17.	9	0.397
18.	21	0.021
19.	30	0.209
20.	76	0.282
21.	72	0.073
22.	74	0.167
23.	29	0.010
24.	75	0.042
25.	78/1	0.063
26.	86	0.209
	Total Area :	3.415

[No. O—14016/252/84-GP]

का.आ. 2961—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3938 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच बी.जे.गैस. पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम छान तहसील चचाड़ा जिला-गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु. क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	30	0.209
2.	26	0.052
3.	34/1	1.182
4.	50	0.251
5.	48	0.031
6.	1/1	0.021
योग :—कुल क्षेत्रफल		1.746

[O-14016/281/84-जीपी]

S.O. 2961.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3938 dated 24-11-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Chhan	Tehsil : Chachoda	Distt. : Guna
S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	30	0.209
2.	26	0.052
3.	34/1	1.182
4.	50	0.251
5.	48	0.031
6.	1/1	0.021
	Total Area	1.746

[No. O-14016/281/84-GP]

का. आ. 2962.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4130 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच.बी.जे.गस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : घोधडिया खुर्द	तहसील : राजगढ़	जिला राजगढ़ (राज्य मध्य-प्रदेश)
अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	167	0.025
2.	168	0.020
3.	169/9	0.253
4.	169/5	0.379
5.	169/15	0.328
6.	169/17	0.005
7	169/8	0.052
8.	169/3	0.500
9.	169/11	0.051
10.	169/6	0.305
11.	169/18	0.112
कुल योग :—क्षेत्रफल		2.030

[सं. O-14016/356/84-जीपी]

S.O. 2962.—Whereas by notification of the Government of ndia in the Ministry of Petroleum S.O. 4130 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Ghodhadiya Khurd	Tehsil : Rajgarh	Distt. : Rajgarh
S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	167	0.025
2.	168	0.020
3.	169/9	0.253
4.	169/5	0.379
5.	169/15	0.328
6.	169/17	0.005
7.	169/8	0.052
8.	169/3	0.500
9.	169/11	0.051
10.	169/6	0.305
11.	169/18	0.112
	Total Area :	2.030

[No. O-14016/356/84-GP]

का.आ. 2963.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर सिटी	कानपुर सिटी	कानपुर सिटी	सरसत पुर	2	1-11-15	
				7	0-0-16	
				8	0-4-04	
				11	0-0-10	
				10	1-4-18	
				14	0-1-19	
				28	0-8-5	
				53	0-1-16	
				54	0-8-08	
				55	0-1-04	

[सं. O-14016/6/84-जी पी]

S.O. 2963.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Sernet-pur	2	1-11-15	
				7	0-0-16	
				8	0-4-04	
				11	0-0-10	
				10	1-4-18	
				14	0-1-19	
				28	0-8-5	
				53	0-1-16	
				54	0-8-08	
				55	0-1-04	

[No. O-14016/6/84-GP]

का. आ. 2964.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4273, तारीख 8-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम बाजपुरा तहसील राजगढ़ जिला-राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3
1.	110	0.080
2.	100	0.036
3.	109	0.033
4.	102	0.025
5.	105	0.132
6.	106	1.200
7.	107	0.600
8.	115	0.102
9.	117	0.084
10.	118	0.0180
11.	119	0.360
12.	41	0.392
13.	120	0.032
14.	40	0.066
15.	38	0.468
16.	37	0.264
17.	101	0.018
18.	104	0.030
19.	39	0.010
कुल योग.—क्षेत्रफल		4.112

[सं. O-14016/359/84-पी

S.O. 2954.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4273 dated 8-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the sal dAct, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bajpura Tehsil : Rajgarh Distt. : Rajgar

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired mo R.O.U. in hecture
1	2	3
1	110	0.080
2.	100	0.036
3.	109	0.033
4.	102	0.025
5.	105	0.132
6.	106	1.200
7.	107	0.600
8.	115	0.102
9.	117	0.084
10.	118	0.0180
11.	119	0.0360
12.	41	0.392
13.	120	0.032
14.	40	0.066
15.	38	0.468
16.	37	0.264
17.	101	0.018
18.	104	0.030
19.	39	0.010
	Total Area	4.112

[No. O-14016/359/84—GP]

का. आ. 2965.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ० सं. 4112 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में

विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम जेतपुरा तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	4	0.360
2	6	0.060
3.	7	0.190
4.	8	0.253
5.	10	0.005
6.	11	0.310
7.	12	0.365
8.	13	0.285
9.	15	0.012
10.	16	0.253
11.	1/7	0.025
12.	17	0.200
13.	3/2/2	0.365
14.	3/2/3	0.320
15.	62/3/8	0.012
16.	3/2/1	0.055
17.	62/3/4	0.012
18.	62/1	0.307
19.	62/3/1	0.300
20.	62/3/2	0.240
21.	62/3/3	0.315
22.	62/3/5	1.000
23.	62/4	0.360
24.	62/8	0.460
25.	62/6	0.090
26.	62/7	0.190
कुल योग क्षेत्रफल		6.344

[सं. O-14016/329/84-जीपी]

S.O. 2965.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4112 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Jetpura Tehsil : Rajagarh Distt : Rajagarh

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired fo R.O.U. in hecture
1.	4	0.360
2.	6	0.060
3.	7	0.190
4.	8	0 253
5.	10	0.005
6.	11	0.310
7.	12	0.365
8.	13	0.285
9.	15	0.012
10.	16	0.253
11.	1/7	0.025
12.	17	0.200
13.	3/2/2	0.365
14.	3/2/3	0.320
15.	62/3/8	0.012
16.	3/2/1	0.055
17.	62/3/4	0.012
18.	62/1	0.307
19.	62/3/1	0.300
20.	62/3/2	0.240
21.	62/3/3	0.315
22.	62/3/5	1.000
23.	62/4	0.360
24.	62/8	0 460
25.	62/6	0.090
26.	62/7	0.190
	Total Area	6.344

[No. O-14016/329/84—GP]

का. आ. 2966:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3668 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच.बी.जे.गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम छावनी तहसील गुना जिला-गुना राज्य (म.प्र.)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	773	0-355
2.	774	0-152
3.	778	0-052
4.	782	0-418
5.	783/1	0-523
6.	784मी	0-063
7.	868/1	0-888
8.	868/2	0-042
9.	880	0-010
10.	882/1	0-021
11.	882/2	0-575
12.	884	0-126
13.	887	0-679
14.	888/1/1	0-261
15.	888/1/2	0-157
16.	888/1/3	0-201
17.	889	0-042
18.	890	0-031
19.	897	0-152
20.	926	0-198
21.	974	0-126
22.	975	0-314
23.	976	0-355
24.	977	0-314
25.	978	0-272
26.	979	0-418
27.	980	0-021
28.	982	0-105
29.	983	0-439
30.	984	0-470
31.	985	0-355
32.	993	0-073
33.	1003	0-083
34.	887/1057	0-261
कुल क्षेत्रफल —		8.552

[सं. 0-14016/92/84-जीपी]

S.O. 2966.—Whereas by notification of the Government of Ind a in the Ministry of Petroleum, S.O. 3668 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has, under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Chhawani Tehsil : Guna Distt : Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1	2	3
1.	773	0.355
2.	774	0.152
3.	778	0.052
4.	772	0.418
5.	783/1	0.523
6.	784 M.	0.063
7.	868/1	0.888
8.	868/2	0.042
9.	880	0.010
10.	882/1	0.021
11.	88/2	0.575
12.	884	0.126
13.	887	0.679
14.	888/1/1	0.261
15.	888/1/2	0.157
16.	888/1/3	0.201
17.	889	0.042
18.	890	0.031
19.	897	0.152
20.	926	0.198
21.	974	0.126
22.	975	0.314
23.	976	0.355
24.	977	0.314
25.	978	0.272

1	2	3
26.	979	0.418
27.	980	0.021
28.	987	0.105
29.	983	0.439
30.	984	0.470
31.	985	0.355
32.	993	0.073
33.	1003	0.083
34.	887/1057	0.261
	Total Area	8.552

[No. O-14016/92/84—GP]

का. आ. 2967:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4113 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम किशनपुरिया तहसील राजगढ़ जिला-राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्रम सं.	खसरा सं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	54/10	0 540
2.	54/11	0 330
3.	54/1	0 850
4	55/1	2.040
	—कुल क्षेत्रफल	3.760

[सं. O-14016/330/84-जीपी]

S.O. 2967.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4113 dated 1-12-84 under sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this decalaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Kishnapura Tehsil : Rajagarh Distt : Rajagarh

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	54/10	0.540
2.	54/11	0.330
3.	54/1	0.850
4.	55/1	2 040
	Total Area	3.760

[No. O-14016/330/84—GP]

का. आ. 2968:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 123 तारीख 2-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य-गुजरात जिला-पंचमहल तालुका-दाहोद

गाव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मोटा खरज	120/4/ए	0	12	00
	120/7	0	20	00
	120/6	0	17	00
	120/8	0	03	00
	128/4	0	17	00
	128/5	0	11	00
	128/6	0	31	00
	130/1/पी	0	38	00
	131/1	0	04	00
	131/2	0	28	00
	101/1/पी	0	10	00
	101/2	0	26	00
	102	0	01	00
	101/4/पी	0	14	00
	100	0	24	00
	99	0	29	00
	292	0	51	00
	291/1	0	10	00
	291/3	0	03	00
	291/4	0	04	00
	291/5	0	08	00
	5/9	0	15	00
	5/10	0	13	00
	5/11	0	15	00
	283	0	01	00
	272/8	0	28	00
	273/1	0	21	00
	273/2	0	10	00
	273/3	0	14	00
	274/1	0	45	00
	274/2	0	34	00
	269	0	04	00
	268	0	26	00
	267	0	06	00
	266	0	60	00
	250/1	0	24	00
	250/2	0	27	00
	249	0	40	00
	248	0	33	00

[सं O-14016/516/84-जी.पी.]

S.O. 2968.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 123 date 2-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Moti Kharaj	120/4/A	0	12	00
	120/7	0	20	00
	120/6	0	17	00
	120/8	0	03	00
	128/4	0	17	00
	128/5	0	11	00
	128/6	0	31	00
	130/1/P	0	38	00
	131/1	0	04	00
	131/2	0	28	00
	101/1/P	0	10	00
	101/2	0	26	00
	102	0	01	00
	101/4/P	0	14	00
	100	0	24	00
	99	0	29	00
	292	0	51	00
	291/1	0	10	00
	291/3	0	03	00
	291/4	0	04	00
	291/5	0	08	00
	5/9	0	15	00
	5/10	0	13	00
	5/11	0	15	00
	283	0	01	00
	272/8	0	28	00
	273/1	0	21	00

1	2	3	4	5
	273/2	0	10	00
	273/3	0	14	00
	274/1	0	45	00
	274/2	0	34	00
	269	0	04	00
	268	0	26	00
	267	0	06	00
	266	0	60	00
	250/1	0	24	00
	250/2	0	27	00
	249	0	40	00
	248	0	33	00

[No. O-14016/516/84—GP]

का . आ . 2969.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 656 तारीख 16-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम मोहना तहसील शाजापुर जिला-शाजापुर राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा सं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
	3	
1.	1456/2	0.073
2.	1614/1	1.129
3.	1617/2	0.031
4.	1615/2	0.125
5.	1620	0.042
6.	1646	0.011
7.	1796	0.052
8.	1797	0.167
9.	1798	0.052
10.	1799	0.052
11.	1800	0.627
12.	1645	0.105
13.	1610/2	0.011
14.	1647/1	0.167
15.	1609	0.082
16.	1610/1	0.021
17.	1624	0.125
18.	1628	0.026
19.	1611	0.042
20.	1610/3	0.010
21.	1612	0.042
22.	1606	0.072
23.	1608/1	—
24.	1608/2	—
25.	1648	0.031
26.	1594/2	0.010
27.	1594/3	0.010
28.	1595/2	0.042
29.	1601/1	0.021
30.	1601/2	0.042
31.	1602	0.021
32.	1559/1	0.159
33.	1566/1	0.219
34.	1566/2	0.272
35.	1568/1	0.188
36.	1568/2	0.084
37.	1579	0.073
38.	1580	0.103
39.	1581/1	0.031
40.	1582/1	0.146
41.	1582/2	0.146
42.	1582/3	0.146
43.	1582/4	0.053
44.	1446	0.282
45.	1448	0.073
46.	1444	0.261
47.	1433	0.502
48.	1434/1	0.180
49.	1435/2	0.031
50.	1434/2	0.366
51.	1560/1	0.345
52.	1560/2	0.142
53.	1436	0.052
54.	1399	0.272
55.	1395	0.011
56.	1396	0.052
57.	1397/1	0.146

58.	1615/1	0.084
59.	1613	0.010
60.	1583	0.010
61.	1616	0.021
62.	1617/1	0.021
63.	1569/2	0.010
64.	1590/1/1	0.031
योग :-	कुल क्षेत्रफल	7.763

[सं० O-14016/51/85-जीपी]

S.O. 2969.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 656 dated 16-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from enumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Mohana Tehsil : Shajapur Distt : Shajapur

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in hecture
1.	1456/2	0.073
2.	1614/1	1.129
3.	1617/2	0.031
4.	1615/2	0.125
5.	1620	0.042
6.	1646	0.011
7.	1796	0.052
8.	1797	0.167
9.	1798	0.052
10.	1799	0.052
11.	1800	0.627
12.	1645	0.105
13.	1610/2	0.111
14.	1647/1	0.167
15.	1609	0.082
16.	1610/1	0.021
17.	1624	0.125
18.	1628	0.026
19.	1611	0.042
20.	1610/3	0.010
21.	1612	0.042
22.	1606	0.072
23.	1608/1	—
24.	1608/2	—
25.	1648	0.031
26.	1594/2	0.010
27.	1594/3	0.010
28.	1595/2	0.042
29.	1601/1	0.021
30.	1601/2	0.042
31.	1602	0.021
32.	1559/1	0.159
33.	1566/1	0.219
34.	1566/2	0.272
35.	1568/1	0.188
36	1568/2	0 084
37	1579	0.073
38	1580	0.103
39	1581/1	0.031
40	1582/1	0.146
41	1582/2	0.146
42	1582/3	0.146
43	1582/4	0 053
44	1446	0.282
45	1448	0.073
46	1444	0.261
47	1433	0.502
48	1434/1	0.180
49	1435/2	0.031
50	1434/2	0.366
51	1560/1	0.345
52	1560/2	0.142
53	1436	0.052
54	1399	0.272
55	1395	0.011
56	1396	0.052
57	1397/1	0.146
58	1615/1	0.084
59	1613	0.010
60	1583	0.010
61	1616	0.021
62	1617/1	0.021
63	1569/2	0.010
64	1590/1/1	0.031
	Total Area	7.763

[No O-14016/51/85-GP]

का. आ. 2970.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 660 तारीख 16-12-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अत: अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : बरनावद तहसील : शाजापुर जिला : शाजापुर राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	963	0.052
2.	298	0.031
3.	331	0.042
4.	367	0.042
5.	952/2	0.150
6.	953	0.418
7.	948	0.293
8.	949	0.199
9.	944	0.094
10.	945	0.031
11.	946	0.063
12.	132/3	0.157
13.	132/1	0.230
14.	138/1	0.240
15.	132/5	0.031
16.	139	0.157
17.	132/2/6	0.094
18.	137/2	0.021
19.	138/2/3	0.021
20.	136/2	0.021
21.	137/1	0.251
22.	138/2/4	0.073
23.	140	0.031
24.	160	0.063
25.	161	0.219
26.	187	0.031
27.	188	0.397
28.	159	0.052
29.	162	0.261
30.	266	0.031
31.	109	0.199
32.	165/1	0.031
33.	168/2	0.094
34.	168/1	0.115
35.	182	0.230
36.	338	0.342
37.	184	0.021
38.	181/3	0.125
39.	180	0.063
40.	335	0.125
41.	183	0.073
42.	181/4	0.063
43.	181/2	0.005
44.	270	0.167
45.	336	0.084
46.	269	0.146
47.	267	0.084
48.	273	0.105
49.	274	0.022
50	301	0.178
51.	302	0.042
52.	299/1	0.272
53.	329/3	0.042
54.	299/2/1/2	0.240
55.	276	0 063
56.	330	0.052
57.	332	0.042
58.	334	0.146
59.	333	0.073
60.	337	0.157
61.	357	0.063
62.	372	0.146
63.	370	0.219
64.	369/1	0.084
65.	369/2	0.157
66.	294	0.031
67.	371/2	0.292
68.	371/1	0.352
69.	304	0.021
योग : —कुल क्षेत्रफल		8.562

[सं. O-14016/55/85-जीपी]

S.O. 2970.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 660 dated 16-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Barnawad Tehsil : Shajapur Distt : Shajapur

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R O U in hectare
1	3	2
1.	963	0.052
2.	298	0.031
3.	331	0.042
4.	367	0.042
5.	952/2	0.150
6.	953	0.418
7.	948	0.293
8.	949	0.199
9.	944	0.094
10.	945	0.031
11.	946	0.063
12.	132/3	0.157
13.	132/1	0.230
14.	138/1	0.240
15.	132/5	0.031
16.	139	0.157
17.	132/2/6	0.094
18	137/2	0.071
19.	138/2/3	0.021
20.	136/2	0.021
21.	137/1	0.251
22.	138/2/4	0.073
23.	140	0.031
24.	160	0.063
25.	161	0.219
26.	187	0.031
27.	188	0.397
28.	159	0.052
29.	162	0.261
30.	266	0.031
31.	109	0.199
32.	165/1	0.031
33.	168/2	0.094
34.	168/1	0.115
35.	182	0.230
36.	338	0.342
37.	184	0.021
38.	181/3	0.125
39.	180	0.063
40.	335	0.125
41.	183	0.073
42.	181/4	0.063
43.	181/2	0.005
44.	270	0.167
45.	336	0.084
46.	269	0.146
47.	267	0.084
48.	273	0.105
49.	274	0.022
50.	301	0.178
51.	302	0.042
52.	299/1	0.272
53.	329/3	0.042
54.	299/2/1	0.240
55.	276	0.063
56.	330	0.052
57.	332	0.042
58.	334	0.146
59.	333	0.073
60.	337	0.157
61.	357	0.063
62.	372	0.146
63.	370	0.219
64.	369/1	0.084
65.	369/2	0.157
66.	294	0.031
67.	371/2	0.292
68.	371/1	0.352
69.	304	0.021
	Total Area	8.562

[No. O-14016/55/85—GP]

का. आ. 2971:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 653 तारीख 16-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्र.म मण्डेड्री तहसील शाजापुर जिला—शाजापुर राज्य(मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	266/1	0.030
2.	632	0.082
3.	659/1	0.376
4.	591	0.031
5.	571	0.291
6.	572	0.021
7.	581	0.005
8.	574	0.167
9.	593	0.010
10.	594	—
11.	569/2	0.219
12.	573	0.010
13.	582	0.115
14.	583/1	0.125
15	583/2	0.021
16.	584	0.084
17.	587	0.073
18.	624	0.010
19	625	0.010
20.	626	0.032
21.	627	0.052
22.	616/1	0.157
23.	629	0.480
24.	616/2	0.157
25.	614	0.271
26.	638	0.093
27.	639	0.042
28.	636/3	0.105
29.	640	0.010
30.	642	0.125
31.	643	0.073
32.	657/1/2	0.345
33.	657/1/1	0.230
34.	628	0.010
35.	636/2	0.031
36.	631	0.021
37.	580	0.021
	योग.;—कुल क्षेत्रफल	3.935

[सं. O-14016/48/85-जी. पी.]

S.O. 2971.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 653 dated 16-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intent'o nto acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bhandedry Tehsil : Shajapur Distt : Shajapur

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for ROU in hectare
1.	266/1	0.030
2.	632	0.082
3.	650/1	0.376
4.	591	0.031
5.	571	0.291
6	572	0.02
7.	581	0.005
8.	574	0.167
9.	593	0 0 0
10.	594	—
11.	569/2	0.219
12.	573	0.010
13.	582	0.115
14.	583/1	0.125
15.	583/2	0 021
16	584	0 084
17	587	0.073
18.	624	0.010
19.	625	0.010
20.	626	0.032
21.	627	0.052
22.	616/1	0.157
23.	629	0.480
24.	616/2	0.157
25.	614	0.271
26.	638	0.903
7.	639	0.042
28.	636/3	0.105
29.	640	0.150
30.	642	0.125
31.	643	0.073
32.	657/1/2	0.345
33.	657/1/1	0.230
34.	628	0.010
35.	636/2	0.031
36.	631	0.021
37.	580	0.021
	Total Area :	3 935

[No. O—14016/48/85/GP]

का. आ. 2972.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 654 तारीख 9-2-85 द्वारा

केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम सागड़िया तहसील शाजापुर जिला—शाजापुर राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हक्टर्स में)
1.	283/1 मी.	0.501
2.	283/1 मी.	1.092
3.	276	0.072
4.	79	0.051
5.	77	1.912
6.	80	0.052
7.	113	0.280
8.	272	0.386
9.	273	0.199
10.	278	0.261
11.	114	0.120
12.	118	0.324
13.	115	0.050
14.	123/286	0.030
15.	139	0.031
16.	111	0.242
17.	76	0.126
18.	274	0.040
19.	81	0.620
20.	61	0.126
21.	75	0.523
	योग :—कुल क्षेत्रफल	7.038

[सं. O-14016/49/85-जी.पी.]

S.O. 2972.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1527 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Sagadiya Tehsil : Shajapur Distt : Shajapur

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	283/1 M	0.501
2.	283/1 M	1.092
3.	276	0.072
4.	79	0.051
5.	77	1.912
6.	80	0.052
7.	113	0.280
8.	272	0.386
9.	273	0.199
10.	278	0.261
11.	114	0.120
12.	118	0.324
13.	115	0.050
14.	123/286	0.030
15.	139	0.031
16.	111	0.242
17.	76	0.126
18.	274	0.040
19.	81	0.620
20.	61	0.126
21.	75	0.523
	Total Area	7.038

[No. O-14016/49/85-GP]

का. आ. 2973:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 661 तारीख 16-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : धतरापदा तहसील : शाजापुर जिला : शाजापुर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	107	0.140
2.	109	0.184
3.	76	0.173
4.	110	0.051
5.	111	0.031
6.	100	0.094
7.	101	0.178
8.	85/1	0.100
9.	86/1	0.052
10.	86/2	0.042
11.	71/2	0.481
12.	69	0.063
13.	68	0.200
14.	57	0.043
15.	645	0.031
16.	646	0.021
17.	644	0.042
18.	643	0.042
19.	661	0.021
20.	56	0.042
21.	48/1	0.241
22.	616	0.130
23.	647/2	0.029
24.	46	0.105
25.	40	0.033
26.	39	0.030
27.	611/1	0.213
28.	37	0.012
29.	612/1	0.523
30.	664/1	0.200
31.	615	0.033
32.	642	0.293
33.	663	0.136
34.	662	0.075
35.	665	0.042
36.	90	0.057
37.	87	0.024
38.	88	0.031
39.	108	0.151
40.	38	0.025
41.	1	0.073
42.	617	0.021
43.	49	0.010
44.	48/2	0.052
45.	55	0.010
46.	112	0.010
47.	51	0.010
	योग :—कुल क्षेत्र फल	4.600

[सं. O-14016/56/85-जी. पी.]

S.O. 2973.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 66 dated 16-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Dhatrawada Tehsil : Shajapur Distt. : Shajapur

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	107	0.140
2.	109	0.184
3.	76	0.173
4.	110	0.051
5.	111	0.031

1	2	3
6.	100	0.094
7.	101	0.178
8.	85/1	0.100
9.	86/1	0.052
10.	86/2	0.042
11.	71/2	0.481
12.	69	0.063
13.	68	0.200
14.	57	0.043
15.	645	0 031
16.	646	0.021
17.	644	0.042
18.	643	0.042
19.	661	0 021
20.	56	0.042
21.	48/1	0.241
22.	616	0.130
23.	647/2	0.029
24.	46	0.105
25.	40	0.033
26.	39	0.030
27.	611/1	0.213
28.	37	0.012
29.	612/1	0.523
30.	664/1	0.200
31.	615	0.033
32.	642	0.293
33.	663	0.136
34.	662	0.075
35.	665	0.042
36.	90	0.057
37.	87	0.024
38.	88	0.031
39.	108	0.151
40.	38	0.025
41.	1	0.078
42.	617	0.021
43.	49	0.010
44.	48/2	0.052
45.	55	0.010
46.	112	0.010
47.	51	0.010
	Total Area	4.600

[No. O-14016/56/85—GP]

का.आ. 2974:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 569 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : डाकर गांव तहसील : शाजापुर जिला : शाजापुर राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	581/1	0.136
2.	580	0.052
3.	578/2	0.042
4.	579	0.230
5.	574/1/1	0.073
6.	565	0.324
7.	575/1	0.178
8.	568/1	0.387
9.	567/2	0.052
10.	534/1	0.021
11.	536	0.293
12.	535	0.314
13.	528	0.146
14.	527	0.314
15.	327	0.094
16.	328/1	0.021
17.	329/2	0.021
18.	333	0.003
19.	333/2	0.002
20.	525	0.063
21.	526	0.157
22.	512	0.199
23.	428	0.345
24.	431	0.157
25.	429	0.031
26	427	0.230
27.	426	0.063
28.	504	0.021
29.	440	0.021
30.	437(मी)	0.366
31.	445	0.334
32.	447/1	0.627
	योग कुल क्षेत्रफल	5.317

[सं. O-14016/16/85-जी. पी.]

S.O. 2974.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 569 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of pewer conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Dokar Gaon, Tehsil : Shajapur Distt : Shajapur

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	581/1	0.136
2.	580	0.052
3.	578/2	0.042
4.	579	0·230
5.	574/1/1	0.073
6.	565	0.324
7.	575/1	0.178
8.	568/1	0.387
9.	567/2	0.052
10.	534/1	0.021
11.	536	0.293
12.	535	0.314
13.	528	0.146
14.	527	0.314
15.	327	0.094
16.	328/1	0.021
17.	329/2	0.021
18.	333	0.003
19.	332/2	0.002
20.	525	0.063
21.	526	0.157
22.	512	0.199
23.	428	0.345
24.	431	0.157
25.	429	0.031
26.	427	0.230
27.	426	0.063
28.	504	0.021
29.	440	0.021
30.	437(M)	0.366
31.	445	0.334
32.	447/1	0.627
	Total Area	5.317

[No. O-14016/16/85-GP]

का. आ. 2975 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1313 तारीख 30-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और, आगे अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : मावन तहसील : गुना जिला : गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र. 1	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	36	0.188
2	24	0.200
3.	27	0.010
4.	20 (मी.)	0.262
5.	16	0.072
6.	21	0.306
7.	15	0.310
8.	14	0.105
9.	13/2	0.090
10.	106/2/1/ड	0.215
11.	106/2/6	0.062
12.	106/2/1क	0.220
13.	108	0.209
14.	111	0.010

1	2	3
15	107/2	0 261
16	109	0 460
17	110	0 175
18	25	0 042
19	20 (भी)	0 021
	योग कुल क्षेत्रफल	3 218

[स O-14016/178/85 जी पी]

S O 2975.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O 1313 dated 30-3 85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Mawan Tehsil : Guna Distt. : Guna

SCHEDULE

S No	Survey No.	Area to be acquired for R O U in hectare
1.	26	0 188
2	24	0 200
3	27	0 010
4	20(M)	0 262
5.	16	0.072
6	21	0 306
7.	15	0 310
8.	14	0 105
9	13/2	0.090
10	106/2/1/D	0 215
11	106/2/6	0 062
12	106/2/1K	0 220
13	108	0 209
14.	111	0 010
15.	107/2	0 261
16	109	0 460
17.	110	0 175
18.	25	0 042
19.	20(M)	0 021
	Total Area	3 218

[No. O-14016/178/85-GP]

का०आ० 2976.—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का०आ० स० 728 तारीख 23-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी जे गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम महुआन तहसील गुना जिला गुना राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

अनुक्रम	खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स म)
1	1/1	0 930
2	2	0 523
3.	3	0 303
4	17/8/1	0 304
5.	17/9	0 126
6	17/10	0 251
7.	17/12	0 271
8.	17/13	0 010
9	19	0.031
10	32/1	0 282
11.	17/6	0 366
12	35	0 031
13	536/1	0 010
14	37	0 020
15	132	0 031
16	133/1	0 314
17	36/7	0 209
	योग —कुल क्षेत्र फल	4 012

[स O-14016/70/85-जी पी]

S.O. 2976.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 728 dated 23-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquired the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Mahukhan Tehsil : Guna Distt :Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	1/1	0.930
2.	2	0.523
3.	3	0.303
4.	17/8/1	0.304
5.	17/9	0.126
6.	17/10	0.251
7.	17/12	0.271
8.	17/13	0.010
9.	19	0.031
10.	32/1	0.282
11.	17/6	0.366
12.	35	0.031
13.	36/1	0.010
14.	37	0.020
15.	132	0.031
16.	133/1	0.314
17.	36/7	0.209
	Total Area	4.012

[No-O-14016/70/85-GP]

का. आ. 2977.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 729 तारीख 23-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम किशनगढ़ तहसील गुना जिला—गुना राज्य (मध्यप्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र. 1 खसरा न. 1		उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	44/1	0.480
2.	44/10[1] ख	0.480
3.	44/10क	0.010
4.	44/11	0.951
5.	44/20	0.135
6.	12	0.052
	योग :—कुल क्षेत्र फल	2.108

[सं. O-14016/71/85-जी. पी.]

S.O. 2977.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 729 dated 23-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now,therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said, Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said, lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

IHBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Kiskangarh Tehsil : Guna Distt. : Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	44/1	0.480
2.	44/10 Kh	0.480
3.	44/10 K	0.010
4.	44/11	0.951
5.	44/20	0.135
6.	12	0.052
	Total Area	2.108

[No. O-14016/71/85-GP]

का. आ. 2978.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1312 तारीख 30-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम पिपरिया तहसील गुना जिला—गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं.	अपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	301	0.010
2.	302	0.010
3.	303	0.292
4.	304	0.072
5.	305	0.042
6.	309में से	0.130
7.	309 मे से	0 450
8.	309 मी.	0.200
9.	310	0.178
10.	311/1	0.062
11.	418/3/1	0.259
12.	422	0.769
13.	421	0.052
14.	427	0.575
15.	428	0.062
16	432	0.032
17	426	0.042
18.	433	0.120
19	434	0.057
योग :—कुल क्षेत्रफल		3.414

[सं. O-14016/177/85 जी. पी]

S.O. 2978.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1312 dated 30-3-85 under sub-section (1) of Sectios 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Pipariya Tehsil : Guna Distt. : Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hecture
1.	301	0.010
2.	302	0.010
3.	303	0.292
4.	304	0.072
5.	305	0.042
6.	309 M.S.	0.130
7.	309 M.S.	0.450
8.	309 M	0.200
9.	310	0.178

1	2	3
10.	311/1	0.062
11.	418/3/1	0.259
12.	422	0.769
13.	421	0.052
14.	427	0.575
15.	428	0 062
16.	432	0.032
17.	426	0.042
18.	433	0.120
19.	434	0.057
	Total Area	3.414

[No. O-14016/177/85-GP]

का. आ. 2979:—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का० आ. सं. 565 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम सोना हेडा तहसील सांचोड़ा जिला—गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	6	0.178
2.	50	0.209
3.	118	0.126
4.	117	0.221
5.	116	0.084
6.	122	0 251
7.	123/1	0.292
8.	128	0 251
9.	130	0.042
10.	127	0.209
11.	126	0.469
12.	131	0.073
13.	133	0.110
14.	132	0.082
15.	190	0.606
16.	191	0.419
17.	188/1	0.105
18.	170/1/9	0.335
19.	170/1/14	0.397
20.	170/1/11	0.449
21.	170/1/4	0.261
22.	170/1/12	0 335
23	170/2	0.188
24	171	0.126
25	172	0.137
26.	175	0.314
27.	176	0.261
28.	177	0.333
29.	178	0.261
30.	179	0.010
31.	180	0.105
32.	181	0.010
33.	170/1/2	0.052
34.	135/1	0.021
35.	189/1	0.021
	योग कुल क्षेत्रफल	7.343

[सं. O-14016/12/85-जी. पी.]

S.O. 2979.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 565 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Sona Hera Tehsil : Chochora, Distt : Guna (M.P.)

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectares
1.	6	0 178
2.	50	0.209
3.	118	0 126
4.	117	0 221
5.	116	0.084
6.	122	0.251
7.	123/1	0.292
8.	128	0.251
9.	130	0.042
10.	127	0.209
11.	126	0.469
12.	131	0.073
13.	133	0 110
14.	132	0 082
15.	190	0 606
16.	191	0.419
17.	188/1	0 105
18.	170/1/9	0 335
19.	170/1/14	0.397
20.	170/1/11	0 449
21.	170/1/4	0.261
22.	170/1/12	0.335
23.	170/2	0.188
24.	171	0.126
25.	172	0.137
26	175	0 314
27.	176	0.261
28.	177	0 333
29	178	0.261
30.	179	0 010
31.	180	0.105
32	181	0 010
33	170/1/2	0 052
34.	135/1	0.021
35	189/1	0 021
	Total Area	7 343

[No. O–14016/12/85-GP]

का. आ. 2980:—यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 730 तारीख 23-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और अगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम उकावद तहसील गुना जिला—गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स मे)
1	2	3
1	22	0 314
2	23	0 366
3	24	0.449
4	60/1	0 481
5.	60/2	0 261
6	48	0.428
7	43	0 240
8	42	0 139
9	112/1	0 523
10	112/2	0 366
11	107	0 439
12	104	0.230
13	106	0 105
14	105	0 302
15.	121	0 261
16.	125	0 293
17	133	0 125
18.	145	0 460
19	144	0 470
20	135	0 010
21	142	0.240
22.	141	0.491
23	162/3	0.408
24	194	0.157
25	193	0 554
26	182/1	0.334
27	181/1	0 157
28	181/2	0.314
29	181/3	0.240
30.	181/4	0.230
31.	180	0.658
32.	178	0.303
33.	177/3	0.637

1	2	3
34.	176	0.606
35.	198/1 मे से	1.358
36.	198/4 मी.	0.052
37	198 में से	0 366
38.	198 मी.	0 105
39.	40	0 115
40.	124	0.084
41.	140	0.042
42.	509	0.105
43.	63	0.052
44.	111	0.052
45.	61/1	0.063
46.	108	0.167
47.	103/1	0.063
48.	132	0.230
49.	143	0.209
50	164	0.157
51.	179	0.188
	योग — कुल क्षेत्रफल	15.309

[सं. O-14016/72/85-जी. पी]

S.O. 2980.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 730 dated 23-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Ukavad Tehsil : Guna Dittt. : Guna

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	22	0.314
2.	23	0.366
3.	24	0.449
4.	60/1	0.481
5.	60/	0 261
6.	48	0.428
7.	43	0 240
8.	42	0.439
9.	112/1	0 521
10.	112/2	0.366
11.	107	0.439
12.	104	0.230
13.	106	0.105
14.	105	0 302
15.	121	0.261
16.	125	0.293
17.	133	0.125
18.	145	0.460
19.	144	0.470
20.	135	0 010
21.	142	0.240
22.	141	0.491
23.	162/3	0 408
24.	194	0.157
25.	193	0.534
26.	182/1	0.334
27.	181/1	0.157
28.	181/2	0.314
29.	181/3	0 240
30.	181/4	0 230
31.	180	0 658
32.	178	0.303
33.	177/3	0.637
34.	176	0 606
35.	198/1 M.S.	1 358
36.	198/4 M	0.052
37.	198 M.S.	0.366
38.	198 M	0.105
39.	40	0.115
40.	124	0 084
41.	140	0.042
42.	509	0.105
43.	63	0.052
44.	111	0.052
45.	61/1	0.063
46.	108	0 167
47.	103/1	0.063
48.	132	0.230
49.	143	0.209
50.	164	0.157
51.	169	0.188
	Total Area	15.309

[No. O-14016/72/85-GP]

का. आ. 2981:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 737 तारीख 23-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा, (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि., में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

एच बी. जे. गैस पाईपलाईन प्रोजेक्ट

ग्राम बरखेड़ा ढेकनी तहसील गुना जिला—गुना राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (अहैक्टर्स में)
1	2	3
1	111	0.314
2.	112	0.304
3	110	0 177
4.	117	0.209
5	116	0.021
6	115	0.105
7.	118	0.105
8.	114	0.314
9.	147	0.063
10.	152/1/5	0.251
11.	152/1क ख	0 784
12.	149	1 105
13.	150	0.418
14.	158/1 मी.	0.283
15.	153/2	0.388
16.	157/1ख	0.585
17.	155/1क	0.042
18.	155/1ख	0.230
19.	177	0.042
20.	62	0.075
21.	158/1 मी	0 335
22.	164/1 मी.	0.011
23.	157/1क	0.042
24.	153/1क	0.011
योग :—कुल क्षेत्रफल		5.214

[सं O-14016/79/85-जी. पी.]

S.O. 2981.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 737 dated 23-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Barkhedi Dhekani Tehsil : Guna Distt. Guna

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hecture
1.	111	0.314
2.	112	0.304
3.	110	0.177
4.	117	0.209
5.	116	0.021
6.	115	0.105
7.	118	0.105
8.	114	0.314
9.	147	0.063
10.	152/1/5	0.251
11.	152/1 K	0.784
12.	149	0.105
13.	150	0.418
14.	158/1 M.	0.283
15.	153/2	0.388
16.	157/1 KH	0.585
17.	155/1 K	0.042
18.	155/1 KH	0.230
19.	177	0.042
20.	62	0.075
21.	158/1 M.	0.335
22.	164/1 M.	0.011
23.	157/1 K	0.042
24.	153/1 K	0.011
Total Area		5.214

[No. O-14016/79-85-GP]

का. आ 2982 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. 738 का. आ. तारीख 23-2-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में

विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम—पड़रिया तहसील—गुना जिला—गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	57	0 784
2	58/2	0 364
3.	60/7	0.021
4.	62	0 063
5.	64	0 105
6.	66	0.293
7.	67	0 178
8	68	0 355
9	68/2 मे से	0 240
10.	68/3	0.010
11	60/6	0.293
12	59	0 021
13.	60/5	0 010
14	56	0.010
15	65	0 010
16.	207	0.021
	योग —कुल क्षेत्रफल	2.778

[सं. O-14016/80/85-जी. पी]

S.O. 2982.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 738 dated 23-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Padriya Tehsil Guna Distt. Guna

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	57	0.784
2.	58/2	0 364
3.	60/7	0 021
4.	62	0.063
5.	64	0.105
6.	66	0.293
7.	67	0.178
8.	68	0.355
9.	68/2 M.S.	0 240
10.	68/3	0 010
11.	60/6	0 293
12.	59	0 021
13.	60/5	0 010
14.	56	0.010
15.	65	0 010
16.	207	0.021
	TOTAL AREA	2.778

[No O-14016 80/85-GP]

का० आ० 2983.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० 579 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच बी जे गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम सुतरा तहसील आगर जिला—शाजापुर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	57	0.094
2.	58	0.355
3.	148/1	0 282
4.	59	0 209
5.	60/1	0 209
6	63	0 251
7.	109	0.042
8.	64	0 251
9.	189	0.146
10.	198	0 355
11	209/1 210	0 021
12.	67	0.146
13	182	0 010
14	183/1	0 209
15	310/1/2/3	0 167
16	75	0 021
17	186	0 116
18.	187	0 010
19	194	0 042
20	208	0.397
21.	76	0 178
22	78	0.188
23	79	0 136
24.	92	0.136
25.	93	0 271
26.	106/2	0 146
27.	108	0 575
28.	160	0 010
29	162	0 042
30.	163	0.031
31.	164	0.125
32.	184	0 188
33	107	0.115
34	185	0.042
35.	196	0.010
36	199	0.021
37.	94	0 021
38	155	0 021
39.	161	0.136
	योग :—कुल क्षेत्रफल	5 755

[स. O-14016/26/85-जी. पी.]

S.O. 2983.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 379 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

"BJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Sutara Tehsil Agar Distt. Shajapur

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1	2	3
1.	57	0.094
2.	58	0.355
3.	148/1	0.282
4.	59	0.209
5.	60/1	0.209
6	63	0.251
7.	109	0 042
8.	64	0 251
9.	189	0 146
10.	198	0.355
11.	209,1	0 021
	210	—
12.	67	0 146
13.	182,	0.010
14.	183/1	0.209
15	310 1/2/3	0.167
16	75	0.021
17.	186	0.146

1	2	3
18.	187	0.010
19.	194	0.047
20.	208	0.307
21.	76	0.178
22.	78	0.188
23.	79	0.136
24.	92	0.136
25.	93	0.271
26.	106/2	0.146
27.	108	0.575
28.	160	0.010
29.	162	0.047
30.	163	0.031
31.	164	0.125
32.	184	0.188
33.	107	0.115
34.	185	0.047
35.	196	0.010
36.	199	0.021
37.	94	0.021
38.	155	0.021
39.	161	0.136
TOTAL AREA		5.755

[No. O-14016/76/85-GP]

का. आ. 2984.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 580 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम चाचाखेड़ तहसील आगर जिला-शाजापुर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र०	खसरा सं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1.	294/1	0.240
2	292/1	0.282
3	292/2	0.010
4	290	0.219
5	300	0.010
6	319	0.010
7	320	0.125
8	321	0.125
9	318/2	0.230
10.	318/3	0.188
11	316	0.084
	317	--
12	313/2	0.063
13	340/6	0.189
14	341/1	0.198
15	502	0.010
16	504/1(ग)	0.617
17	491	0.010
18.	493	0.021
19	490/3	0.157
20	504/3	0.178
21	527	0.031
	528	--
22	505/2	0.230
23.	507	0.167
24.	485/1	0.125
25	509/1	0.240
26	494/2/3	0.063
27	438/2(क)	0.157
28	435/2	0.293
29	436	0.042
30	435/1	0.052
31	447	0.010
32.	446/2	0.010
33.	439/2(ग)	0.063
34	445	0.042
35.	446/1	0.209
36.	444/1	0.021
37.	444/2	0.199
38.	460/2	0.010
39.	461	0.157
40	462	0.142
41.	465	0.105
42	463	0.352
43.	464	0.010
44.	293	0.010
45.	291	0.010
46.	318/1(ग)	0.010
47.	322	0.003
48.	339	0.010
योग कुल क्षेत्रफल		5.740

[सं० O-14016/27/85-जीपी]

S.O. 2984.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 580 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 5 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Chacha Khedi	Tehsil Agar	Distt. Shajapur
S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hecatre
1	2	3
1.	294/1	0.240
2.	292/1	0.232
3.	292/2	0.010
4.	290	0.219
5.	300	0.010
6.	319	0.010
7.	320	0.125
8.	321	0.125
9.	318/2	0.230
10.	318/3	0.188
11.	316/	0.084
	317	—
12.	313/2	0.063
13.	340/6	0.188
14.	341/1	0.198
15.	502	0.010
16.	504/1 G	0.617
17.	491	0.010
18.	493	0.021
19.	490/5	0.157
20'	504/3	0.178
21.	527	0.031
	528	—
22.	505/2	0.230
23.	507	0.167
24.	485/1	0.125
25.	509/1	0.240
26.	484/2/3	0.063
27.	438/2 K	0.157
28.	435/2	0.293
29.	436	0.042
30.	435/1	0.052
31.	447	0.010
32.	446/2	0.010
33.	438/2 G	0.063
34.	445	0.042
35.	446/1	0.209
36.	444/1	0.021
37.	444/2	0.199
38.	460/2	0.010
39.	461	0.157
40.	462	0.142
41.	465	0.105
42.	463	0.352
43.	464	0.010
44.	293	0.010
45.	291	0.010
46.	318/1 G	0.010
47.	322	0.005
48.	339	0.010
	TOTAL AREA	5.740

[No. O-14016/27/85—GP]

का०आ० 2985.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ. 597,/तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम कड़ूला	तहसील आगर	जिला-शाजापुर	राज्य (मध्य प्रदेश)
अनु.क्र०	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)	
1	2	3	
1.	1629	0.366	
2.	1628	0.042	

1		3
3.	1627	0 282
4.	1626	0 010
5.	1632/1	0 199
6	1631/1	—
7.	1632/2	0 178
8	1631/2	—
9	1632/3	0 115
10	1631/3	—
11	1635/3	0 178
12	1635/1	0.219
13.	1636	1.714
14	1637	0 267
	योग :—कुल क्षेत्रफल	3.570

[स O-14016/10/85-जीपी]

S.O. 2985.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 597 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Kadula Tehsil Shajapur Distt. Shajapur

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1.	1629	0 366
2.	1628	0.042
3.	1627	0 282
4.	1626	0.010
5.	1632/1	0.199
6.	1631/1	—
7.	1632/2	0.178
8.	1631/2	—
9.	1632/3	0.115
10.	1631/3	—
11.	1635/3	0.178
12.	1635/1	0.219
13.	1636	1.714
14.	1637	0.267
	TOTAL AREA	3 570

[No. O-14016/40/85/GP[

का. आ. 2986.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 662 तारीख 16-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम बडोदी तहसील शाजापुर जिला शाजापुर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु०क्र०	सर्वे नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	397	0 052
2	566/1	0.063
3	564	0 157
4	551/1	0.010
5	554	0.042
6.	555	0.020
7	627	0 199
8	637	0.084
9	522	0.031
10	517/1/2	0.010
11	517/4/2	0.031
12.	560	0.219
13.	561/1	—
14	568/2	
15.	557	0.293
16.	559/1	—
17	559/2	—

1	2	3
18.	570	0.105
19.	567/2	0 042
20.	646	0 065
21	551/2	0 167
22	552	--
23.	553/1	--
24	524/1	0 240
25.	524/2	—
26	524/3	—
27.	602/1	0.125
28.	602/2	0.251
29.	518/1	0 157
30.	517/2/1	0 052
31.	517/3/1	0 042
32	517/4/1	0.021
33.	517/5/1	0 030
34	517/6/1	0.136
35.	523	0.010
36	513	0.063
37	518/3	0.125
38.	512/2	0 157
39.	519/1	0 010
40.	519/4	—
41.	511/1	0 031
42	511/2	0 146
43	512/1	0 020
44	628	0.178
45.	632	0.020
46.	631	0 125
47.	553/2	0.021
48.	534/2	0.084
49.	256/1	157
50.	518/2	0.010
51.	644/2	0.042
52.	601	0 010
53	634/1	0.199
51	634/4	—
55.	634/3	0.178
56	635/2	—
57.	643	0 272
58	644/1	—
59.	633	0 082
60.	645	0.063
	योग :—कुल क्षेत्रफल	4 617

[स. O-14016/57/85-जीपी]

S.O. 2986.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 662 dated 16-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Badodi Tehsil Shajapur Distt. Shajapur

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in hectare
1.	397	0.052
2.	566/1	0.063
3.	564	0.157
4.	551/1	0.010
5.	554	0.042
6.	555	0,020
7.	627	0.199
8.	637	0.084
9.	522	0.031
10.	517/1/2	0.010
11.	517/4/2	0.031
12.	560	0.219
13.	561/1	—
14.	568/2	—
15.	557	0.293
16.	559/1	—
27.	559/2	—
18.	570	0.105
19.	567/2	0.042
20.	646	0.065
21.	551/2	0.167
22.	552	—
23.	553/1	—
24.	524/1	0.240
25.	524/2	—
26.	524/3	—
27.	602/1	0.125
28.	602/2	0.251
29.	518/1	0.157
30.	517/2/1	0.052
31.	517/3/1	0.042
32.	517/4/1	0.021
33.	517/5/1	0.030
34.	517/6/1	0.136
35.	523	0.010
36.	513	0.063
37.	518/3	0.125
38.	512/2	0.157
39.	519/1	0.010
40.	519/4	- -
41.	511/1	0.031
42.	511/2	0.146
43.	512/1	0.020
44.	628	0.178
45.	632	0.020
46.	631	0.125
47.	553/2	0 021
48.	634/2	0.084
49.	256/1	0.157

1	2	3
50.	518/2	0.010
51.	644/2	0.042
52.	601	0.010
53.	634/1	0.199
54.	634/4	—
55.	634/3	0.178
56.	635/2	—
57.	643	0.272
58.	644/1	—
59.	653	0.082
60.	645	0.063
	TOTAL AREA	4.647

[No. O—14016/57/85-GP]

का. आ. 2987.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 596 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम गोविन्दा तहसील शाजा पुर जिला-शाजापुर राज्य (मध्य-प्रदेश)

क्रमांक.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स मे)
1	2	3
1.	76/2	0.774
2.	76/4	0.250
3.	86	0.105
4.	97	0.052
5.	115	0.094
6.	381	0.073
7.	428	0.030
8.	380	0.021
9.	120	0.209
10.	122/1	0.418
11.	121	0.020
12.	99	0.230
13.	122/2	0.272
	125/1	—
14.	96	0.052
15.	88	0.125
16.	91	0 063
17.	90	0.021
18.	89	0.188
19.	85	0.157
20.	297/2	0.094
21.	78	0.042
22.	79	0 366
23.	80	0.025
24.	81	0.005
25.	45/2	0.073
26.	290	0.031
27.	299	0.324
28.	300/1	0.084
29.	302	0.427
30.	307	0 178
31.	305/1/1	0.105
	305/2/1	—
32.	427	0.209
33.	429	0.251
34.	306	0.021
35	384/1	0.061
36.	413	0.188
37.	414	0.115
38.	415	0.209
39.	387	0.031
40.	416	0.094
41.	377	0.084
42.	158	0.021
43.	379	0.219
44	98	0.031
45.	77	0.010
46.	378	0.324
47.	385/1	0.293
	385/2	—
48.	364/2	0.020
	योग :—कुलक्षेत्रफल	7.089

[सं. O-14016/39/85-जीपी]

S.O. 2987.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 596 dated 9-2-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the

lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government, vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Govinda Tehsil : Shajapur Distt. : Shajapur

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in hectare
1	2	3
1.	76/2	0.774
2.	76/4	0.250
3.	86	0.105
4.	97	0.052
5.	115	0.094
6.	381	0.073
7.	428	0.030
8.	380	0.021
9.	120	0.209
10.	122/1	0.418
11.	121	0.020
12.	99	0.230
13.	122/2	0.272
	125/1	—
14.	96	0.052
15.	88	0.125
16.	91	0.063
17.	90	0.021
18.	89	0.188
19.	85	0.157
20.	297/2	0.094
21.	78	0.042
22.	79	0.366
23.	80	0.025
24.	81	0.005
25.	45/2	0.073
26.	298	0.031
27.	299	0.324
28.	300/1	0.084
29.	302	0.427
30.	307	0.178
31.	305/1/1	0.105
	305/2/1	—
32.	427	0.209
33.	429	0.251
34.	306	0.021
35.	384/1	0.061
36.	413	0.188
37.	414	0.115
38.	415	0.209
39.	387	0.031
40.	416	0.094
41.	377	0.084
42.	158	0.021
43.	379	0.219
44.	98	0.031
45.	77	0.010
46.	378	0.324
47.	385/1	0.293
	385/2	
48.	364/2	0.020
	TOTAL AREA	7.089

[No. O-14018/39/85-GP]

का. आ. 2988.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1902 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	डेसीमल	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5
फतेहपुरा	341	0	07	35
	340	0	56	40
	346	0	32	70
	347	0	26	40

1	2	3	4	5
	348	0	04	80
	349	0	33	23
	382	0	12	48
	350	0	02	00
	381	0	19	94
	380	0	48	30
	379	0	06	60
	378	0	13	50
	377	0	21	00
	376	0	52	80
	375	0	17	10
	383	0	11	70
	412	0	00	40
	415	0	24	50
	416	0	40	50
	417	0	33	90
	418	0	45	15
	419	0	08	70
	420	0	11	74
	421	0	05	20
	422	0	01	67
	423	0	01	13
	424	0	05	46
	425	0	11	70
	111	0	90	30

[संख्या O-14016/305/85-जीपी]

S.O. 2988.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1902 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Fatehpur	341	0	07	35
	340	0	56	40
	346	0	32	70
	347	0	26	40
	348	0	04	80
	349	0	33	23
	382	0	12	48
	350	0	02	00
	381	0	19	94
	380	0	48	30
	379	0	06	60
	378	0	13	50
	377	0	21	00
	376	0	52	80
	375	0	17	10
	383	0	11	70
	412	0	00	40
	415	0	24	50
	416	0	40	50
	417	0	33	90
	418	0	45	15
	419	0	08	70
	420	0	11	74
	421	0	05	20
	422	0	01	67
	423	0	01	13
	424	0	05	46
	425	0	11	70
	111	0	90	30

[No. O-14016/305/85-GP]

का०आ० 2989.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1892 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकारण लि० में सभी भाराओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाइन बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गाँव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
राजपुरा	349	0	50	33
	350	0	62	62
	357	0	27	75
	358	0	33	
	351	0	03	50

[सं. O-14016/295/85-जीपी]

S.O. 2989.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1892 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj).
State : Rajasthan District : Kota Tehsil: Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Rajpura	349	0	50	33
	350	0	62	62
	357	0	27	75
	358	0	33	00
	351	0	03	50

[No. O-14016/295/85-GP]

का०आ० 2990.— यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1894 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर(म प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य: राजस्थान जिला: कोटा तहसील: मांगरोल

गाँव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5
घूमरखेड़ी	112	0	70	72
	120	0	16	20
	119	0	12	3 0
	121	0	12	00
	118	0	45	00
	117	0	55	50
	125	0	14	70
	136	0	20	70
	183	0	17	5 4
	181	0	00	16
	182	0	02	10
	185	0	04	80
	204	0	30	00
	296	0	39	25
	205	0	01	90
	199	0	06	25
	215	0	04	65
	216	0	18	90
	220	0	08	80
	167	0	30	65
	166	0	24	97
	165	0	00	18
	163	0	05	22
	162	0	04	50
	270	0	17	17
	273	0	18	22
	271	0	00	16

1	2	3	4	5
	272	0	04	65
	263	0	06	38
	147	0	03	60

[S O 14016/297/85-जीपी]

S O. 2990 —Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O 1894, dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline

And whreas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further in exercise of the power conferred by sub section considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Ghumar Khedi	112	0	70	72
	120	0	16	20
	119	0	12	30
	121	0	17	00
	118	0	45	00
	117	0	55	50
	125	0	14	70
	126	0	20	70
	183	0	17	54
	181	0	00	16
	185	0	04	80
	182	0	02	10
	204	0	30	00
	206	0	39	25
	205	0	01	90
	199	0	06	25
	215	0	04	65
	216	0	18	90
	270	0	08	80
	167	0	30	65
	166	0	24	97
	165	0	00	18
	163	0	05	22
	162	0	04	50
	270	0	17	17
	273	0	18	22
	271	0	00	16
	272	0	04	65
	263	0	06	38
	147	0	03	60

[No O-14016/297/85-GP]

का. आ. 2991 —यत पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ स 1899, त रीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला : कोटा तहसील : छबड़ा

गाँव	खसरा न	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
बिन्दाराडी				
	23	0	27	09
	24	0	29	40
	25	0	12	27
	26	0	22	28
	30	0	10	99
	32	0	58	02
	33	0	20	98
	35	0	14	85
	34	0	38	81
	211	0	03	27
	226	0	06	39
	227	0	18	27
	229	0	26	73
	230	0	10	99
	235	0	18	72
	234	0	31	48
	232	0	12	14
	239	1	62	76
	233	0	24	98
	27	0	00	12
	28	0	02	68

[स. O-14016/302/85-जीपी]

S.O. 2991.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1899 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Chabra

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Bindaradi	23	0	27	09
	24	0	29	40
	25	0	12	27
	26	0	22	28
	30	0	10	99
	32	0	58	07
	33	0	20	98
	35	0	14	85
	34	0	28	81
	211	0	03	27
	226	0	06	39
	227	0	18	27
	229	0	26	73
	230	0	10	99
	235	0	18	72
	34	0	31	48
	32	0	12	14
	39	1	62	7
	233	0	24	98
	27	0	00	12
	28	0	02	68

[No. O-14016/302 5-GP]

का. आ. 2992.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ.सं. 1900 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

बिजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य: राजस्थान जिला : बून्दी तहसील: इन्द्रगढ़

गाँव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
खेड़ली कलाँ	72	0	29	16
	77	0	00	54
	88	0	34	43
	76/108	0	03	62
	119/84	0	72	90

[सं. O-14016/303/85-जीपी]

S.O. 2992.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1900 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Bundi Tehsil : Indergarh

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Khedli Kalan	72	0	29	16
	77	0	00	54
	78	0	24	43
	76/108	0	03	62
	119/84	0	72	90

[No. O-14016/303/85-GP]

का. आ. 2993:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1901 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5
सीनोता	1	0	54	30
	1/393	0	03	10
	1/392	0	11	55
	2	0	05	40
	115	0	15	60
	116	0	29	45
	114	0	15	30
	113	0	32	16
	127	0	65	55
	129	0	00	80
	138	0	13	69
	130	0	01	04
	131	0	06	30
	143	0	18	86
	142	0	25	30
	156	1	32	90
	[illegible]	0	11	10
	[illegible]	0	01	24
	254	1	04	07
	254/367	0	21	44
	255	0	20	40
	253	0	05	55
	248/368	0	06	90
	248	0	01	80
	247	0	60	30
	244	0	26	70
	246	0	10	80
	245	0	64	35
	240	0	12	90
	239	0	40	80
	251	0	01	50
	287/376	0	13	20
	386	0	58	50
	290	0	59	40
	293	0	12	00
	291	0	27	00
	292	1	04	80
	301	0	37	50
	300	0	48	00
	237	0	49	20
	298	0	00	50
	288	0	04	50
	238	0	02	40

[सं. O-14016/304/85-जीपा]

S.O. 2993.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1901 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline:

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Autnority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M P) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiar
Sinota	1	0	54	30
	1/393	0	03	10
	1/392	0	11	55
	2	0	05	40
	115	0	15	60
	116	0	29	45
	114	0	15	30
	113	0	32	16
	129	0	65	55
	129	0	00	80
	128	0	13	69
	130	0	01	04
	131	0	06	30
	143	0	18	76
	142	0	25	50
	156	1	32	90
	155	0	11	10
	254/365	0	01	24
	254	1	04	07
	254/367	0	24	44
	255	0	20	40
	253	0	05	55
	248/368	0	06	90
	248	0	01	80
	247	0	60	30
	244	0	26	70
	246	0	10	80
	245	0	64	35
	240	0	12	90
	239	0	40	80
	251	0	01	50
	287/376	0	13	20
	286	0	58	50
	290	0	59	40
	293	0	12	00
	291	0	27	00
	292	1	04	80
	301	0	37	50
	300	0	48	00
	237	0	49	20
	298	0	00	50
	288	0	04	50
	238	0	02	40

[No. O-14016/304/85-GP]

का. आ. 2994—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1891 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : पीपल्दा

गाँव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
नीमसरा	264	0	02	40
	262	0	23	70
	263	0	76	80
	267	0	00	42
	268	0	41	58
	269	0	34	20
	270	0	05	70
	332	0	93	90
	363	0	40	20
	362	0	03	30
	361	0	56	40
	360	0	12	60
	367	0	66	00
	356	0	03	00
	409	0	25	80
	408	0	00	56
	407	0	31	84
	416	0	44	55
	417	0	06	30

[सं. O-14016/294/85-जीपी]

S.O. 2994.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1891 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Rai.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Mimsara	264	0	02	40
	262	0	23	70
	263	0	76	80
	267	0	00	42
	268	0	44	58
	269	0	34	20
	270	0	05	70
	332	0	93	90
	363	0	40	20
	362	0	03	30
	361	0	56	40
	360	0	12	60
	367	0	66	00
	356	0	03	00
	409	0	25	80
	408	0	00	56
	407	0	31	84
	416	0	44	55
	417	0	06	30

[No. O—14016/294/85-G.P.]

का.आ. 2995:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1893 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार कर अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.)) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील पीतलदा

गाँव	खसरा सं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
चान्दा	119	0	04	80
	120	0	18	60
	121	0	42	60
	122	1	00	35
	122/173	0	23	10
	129	0	04	80
	136	0	42	00
	134	0	48	90
	132	0	01	56
	133	0	19	92
	151	0	00	10

[म. O-14016/296/85-जीपी]

S.O. 2995.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1893 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chanda	119	0	04	80
	120	0	18	60
	121	0	42	60
	122	1	00	35
	122/173	0	23	10
	129	0	04	80
	136	0	42	00
	134	0	48	90
	132	0	01	56
	133	0	19	92
	151	0	00	10

[No. O—14016/296/85-GP]

का०आ० 2996.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1898 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयाजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील पीपल्दा

गाव	खसरा न	हेक्टर	आर सेन्टीआर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ककरावता	259	0	92	25
	260	0	39	45
	288	0	29	70
	287	0	31	20
	285	0	81	15
	290	0	03	15
	298	0	03	60
	302	0	95	40
	303	0	28	09
	303/357	0	02	66
	305	0	12	90
	304	0	61	80

[म -O-14016/301/85-जीपी]

S.O 2996.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O 1898 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Kakravada	259	0	92	25
	260	0	39	45
	288	0	29	70
	287	0	31	20
	285	0	81	15
	290	0	03	15
	298	0	03	60
	302	0	95	40
	303	0	28	09
	303/357	0	02	66
	305	0	12	90
	304	0	61	80

[No O—14016/301/85-GP]

का०आ० 2997.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 566 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट

भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम बरखेड़ी माफी तहसील चाचोड़ा जिला-गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	99/1	0.679
2	95/509	0.188
3.	95	0.449
4.	96	0.366
5	93	0.021
6	21/2	0.146
7.	21/5	0.261
8.	21/3	0.261
9	21/8	1.390
10	20/1/3	0 700
11.	20/1/1	0 209
12.	17/2	0 157
13.	17/1	0 209
14	16	0.272
15	11	0.335
16.	9	0.679
17.	8/2	0 418
18.	100	0 052
19.	250/1	0 031
20.	20/1/2	0.021
21.	184	0 010
22.	12	0.083
योग : कुल क्षेत्रफल		6 937

[सं. O-14016/13/85-जी.पी.]

S.O. 2997.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 566, dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on thsi date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Barkhedi Mafi Tehsil : Ckachoda Distt. : Guna

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U in Hectares
1.	99/1	0.679
2.	95/509	0.188
3.	95	0.449
4.	96	0.366
5.	93	0.021
6.	21/2	0.146
7.	21/5	0.261
8.	21/3	0.261
9.	21/8	1.390
10.	20/1/3	0.700
11.	20/1/1	0.209
12.	17/2	0.157
13.	17/1	0.209
14.	16	0.272
15.	11	0.335
16.	9	0.679
17.	8/2	0.418
18.	100	0.052
19.	250/1	0.031
20	20/1/2	0.021
21.	184	0.010
22.	12	0.083
	Total Area :	6.937

[No. O-14016/13/85-GP]

का.आ. 2998.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 724, तारीख 13-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला पंचमहल तालुका दाहोद

गांव	सर्वे नं	हक्टेयर	आर	सेन्टीयर
बोरखेड़ा	124	0	56	00
	125	0	41	00
	126/2	0	32	00
	127/1	0	20	00
	128	0	26	00
	129/2	0	61	00
	133/2	0	18	00
	134/1	0	17	00
	134/2	0	19	00
	135/1	0	16	00
	135/2	0	04	00
	135/4	0	05	00

[सं O-14016/65/85-जीपी]

S.O. 2998.—Whereas by notification of the Government of Indian in the Ministry of Petroleum S.O. 724 dated 13-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe line from Hasira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Heatare	Area	Centiare
Borkheda	124	0	56	00
	125	0	41	00
	126/2	0	32	00
	127/1	0	20	00
	128	0	26	00
	129/2	0	61	00
	133/2	0	18	00
	134/1	0	17	00
	134/2	0	19	00
	135/1	0	16	00
	135/2	0	04	00
	135/4	0	05	00

[No. O-14016/65/85-GP]

का.आ. 2999.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 725 तारीख 13-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को हन होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप बिछाने के लिए ।

राज्य गुजरात जिला : पंच महल तालुका : देवगढ़ बरीया

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टी-आर
सिमलीया	699/पी	12	98	10
	209/1/1	0	02	02
	212	0	09	60
	213/पी	0	42	49
	214	0	15	17
	215	0	13	15
	219	0	17	19
	220	0	33	00
	307/25	0	07	08
	817	0	19	22
	291	0	00	32
	307/18	0	32	37
	222/1/1	0	08	09
	222/1/3	0	05	06
	307/19	0	24	28
	307/50	0	04	05
	330	0	20	80
	329/1	0	16	18
	329/2	0	02	40
	328	0	62	73
	338	0	22	80
	336/1	0	00	07
	313/1	0	20	40
	343/2	0	06	90
	केटार	0	17	60
	349/1	0	15	40
	349/2	0	05	44
	349/3	0	20	00
	349/4	0	12	00
	319/5	0	12	20
	349/6	0	13	60
	351	0	04	05
	352	0	09	76
	307/66/2	0	05	27
	353	0	30	00
	354	0	26	40
	44	0	14	16
	43/3	0	00	60
	41/4	0	11	13
	43/5	0	13	15
	कार्ट ट्रैक	0	02	02
	34/1	0	09	11
	34/2	0	09	11
	34/3	0	10	20
	33	0	24	28
	434/1	0	23	27
	434/2	0	00	40
	435	0	17	20
	444	0	09	76
	441	0	06	07
	443	0	27	50
	449/1	0	23	80
	612	—	43	50
	613/3	0	18	00
	613/4	0	19	00
	613/5	0	13	60
	614/1P	0	31	40
	615	0	37	20
	617	0	17	00
	618	0	10	00
	620/1	0	01	50
	620/2	0	10	00
	620/3	0	05	40
	620/4	0	06	00
	620/5	0	06	60
	620/6	0	06	30
	620/7	0	10	50
	600/1	0	08	10
	600/2	0	04	20
	600/3	0	03	00
	600/4	0	08	00
	599	0	22	80
	597/1/1	0	37	80

[सं. O-14016/66/85-ज पी]

S.O. 2999.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 725 dated 13-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.'

SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Devgadhbariy

Village	Survey No .	Heatare	Area Centiare	
Simaliya	699/P	12	98	10
	209/1/1	0	02	02
	212	0	09	60
	213/P	0	42	49
	214	0	15	17
	215	0	13	15
	219	0	17	19
	220	0	33	00
	307/25	0	07	08

1	2	3		4
	817	0	19	2
	221	0	00	32
	307/18	0	32	37
	222/1/1	0	08	09
	222/1/2	0	05	06
	307/19	0	24	28
	307/50	0	04	05
	330	0	20	80
	329/1	0	16	18
	329/2	0	02	40
	328	0	62	73
	338	0	22	80
	336/1	0	00	07
	343/1	0	20	40
	343/2	0	06	90
	Kotar	0	17	60
	349/1	0	15	40
	349/2	0	05	44
	349/3	0	20	00
	349/4	0	12	00
	349/5	0	12	20
	349/6	0	13	60
	351	0	04	05
	352	0	09	76
	307/66/2	0	05	27
	353	0	30	00
	354	0	26	40
	44	0	14	16
	43/3	0	00	60
	43/4	0	11	13
	43/5	0	13	15
	Cart track	0	02	02
	34/1	0	09	11
	34/2	0	09	11
	34/3	0	10	20
	33	0	24	28
	434/1	0	23	27
	434/2	0	00	40
	435	0	17	20
	444	0	09	76
	441	0	06	07
	443	0	27	50
	449/1	0	22	80
	617	0	43	5
	613/3	0	18	0
	613/4	0	19	00
	613/5	0	13	60
	614/1/P	0	31	40
	615	0	37	20
	617	0	17	00
	618	0	10	00
	620/1	0	01	50
	620/2	0	10	00
	620/3	0	05	40
	620/4	0	06	00
	620/5	0	06	60
	620/6	0	06	30
	620/7	0	10	50
	600/1	0	08	10
	600/2	0	04	20
	600/3	0	03	00
	600/4	0	08	00
	599	0	22	80
	597/1/1	0	37	80

[No O - 14016/66/85 GP]

का आ 3000—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का आ स 813 तारीख 2-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच०बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम रिछेरा तहसील गुना जिला गुना (मध्य प्रदेश)

अनु क्र	खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स मे)
1	2	3
1	3/2	0 261
2	4	0 052
3	7/1	0 282
4	7/2	0 449
5	6/2	0 052
6	6/3	0 105
7	14/1	0 105
8	16	0 327
9	14/9	0 105
10	14/8	0 502
11.	18	0 105
12	23/1	1 202

1	2	3	4	5
13	1	0.052		
14	26	0.092		
15	23/2	0.010		
कुल योग: क्षेत्रफल		3.691		

[सं. O-14016/89/85-ज.प]

S.O. 3000.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 873 dated 2-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Richhera Tehsil : Guna Distt. Guna

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	3/2	0.261
2.	4	0.052
3.	7/1	0.282
4.	7/2	0.449
5.	6/2	0.042
6.	6/3	0.105
7.	14/1	0.105
8.	16	0.327
9.	14/9	0.105
10.	14/8	0.502
11.	18	0.105
12.	23/1	1.202
13.	1	0.052
14.	26	0.092
15.	23/2	0.010
	Competent Authority	3.691

[No. O-14016/89/85-GP]

का०आ० 3001.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं० 577 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच० बी० जे० गैस पाईप प्रोजक्ट

ग्राम. महामरकला तहसील : चाचौड़ा जिला.गुना राज्य : मध्यप्रदेश

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	168	0.031
2.	182/1	0.105
3.	206	0.42
4.	207	0.261
5.	210	0.157
6.	211	0.021
7.	212	0.125
8.	214/1	0.105
9.	220	0.030
10.	216	0.257
11.	217	0.030
12.	214/2	0.105
13.	218	0.157
14.	219	0.021
15.	1	0.105
16.	219/282	0.052
17.	222	0.295
18.	223	0.115
19.	224	0.105
20.	227	0.081
21.	228/3	0.314
22.	235	0.042
23.	236	0.063

1	2	3	4	5	6
24	237	0 178			
25	238	0 523			
26	240	0 105			
27	221	0 021			
	योग कुल क्षेत्रफल	3,449			

[सं. O-14016/24/85-जी पी०]

S.O. 3001.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 577 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas he Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-sectioon (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Muhasakalan, Tehsil : Chachora, Distt Guna (M.P.)

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectare
1.	168	0 031
2.	182/1	0.105
3	206	0.042
4.	207	0 261
5.	210	0.157
6.	211	0.021
7.	212	0.125
8.	214/1	0.105
9.	220	0.030
10.	216	0.257
11.	217	0 030
12.	214/2	0 105
13.	218	0.157
14.	219	0.021
15.	1	0 105
16.	219/282	0.052
17.	222	0.295
18.	223	0.115
19.	224	0.105
20.	227	0 084
21.	228/3	0.314
22.	235	0 042
23.	236	0.063
24.	237	0 178
25.	238	0.523
26.	240	0 105
27.	221	0.021
	Total Area	3 449

[No. O - 14016/24/85-GP]

का०आ० 3002—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं 1895 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अत, अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म प्र) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला. कोटा तहसील प.पलवा

गांव	खसरा नं	हैक्टयर	आर	सेन्टीआर
चक काकना	1	0	06	65
	4	0	54	55
	1/30	0	03	70
	14	0	36	30
	13	0	70	65
	12	0	03	00
	5	0	00	20

[O-14016/298/85 जी. पी]

S.O. 3002.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1895 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Pi plada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chak Kakavata	1	0	06	65
	4	0	54	55
	1/30	0	03	70
	14	0	36	30
	13	0	70	65
	12	0	03	0)
	5	0	00	20

[No. O-14016/298/85-G.P.]

का.आ. 3003.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1896 तारीख 23-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए
राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मागरोल

गाव		खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5	6
रकसपुरा		4	0	04	80
		3	0	12	60
		5	0	02	40
		7	0	72	00
		8	8	14	40
		36	0	02	40
		35	0	02	48
		31	0	00	34
		32	0	17	22
		33	0	03	90
		34	0	02	40
		80	0	38	70
		83	0	24	60
		79	0	19	70
		78	0	14	70
		76	0	00	42
		77	0	32	52
		73	0	36	90
		72	0	02	85
		86	0	08	40
		164	0	37	50
		161	0	31	95
		160	0	39	60
		158	0	02	10
		165	0	15	90
		337	0	02	55
		336	0	05	55
		334	0	14	60
		335	0	42	40
		351	0	02	70
		350	0	18	00
		347	0	38	85
		349	0	02	55
		84	0	00	10

[सं. O-14016/299/85-जी.पी.]

S.O. 3003.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1986 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur Raj.
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Rakaspura	4	0	04	80
	3	0	12	60
	5	0	02	40
	7	0	72	00
	8	0	14	40
	36	0	02	40
	35	0	02	84
	31	0	00	34
	32	0	17	22
	33	0	03	90
	34	0	02	40
	80	0	38	70
	83	0	24	60
	79	0	19	70
	78	0	14	70
	76	0	00	42
	77	0	32	52
	73	0	36	90
	72	0	02	85
	86	0	08	40
	164	0	37	50
	161	0	31	95
	160	0	39	60
	158	0	02	10
	165	0	15	90
	337	0	02	55
	336	0	05	55
	334	0	14	60
	335	0	42	40
	351	0	02	70
	350	0	18	00
	347	0	38	85
	349	0	02	55
	84	0	00	10

[No. O—14016/299/85-GP]

का. आ. 3004:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ. सं. 1897 तारीख/234-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए
राज्य : राजस्थान जिला: कोटा तहसील : मांगरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टयर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5
मोरवा	97	0	05	10
	102	0	04	20
	100	0	11	20
	101	0	24	50
	96	0	54	64
	107	0	01	32
	108	1	13	99
	109	0	23	85
	94	0	14	10
	81	0	49	20
	80	0	27	90
	75	0	20	40
	76	0	18	60
	73	0	15	90
	71	0	18	30
	70	0	41	10
	69	0	28	35
	64	0	72	96
	65	0	08	22
	66	0	22	02
	61	0	76	44
	52	0	12	60
	50	0	05	40
	51	0	16	19
	49	0	83	10
	43	3	01	70
	41	0	53	35
	40	0	37	61
	38	0	02	38
	39	0	06	46
	23	0	15	42

1	2	2	4	5
	4	0	04	14
	1	0	02	40
	82	0	15	30
	59	0	00	36
	47	0	00	16

[स. O—14016/300/85 जी पी]

S.O. 3004.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1897 dated 23-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajsthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Borda	97	0	05	10
	102	0	04	20
	100	0	11	20
	101	0	24	50
	96	0	54	64
	107	0	01	32
	108	1	13	99
	109	0	23	85
	94	0	14	10
	81	0	49	20
	80	0	27	90
	75	0	28	40
	76	0	18	60
	73	0	15	90
	71	0	18	30
	70	0	41	10
	69	0	28	35
	64	0	72	96
	65	0	08	22
	66	0	22	02
	61	0	76	44
	52	0	12	60
	50	0	05	40
	51	0	16	19
	49	0	83	10
	43	0	01	70
	41	0	53	35
	40	0	37	61
	38	0	82	38
	39	0	06	46
	23	0	15	42
	4	0	04	14
	1	0	02	40
	82	0	15	30
	59	0	00	36
	47	0	00	16

[No. O-14016/300/85-GP]

का. आ. 3005.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 651 तारीख 6-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इसतारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाईन बिछाने के लिए
राज्य-गुजरात जिला-पंचमहाल तालुका-दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेमीयर
कठला	135/p	1	47	00
	50/1	0	10	32
	20/7	0	04	80
	40	0	39	68

1	2	3	4	5	6	7
		39		0	46	17
		43		0	51	00
		198		0	37	18
		45		0	38	00
		211		0	01	66
		212		0	30	60
		221		0	01	72

[स O 14016/45/85 जी पी]

S O 3005 —Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O 651 dated 6 2 85 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline

And whereas the Competent Authority has under Sub Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline From Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State Gujrat District Panchamahal Taluka Dahod

Village	Survey No	Hectare	Area	Centiare
KATHALA——	135/A	1	47	00
	50/1	1	40	32
	207	0	04	80
	40	0	39	68
	39	0	46	17
	43	0	54	00
	198	0	37	18
	45	0	38	00
	211	0	04	76
	212	0	30	60
	221	0	01	72

[No O 14016/45/85-GP]

का आ 3006 —यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयाग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का आ स 570 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची म विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने क पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची म विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची म विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने क लिए प्रयाजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप म घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच बी जे गैस पाईप लाईन प्राजक्ट

ग्राम माकडान तहसील तराना जिला उज्जैन राज्य (मध्यप्रदेश)

अनु क्र	खसरा नं	उपयाग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स म)
1	2	3
1	1	0 150
2	2	0 180
3	4	0 011
4	7	0 113
5	8	0 105
6	9	0 113
7	10	0 113
8	11	0 497
9	16/2	0 185
10	16/1	0 244
11	26	0 102
12	28	0 150
13	29	0 160
14	30/1	0 080
15	216	0 409
16	220	0 069
17	221	0 324
18	222 225	0 494
19	223	0 222
20	230	0 032
21	244/1	0 085
22	246/1 46/2	0 256

1	2	3
23	250	0.290
24.	251 252	0.340
25	253	0.137
26	255/1	0.182
27	255/2	0.101
28	256	0.202
29	257	0.008
30.	261	0 020
31	262	0.089
32	263/1	0.121
33	263/3	0.125
34	1169	0.485
35.	1170	0.413
36	1171	0.040
37	1172	0.425
38.	1175	0.032
39.	1175	0.122
40	5	0.180
	योग कुल क्षेत्रफल	7.469

[स O-14016/17/85 जी. पी.]

S.O. 3006.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 570 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village Makdon Tehsil : Tarana Distt. Ujjain State (M.P.)

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. .O.U. in Hecture
1	2	3
1.	1	0.150
2.	2	0.180
3.	4	0.014
4.	7	0.113
5.	8	0.105
6.	9	0 113
7.	10	0.113
8.	14	0.407
9.	16/2	0.185
10.	16/1	0.244
11.	26	0.102
12.	28	0.180
13.	29	0.160
14.	30/1	0.080
15.	216	0.409
16.	220	0.069
17.	221	0.324
18.	222 225	0.494
19.	223	0.222
20.	230	0 032
21.	244/1	0.085
22.	246/1 246/2	0.286
23.	250	0.290
24.	251/ 252	0.340 0.137
25.	253	
26.	255/1	0.182
27.	255/2	0.101
28.	256	0 202
29.	257	0 008
30.	261	0 020
31.	262	0 089
32.	263/1	0.121
33.	263/3	0.125
34.	1169	0.485
35.	1170	0.413
36.	1171	0.040
37.	1172	0.425
38.	1173	0.032
39.	1175	0.122
40.	5	0.180
TOTAL AREA		7.469

[No. O-14016/17/85-GP]

का. आ. 3007.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 48 तारीख 5-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम—भगवतपुरा तहसील—तराना जिला—उज्जैन राज्य (म प्र)

अनुसूची

अनु. क्र	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	117/2	0.016
2	120	0 192
3.	172/2	0.056
4.	274	0.240
5.	281	0 211
6	275	0 190
7	272	0.202
8.	280	0.088
9.	279	0.360
10.	278	0.022
11.	277/1	0.240
12	282	0 230
13.	285	0 530
14.	287	0.224
15	276/1/1	0.040
16	288/3	0.104
17	172/1	0 091
18.	292/1	0.041
19.	291	0.022
20.	292/2	0.144
21	293	0.052
22.	294	0 020
23	296	0.517
24.	297	0.214
25.	299	0.405
26	300	0.445
	योग कुल क्षेत्रफल	4.896

[सं. ओ-14016/498/84-जी०पी०

S.O. 3007.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 48 dated 5-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Bhagwatpura Tehsil Tarana Distt. Ujjain

SCHEDULE

S.No.	Survey No	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares
1.	117/2	0.016
2	120	0.192
3.	172/2	0 056
4.	274	0 240
5.	281	0 211
6.	275	0 190
7.	272	0 202
8.	280	0 088
9.	279	0 360
10.	278	0 022
11.	277/1	0 240
12.	282	0 230
13.	285	0.530
14.	287	0 224
15.	276/1/1	0 040
16.	288/3	0.104
17.	172/1	0 091
18.	292/1	0 041
19.	291	0 022
20.	292/2	0.144
21.	293	0.052
22.	294	0.020
23	296	0.517
24.	297	0.214
25.	299	0.405
26.	300	0.445
TOTAL AREA		4.896

[No O-14016/498/84-GP]

का. आ. 3008.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय का अधिसूचना का० आ. स. 4280 तारीख 8-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम लाला तलाई तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का (हैक्टर में) क्षेत्र
1	2	3
1	83	0 005
2	145	0 005
3	148	0 005
4	166	0 080
5.	165	0 234
6	80	0 171
7	164	0 234
8	163	0 132
9	81	0 258
10	84	0 234
11	85	0 144
12	86	0 025
13.	88	0.300
14.	89	0 010
15	152/1	0 030
16.	152/2	0 015
17.	139	0.010
18.	167	0.025
19	149	0.010
20.	140	0 032
21.	141	0 032
22.	142	0 032
23	143	0 064
24.	144	0 100
25.	150	0 030
26.	151	0.234
27.	196	0.132
28	197	0 312
9.	217	0 776
30	222	0 013
31.	218	0 276
32.	219	0 696
33	242/3	0.372
34.	243	0 048
	कुल योग: क्षेत्रफल	5 076

[सं० O-14016/366/84-जीपी]

S.O. 3008.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4280 dated 8-12-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Lala Talai, Tehsil : Rajgarh, Distt : Rajgarh (M.P.)

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectare
1	2	3
1.	83	0.005
2	145	0.005
3.	148	0.005
4.	166	0.080
5.	165	0.234
6	80	0 171
7.	164	0 234
8.	163	0.132
9.	81	0.258
10.	84	0.234
11.	85	0.144
12.	86	0.025
13.	88	0.300
14.	89	0.010
15.	152/1	0.030
16.	152/2	0.015
17.	139	0.010
18.	167	0.025
19.	149	0.010

1	2	3
20.	140	0.032
21.	141	0.032
22.	142	0.032
23.	143	0 064
24	144	0 100
25	150	0 030
26.	151	0 234
27	196	0.132
28.	197	0.312
29.	217	0.776
30.	222	0.013
31.	218	0.276
32.	219	0.696
33,	242/3	0 372
34.	243	0 048
TOTAL AREA		5 076

[No. O-14016/366/84-GP]

का.आ. 3009.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 4274 तारीख 8-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

347 GI/85—19

एच. बी. जे. प्रोजेक्ट, जिला उज्जैन

एच बी जे गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम—चुनाखेड़ी तहसील—तराना जिला—उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1	1	0.243
2	2/1/2	0 243
3	9	0 425
4	10	—
5	11	0.352
6	12/1	0.607
7	12/2	
8	15/1	0.025
9	36	0 085
10.	15/2	0 015
	योग कुल क्षेत्रफल	1.995

[सं O-14016/360/84-जीपी]

S.O. 3009.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4274 dated 8-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Churakhedi Tehsil : Tarana Distt: Ujjain (M.P.)

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquire in R.O.U. Hector
1	2	3
1.	1	0.243
2.	2/1/2	0.243
3.	9	0.425
4.	10	—
5.	11	0 352
6.	12/1	0.607

1	2	3
7.	12/2	—
8.	15/1	0.025
9.	36	0 085
10.	15/2	0 015
TOTAL AREA		1 995

[No O-14016/360/84-GP]

का० आ० 3010.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3778 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर-पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लाट संख्या	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	सेमरौता	बरवालिया	1	0 11 0	
				3	0 1 5	

[स० O-14016/165/84-जीपी]

S.O. 3010.—Whereas by notification of the Government of India is the Ministry of Petroleum, S.O. 3778 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdispur Pipe Line Project

Distt	Tahsil	Pargara	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rae Bareli	Maharaj-Ganj	Semrauti	Berwalia	1	0 11 0	
				3	0 1–5	

[No. O-14018/165/84-GP]

का. आ. 3011:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 592 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे गैस पाईप लाईन प्राजेक्ट

ग्राम सालपुरा तहसील राजगढ़ जिला—राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स मे)
1	2	3
1.	28	0.170
2	31	0.095
3	23	0.030
4.	22	0.010
5	24	0 120
6.	25	0.150
7.	45	0.200
8	47	0.040
9	59	0.090
10	60	0.010
11	58	0 110
12	53	0.050
13	27	0 010
14	29	0.010
15	30	0.015
16.	76	0.010
17.	44	0.010
18.	57	0.010
19	56	0.090
20.	55	0.200
21.	79	0.260
22	98	0.060
23	99	0.080
24	100	0.200
25.	101	0.150
26	92	0.035
27	90	0 180
28.	91	0.030
29	89	0.090
30	58/131	0.040
	योग कुल क्षेत्रफल	2.555

[सं० O-14016/35/85-जीपी]

S.O. 3011.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S. O. 592] dated 9-2-85 under sub-sectios (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-sectioon (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Salpura Tehsil Rajgarh Distt. Rajgarh

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hecture
1.	28	0 170
2.	31	0.095
3.	23	0.030
4.	22	0.010
5.	24	0 120
6.	25	0.150
7.	45	0.200
8.	47	0.040
9.	59	0.090
10.	60	0.010
11	58	0 110
12.	53	0.050
13.	27	0.010
14.	29	0 010
15.	30	0 015
16	76	0 010
17.	44	0.010
18.	57	0 010
19.	56	0 090
20.	55	0.200
21.	79	0.260
22.	98	0.060
23.	99	0.080
24.	100	0.200
25.	101	0 150
26.	92	0.035
27.	90	0.180
28.	91	0 030
29.	89	0.090
30.	58/131	0.040
TOTAL AREA		2.555

[No. O-14016/35/85-GP]

का. आ. 3012.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ स. 576 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत . उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम गोरखपर तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र	खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1	72	0 040
2	75	0 080
3	71	0 510
4	70	0 020
5	84	0.150
6	83	0 180
7	85	0.105
8	94	0 360
9	106	0.330
10	105	0 100
11	102	0 010
12	109	0 030
13	110	0.060
14	119	0 240
15	120	0.180
16	132	0.350
17	131	0 240
18	130	0.130
19	137	0 180
20	138	0 100
21	136	0.020
22	136/963	0 130
23	139	0 310
24.	178	0.050
25.	142	0.030
26.	179	0.030
27	177	0 510
28.	176	0 030
29	175	0 060
30	228	0 040
31	240	0 360
32	239	0 010
33	265	0 150
34	264	0 310
35	269	0 430
36	268	0 180
36क	278	0 200
37	280	—
38	284	0 050
39	285	0 030
40	282	0 089
41	281	0 023
42	286	0 010
43	287	0 020
44	279	0 090
45	719	0 085
46	603	0 080
47	602	0 020
48	601	0 050
49.	600	0 030
50.	589	0 050
51	601	0 030
52	588	0 090
53	593	0 090
54	590	0.020
55	591	0 030
56	592	0 063
57.	575	0 180
58.	553	0 020
59	554	0 045
60	555	0 180
61	558	0.180
62	559	0 130
63	552	0 020
64	551	0 180
65	560	0 170
66	55/969	0.030
67	505/947	0 060
68	550	0 020
69	505/946	0 170
70	537	0.300
71	536	0 010
72	533	0 240
73	532	0 330
74	531/956	0 120
75	531	0.080
76	530	0 030
77	527	0 060
78.	526	0 010
79	529	0 200
80.	528	0.120
81.	524	0.120
82	523	0 060
83	511/1	0 200

1	2	3
84.	513/1	0.080
85.	515	0.420
86.	516	0.480
87.	517	0.220
88.	522	0.220
89.	557	0.010
90.	538	0.010
91.	174	0.030
92.	270	0.150
93.	518	0.030
94	628	0.020
95.	610	0.020
96.	548	0.020
	योग कुल क्षेत्रफल	12.200

रु०/-

सक्षम प्राधिकारी,

S.O. 3012.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 3575 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Gorkha Par Tehsil: Rajgarh: District Rajgarh(M.P.)

SCHEDULE

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hec.
1	2	3
1.	72	0.040
2.	75	0.080
3.	71	0.510
4.	70	0.020
5.	84	0.150
6.	83	0.180
7.	85	0.105
8.	94	0.360
9.	106	0.330
10.	105	0.100
11.	102	0.010
12.	109	0 030
13.	110	0.060
14.	119	0.240
15.	120	0.180
16.	132	0.350
17.	131	0.240
18.	130	0.130
19.	137	0.180
20.	138	0.100
21.	136	0.020
22.	136/963	0.130
23.	139	0.310
24.	178	0.050
25.	142	0.030
26.	179	0.030
27.	177	0 540
28.	176	0.030
29.	175	0.060
30.	228	0.040
31.	240	0.360
32.	239	0.010
33.	265	0.150
34.	264	0.310
35.	269	0.430
36.	268	0.180
36.(a)	278	0.200
37.	280	—
38.	284	0.050
39.	285	0.030
40.	282	0.089
41.	281	0.023
42.	286	0.010
43.	287	0.020
44.	279	0.090
45.	719	0.085
46.	603	0.080
47.	602	0.020
48.	601	0.050
49.	600	0.030
50.	589	0 050
51.	604	0 030
52.	588	0.090
53.	593	0.090
54.	590	0.020
55.	591	0.030
56.	592	0.063
57.	575	0.180
58.	553	0 .020
59.	554	0.045
60.	555	0.180
61.	558	0.180
62.	559	0.130
63.	552	0.020
64.	551	0.180
65.	560	0.170
66.	55/969	0.030
67.	505/947	0.060
68.	550	0 070
69.	505/946	0.170
70.	537	0.300
71.	536	0.010
72	533	0.240
73	532	0.330
74	534/956	0 120
75	531	0.080
76.	530	0.030
77.	527	0.060
78.	526	0.010
79.	529	0.200

1	2	3
80.	528	0 120
81.	524	0 120
82.	523	0 060
83.	514/1	0 200
84.	513/1	0 080
85.	515	0 420
86.	516	0.480
87.	517	0.220
88.	522	0.220
89.	557	0.010
90.	538	0 010
91.	174	0 030
92.	270	0 150
93.	518	0 030
94.	682	0 020
95.	610	0 020
96.	548	0.020
	Total Area	12 200

[F. No. O-14016/23/85-GP]

का. आ. 3013:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 599 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए, अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम—दलेलपुरा तहसील—राजगढ़ जिला—राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	सर्वे नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1.	1	0 400
	योग—कुल क्षेत्रफल	0 400

[सं. O-14016/42/85-जीपी]

S.O. 3013.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 599 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village-Dalelapur Tehsil-Rajgarh Distt.-Rajgarh State (M.P.)

SCHEDULE

S.No	Survey No	Area to be acquired for R.O.U in Hec.
1.	1	0 400
	Total Area	0 400

[No O-14016/42/85-GP]

का. आ. 3014.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 582 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट

ग्राम—पाड़लियाखेड़ी तहसील—राजगढ़ जिला—राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	49	0 015
2.	50	0.590
3	51	0 200
4.	52	0.010
5	53	0.390
6	57	0.015
7.	58	0.300
8	59	0.440
9	60	0.090
10.	62	0.225
11.	65	0.050
12.	359/1	0.255
13	360	0.075
14.	361	0.870
15.	371	0.050
16	373	0.595
17.	794	0.060
18	800	0 140
19.	801	0 070
20	802	0 340
21.	803	0 340
22.	804	0 010
23	805	0 190
	योग कुल क्षेत्रफल	5.320

[सं. O-14016/29/85-जीपी]

S.O. 3014.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 582 dated 9-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village-Padliakhedi Tehsil-Rajgarh Distt.-Rajgarh State (M.P.)

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be aquired for R. O. U. in Hecture
1.	49	0.015
2.	50	0.590
3.	51	0.200
4.	52	0.010
5.	53	0.390
6.	57	0.015
7.	58	0.300
8.	59	0.440
9.	60	0.090
10.	62	0.225
11.	65	0.050
12.	359/1	0.255
13.	360	0.075

14.	361	0.870
15.	371	0 050
16.	373	0 595
17.	794	0.060
18.	800	0.140
19.	801	0.070
20.	802	0.340
21.	803	0.340
22.	804	0 010
23.	805	0.190
	Total Area	5.320

[F. No. O-14016/29/85-G.P.]

का०आ० 3015—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 658 तारीख 16-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्राजेक्ट

ग्राम—मोहकमपुरा तहसील—राजगढ़ जिला—राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु. क्र	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	20	0.050
2.	19/1	0.070
3	19/2	0 300
4	19/3	0 210
5	18	0.110
6.	17	0.500
7	15/2	0 150
8	15/1	0 430
9.	8	0 020
10.	9/2	0 400
11.	9/1	0.050
12	10	0 480
13.	5	0 220
14.	4	0 850
15.	3	0 100
16	16	0 325
17.	14	0 030
	योग—कुल क्षेत्रफल	4 295

[सं-O 14016/53/85-जी.पी.]

S.O. 3015.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 658 dated 16-12-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified n the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laving the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declartion in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe line Project

Village: Mohakampura Tehsil: Rajgarh Distt : Rajgarh

S No.	Survey No.	Area to be acquired for R. O U. in Hectare
1.	20	0 050
2	19/1	0.070
3.	19/2	0.300
4.	19/3	0 210
5.	18	0.110
6	17	0 500
7	15/2	0 150
8.	15/1	0.430

1	2	3
9.	8	0 020
10.	9/2	0 400
11.	9/1	0 050
12	10	0.480
13.	5	0.220
14.	4	0 850
15.	3	0.100
16	16	0 325
17	14	0.070
	Total Area	4 295

[No. O-14016/53/85-G. P]

का. आ. 3016.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 46 तारीख 5-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच बी जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम—सुचाई तहसील—तराना जिला—उज्जैन राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1	87	0 202
2	86	0.405
3.	96	0 506
4.	84	0 072
5.	91	0 168
6.	90/4	0.235
7.	90/1	0 175
8.	90/3	0 235
9.	90/2	0.240
10	89	0.128
11.	85	0.008
12.	94	0.008
	योग—कुल क्षेत्रफल	2 382

[स O 14016/496/84—जी पी]

S.O. 3016.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 46 dated 5-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Suchai Tehsil Tarana Distt. Ujjain

S No	Survey No.	Area to be acquired for R O. U. in Hectare
1.	87	0.202
2.	86	0.405
3.	96	0.506
4.	84	0.702
5.	91	0 168
6.	90/4	0.235
7.	90/1	0 175
8	90/3	0 235
9.	90/2	0 240
10	89	0.128
11.	85	0 008
12.	94	0 008
	Total Area	2.382

[No. O-14016 496 84-G.P

का. आ. 3017.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 132 तारीख 12-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्हित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निर्हित होगा ।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम—सागी तहसील—राजगढ़ जिला—राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	1	0 215
2	21	0.038
3	18	0.164
4	19	0 180
5	16	0 228
6	13	0 360
7	12	0 065
8	54	0.065
9	53	0 390
10	56	0.105
11	69	0 215
12	68	0 240
13	64	0 180
14	65/2	0 089
15	65/1	0 240
16	10	0 005
17.	59	0 005
18.	29	0.013
19.	26	0.013
	योग—कुल क्षेत्रफल	2.810

[फा.सं. O-14016/525/84-जीपी]

S.O. 3017.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 132 dated 12-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition or Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Sagi Tehsil Rajgarh Distt. Rajgarh

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R. O. U. in Hectare
1.	1	0.215
2.	21	0.038
3	18	0.164
4.	19	0.180
5.	16	0 228
6.	13	0 360
7.	12	0.065
8.	54	0 065
9.	53	0.390
10	56	0.105
11.	69	0 216
12	68	0 240
13.	64	0.180
14	65/2	0.089
15.	65/1	0 240
16	10	0.005
17.	59	0.005
18.	29	0 013
19.	26	0 013
	Total Area	2.810

[F. No. O-14016/525/84-GP]

का. आ. 3018.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 4537 तारीख 10-12-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—देवगढ़ बारीया

गांव	सर्वे नं	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
रामडीया	42	0	42	60
	41	0	23	27
	40	0	05	06
	83	0	00	50
	82	0	14	16
	50/1	0	21	24
	50/2	0	21	00
	53/पी	0	59	00

[फा० सं० O-14016/439/84-जी पी]

S.O. 3018.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4537 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the scheduled appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Devgad Bariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ratadiya	42	0	42	60
	41	0	23	27
	40	0	05	06
	83	0	00	50
	82	0	14	16
	50/1	0	21	24
	50/2	0	21	00
	53/P	0	59	00

[F. No. O-14016/439/84-G.P]

का. आ. 3019.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 581 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच०बी०जे०गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : खजूरी, तहसील : राजगढ़, जिला : राजगढ़, राज्य (म०प्र०)

अनु०क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1	344	0 110
2	345	0 450
3	347	0.480
4	352	0.160
5	351	0.360
6.	348	0 010
7.	360	0 450
8.	386	0.160
9	385	0.160
10	388	0.150
11.	389	0 036
12	390	0.490
13.	391	0.060
14	801	0 490
15.	823	0.330
16	824	0 230
17.	825	0.180
18	827	0.030
19	828/866	0 050
20	762	0 090
21	765	0 010
22	766	0 180
23	760	0.050
24	767	0 030
25	758	0 320
26	756	0 010
27	755	0 340
28.	734	0.240
29.	737	0.360
30.	739	0.180
31.	711	0.050
32	701	0 270
33.	700	0 250
34.	699	0 180
35	387	0.010
36	807	0.010
37.	803	0.005
38	822	0.005
39	826	0 005
40.	792	0.010
41.	736	0 005
42.	738	0.005
43.	702	0.005
44.	821	0 015
45.	820	0.010
	योग कुल क्षेत्रफल .	7.031

[फा.सं० O-14016/28/85-जी पी]

S.O. 3019.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 581 dated 7-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd., free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ Gas Pipe line Project

Village : Khajuri Tehsil : Rajgarh Distt. : Rajgarh State (M P)

S No	Survey No.	Area to be acquired for R. O U in Hectare
1	2	3
1.	344	0 110
2.	345	0.450
3.	347	0.480
4.	352	0.160
5	351	0.360
6.	348	0 010
7.	360	0.450

1	2	3
8	386	0 160
9	385	0 160
10	388	0 150
11.	389	0 036
12.	390	0 490
13.	391	0 060
14.	801	0.490
15.	823	0.330
16	824	0 230
17	825	0 180
18.	827	0.070
19.	828/866	0.050
20.	762	0.090
21.	765	0.010
22.	766	0.180
23.	760	0.050
24.	767	0 030
25.	753	0 320
26	756	0.010
27	755	0.340
28.	734	0.240
29.	737	0 360
30.	739	0.180
31.	711	0 050
32.	701	0.270
33	700	0 250
34.	699	0.180
35.	387	0.010
36.	807	0 010
37.	803	0.005
38	822	0.005
39.	826	0 005
40.	792	0.010
41.	736	0.005
42.	738	0.005
43.	702	0 005
44	821	0 015
45.	820	0 010
	Total Area	7.031

[F. No. O-14016/28/85-GP]

का. आ. 3020.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4120 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और अगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

ग्राम : जलालपुरा तहसील : राजगढ़ जिला : राजगढ़ राज्य (म० प्र०)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	272	0.152
2.	33/3	0.164
3	271	0 019
4.	273	0 228
5.	35	0 266
6.	29	0.058
7.	28	0.342
8.	27	0.215
9.	47	0.019
10.	22	0.038
11.	21	0 354
12	19	0 139
13.	20	0.051
14	18	0.038
15.	15	0.101
16.	14	0.152
17	13(अ)	0.089
18.	13(ब)	0.089
19.	12	0.139
	कुल योग :—क्षेत्रफल	2.653

[फा. न.O–14016/338/84–जीपी]

S.O. 3020.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 4120 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Gooverment directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Jalalpura, Tehsil Rajgarh, Distt. Rajgarh

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hecture
1.	272	0.152
2.	33/3	0 164
3.	271	0.019
4.	273	0 228
5.	35	0 266
6.	29	0 058
7.	28	0.342
8.	27	0.215
9.	47	0.019
10.	2	0.038
11.	21	0.354
12.	19	0.139
13.	20	0.051
14.	18	0.038
15.	15	0.101
16.	14	0 152
17.	13(A)	0.089
18.	13(B)	0.089
19.	12	0.139
	Total Area	2.653

[F. No.O 14016/338/85-GP]

का. आ. 3421.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 113 तारीख 12-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : बटावदा तहसील आगर जिला : शाजापुर राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	सर्वे नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	1	0 031
2.	4	0.084
3	10	0.010
4.	11	0.021
	योग कुल क्षेत्रफल :	0.146

[फा० सं० 14016/506/85-जी० पी०]

S.O. 3021.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 113 dated 12-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Bitawada Tehsil Agar Distt. Shajapur

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hectare
1.	1	0 031
2.	4	0 084
3.	10	0 010
4.	11	0 021
	Total Area	0.146

[F. No.O-14016/506/85GP]

का. आ. 3022.—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 4093 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : सुवाडेवी तहसील राजगढ़ जिला : राजगढ़ राज्य : (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र	खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स मे)
1	2	3
1.	376/14	0.360
2.	376/13	0.200
3.	420/4	0.300
4.	420/3	0.300
5.	420/2	0.348
6.	420/6	0.120
7.	420/5	0.156
8.	420/7	0.600
9.	420/8	0.660
10.	457/4	0.200
11.	457/3	0.240
12.	457/2	0.101
13.	455	0.360
14	421	0.005
15.	456	0 171
16	450	0.250
17.	449	0.132
18.	448	0.036
19.	425	0.090
20.	437/2	0.240
21.	438(मी)	0.005
22.	439	0.018
23.	440(मी)	0.096
24.	442	0.076
25.	441	0.042
	योग :—कुल क्षेत्रफल	5.466

[फा० सं० 14016/342/84—जी०पी०]

S.O. 3022.—Whereas by not fication of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4093 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all ensumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Suwahen, Tehsil : Rajgarh, Distt. Rajgarh

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hecture
1	376/14	0 360
2	376/13	0.200
3	420/4	0.300
4	420/3	0.300
5.	420/2	0.348
6	420/6	0 120
7.	420/5	0 156
8.	420/7	0.600
9.	420/8	0.660
10	457/4	0.200
11.	457/3	0 240
12.	457/2	0 101
13	455	0.360
14.	421	0 005
15.	456	0.171
16	450	0 250
17.	449	0 132
18.	448	0.036
19.	425	0 090
20	437/2	0 240
21.	438m.	0.005
22	439	0 018
_ .	440m	0.096
24.	442	0.076
25.	441	0 402
	Total Area	5.466

[F. No.O—14016/342/84-GP]

का. आ. 3023.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 4095 सं. तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : रामपुरिया तहसील : राजगढ़ जिला : राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	सर्वे नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1.	2.	3.
1.	48/1/2	0.720
2.	62/2	1.332
	योग :— कुल क्षेत्रफल	2.052

[फा सं 0—14016/344/84—गा पी]

S.O. 3023.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4095 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Rampuria Tehsil Rajagarh Distt Rajgarh

SCHEDULE

S No	Survey No	Area to be Acquired for R O U. in Hecture
*1.	48/1/2	0 720
2	62/2	1 332
	Total Area	2 052

[F.No.O-14016/344/84—GP]

का. आ. 3024:—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3716 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

एच०बी०जे०गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम पिटोल बड़ी तहसील झाबुआ जिला—झाबुआ राज्य (मध्य प्रदश)

अनुसूची

अनु क्र. 1	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	59/1	0 024
2	33	0 097
	31	0 040
3.	15	0.024
4	36	0.039
5	4^/2	0 364
6	43	0 031
7	59/2	0 150
	65	0 057
8	84	0 024
9	64	0 032
10	59/3	0 052
11.	82	0○040
12.	80	0 405
13.	106/1	0.283
14	23	0.526
15.	105	0 040
16	22	0.040
17	21	0.486
18	106/2	0.283
	योग कुल क्षेत्रफल —	3 137

[फा॰ सं॰ O-14016/205/84—जी पी]

S.O. 3024.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 3716 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Name Pitoe Badi Tehsil Zabua Distt. Zabua

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hecture
1.	59/1	0 024
2.	83	0 097
3.	81	0 040
	45	0.024
4.	36	0 089
5.	42/2	0 364
6.	43	0 081
7.	59/2	0.150
	65	0 057
8.	84	0 024
9.	64	0 032
10.	59/3	0 052
11.	82	0 040
12.	80	0 405
13.	106/1	0 283
14.	23	0 526
15	105	0 040
16	22	0 040
17	21	0 486
18	106/2	0 283
	Total Area	3 137

[No. O-14016/205/84 G.P.]

का. आ. 3025:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4570 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य गुजरात जिला—पंचमहल तालुका वाघोद

गाँव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आरे०	सेन्टीयर
मानवा	201	0	00	18
	200	1	22	27
	208/2	0	00	49
	209/2/ए	0	05	46
	209/2/बी	0	06	06
	209/1/बी	0	01	12
	210/बी	0	11	29
	212	0	23	75
	213	0	16	60
	214	0	39	12
	215	0	38	80
	133	0	00	14
	122	0	58	14
	121	0	18	25
	118/ए	0	14	40
	119	0	34	55
	95	0	52	65
	143	0	54	52
	94	0	02	20
	58/ए	0	34	98
	63	0	00	60
	62	0	40	00
	61/ए	0	60	35
	61/बी	0	19	55
	64	0	21	18
	60	0	13	25
	54	0	07	00
	53	0	25	60
	52	3	72	15
	51	0	34	60

[सं. O-14016/473/84-जी पी]

S.O. 3025.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O 4570 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira–Bijaipur–Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Matva	201	0	00	18
	200	1	22	27
	298/2	0	00	4
	209/2/A	0	05	46
	209/2/B	0	06	06
	209/1/B	0	01	12
	210/B	0	32	29
	212	0	23	75
	213	0	26	60
	214	0	39	12
	215	0	38	80
	123	0	00	14
	122	0	58	14
	121	0	18	25
	118/A	0	14	40
	119	0	34	55
	95	0	52	65
	143	0	54	52
	94	0	02	20
	58/A	0	34	98
	63	0	00	60
	62	0	40	00
	61/A	0	60	35
	61/B	0	19	55
	64	0	21	18
	60	0	13	25
	54	0	07	00
	53	0	25	60
	52	2	72	15
	51	0	34	60

[No. O-14016/473/84-G.P.]

का०आ० 3026.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 4114 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम : काली पीठ तहसील राजगढ़ जिला : राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	1160	0.150
2	1159/1	0.090
3.	1159/2	0.450
4	1146/1	0.420
5.	1155	0.180
6.	1156	0.182
7	1154	0.240
8	1153	0.180
9.	1151	0.065
10.	1130	0.026
11	1096	0.600
12.	1095	0.180
13.	1100	0.090
14.	1101/1	0.200
15.	1101/2	0.340

1	2	3
16.	1102	0 030
17.	1089	0 100
18.	1036	0 026
19.	1059	0.010
20.	1060	0.300
21.	1061	0.240
22.	1063	0.240
23.	1070/2	0.300
24.	1071	0 150
25	1072	0 145
26.	1073	0 090
27.	1074	0.250
28	1075	0.010
29.	1083	0.020
30	1069	0.020
31.	1089/1180	0 005
32.	1152	0.005
	कुल योग . क्षेत्रफल	5.334

[सं० O-14016/331/84-जी० पी०]

S.O. 3026.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4114 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Kalipith Thehsil Rajgarh Distt. Rajgarh

S. No.	Survey No.	Area To Be Acquired for R.D.V. in Hecture
1	2	3
1.	1160	0.150
2.	1159/1	0 090
3.	1159/2	0 450
4.	1146/1	0.420
5.	1155	0 180
6.	1156	0 182
7.	1154	0 240
8	1153	0.180
9.	1151	0 065
10.	1130	9.026
11.	1096	0 600
12.	1095	0 180
13.	1100	0.090
14.	1101/1	0 200
15	1101/2	0.340
16.	1102	0 030
17	1089	0 100
18.	1086	0.026
19.	1059	0 010
20	1060	0 300
21	1061	0 240
22.	1063	0.240
23.	1070/2	0 300
24.	1071	0 150
25.	1072	0 145
26	1073	0 090
27.	1074	0 250
28.	1075	0.010
29.	1083	0 020
30.	1069	0 020
31.	1089/1180	0.005
32.	1152	0.005
	Total Area	5.334

[F. N. O—14016/331/84—G.P.]

का. आ. 3027 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 872 तारीख 2-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 को उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : चोरोल तहसील : गुना जिला : गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

क्रम.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	1	0.031
2.	101/1क	0.105
3.	102/1	0.042
4.	102/2	0.063
5.	103/1	0.440
6	123	0.115
7	122/1	0.366
8.	125	0.363
9	126	0.073
10.	99	0.031
11.	84/2	0.261
12	82	0.363
13.	73	0.575
14.	74	0.105
15.	72	0.010
16.	71	0.461
17.	70	0.272
18.	141	0.209
19.	140	0.468
20.	145	0.131
21.	146/1	0.627
22.	150	0.387
23.	149/1	0.063
24.	151/2	0.366
25	152	0.209
26.	151/1	0.449
27	200	0.250
28	195	0.042
29.	197/3	0.366
30.	197/1	0.115
31.	196	0.209
32.	190	0.305
33	189	0.040
34	192/2	0.010
35.	191	0.209
36.	165/1/3ख	0.941
37.	165/1/1	0.084
37	165/1/3क	0.063
39.	186	0.082
40.	103/2	0.010
41	80	0.042
42.	75	0.010
43.	146/2	0.010
44.	252	0.062
45.	197/2	0.010
46.	128	0.010
	योग—कुल क्षेत्र फल	9.555

[सं० O-14016/88/85-जी० पी०]

S.O. 3027.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 872 dated 2-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Chorol Tehsil Guna Distt Guna

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be acquired R. O in—Hectare
1.	1	0.031
2	101/1/K	0.105
3	102/1	0.042
4	102/2	0.063
5	103/1	0.440
6.	123	0.115
7.	122/1	0.366
8.	125	0.363
9	126	0.073
10.	99	0.031
11.	84/2	0.261
12	82	0.363
13.	73	0.575
14.	74	0.105
15.	72	0.010
16	71	0.461
17	70	0.272
18	141	0.209
19.	140	0.468
20.	145	0.131
21.	146/1	0.627
22.	150	0.387
23.	149/1	0.063
24	151/2	0.366
25.	152	0.209
26	151/1	0.449
27.	200	0.250
28.	195	0.042
29.	197/3	0.366
30	197/1	0.115
31.	196	0.209
32.	190	0.305
33.	189	0.040
34.	192/2	0.010
35	191	0.209
36	165/1/3/KH	0.941
37.	165/1/1	0.18[illegible]

1	2	3
38	165/1/3/K	0 063
39.	186	0 083
40.	103/2	0 010
41	80	0 012
42	75	0 010
43.	146/2	0 010
44	252	01062
45.	197/2	0 010
46	125	0 010
	Total Area	7.555

[No. O-14016/88/85 G.P.]

का. आ. 3028.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 666 तारीख 16-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम किशनपुरिया तहसील राजगढ़ जिला—राजगढ़ (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

क्रम सं०	सर्वे नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	179/214	0 020
2	179/1	0 120
3.	71	0.090
4	177	0.300
5	176	0.240
6.	174	0 060
7	172	0 040
8.	178	0 020
9.	182	0 030
10	184	0 120
11.	186	0 030
12	183	0 050
13	188	0.080
14	187	0 090
15.	189/1	0.150
16.	192/3	0 120
17	192/2	0.300
18.	193/2	0.300
19	193/3	0 390
20	198/2	0.120
21.	198/1	0 300
22.	194/3	0.060
23	196	0 110
24	163	0 100
25	191	0.110
26.	141/1	0.010
27.	190	0 100
28	193/1	0.060
29	195	1.200
	योग:—कुल क्षेत्रफल	4 650

[फा. स. O-14016/62/85-जीपी]

S.O. 3028.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 666 date 16-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Kishanpuria Tehsil Rajgarh Distt. Ragarh Distt. (M.P.)

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R. O. U. in Hecture
1.	179/214	0 020
2.	179/1	0.120
3.	71	0.090
4.	177	0.300

1	2	3
5.	176	0.240
6.	174	0 060
7	172	0 040
8	178	0 020
9	182	0.030
10	184	0 120
11	186	0 030
12.	183	0 080
13.	188	0.080
14.	187	0 090
15	189/1	0.150
16	192/3	0 120
17.	192/2	0 300
18	193/2	0 300
19	193/3	0 390
20	198/2	0 120
21.	198/1	0.300
22	194/3	0 060
23.	196	0 010
24	163	0 100
25.	191	0 110
26	141/1	0.010
27	190	0.100
28.	193/1	0.060
29.	195	1.200
	Total Area	4 650

[F. No. O—14016/62/85-GP]

का. आ. 3029.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 664 तारीख 16-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच० बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम कुण्डवे तहसील राजगढ़ जिला—राजगढ़ राजस्व (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र०	खसरा सं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	522/2	0 360
2.	524	0 020
3	526/1	0.090
4	526/2	0.100
5	526/3	0.600
	योग : कुल क्षेत्रफल	1.170

[फा० सं० O-14016/59/85-जीपी]

S.O. 3029.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 564 dated 16-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ Gas Pipe Line Project

Village Kundway Tehsil Rajgarh Distt. Rajgarh

SCHEDULE

S No.	Survey No.	Area to be Acquired for R O. U. in Hecture
1	2	3
1.	522/2	0.360
2	524	0 020
3.	526/1	0.090
4	526/2	0 100
5.	526/3	0.600
	Total Area	1 170

[F No. O—14016/59/85-GP]

का.आ. 3030.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 732 तारीख 23-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : लालपुरिया तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	2	3
1	4/2	1.400
2	3	0.150
3	2/1	0.740
4	10/3	0.700
5.	10/1	0.040
6	19/1	0.040
7.	13	0.060
8.	11	0.550
9	2/2	0.150
	योग कुल क्षेत्रफल	3.830

[फा० सं०—14016/74/85-जी०पी०]

S.O. 3030.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 732 dated 23-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Lalpuriya Tehsil : Rajgarh, Distt : Rajgarh

SCHEDULE

S No.	Survey No	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1	2	3
1	4/2	1.400
2	3	0.150
3.	2/1	0.740
4.	10/3	0.700
5.	10/1	0 040
6.	19/1	0 040
7.	13	0.060
8.	11	0.550
9.	2/2	0.150
	Total Area :	3 830

[F. No. O. -14016/74/85-G.P.]

का०आ० 3031.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० सं० 663 तारीख 16-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम रसूलपुरा तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

क्रम सं.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	115/2	0.300
2	117	0.240
3	118	0.120
4	119	0.120
5	120	0.100
6	121	0.070
7	122/1	0.030
8	123	0.030
9	124	0.300
10	125	0.020
11	129	0.250
12	129/617	0.250
13	130	0.270
14	131	0.090
15	132/1	0.015
16	135	0.300
17	137	0.130
18	138	0.240
19	157	0.090
20	456	0.040
21	455	0.025
22	458	0.120
23	469	0.065
24	460	0.180
25	466	0.120
26	467	0.135
27	468	0.075
28	479	0.010
29	470	0.040
30	473	0.040
31	479	0.090
32	480	0.360
33	481	0.250
34	483	0.040
35	486	0.040
36	599	0.050
37	598	0.180
38	520	0.110
39	492	0.030
40	524	0.050
41	525	0.115
42	521	0.010
43	530	0.300
44	534	0.400
45	535	0.050
46	549	0.030
47	550	0.510
48	552	0.050
49	553	0.110
50	560	0.600
51	556	0.490
52	559	0.040
53	557	0.050
54	478	0.010
55	571/1	0.090
56	563	0.050
57	562	0.135
58	565	0.090
59	511	0.030
60	571/2	0.090
61	533	0.020
	योग कुल क्षेत्रफल	8.365

[फा० सं० —14016/58/85-जी०पी०]

S.O. 3031.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 663 dated 16-2-85 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification .

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd, free from all encumbrances

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Rasulpura. Tehsil : Rajgarh. Distt : Rajgarh.

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	115/2	0.300
2.	117	0 240
3.	118	0 120
4.	119	0.120
5	120	0 100
6.	121	0.070
7.	122/1	0.030
8.	123	0.030
9.	124	0.300
10.	125	0 020
11.	129	0.250
12.	129/617	0 250
13.	130	0.270
14.	131	0.090
15.	132/1	0.015
16.	135	0.300
17.	137	0.130
18.	138	0.240
19.	457	0.090
20.	456	0 040
21.	455	0.025
22.	458	0.120
23.	469	0.065
24.	460	0.180
25.	466	0.120
26.	467	0.135
27.	468	0.075
28.	469	0.040
29.	470	0.040
30.	473	0.040
31.	479	0.090
32.	480	0.260
33.	481	0.250
34.	483	0.040
35.	486	0.040
36.	599	0.050
37.	598	0.180
38.	520	0 110
39.	482	0.030
40.	524	6.050
41.	525	0.115
42.	521	0.040
43.	530	0.300
44.	534	0.400
45.	535	0.050
46.	549	0.030
47.	550	0.540
48.	552	0.050
49.	553	0.110
50.	550	0.600
51.	556	0.480
52.	559	0.040
53.	557	0.050
54.	478	0.010
55.	571/1	0 090
56.	563	0.050
57.	562	0.135
58.	565	0.090
59.	514	0.030
60.	571/2	0.090
61.	533	0.020
योग : कुल योग्यफल		8 365

[F. No. O.—14016/58/85-G.P.]

का. आ. 3032.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4542 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—लिमखेडा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
बार	24	0	08	00
	12/ए/पी	0	34	00
	12/बी	0	00	50
	138	0	34	00
	11/1	0	03	00
	6/1	0	10	80
	6/2	0	30	00
	7/1	0	20	00
	7/2	0	52	00
	7/3	0	45	00
	142	0	37	50
	8/पी	1	77	00

[फा० सं० O—14016/444/84-जी० पी०]

S.O 3032.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4542, dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has, under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka Limkheda

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bar	24	0	08	00
	12/A/P	0	34	00
	12/B	0	00	50
	138	0	34	00
	11/1	0	03	00
	6/1	0	10	80
	6/2	0	30	00
	7/1	0	20	00
	7/2	0	52	00
	7/3	0	45	00
	142	0	37	50
	8/P	1	77	00

[No. O.—14016/444/14-G. P.]

का. आ. 3033.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4092 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम महुवाबे महसील : राजगढ़ जिला—राजगढ़ (राज्य मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र०	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	192/1	0.013
2	193	0.230
3.	195	0.192
4	217	0.030
5	222(मी)	0.026
6	221(मी)	0.635
7.	218/1(मी)	0.720
8.	219/2	0.160
9	219/3	0.090
10	208/8	0.420
11.	208/3	0.025
	कुल योग :—क्षेत्रफल	2.561

सक्षम प्राधिकारी,

[सं० O—14016/341/84/जी०पी०]

S.O. 3033.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4092 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Mahuabe Tehsil : Rajgarh Distt. : Rajgarh

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hecture
1.	192/1	0.013
2	193	0.230
3	195	0.192
4.	217	0.030
5	222 m.	0.076
6.	221m.	0.635
7	218/1	0.720
8.	219/2	0.180
9.	219/3	0.090
10.	208/8	0.420
11.	208/3	0.025
	TOTAL AREA	2.561

[No. O—14016/341/84-G.P]

का. आ 3034 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4111 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : भवाखेड़ा तहसील : राजगढ़ जिला: राजगढ़ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र.	खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स मे)
1	2	3
1.	1/1	0.600
2.	1/2	0.360
3.	1/3	0.240
4.	2/4	0.180
5.	2/2	0.252
	कुल योग :—हैक्टर्स	1.632

[स. O-14016/328/84-जी पी]

S.O. 3034.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 4111 dated 14-12-84 Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd., free from all encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bhadwakhida Tehsil : Rajgarh Distt. : Rajgarh

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hecture
1.	1/1	0.600
2.	1/2	0.360
3.	1/3	0.240
4.	2/4	0.180
5.	2/2	0.252
	Total Area	*1.632

[S O-14016/328/85 G.P.]

का. आ. 3035.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 652 तारीख 6-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुक : दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
भूटोड़ी	110	00	28	75
	99	01	02	20
	97	01	32	00
	90	01	23	00
	96	01	29	00
	91	00	97	50
	92/1	00	79	50

[सं. O-14016/45/85-जी पी]

S.O. 3035.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 652 dated 6-2-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of th said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances :

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bhutodi	110	00	28	75
	99	01	02	20
	97	01	32	00
	90	01	23	00
	96	01	29	00
	91	00	97	50
	92/1	00	79	50

[No. O-14016/45/85-GP]

का. आ. 3036.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ए० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : ओलपाड

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टर	आर	सेंटीयर
कडोदरा	312	0	01	80
	313	0	22	00
	331	0	01	00
	338	0	51	60
	339	0	00	70
	341	0	24	00
	336	0	45	65
	349	0	07	50
	314	0	17	18
	328	0	26	76
	342	0	10	76

[सं० O-14016/47/85-जीपी०]

S.O. 3036.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from HAZIRA-BARILLY to JAGADISHPUR in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, of Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly—Jagdishpur

STATE; GUJARAT DISTRICT; SURAT TALUKA; OLPAD

Vilage	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Kathodra	312	0	01	80
	313	0	22	00
	331	0	01	00
	338	0	51	60
	339	0	00	70
	341	0	24	00
	336	0	45	65
	349	0	07	50
	314	0	17	18
	328	0	26	76
	342	0	10	76

[No. O-14016/373/85-G.P.]

का. आ. 3037 .—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) [अधिनियम, 1962] (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. सी.-58/बी., अलीगंज, लखनऊ-226030 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा- बरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्राजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स.	लिया गया रकबा (बीघों) में	विवरण
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	सेरहा-पुख्ता	1	0-01-00	
				18	1-02-10	
				17	0-00-02	
				15	0-05-17	
				16	0-15-00	
				14	0-10-05	
				4	0-12-15	
				12	0-01-00	
				6	1-10-10	
				5	0-00-05	
				8	0-01-00	
				7	0-12-15	
				172	0-00-18	
				162	0-04-13	
				167	0-10-04	
				166	1-01-00	
				165	0-01-00	
				156	0-03-10	
				157	0-00-05	छूटा था
				150	0-01-16	
				151	0-02-10	
				153	0-04-10	
				210	0-01-10	
				211	0-13-15	
				152	0-06-00	छूटा था
				212	0-10-04	
				213	0-03-10	
				219	0-18-14	
				220	0-16-16	
				221	0-14-10	
				222	0-00-05	
				123	0-19-00	
				333	0-01-16	
				301	1-03-00	
				300	0-06-00	
				302	0-05-10	
				303	0-09-00	
				304	0-11-05	
				305	0-12-00	
				306	0-33-06	
				313	0-03-15	
				307	0-10-16	
				308	0-04-10	
			कुल योग	43	18-08-07	बीघा या

[सं० 14016/372/85-जी०पी०]

S.O. 3037.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority of India Ltd. HBJ Pipeline Project B-58/B Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Dataganj	Salempur	Sarha Pakhta	1	0-01-00	
				18	0-02-10	
				17	0-00-02	
				15	0-05-17	
				16	0-15-00	
				14	0-10-05	
				4	0-12-15	
				12	0-01-00	
				6	1-10-10	
				9	0-00-05	
				8	0-01-00	
				7	0-12-15	
				172	0-00-18	
				162	0-04-13	
				167	0-10-04	
				166	1-01-00	
				165	0-01-00	
				156	0-03-00	
				157	0-00-05	छूटा हुआ
				150	0-01-16	
				151	0-02-10	
				153	0-04-10	
				210	0-01-10	
				211	0-13-15	
				152	0-06-00	छूटा था
				212	0-10-04	
				213	0-03-10	
				219	0-18-14	
				220	0-16-16	
				211	0-14-10	
				222	0-00-05	
				123	0-19-00	
				333	0-10-16	
				301	1-03-00	
				300	0-06-00	
				302	0-05-10	
				303	0-09-00	
				304	0-11-15	
				305	0-12-00	
				306	0-13-06	
				313	0-03-15	
				307	0-10-15	
				308	0-04-10	
		Total		4	18-08-07 बीघा या (4.6596) हे०	

[No. 14016/372/85-G.P.]

का. आ. 3038—मतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये ,

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ,

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत् ।

अनुसूची

हजीरा से बरेली जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य— गुजरात जिला—सूरत तालुका—मांगरोल

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
कुंवरदा	338	0	05	04
	341	0	05	32
	142	0	00	30

[सं० ओ०-14016/374/85-जी०पी०]

S.O. 3038.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hasira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Mangrol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kuvarda	338	0	05	04
	341	0	05	32
	342	0	00	30

[No. O-14016/374/85-G.P.]

का. आ. 3039—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 572 तारीख 9-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : कडोदिया तहसील : नागदा जिला : उज्जैन राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	1811/1	1.832
2.	1802	0.032
3	1785	0.056
4.	1784	0.010
5	1787	0.084
6.	1786	0.020
7.	1789	0.693
8.	1788/2	0.437
9	1792	0.190
10.	1760/1	0.337
11.	1760/2	0 500
12.	1760/3	0.501
13.	1759	0.050
14.	58	0 220
15.	59	0.356
16.	197	0.010
17	202	0.340
18	203	0 076
19.	204	0.232
20.	1633	0.030
21.	205	0 015
22	199	0 010
23.	206	0 120
24.	207	0 072
25.	200	0.020
26	208	0.088
27.	209	0.010
28	210	0.282
29.	210/2748	—
30	211	0.010
31	219	0 010
32	213	0 232
33.	215	—
34.	212	0 056
35.	217	0 340
36.	218	—
37.	220	0.048
38	214	0 101
39	221	0 312
40.	223	0.072
41.	224	0 064
42	225	0 044
43	226	0 044
44	229	0.304
45	227	0 168
46	235	0.032
47	238	0.016
48	239	0 112
49.	240	0.120
50.	245	0 120
51	246	0.144
52	248	0.024
53	249/1	0.288
54.	261	0.549
55	272	0.577
	273	
56.	273/2754	0.234
57.	285	0.196
58.	299	0.020
59.	303	0.048
60.	300	0.044
61.	304	0.240
62	301	0.044
63.	306	0.085
64	305	0.054
65	284	0.225
66	311	0.056
67	431	0 050
68.	430	0 168
69.	432	1 104
70.	433	0.080
71	434	0 012
72	385	0.024
73.	429	0.312
74.	437	0.216

1	2	3
75	438	0.200
76	439	0.064
77	202/2746	0.344
	योग कुल क्षेत्रफल :—	13.461

[सं० O-14016/19/85-जी०पी० ०]

S.O. 3039.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. date under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Kadodia Tehsil : Tarana Distrist : Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	1811/1	1.832
2.	1802	0.032
3.	1785	0.056
4.	1784	0.010
5.	1787	0.084
6.	1786	0.020
7.	1789	0.093
8.	1788/2	0.437
9.	1792	0.190
10.	1760/1	0.337
11.	1760/2	0.500
12.	1760/3	0.500
13.	1759	0.050
14.	58	0.220
15.	59	0.356
16.	197	0.010
17.	202	0.340
18.	203	0.076
19.	204	0.232
20.	1633	0.030
21.	205	0.015
22.	199	0.010
23.	206	0.120
24.	207	0.072
25.	200	0.020
26.	208	0.088
27.	209	0.040
28.	210	0.282
29.	210/2748	—
30.	211	0.016
31.	219	0.010
32.	213	0.232
33.	215	—
34.	212	0.056
35.	217	0.0540
36.	218	—
37.	220	0.048
38.	214	0.101
39.	221	0.312
40.	223	0.072
41.	224	0.064
42.	225	0.044
43.	226	0.044
44.	229	0.304
45.	227	0.168
46.	235	0.032
47.	238	0.016
48.	239	0.112
49.	240	0.120
50.	245	0.120
51.	246	0.144
52.	248	0.024
53.	249/1	0.288
54.	261	0.549
55.	272 273	0.573
56.	273/2754	0.234
57.	285	0.196
58.	299	0.020
59.	303	0.048
60.	300	0.044
61.	304	0.240
62.	301	0.044
63.	206	0.085
64.	305	0.054
65.	284	0.225
66.	311	0.056
67.	431	0.050
68.	430	0.168
69.	432	0.104
70.	433	0.080
71.	434	0.012
72.	385	0.024
73.	429	0.312
74.	437	0.216
75.	438	0.200
76.	439	0.064
77.	202/2746	0.344
	Total Area	13.461

[F. No. O-14016/19/85-G.P.

का० आ० 3040.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकारी लि० बी–58/बी अलीगंज लखनऊ–226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स.	क्षेत्रफल (बीघा) में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	बिसौली	बिसौली	निजरा	374	1–04–00	
				372	0–00–05	
				373	0–10–16	
				375	0–01–00	
				393	0–08–08	
				392	0–03–00	
				394	0–04–00	
				404	0–08–10	
				403	0–03–00	
				405	0–06–00	
				102	0–06–00	
				315	0–03–10	
				312	0–02–10	
				311	0–11–08	
				316	0–00–05	
				307	0–05–00	
				308	0–10–10	
				284	0–01–10	
				281	1–18–00	
				282	0–01–15	
				280	0–03–00	
				272	0–18–00	
				273	0–00–05	
				269	0–14–08	
				270	0–03–00	
				270/537	0–02–10	
बदायूं	बिसौली	बिसौली	निजरा	54	0–06–12	
				56	0–13–00	
				57	0–04–00	
				58	0–01–00	
				60	0–12–12	
				61	0–03–00	
				199	0–00–15	
				200	0–01–05	
				201	0–10–00	
				202	0–07–04	
				62	1–02–16	
				64	0–12–10	
				65	1–05–04	
				85	0–00–05	
				87	0–03–00	
				182	0–00–05	
				181	0–10–16	
				180	0–07–15	
				109/535	0–00–05	
				109	0–03–00	
				179	0–05–00	
				127	0–00–05	
				123	0–01–00	
				122	0–03–00	
				120	0–00–15	
				119	2–10–15	
				111	0–00–05	
				112	0–00–05	
				116	0–00–05	
			कुल योग	55	19–17–16 या (5.0322) है.	

[सं O-14016/37/85-जी.पी]

S.O. 3040.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Bisauli	Bisauli	Nizra	374	1-04-00	
				372	0-00-05	
				373	0-10-16	
				375	0-01-00	
				393	0-08-08	
				392	0-03-00	
				394	0-04-00	
				404	0-08-10	
				403	0-03-10	
				405	0-06-00	
				402	0-06-00	
				315	0-03-10	
				312	0-02-10	
				311	0-11-08	
				316	0-00-05	
				307	0-05-00	
				308	0-10-10	
				284	0-01-10	
				281	1-18-00	
				282	0-01-15	
				280	0-03-00	
				272	0-18-00	
				273	0-00-05	
				269	0-14-08	
				270	0-03-00	
				270/537	0-02-10	
				54	0-06-12	
				56	0-13-00	
				57	0-04-00	
				58	0-01-00	
				60	0-12-12	
				61	0-03-00	
				199	0-00-15	
				200	0-01-05	
				201	0-10-00	
				202	0-07-04	
				62	1-02-16	
				64	0-12-10	
				65	1-05 04	
				85	0-00-05	
				87	0-03-00	
				182	0-00-05	
				181	0-10-16	
				180	0-07-15	
				109/535	0-00-05	
				109	0-03-00	
				179	0-05-00	
				127	0-00-05	
				123	0-01-00	
				522	0-03-00	
				120	0-00-15	
				119	2-10-15	
				111	0-00-05	
				112	0-00-05	
				116	0-00-05	
			Total	55	19-17-16 Bighas or (5 0322 Hec)	

[No. O-14066/371/85-G.P.]

का. आ. 3041.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आंवला	आंवला	गुमैला	495	0-1-0	
				544	0-3-10	
				543	0-11-12	
				542	1-7-12	
				496	0-0-12	
				497	0-0-18	
				498	0-9-17	
				535	0-19-16	

1	2	3	4	5	6	7
				533	2-7-16	
				534	0-0-10	
				523	0-1-4	
				524	0-1-4	
				510	1-0-0	
				511	1-5-8	
				512	0-13-10	
				514	0-1-0	
				515	0-2-0	
				516	0-3-10	
				494	1-18-0	

[फा. सं. O-14016/370/85 जीपी]

S.O. 3041.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Barielly	Awlah	Awlah	Gulauti	495	0-1-0	
				544	0-3-10	
				543	0-11-12	
				542	1-7-12	
				496	0-0-12	
				497	0-0-18	
				498	0-9-17	
				535	0-19-16	
				533	2-7-16	
				534	0-0-10	
				523	0-1-4	
				524	0-1-4	
				510	1-0-0	
				511	1-5-8	
				512	0-13-10	
				514	0-1-0	
				515	0-2-0	
				516	0-3-10	
				494	1-18-0	

[F. No. O-14016/370/85-GP]

का. आ. 3042.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाईपों के बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत् ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल अर्जित किया जाना	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आंवला	आंवला	दशरथनगर	480	0-2-8	
				481	0-15-0	
				466	2-2-0	
				465	0-13-5	
				467	0-0-15	
				468	0-0-15	
				474	0-5-0	
				473	0-6-0	
				472	0-6-0	
				471	0-12-0	
				469	1-6-8	
				462	0-1-10	
				431	0-5-10	
				426	0-6-0	
				425	1-3-3	
				458	0-0-10	
				414	0-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				433	0–1–0	
				457	0–4–18	
				435	1–14–10	
				416	0–1–16	
				279	0–1–10	
				415	0–1–10	
				280	1–4–10	
				290	0–3–10	
				289	0–1–8	
				288	0–2–15	
				287	0–2–8	
				286	0–1–4	
				283	0–14–10	
				284	0–0–8	
				252	0–1–16	
				268	0–1–4	
				254	0–11–12	
				42	0–0–14	
				41	0–17–10	
				40	0–13–0	
				39	1–7–5	
				38	0–15–5	
				50	0–12–0	
				51	0–15–0	
				52	0–1–5	
				54	2–8–0	
				58	0–3–10	
				65	0–5–0	
				37	0–11–8	
				55	1–7–0	
				59	2–5–0	
				60	0–11–10	
				61	0–0–2	
				53	0–0–5	

[फा० सं० O-14016/369/85-जीपी]

S.O. 3042.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira Barilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares, its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U P

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Hajira Barielly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareilly	Awlah	Awlah	Daraw-nagar	480	0–2–8	
				481	0–15–0	
				466	2–2–0	
				465	0–13–5	
				467	0–0–15	
				468	0–0–15	
				474	0–5–0	
				473	0–6–0	
				472	0–6–0	
				471	0–12–0	
				469	1–6–8	
				462	0–1–10	
				431	0–5–10	
				426	0–5–0	
				425	1–3–3	
				458	0–0–10	
				434	0–1–0	
				433	0–1–0	
				457	0–4–18	
				435	1–14–10	
				416	0–1–16	
				279	0–1–10	
				415	0–1–10	
				280	1–4–10	
				290	0–3–10	
				289	0–1–8	
				288	0–2–15	
				287	0–2–8	
				286	0–1–4	
				283	0–14–10	
				284	0–0–8	
				252	0–1–16	
				268	0–1–4	
				254	0–11–12	
				42	0–0–14	
				41	0–17–10	
				40	0–13–0	
				39	1–7–5	
				38	0–15–5	
				50	0–12–0	
				51	0–15–0	
				52	0–1–5	
				54	2–8–0	
				58	0–3–10	
				65	0–5–0	
				37	0–11–8	
				55	1–7–0	
				59	2–5–0	
				60	0–11–10	
				61	0–0–2	
				53	0–0–5	

[No. O-14016/369/85-G.P.]

का. आ 3041.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये;

और यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ·

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी०-58-बी, अलीगंज लखनऊ-226 020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बरेली	आंवला	आंवला	कन्थरी	312	1-7-0	
			जाफर-	287	0-12-10	
			पुर	286	0-3-0	
				237	0-2-5	
				236	0-16-15	
				239	0-14-2	
				240	1-2-10	
				233	0-0-15	
				232	0-19-4	
				231	0-0-12	
				230	0-10-16	
				228	0-10-0	
				226	1-13-16	
				243	0-0-16	
				223	0-0-2	
				224	2-1-0	
				242	0-0-14	
				198	0-0-6	
				195	1-0-8	
				192	0-1-0	
				134	0-15-0	
				139	0-1-9	
				153	0-1-12	
				152	0-7-15	
				151	0-9-4	
				150	0-6-10	
				146	0-1-2	
				149	0-17-6	
				148	0-1-5	
				147	1-6-16	
				32	0-0-12	
				25	1-0-14	
				26	0-1-10	
				24	1-14-8	
				28	0-0-10	
				27	1-8-0	
				36	0-2-8	
				314	0-0-2	
				234	0-0-10	
				22	0-0-2	

[सं० O-14016/36 8/85-जी०पी०]

S.O. 3043.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira Barielly Jadishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Bareli	Awlah	Awlah	Kanthari	312	1-7-0	
			Jafarpur	287	0-12-10	
				286	0-3-0	
				237	0-2-5	
				236	0-16-15	
				239	0-14-2	
				240	1-2-10	
				233	0-0-15	
				232	0-19-4	
				231	0-0-12	
				230	0-10-16	
				228	0-10-0	
				226	1-13-16	
				243	0-0-16	
				223	0-0-2	
				224	2-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				242	0-0-14	
				198	0-0-6	
				195	1-0-8	
				192	0-1-0	
				134	0-15-0	
				139	0-1-9	
				153	0-1-12	
				152	0-7-15	
				151	0-9-4	
				150	0-6-10	
				146	0-1-2	
				149	0-17-6	
				148	0-1-5	
				147	1-6-16	
				32	0-0-12	
				25	1-0-14	
				26	0-1-10	
				24	1-14-8	
				28	0-0-10	
				27	1-8 0	
				36	0-2-8	
				314	0-0-2	
				234	0-0-10	
				22	0-0-2	

[No. O-14016/368/85 G.P.]

का. आ. 3044—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तरप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति, विनिर्दिष्टतया यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा (बीघो) में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायूं	बिसौली	बिसौली	रारेट—	1	0-06-15	
			गोविन्दपुर	2	0-01-00	
				3	0-00-10	
				4	0-00-10	
			योग	4	0-08-15 बीघा या (0 1107) हे.	

[सं० O 1-4016/367/85-जी०पी०]

S.O. 3044.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hazira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Bisauli	Bisauli	Raret	1	0-06-15	
			Govind-pur	2	0-01-00	
				3	0-00-10	
				4	0-00-10	
			Total	4	0-08-15 Bighas or (0.1107) Hect.	

[No. O-14016/367/84-G.P.]

का. आ. 3045—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तरप्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने के प्रयोजन क लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि म उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 1 दिनो के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाईप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स	लिया गया रकबा (बीघो) मे	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बदायू	दातागंज	सलेमपुर	सेरहा खाम	25	0—05—05	
				23	0—01—00	
				20	0—01—00	
				24	1—06—00	
				26	0—01—00	
				27	0—05—00	
				97	0—02—08	
				12	0—08—01	
				102	0—06—15	
				100	0—00—02	
				101	0—10—15	
				99	0—01—15	
				98	0—07—05	
				105	1—00—00	
				106	0—15—15	
				183	1—15—08	
				180	0—18—00	
				216	0—09—12	
				215	0—17—02	
				214	0—05—05	
				213	0—15—00	
				184	0—00—05	
				85/2	0—01—04	
				237	1—06—00	
				239	0—06—12	
				293/1	0—14—00	
				323	0—06—00	
				319	0—00—05	
				321	0—01—15	
				320	0—15—00	
				317	1—00—05	
				316	0—06—10	
				370	0—15—15	
				387	0—04—16	
				386	0—15—06	
				385	1—01—00	
				384	0—13—00	
				383	0—07—10	
				392	0—00—07	
				404	0—18—10	
				334	0—04—00	
				335	0—00—02	
				391	0—00—02	
				389	0—14—00	
				324	0—10—10	
				322	0—10—04	
			कुल योग	46	21—14—16 बीघा या (5 5002) है	

[स० O-14016/375/85 जीपी]

एम० एस० श्रीनिवासन उप सचिव

S O 3045 —Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H B J Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow 226020 U P

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Badaun	Data-ganj	Solempur	Serha kham	25	0 05-05	
				23	0 01—00	
				20	0—01—00	
				24	1—06—00	
				26	0—01—00	
				27	0—05—00	
				97	0—02—08	
				12	0—08 01	
				102	0 06—15	
				100	0 00—02	
				101	0—10—15	
				99	0 01—15	

1	2	3	4	5	6
				98	0–07–05
				105	1–00–00
				106	0–15–15
				183	1–15–08
				180	0–18–00
				216	0–09–12
				215	0–17–02
				214	0–05–05
				213	0–15–00
				184	0–00–05
				85/2	0–01–14
				237	1–06–00
				239	0–06–12
				293/1	0–14–00
				323	0–06–00
				319	0-00-05
				321	0-01.15
				320	0–15–00
				317	1–00–05
				316	0–06–10
				370	0–15–15
				387	0–04–16
				386	0–15–06
				385	1–01–00
				384	0–13–06
				383	0–07–10
				392	0–00–07
				404	0–18–10
				334	0–04–00
				335	0–00–02
				391	0–00–02
				389	0–14–00
				324	0–10–10
				322	0–10–04
			Total	46	21–14–16 (5.5002)

[No. O-4016/375/85/GP]
M. S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

का. आ. 3046:—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, तारीख 18 जून, 1983, में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2578, तारीख 31 मई, 1983 द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 7400.00 एकड़ (लगभग) या 2994.63 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि की बाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 जून, 1985 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

347 GI/85—24

अनुसूची

अशोक ब्लाक

(उत्तरी कर्णपुरा–कोयला क्षेत्र)

ड्राइंग सं. राजस्व/68/82

तारीख 5-10-1982

(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वर्णित की गई है)

क्रम. सं०	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	बालो	टंडवा	69/226	हजारी बाग	119.36	भाग
2.	बिजैन	"	83/240	"	370.00	भाग
3.	सिवालु	"	84/241	"	155.00	भाग
4.	पथांगी	"	86/243	"	250.00	भाग
5.	मराय	"	87/244	"	502.09	पूर्ण
6.	चिरलौंगा	"	88/245	"	217.00	भाग
7.	केलारा	"	89/246	"	810.00	भाग
8.	दैम्बुआ	"	90/247	"	397.56	पूर्ण
9.	मुलुम्बा	"	91/248	"	390.82	पूर्ण
10.	लुकूईया	"	92/349	"	550.23	पूर्ण
11.	तोरहाद	"	93/250	"	458.47	पूर्ण
12.	हेंजवा	"	94/251	"	988.83	पूर्ण
13.	कुटकी	"	95/252	"	1227.26	भाग
14.	बेस्ता	"	96/253	"	448.00	पूर्ण
15	कुटकी कुरदौर येना	"	97 254	"	515.39	भाग

कुल क्षेत्र : 7400.00 एकड़ (लगभग)
या 2994.63 हेक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन

क-ख रेखा बालो, चिरलौंगा और कोईनारा ग्रामों से होकर जाती है और फिर कोइलारा ग्राम में देमोनद या दामोदर नदी से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा देमोनद या दामोदर नदी की भागतः मध्य रेखा के साथ साथ जाती है (जो हजारीबाग और रांची की भागतः जिला सीमा है) और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा देमोनद या दामोदर नदी की भागतः मध्य रेखा के साथ साथ जाती है (जो हजारीबाग और रांची की भागतः जिला, सीमा बनाती है) और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ. रेखा देमोनद या दामोदर नदी की भागतः मध्य रेखा के साथ साथ जाती है (जो हजारीबाग और रांची की भागतः जिला सीमा बनाती है) और बिन्दु "ङ" पर मिलती है:

ङ.-च रेखा देमोनद या दामोदर नदी की भागतः मध्य रेखा के साथ साथ जाती है (जो हजारीबाग और रांची की भागतः जिला सीमा बनाती है) और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च-छ रेखा ग्राम बेन्ती में देमोनद या दामोदर नदी से होकर बेन्ती और कुटुकी ग्रामों से होकर जाती है (जो उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अर्जित पिपरवार ब्लाक की भागतः/सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ–ज रेखा ग्राम बेन्ती से होकर जाती है (जो उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अर्जित पिपरवार ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज -झ रेखा ग्राम बेन्ती से होकर जाती है और फिर कुटुके खुर्द या थेना और बेन्ती, बिजैन और बेन्ता, ग्रामों क भागत सम्मिलित स मा के साथ-साथ जाती है और फिर बिजैन और सिदालु ग्रामों से होकर जाती हैं और बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ -क रेखा सिदालु और थथांगे ग्रामों से होकर जाती है और फिर सराय और कलन्धर चिरलौंगा और कलन्धर, ग्रामों क सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और फिर ग्राम बाली से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 19/97/82-सं. एल./स . ए.]

MINISTRY OF STEEL MINES, AND COAL

(Department of Coal)

New Delhi, the 12th June, 1985

S.O.—3046 Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 2578, dated the 31st May, 1983, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 to 1957), and published in the Gazette of India dated the 18th June, 1983, the Central Government hereby gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 7400.00 acres (appoximately) or 2994.63 hectares (apprximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from 18th June, 1985, as the period within which the Central Government may give notice of its intension to acquire the said lands or over such lands.

SCHEDULE

Ashoke Block

(North Kalanpura Coalfield)

Drg. No. Rev/68/82
Dated 5-10-1982
(showing lands notified for prospecting)

Serial Number	Village	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1.	Bali	Tandwa	69/226	Hazaribagh	119.36	Part
2.	Bija	,,	83/240	,,	370.00	,,
3.	Sidalu	,,	84/241	,,	155.00	,,
4.	Thathangi	,,	86/243	,,	250.00	,,
5.	Saraya	,,	87/244	,,	502.09	Full
6.	Chirlaunga	,,	88/245	,,	217.00	Part
7.	Keilara	,,	89/246	,,	810.00	,,
8.	Dembua	,,	90/247	,,	397.55	Full
9.	Jhulunda	,,	91/248	,,	390.82	,,
10	Lukuia	,,	92/249	,,	550.23	,,
11.	Torhad	,,	93/250	,,	458.47	,,
12.	Henjda	,,	94/251	,,	988.83	,,
13.	Kutki	,,	95/252	,,	1227.26	Part
14.	Benti	,,	96/253	,,	448.00	Full
15.	Kutki Khurd or Thena	,,	97/254	,,	515.39	Part
			Total Area :	7400.00 Acres (approximately)		
			or	2994.63 hectares (approximately)		

BOUNDARY DESCRIPTION :

A—B line passes through villages Bali, Chirlaunga and Koilara then through River Deonod or Damodar in village Koilara and meets at point 'B'.

B—C line passes along the part Central line of River Deonod or Damodar (which is the part District boundary of Hazaribagh and Ranchi) and meets at point 'C'.

C—D line passes along the part Central line of River Deonod or Damodar (which forms part District boundry of Hazaribagh and Ranchi) and meets at point 'D'.

D—E line passes along the part Central line and River Deonod or Damodar (which forms part District boundary of Hazaribagh and Ranchi) and meet at point 'E'.

E—F line passes along the part Central line of River Deonod or Damodar (which forms part district boundary of Hazaribagh and Ranchi) and meets at point 'F'.

F—G line passes through River Deonod or Damodar in village Benti, through villages Benti and Kutki [which form part common boundary of Piperwar Block acquired under sub-section (1) of secton 9 of the said Act] and meets at pont 'G'.

G—H line passes through village Benti [which forms part common boundary of Piperwar Block acquired under sub-section (1) of section 9 of the said Act] and meets at point 'H'.

H—I line passes through village Benti, then passes along the part common bundary of village Kutkikhurd or Thena and Benti, Bijain and Benti, then passes through villages Bijain and Sidalu and meets at point 'I'

I—A line passes through villages Sidalu and Thathangi, then passes along common boundary of villages Saraya and Klandhar, Chirlaunga and Klandhar, then through village Bali and meets at starting point 'A'.

[No. 19/97/82-CL/CA]

का. आ. 3047.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2481, तारीख 19 जून, 1982 द्वारा जो भारत के राजपत्र, तारीख 10 जुलाई, 1984 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 394 एकड़ (लगभग) या 160 हैक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 2340 तारीख 5 जुलाई, 1984 द्वारा 10 जुलाई, 1984 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में से 394 एकड़ (लगभग) या 160 हैक्टर (लगभग) कोयला अभिप्राप्य है;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 394 एकड़ (लगभग) या 160 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का सभी अधिकारों सहित जैसाकि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पणी-1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. ए. जी. एम./XII/एम. आई. एस./81/227 तारीख 1 अगस्त 1981 का निरीक्षण उपायुक्त धनबाद (बिहार) के कार्यालय में या निदेशक (निगमित योजना और परियोजना) भारत कोकिंग कोल लि. कोयला भवन डाकघर-कोयला नगर, जिला धनबाद (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण-2 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :—

8(1) किसी ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी व्यक्ति की ओर से यह कहना आक्षेप नहीं माना जाएगा कि वह स्वयं किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जाँच यदि कोई है करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आक्षेपों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के संबंध में भूमि में हितबद्ध होने का विनिश्चय किया जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिया जाता।

टिप्पण-3 केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक 1 काउंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है

इंदकाटा ब्लाक]
रानीगंज कोयला क्षेत्र
उप-ब्लाक "क"
अनुसूची "क"

क्र. सं.	मौजा (ग्राम)	थाना सं.	पुलिस स्टेशन (थाना)	जिला	क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणियां
1	इंदकाटा	03	कुल्टी	बर्दवान	287.00	संपूर्ण

सभी अधिकार

कुल क्षेत्र : 287.00 एकड़ (लगभग)
116.194 हैक्टर

मौजा इंदकाटा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

सभी अधिकार

1सँ 086

सीमा वर्णन

क-ख रेखा, मौजा इंदकाटा की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु "ख" पर मिलती है

ख-ग रेखा, मौजा इंदकाटा की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा, मौजा इंदकाटा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु "घ" पर मिलती है।

घ-क रेखा, मौजा इंदकाटा की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु "क" पर मिलती है।

सालनपुर ब्लाक
रानीगंज कोयला क्षेत्र
उप-ब्लाक "ख"
अनुसूची "ख"

सभी अधिकार

क्रं. सं.	मौजा (ग्राम)	थाना सं.	पुलिस स्टेशन (थाना)	जिला	क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणियां
1.	सालनपुर	27	कुल्टी	बर्दवान	93.00	भाग
2.	नाकराजुरिया	26	कुल्टी	बर्दवान	14.00	भाग

कुल : 107.00 एकड़
(लगभग)
43.32 हैक्टर
(लगभग)

मौजा सालनपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

सभी अधिकार

31 (भाग), 34 (भाग), 68 (भाग), 69 (भाग), 70 (भाग), 72/73 (भाग), 74 से 81 84, से 92, 93 (भाग)! 94 (भाग), 95 से 99, 101, 119, 121, 122, 124, 126 से 129, 131 से 141, 142 (भाग), 143 (भाग), 145 से 156, 245 (भाग), 262, 264 (भाग), 267 (भाग), 357 (भाग), 358 (भाग), 359 से 361, 363, 340 (भाग), 342 (भाग), 34 , 44, 345 (भाग), 346 (भाग), 347 से 356, 366 से 505, 506, (भाग), 507, (भाग), 508 (भाग), 509, 510 (भाग), 511 (भाग), 519 (भाग), 520 से 549, 550 (भाग), 511 से 554, 555 (भाग), 2564 (भाग), 2565 (भाग), 2566 (भाग), 2567 (भाग), 2568 से 2585, 2586 (भाग), 2587 (भाग), 2588 (भाग), 2592, 2593 (भाग), 2594 (भाग), 2604, 2605 (भाग), 3014, 3023 और 3026।

मौजा नाकराजुरिया अर्जित किए जा वाले प्लाट सं.

सभी अधिकार

396 (भाग), 397 (भाग), 385, 387 (भाग), 388 (भाग), 898 (भाग), 899 (भाग), 900, 901 (भाग), 902, 904 (भाग), 986 (भाग), 1029 (भाग), 1028, (भाग), 1024, 1023 (भाग), 1022 (भाग), 1021, 1039 (भाग), 1020 (भाग), 1019 (भाग), 1018 (भाग), 1013 (भाग), 1017, 1016 1015, 1014, और 1042।

सीमा वर्णन :

ङ-च रेखा, प्लाट सं. 1018, 1020, 986, 1039, 1022, 1023, 1028, 904, 388, 387 में से होकर जाती है और बिंदु "च" पर मिलती है।

च-छ रेखा, प्लाट सं. 307, 397, 396, 899, 901, 1029 और प्लाट सं. 95, 96, 97, 382, 383, 384, 387, 388 389, 390, 391, 393, 129, 431, 440, 442 की पश्चिमी सीमा में से होकर जाती है और फिर प्लाट सं. 94, 450 में से होकर जाती है और बिंदु "छ" पर मिलती है।

छ-ज रेखा, प्लाट सं. 2586, 2587, 2588, 2589, 2591, 2593, 2604, 2605 में से होकर जाती है और बिंदु "ज" पर मिलती है।

ज-झ रेखा प्लाट सं. 2605, 2567 2566, 2565, 2564, 553, 554, 550, 518, 519, 511, 512, में से होकर जाती है और बिंदु "झ" मिलती है।

झ-ञ रेखा, प्लाट सं. 512 510, 508, 507, 506 340, 342, 3029, 345, 346, 267, 508, 264, 357, 358 245, 142, 143 144 और प्लाट सं. 145, 154, 155 156, 157 की पूर्वी सीमा में से होकर जाती है और बिंदु "ञ" पर मिलती है।

ञ-ङ रेखा, प्लाट सं. 0, 68, 69, 73, 74, 75, 32, 31, 1013, 1012, 1018 में से होकर जाती है और बिंदु "ङ" पर मिलती है

[सं. 43019/27/84-सी. ए.]

समय सिंह, अवर सचिव

S.O.3047. Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2481 dated the 19th June, 1982 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), published in the Gazette of India dated the 10th July, 1984, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 394 acres (approximately) or 160 hectares (approximately) of lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S. O. 2340 dated the 5th July,1984 under sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government specified a further period of one year commencing from the 10th July, 1984 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in 394 acres (approximately) or 160 hectares (approximately) out of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the lands measuring 394 acres (approximately) or 160 hectares (approximately), and all rights therein, as described in the schedule appended hereto,

Note 1. The plan No. AGM/XII/MIS/81/227 dated the 1st August, 1981 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Dhanbad (Bihar) or in the Office of the Director (Corporate Planning and project), Bharat Coking Coal limited, Koyla Bhawan, Post Office—Koyla Nagar, District Dhanbad (Bihar).

Note 2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (0 of 1957), which provides as follows;

"8 (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desire to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be decided to be interested in land who would be entitled to claim as interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3. The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

Indkata Block
Raniganj Coal Fields
Sub Block "A"
Schedule

All rights

S. No.	Mouza (Village)	Thana (number)	Police station (Thana)	District	Area in acres	Remarks
1	Indkata	03	Kulti	Burdwan	287.00	Full
				Total area :	287.00 acres (approximately) 116.194 hectares (approximately)	

Plot number to be acquired in Mouza Indkata

All Rights

1 to 986

Boundary description

A—B	Line passes along the western boundary of Mouza Indkata and meets at point 'B'.
B—C	Line passes along the southern boundary of Mouza Indkata and meets at point 'C'
C—D	Line passes along the eastern boundary of Mouza Indkata and meets at point 'D'.
D—A	Line passes along the northern boundary of Mouza Indkata and meets at point 'A'.

Salanpur Block
Raniganj Coal Fields
Sub Block 'B'
Schedule 'B'

All rights

S. No.	Mouza (Village)	Thana number	Police station (Thana)	District	Area in acres	Remarks
1.	Salanpur	27	Kulti	Burdwan	93.00	Part
2.	Nakrajoria	26	Kulti	Burdwan	14.00	part
					Total :	107.00 acreas (approximately) 43.32 hectares (approximately)

Plot numbers to be acqured in Mouza Salanpur
All rights

31 (Part), 32 (Part), 68 (Part), 69 (Part), 70 (Part), 72, 73 (Part), 74 to 81, 84 to 92, 93 (Part), 94 (Part), 95 to 99, 101 to 119 121, 122, 124, 126 to 129, 131 to 141, 142 (Part), 143 (Part), 145 to 156, 245 (Part),) 262, 264 (Part), 267(Part), 357 (Part), 358 (Part), 359 to 361,363, 340 (Part), 342 (Part), 343, 344, 345 (Part), 346 (Part), 347 to 356, 366 to 505, 506 (Part), 507 (Part), 508 (Part), 509, 510(Part), 511(Part), 519 (Part), 520 to 549, 550 (Part), 511 to 554, 555 (Part), 2564 (Part), 2565((Part), 2566 (Part), 2567 (Part), 2568 to 2585, 2586 (Part), 2587 (Part), 2588 (Part), 2592, 2593 (Part), 2594 (Part), 2604, 2605 (Part), 3104, 3023 and 3026.

Plots numbers to be acquired in Mouza Nakrajorai
All rights

396 (Part), 397 (Part), 385, 387 (Part), 388 (Part). 898 (Part), 899 (Part), 900, 901 (Part), 902, 904 (Part), 986 (Part), 1029 (Part), 1028 (Part), 1024, 1023 (Part), 1022 (Part), 1021, 1039 (Part), 1020 (Part), 1019 (Part), 1018 (Part) 1013 (Part), 1017, 1016, 1015, 1014 and 1042.

Boundary description

E—F	Line passes through plot nmbers 1018, 1020, 986, 1039, 1022, 1023, 1028, 904, 388, 387 and meets at point 'F'.
F—G	Line passes through plot numbers 387, 397, 396, 899, 901, 1029 and western boundary of plot numbers 95, 96, 97, 382, 383 384, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 429, 431, 440, 442 and through plot numbers 94, 450 and meets at point "G".
G—H	Line passes through plot numbers 2586, 2587, 2588, 2589, 2591, 2593, 2594, 2604, 2605 and meets at point "H".
H—I	Line passes through plot numbers 2605, 2567, 2566, 2565, 2564, 553, 554, 550, 518, 519, 511, 512, and meets at point "I'
I—J	Line passes through plot numbers 512, 510, 508, 507, 506, 340, 342, 3029, 345, 346, 267, 508, 264, 357, 358, 245, 142, 143 144 and Eastern boundary of plot numbers 145, 154, 155, 156, 157, and meets at point "J".
J—E	Line passes through plot numbers 70, 68, 69, 73, 74, 75, 32, 31, 1013, 1012, 1018 and meets at point "E".

[No. 43019/27/84-CA].
SAMAY SINGH, Under Secy.

आपूर्ति व वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 1985

का. आ. 3048:—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) के खंड 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ब्रह्म दत्त, संयुक्त विकास आयुक्त को, श्री ए. पी. भाटिकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (तमिलनाडू : 1966) के तमिलनाडू राज्य सरकार में परावर्तन होने के फलस्वरुप, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर में 16 जून 1985 से आगामी आदेशों तक के लिये सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री ब्रह्म दत्त, भारत सरकार, वस्त्र विभाग, हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय में संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) के अपने सामान्य कार्यभार के अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड बंगलौर के अस्थायी सचिव होंगें।

[फाइल सं. 25012 (39)/81-रेशम]

एन. एन. वासुदेव, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF SUPPLY & TEXTILES

(Department of Textiles)

New Delhi, the 17th June, 1985

S.O. 3048.—In exercise of powers conferred by Section 7 of Central Silk Board Act, 1948 (LXI of 1948) Shri Brahm Dutt, Joint Development Commissioner, is appointed as Secretary, Central Silk Board, Bangalore with effect from 16-6-85 and until further orders vice, Shri A. P. Bhatikar I.A.S. (TN : 1966) who has reverted to the State Government of Tamil Nadu from that date, Shri Brahm Dutt will hold the charge of Secretary, Central Silk Board, Bangalore temporarily in addition to his normal duties as Joint Development Commissioner in the office of the Development Commissioner (Handlooms) Department of Textiles, Government of India, New Delhi.

N. N. VASUDEV, Addl. Development Commissioner
[F. No. 25012(39)|81-Silk]

परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 29 अप्रैल, 1985

का. आ. 3049:—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस बारे में उनको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का

प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तारीख 26 फरवरी, 1974 के सा. आ. 752 के अधिक्रमण में, यह निदेश देते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग में अथवा उसके अंतर्गत सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "क" में शामिल किये गये केन्द्रीय सिविल पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में, उपर्युक्त नियमावली के नियम 11 की धारा (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट दंडों में से किसी भी दंड को अधिरोपित करने की शक्ति का प्रयोग "सचिव" द्वारा उपर्युक्त नियम के नियम 2 (1) में परिभारित के अनुसार किया जाएगा।

[सं. 2/2/82-सतर्क]

एस. पी. सिंह, उप सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 29th April, 1985

S.O. 3049.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of the Government of India in the Department of Atomic Energy notification S.O. No. 752 dated the 26th February, 1974, the President hereby directs that in respect of persons appointed to Central Civil Posts included in the General Central Service Gr. A in or under the Department of Atomic Energy, the power to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 11 of the said rules shall be exercised by the 'Secretary' as defined in rule 2(1) of the said rules.

[No. 2/2/82-Vig.]

S. P. SINGH, Dy. Secy.

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

(पुरातत्व)

का. आ. 3050.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संमारक राष्ट्रीय महत्व के हैं, अतः, अब, केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

ऐसे आक्षेप पर, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी किये जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारकों में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लाट संख्यांक	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
जम्मू-कश्मीर	पुलवामा	पुलवामा	पायेर	प्राचीन शिव मंदिर	सर्वेक्षण प्लाट सं. 563, 982/555 और 984/568	0.003 हैक्टर

सीमाएं (8)	स्वामित्व (9)	टिप्पणी (10)
उत्तर: सर्वेक्षण प्लाट सं. 985/568 पूर्व: सर्वेक्षण प्लाट सं. 985/568 और 983/556 दक्षिण: सर्वेक्षण प्लाट सं. 983/556 पश्चिमी: सर्वेक्षण प्लाट सं. 983/556 और 985/568	आहली हिन्दू	धार्मिक उपयोग में नहीं है।

[सं. 2/7/85-एम.]

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archeological Survey of India)

New Delhi, the 12th June, 1985

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 3050.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within period of two months from the date of issue of this Notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be taken in to consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Owner-ship	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jammu and Kashmir	Pulwama	Pulwama	Payer	Ancient Siva Temple	Survey plot Nos. 563, 982/556 and 984/568	0.003 Hectares	North.—Survey plot No. 985/568 East.—Survey plot Nos. 985/568 and 983/556 South.—Survey plot No. 983/556 West.—Survey plot Nos. 983/556 and 985/568.	Ahli Hindu	Not in religious use.

[No. 2/7/85-M]

का. आ. 3051.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त स्थान में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लाट संख्यांक	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	धौलपुर	धौलपुर	झोर	प्राचीन संरचनाओं से लगा हुआ बाबर के बाग का स्थल	सर्वेक्षण प्लाट संख्यांक 73 से 158	63 बीघे और .03 बिस्वा

सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणी
8	9	10
उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं. 68, 68/395 68/396 पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट सं. 160, 161, 162, 187, 198, 199, 200 और सर्वेक्षण प्लाट सं. 321/385 का भाग दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट सं. 322, 323 और सर्वेक्षण प्लाट स. 321/385 का भाग पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट सं. 69, 70,, 71 और 72	सर्वेक्षण प्लाट सं. 73, 79, 88, 107, 110 116, 117, 122, 129, 131, 141, 147, 155 और 158 सरकार के स्वामित्वाधीन है और शेष सर्वेक्षण प्लाट निजी स्वामित्वाधीन है।	आधुनिक संरचना के साथ-साथ निजी स्वामित्वाधीन क्षेत्र को अर्जित करने की प्रस्थापना की गई है

[सं. 2/10/85-एम.]

एम एस. नागराजराव, महानिदेशक और पदेन संयुक्त सचिव

S.O. 3051.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient site specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient site to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient site will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of site	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rajasthan	Dholpur	Dholpur	Jhor	Site of Babur's Garden along with ancient structures	Survey plot Nos. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 and 158.	63 Bighas and .03 Biswas	North.—Survey plot Nos. 68, 68/395, 68/396 East.—Survey plot Nos. 160, 161, 162, 187, 198, 199, 200 and a portion of survey plot No. 321/385 South.—Survey plot Nos. 322, 323 and portion of survey plot No. 321/385 West.—Survey plot Nos. 69, 70, 71 and 72	Survey plot Nos. 73, 79, 88, 107, 110, 116, 117, 122, 129, 131, 141, 147, 155 and 158 are Government owned and remaining survey plots are privately owned.	Area under private ownership along with modern structure is proposed to be acquired

[No. 2/10/85-M].

M. S. NAGARAJA RAO, Director General and Ex-Officio, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 4 जून, 1985

का. आ. 3052 :—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4 के साथ पठित वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्व श्री गुरुदास कामत, जुल्फिकार अली खान, सी. माधव रेड्डी और श्रीमती उषा-बेन राघवजी ठक्कर, लोकसभा सदस्य और डा० जोसेफ लियोन डीसूजा, राज्य सभा सदस्य को राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और इसके लिए का. आ. सं 2243 दिनांक 2/7/84 (14.7.1984) के राजपत्र में प्रकाशित) द्वारा यथासंशोधित भारत सरकार नौवहन और परिवहन (नौवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 3931 दिनांक 20 सितम्बर 1983 (15 अक्टूबर, 1983 के राजपत्र में, प्रकाशित) में पुनः संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद सं. 2,3,4,5 और 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित रखे जायेंगे, अर्थात् :—

2. श्री गुरुदास कामत	लोक सभा द्वारा चुने गये।
3 श्री जुल्फिकार अली खान	
4. श्री सी. माधव रेड्डी	
5. श्रीमती उषाबेन राघवजी ठक्कर	

6. डा. जोसेफ लियोन डीसूजा) राज्यसभा द्वारा चुने गए

[फा. सं. –एसएम/एमएसबी– 5/82 एमएफ (एसएल)]

डी. डी. सूद, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Shipping Wing)

New Delhi, the 4th June, 1985.

S.O. 3052.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with rule 4 of the National Shipping Board Rules, 1960, the Central Government hereby appoints Sarvashri Gurudas Kamat, Zulfiquar Ali Khan, C. Madhav Reddy and Shrimati Ushaben Raghavji Thakkar, Members of Lok Sabha and Dr. Joseph Leon D'Souza, Member of Rajya Sabha to be the members of the National Shipping Board and for that purpose further amends the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Shipping Wing) S.O No. 3931 dated the 20th September, 1983 (published in the Gazette dated 15th October, 1983) as amended by S.O.No. 2243 dated 2-7-1984 (published in the Gazette dated 14-7-1984) as follows namely :—

In the said notifications, for items 2, 3, 4, 5 and 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely

2. Shri Gurdas Kamat 3. Shri Zulfiqaar Ali Khan 4. Shri C. Madhav Reddy 5. Shrimati Ushaben Raghavji Thakkar	Elected by the Lok Sabha
6. Dr. Joseph Leon D'Souza	Elected by the Rajya Sabha.

[File No.SM/MSB-5/82—MF(SL)]

D. D. SOOD, Under Secy.

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 11 जून, 1985

का. आ. 3053.—चूंकि कैप्टन डी. प्रसाद को बंबई डाक लेबर बोर्ड में (जिसे इसके बाद उक्त बोर्ड कहा गया है) गोदी श्रमिकों के नियोक्ताओं और नौवहन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का. आ. 756 (अ) दिनांक 21 अक्टूबर 1982 के तहत नियुक्त किया गया था,

और चूंकि इंडियन नैशनल शिपओनर्स एसोसियेशन ने अब कैप्टन डी. प्रसाद के स्थान पर कैप्टन सी. पी. अलेक्जेंडर को गोदी श्रमिकों के नियोक्ताओं और नौवहन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामजद किया है,

और चूंकि इस प्रकार उक्त बोर्ड में एक स्थान रिक्त हुआ है, इसलिए अब केन्द्रीय सरकार गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (5) के खंड (V) के अनुसरण में उक्त रिक्ति की अधिसूचित करती है।

[फा. सं. –एलडीबी/6/82–यूएम (एल) (1)]

सुदेश कुमार, अवर सचिव

(Transport Wing)

New Delhi, the 11th June, 1985

S.O. 3053.—Whereas Captain D. Prasad was appointed as a member of the Bombay Dock Labour Board (hereinafter referred to as the said Board) representing the Employers of Dock Workers and Shipping Companies by the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 756(E) dated the 21st October, 1982;

And whereas the Indian National Shipowners' Association has since nominated Captain C. P. Alexander vice Captain D. Prasad to represent the employers of the Dock Workers and Shipping Companies on the said Board;

And whereas a vacancy has thus occurred in the said Board;

Now, therefore, in pursuance of clause (v) of sub-rule (5) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government, hereby notifies the said vacancy.

[F. No. LDB|6|82-US(L)(I)]

SUDESH KUMAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जून, 1985

का. आ. 3054 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लि. के मुख्यालय के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक और उनके कर्मकार के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 6-6-1985 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 10th June, 1985

S.O. 3054.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Headquarters of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th June, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 76 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Headquarters of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri G. Prasad, Advocate.
On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary, R.C.M.S., Dhanbad.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 31st May, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(287)/84-D.III (A) dated the 25th October, 1984.

SCHEDULE

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that the management of the Headquarters of M/s. Bharat Coking Coal Limited should give to their Survey Apprentices mentioned in the Annexure below who are working in the colliery mentioned against each of them, Category I wages with fringe benefits and allowances, is justified ? If so, to what relief are these Survey Apprentices entitled and from what date ?"

ANNEXURE

1. Shri Chhotelal Yadav—Kendwadih Colliery
2. Shri Anil Kumar—Moonidih Project
3. Shri Amal Kanti Laha—Dobari Colliery
4. Shri Ashok Kumar—North Tisra Colliery
5. Shri Kameshwar Yadav—Patherdih Colliery
6. Shri Anil Kumar Gupta—Putkee Balihari Project.

The case of the workmen is that all the six concerned workmen named in the schedule of the order of reference had passed from ITI and were engaged by the management of BCCL in Survey department and were posted in different establishment The management were wrongly treating the concerned workmen and several other workman who were appointed with them as Apprentices and were being paid consolidated fixed sum of Rs. 150 or Rs. 200 per month as the case may be. The concerned workmen were put on independent job of Survey in their respective places of posting and were performing the duties of 8 hours per day in one complete shift totalling 48 hours in a week like all other workmen of the establishment where they were posted. The concerned workmen are entitled to be treated as regular workmen in view of their qualification and the nature of job performed by them. The management by their own action have accepted the aforesaid principle and have introduced time rated wages to a number of similar workmen but the management have refused the said time rated wages to the concerned workmen. By an Office order dated 5-11-82 issued by Shri A. A. Zafri, Dy. Chief Personnel Manager (R), the period of apprenticeship of the 22 persons including the 6 concerned workmen were extended for a further period of six months and they were to be paid stipends. By another Office order dated 30-9-83 Shri C. Choubey, Dy. Personnel Manager regularised the services of 9 similar workmen in time scale of Cat. I rate of wages and allowances and their service conditions were to be governed like other employees under NCWA-II but 6 concerned workmen were not so regularised. No reason was assigned by the management as to why the concerned workmen were not regularised. The union of the workmen namely RCMS raised the issue with the BCCL Headquarters management but without any effect. The union by letter dated 7-1-84 raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad who took the matter. During the course of discussion before the ALC(C) the representative of the management desired to settle the issue by mutual negotiation and on that assurance the union withdrew the case before the ALC(C) but the management went back to their assurance of settlement of the dispute by mutual negotiation. The union again raised the industrial dispute before the ALC(C) Dhanbad by letter dated 2-4-84 and the ALC(C) invited the parties for discussion and subsequently held the conciliation proceeding which ended in failure due to the adamant attitude of the representative of the BCCL management. The ALC(C), Dhanbad submitted the report of failure of conciliation to the Ministry of Labour and thereafter the present reference was made for adjudication. It is further contended that there is no provision under the Apprenticeship Act and also the syllabus under the National Council of Vocational training under the said Act for imparting training as Survey Apprentice and as such the concerned workmen are not apprentices as per the Apprenticeship Act and that as per Coal Wage Board Recommendation and NCWA the concerned workmen should get Cat. I wages from the date of their appointment. It is submitted that the concerned workmen are entitled to be regularised in time rated Cat. I wages and other allowances as are admissible to similar regular employees of BCCL under NCWA-II with other consequential benefits with effect from 30-9-83.

The case of the management is that the reference is not legally maintainable in as much as the workmen have been demanding promotion from apprenticeship to be regularise workmen. The concerned workmen were appointed as apprentices under the Apprenticeship Act, 1961 and as such they are not "Workmen" under the Industrial Disputes Act, 1947 and as such the reference is not maintainable. There was no condition in the terms of appointment that the concerned workmen shall be paid Cat. I wages after completion of the Apprenticeship period. The employment of a number of apprentices has since been terminated after completion of the training and they are no longer in the employment. As the concerned workmen are apprentices they were being paid stipend payable under the Apprenticeship Act. There is no such condition in the terms of employment of the concerned workmen that the apprentices shall be automatically employed as workmen of the Company. It is a function of the management to employ an apprentice as a workmen. It is not obligatory under the Apprentices Act for an employer to employ or regularise a workman. The concerned workmen do not fulfil the requisite qualifications and experience and as such they are not entitled to be regularised as workmen. The concerned workmen cannot claim wages of Cat. I unless they are employed and regularised. The management did not agree to settle the dispute in the conciliation proceeding. On the above plea it is submitted that the demand of the concerned workmen is not justified and that they are not entiled to any relief.

The point for consideration in this case is whether the concerned workmen are entitled to Cat. I wages with fringe benefits and allowances.

The point for consideration in this case is whether the out of the six concerned workmen. The management have examined two witnesses out of whom MW-1 is the Dy. Personnel Manager and MW-2 is an Assistant and is a formal witness and has proved Ext. M-20. Besides that, the union have exhibited two documents which are marked Ext. W-1 and W-2. The management have produced several documents which have been marked Ext. M-1 to M-20. Ext. W-1 dated 5-11-82 is an Office order issued by the Dy. Chief Personnel Manager of BCCL which shows that 22 ITI boys (Survey) were taken in training as Survey Apprentice for 2-1/2 years and that their apprenticeship of 2-1/2 years completed and they were further allowed 6 months extension of training to pass the DGMS Survey competancy examination. The said extension of 6 months was to expire on 30-4-83. It is further stated in Ext. W-1 that no further extension beyond 30-4-83 was to be allowed and that during the extended period of training the 22 persons were to get some stipend as was being paid to them on the date of their termination. All the five witnesses examined on behalf of the union have stated that even after the expiry of 6 months period, they continued to work till October, 1983 and they were stopped from 31-10-83. Ext. W-1 includes the name of the 6 concerned workmen and as such it is clear that the concerned workmen were taken in training vide Ext. W-1 and that as stated by them they continued working till the termination on 31-10-83, Ext. M-4 dated 10-5-83 is an Office order which shows that the training of the concerned workmen and others were further extended for a period of 6 months from 1-5-83 and that the extension of 6 months was to expire on 31-10-83 and that no further extension beyond 31-10-83 was to be allowed and they were to get the same stipend as was being paid on the date of their termination. It is clear therefore that the period of training was extended by the management till 31-10-83. Ext. M-11 to M-19 are the letters of appointment as Survey Apprentices under the Apprenticeship Act issued to the concerned workmen and some other persons who were appointed as Apprentices. It will appear from the terms of appointment that after satisfactory completion of the training and on obtaining Surveyor's certificate of competency from the Department of Mines they were to be placed in appropriate grade of the Asstt. Surveyor as per Wage Board Recommendation/NCWA and in case of their failure is obtain the aforesaid certificate of competency they were to be given extension of 6 months to enable them to obtain the said certificate and even after extended period of training they fail to obtain the certificate the management shall terminate their apprenticeship without giving any notice. Their service conditions were to be governed as recommended by the Wage Board and accepted by the Government of India and

adopted by the management and further revised by the NCWA. They were to be treated as whole time employees of the Company and were to be employed in any manner required in connection with the work of the Company. Thus the terms and conditions of service of the concerned workmen and other persons who were appointed as apprentice has been stated in their appointment letters.

Ext. W-2 is an Office order dated 30-9-83 by which 9 of the survey trainees were regularised in Cat. I wages in the scale of Rs. 15.00-0.26-18.12 per day. It is further stated that these 9 trainees will be further placed in the scale/grade suitable to them in the event of their passing the requisite examination. These 9 trainees are included in Ext. W-1 along with the concerned workmen. There is no evidence adduced on behalf of the management to show the circumstances in which these 9 trainees named in Ext. W-2 were regularised and given Cat. I wages. There is also no evidence to show as to why the concerned workmen were not regularised along with the other 9 trainees. The concerned workmen have stated in their evidence that the selection was made for regularisation in Cat. I and that no information had been given to them at the time of regularisation in Cat. I MW-1 is quite silent on this point. He has stated in his cross-examination that there is a policy of training of apprentices in the BCCL but the said paper has not been filed to show as to what were the policies of training of apprentices in the BCCL. MW-2 has only proved Ext. M-20 and has not stated anything regarding the facts of the case.

It will appear from the evidence of MW-1 that the management have created a scheme of their own for the training of apprentices in the BCCL. The same has not been produced. If the management have created a scheme of their own for training of apprentices the management have to be governed by any of the pay scales obtainable in the coal industry because such unrecognised apprentices for all purposes and are regular employees shown as apprentices by the management. Ext. M-1 which is the same as Ext. W-2 will show that out of 22 apprentices named in Ext. W-1 only nine regularised in Cat. I with immediate effect. This office order shows that 9 trainees were regularised in Cat. I which means that they were already working in the said Category. They were to be placed in a suitable grade and scale on passing the requisite examination. It is nowhere stated that these 9 trainees had passed Surveyor's certificate of competency examination. The management has tried to show that the concerned workmen were not regularised or given Cat. I scale as they did not pass Surveyor's certificate of competency examination. If that was so there is no evidence that the 9 trainees who were regularised in Cat. I vide office order Ext. M-1 had passed the Surveyor's certificate of competency from the department of mines. Thus the position of the concerned workmen were almost the same as that of the 9 trainees who were regularised in Cat. I. It has been stated that all the 22 trainees were doing the same type of work and as there is no evidence to the effect that the 9 trainees were specifically found suitable by any competent authority, there was no reason for not treating the concerned workman as the 9 trainees have been treated vide Ext. M-1. Admittedly the concerned workmen had passed the survey examination from the ITI prior to their appointment as Survey apprentices in the BCCL and they were posted in different establishment, as has been mentioned against their respective names in the annexure to the schedule of the order of reference. It is asserted that the concerned workmen were put on independent job of survey in their respective places of posting and were performing the duties like all other workmen of the establishment. The management has by their own order accepted vide Ext. M-1 that the trainees were working independently in the establishment and as such the 9 trainees were regularised in Cat. I and there is no reason as to why the concerned workmen were not regularised in Cat. I. Ext. M-2 has been produced to show that Sarit Sudha Sarkar was granted certificate of competency after passing the examination held in December, 1981 but there is no evidence to show that other eight trainees regularised vide Ext. M-1 had passed their certificate of competency. Ext. M-3 dated 23-1-85 shows that Anil Kumar (one of the concerned workmen) inspite of the extension of period of apprenticeship failed to pass the D.G.M.S. certificate competency examination and his apprenticeship was terminated from the afternoon of 28-1-85. It appears, therefore, that the management was terminating the apprenticeship of the concerned workmen as they failed to pass the D.G.M.S. Survey Competency examination. There is no evidence to the effect that the 9 apprentices except Sarit Sudha Sarkar had passed the D.G.M.S. Survey Competency examination and as such there appears to be different ation between the concerned workmen and the trainees who were regularised in Cat. I. As the 9 trainees were regularised in Cat. I, I think that the concerned workmen whose case also stand; in the similar footing should also get Cat. I wages which is the minimum wage of the Category in which they are asked to work and they cannot get less than the minimum wage which is suggested by the Wage Board to an unskilled workman. At page 200 of the Compendium of the circulars issued by JBCCL (NCWA-II) the cadre scheme for the Mining Survey personnel is stated. The cadre scheme for mining survey personnel has been categorised in two groups. In Group-B there is one Head Chairman in technical Grade-E (Survey) (2) Chairman technical Grade-E (Survey) and (3) Survey Mazdoor Cat. I scale of pay @ Rs. 15.00-18.12. The minimum educational qualification for survey mazdoor in Cat. I is literate with aptitude for survey work. Thus no DGMS certificate of competency is required for Cat. I for Survey mazdoor and when 9 persons were appointed as Survey Mazdoor in Cat. I vide Ext. M-1 there was no reason as to why the concerned workmen were also not regularised in Cat. I along with 9 trainees.

It has been submitted on behalf of the management that the concerned workmen were apprentices under the apprenticeship Act, 1961 and as such they are not the workmen as defined under Section 2(s) of the I.D. Act and accordingly the reference was bad. It is true that the concerned workmen were taken as trainees under the Apprenticeship Act but as discussed above it will appear that the concerned workmen as well as other trainees were actually working as Survey Mazdoors and as such nine out of them were regularised in Cat. I. The concerned workmen were also doing the same job as that of the 9 trainees who were regularised in Cat. I and as such the concerned workmen were also working as Survey Mazdoors and they were not apprentices and they were actually workmen of the management.

In view of the discussions made above the concerned workmen who were actually working in the Colliery are entitled to Cat. I wages with fringe benefits and allowances with effect from 30-9-83. As the concerned workmen were not apprentices on the date of the termination the termination of their work with effect from 31-10-83 was not justified because of the fact that they were the workmen of the management and the stoppages of their work with effect from 31-10-83 without going into the formalities was not justified. The concerned workmen, therefore are entitled to be reinstated as Survey Mazdoors in Cat. I from the date of their termination with full back wages and other benefits accruing to them.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(287)/84-D.III (A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 1985

का.आ. 3055.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, संगरुर, के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजक और उसके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अधिकार, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 जून 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 11th June, 1985

S.O. 3055.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Sangrur, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th June, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CHANDIGARH

Case No. I.D. 20/84

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India-Punjab Region, Chandigarh.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Sh. Mangu Ram

For the Workmen—Sh. P. K. Singla

INDUSTRY : Food Corporation of India STATE : Punjab

AWARD

Dated the 3rd of June, 1985

The Central Govt., Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-42012(13)/83-D.IV(B)/D.V. dated the 22nd of May and 12th of December, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication.—

(i) 'Whether the management of Food Corporation of India in relation to their Distt. Manager, Sangrur is justified in refusing to regularise the services of the 20 workman as mentioned in Annexure 'A' who are working continuously since the dates indicated against each ? If not to what relief are the concerned workmen entitled?

(ii) Whether the action of the management of FCI in relation to their Distt. Manager, Sangrur in terminating the services of Shri Jagdev Singh S|o Shri Kapoor Singh with effect from 31-1-83 in violation of Sec. 25G and the services of the 17 workmen as mentioned in Annexure 'B' in violation of Sec. 25-F, is justified ? If not, to what relief are the concerned workman entitled?"

S.No.	Name of the Workmen	Date of Appointment
1	2	3
	S/Shri	
1.	Gurmad Singh S/o Sh. Bhan Singh	25-11-82
2.	Tersem Singh S/o Sh. Jangir Singh	25-11-82
3.	Darshen Singh S/o Sh. Joginder Singh	1-3-82
4.	Gurdev Singh S/o Sh. Bachan Singh	30-10-81
5.	Nirmal Singh S/o Sh. Gurbaksis Singh	26-11-82
6.	Nanu Ram S/o Sh. Ganga Ram	26-11-82
7.	Jogga Singh S/o Sh. Nachhatar Singh	1-1-80
8.	Chand Singh S/o Booh Singh	22-10-80
9.	Surjit Singh S/o Sarwan Singh	15-10-81
10.	Hari Singh S/o Sh. Ganda Singh	22-1-82
11.	Harjinder Singh S/o Sh. Sarwan Singh	18-12-81
12.	Harcharan Singh S/o Sh. Mohinder Singh	22-10-80
13.	Ram Singh S/o Sh. Nand Singh	24-3-82
14.	Jasbir Singh S/o Sh. Ranjit Singh	16-10-81
15.	Jaswant Singh S/o Sh. Hardem Singh	5-11-81
16.	Baljit Singh S/o Sh. Bharpur Singh	12-9-79
17.	Sukhinvender Singh S/o Sadhu Singh	11-3-82
18.	Baldev Singh S/o Sh. Joginder Singh	1-6-82
19.	Krishan Gopal S/o Sh. Charanjit Chopra	15-11-81
20.	Surjan Singh S/o Sh. Sadhu Singh	15-11-81
21.	Bant Singh S/o Sh. Jaggat Singh	15-9-79
22.	Hakam Singh S/o Sh. Lakhmir Singh	28-4-81
23.	Ram Lal S/o Sh. Bawa Singh	21-9-79
24.	Sukhpa Singh S/o Sh. Gopi Singh	23-10-80

ANNEXURE 'B'

S.No.	Name of the Workmen	Date of Appointment	Date of Termination
	S/Shri		
1.	Kuldip Singh S/o Sh. Kartar Singh	14-11-78	1-3-83
2.	Bhagwan Singh S/o Sh. Simla Singh	25-1-82	24-8-83
3.	Madan Lal S/o Sh. Chatta Ram	1-10-79	4-2-83
4.	Ranjit Singh S/o Sh. Bachan Singh	5-2-82	31-1-83
5.	Bhagwan Singh S/o Sh. Partap Singh	16-6-81	24-5-83
6.	Harbans Singh S/o Sh. Bachan Singh	1-6-81	31-1-83
7.	Nachhatar Singh S/o Sh. Ujagar Singh	20-1-79	1-3-83
8.	Jagdev Singh S/o Sh. Kapoor Singh	15-6-82	31-1-83
9.	Darshan Singh S/o Sh. Ujagar Singh	4-12-81	1-3-83
10.	Gain Singh S/o Sh. Ujagar Singh	17-10-80	1-3-83
11.	Sukchain Singh S/o Sh. Sampurar Singh	3-3-82	31-1-83
12.	Nachhater Singh S/o Sh. Ujagar Singh	29-5-80	24-5-83
13.	Amrik Singh S/o Hari Singh	24-1-82	31-1-83
14.	Ranjit Singh S/o Narangan Singh	5-11-80	31-1-83
15.	Malik Singh S/o Chetta Singh	14-10-80	31-1-83
16.	Kulwant Singh S/o Sh. Hazzera Singh	13-3-81	1-3-83
17.	Surinder Singh S/o Sh. Kartar Singh	17-1-79	24-5-83
18.	Balwant Singh S/o Sh. Jagar Singh	16-12-80	6-11-83

2. Brief facts of the case, according to the petitioner-workmen are that the Respdt. Corporation was involved in the industrial activity of purchase, sale, distribution and

storage of food grains in various parts of the state of Punjab through its district level depots and that they were employed by it as Casual-watchmen under the immediate charge of the Distt. Manager Sangrur. As a matter of fact about 4,000 Casual Watchmen were engaged on such depots under the Respdt. Corporation and out of them about 3,000 were on the regular strength whereas the remaining were being banded as 'Casuals' and because of the inferior nature of their status as 'Casuals' were being denied the regular pay scales and other fringe benefits usually accorded to their collegues working on the regular cadre strength. They complained that even though the Corporation required a large number of regular hands yet it was deliberately keeping them on the Casual-list and discriminating against them in the context of payment of wages despite the fact that they were doing exactly the same type of job both quantity wise as well as quality wise, as was being done by the regulars.

3. Forced by the circumstances the petitioners raised an issue before the Conciliation Officer for regularisation of their services and even as the matter was under consideration with him the Management terminated the services of some of them viz; Kuldip Singh and others as enumerated in annexure 'B' of the aforesaid Schedule of reference; in gross violation of the mendatory provisions of sections 25-F; 25-G; 25-H and 25-N of the Act.

4. The petitioners' Union, therefore, raised a demand on the Management of the Respdt. Corporation for regularising their services and also for the reinstatement of those, who had been illegally disengaged, as stated above, but the Management was found unresponsive desplte the intervention of the ALC(C) at the Conciliation Stage and hence the Reference.

5. Resisting the proceedings, the Management denied any relationship of master and servant between the parties it rather avered that the petitioners were drawn on loan basis from the Punjab Home Guards to supplement the Watch and Ward Staff on Open Storage Complexes and were paid wages for the particular days they worked there in accordance to the rates approved by the Deputy Commissioners concerned. Elaborating its cause the Management contended that on liquidation of the food grain stocks lying in the Open, surplus Casual Watchmen were repatriated to their parent Deptt. i.e. Punjab Home Guards before reference by the Appropriate Government. In short, the Management pleaded the futility of the petitioners' cause.

6. In support of their respective versions both the parties adduced verbal as well as documentary evidence, which I have carefully perused and heard them. The burden of the argument raised on behalf of the Mangement was that there was no master servant relationship between the parties and that otherwise also the petitioners were employed only on casual basis which did not qualify them as "workmen" to claim a reference to the Tribunal.

7. The objection against the petitioners locus-standi does not require any serious attention because the definition of "workman" as laid down in section 2(s) of the Act ibid is wide enough to include even the Casual-work force. For my views I draw support from the observations in the cases of Pilot Pen Company (Ind). Pvt. Ltd. Vs. Presiding Officer Additional Labour Court 1971 (1) LLJ 241, and Crompton Engg. Co. Madras P. Ltd. Vs. Additional Labour Court Madras 1975 (I) LLJ 207.

8. Similarly the submission that there was any inherent lack of master servant relationship between the parties is also devoid of force. Even though it was urged that the petitioners were employees of Punjab Home Guards and were working under the Corporation on loan or deputation basis yet the Management's own witness Sh. T. R. K. Murti, District Manager, conceded in his cross-examination that they did not have any rule to draw Class IV employees of other departments on loan or deputation. Obviously no service terms or conditions were prescribed, and reduced into writing even when the petitioners were allegedly drawn from the Punjab Home Guards.

9. Otherwise also, there are certain time honoured fundamentals to decide the proposition of somebody's working on deputation. To be precise, there has to be a parent department and borrowing Organisation who wants to utilise the services of an employee of the former for some limited purpose or period. Necessarily, it requires the consent of all the three parties, including the concerned employee whose tenure and service conditions, while working on deputation, are then settled and fixed on mutual agreement : all the same his roots keep on sticking to the parent department in the form of lien against the original post and that is how that normally temporary employees are not sent out on deputation. Significantly enough, in the case in hand, it was not even suggested by the Management that the petitioners were a consenting party to such an arrangement. Similarly their appointment letters containing the terms and conditions of the alleged deputation should have also been prepared and shown to the Tribunal. But it was not to be and the reasons are not far too difficult to seek.

10. Be that as it may, the matter has already been finally settled between the parties by this Tribunal in yet another similar dispute relating to the matter of Labh Singh and others per I.D. No. 18 of 1983 decided on 29th Sept. 1984; a certified copy thereof was fixed by the petitioners as Exb. W12. The same very question again arose in yet another dispute between the Respdt. Corp. and its workmen Jai Dev and Others per I.D. No. 17 of 1983 decided on 22nd of November, 1984. (Exb. W55). Both these Awards have since been accepted by the Appropriate Government and published in the Gazette. After examining various aspects of the issue the Tribunal had concluded therein that there was a meaningful relationship of Master and Servant between the parties and that the petitioners being "workmen" within the province of Section 2(s) of the Act were elligible to agitate their service conditions before the Tribunal on a reference under section 10 of the I.D. Act. It was further held therein that the Punjab Home Guards had acted only as a conduit in Sponsoring them for recruitment as Casual Watchmen by the Respdt. Corporation otherwise the former never held any control on their work and conduct, and that by no stretch of imagination it could ever assume the powers and pedestal of their Employer.

11. Neither of these Awards have yet been avoided by the Respdt. Corporation by any legal process and hence they would be deemed to be binding on it both under the concept of estoppel and resjudicate. As a necessary consequence it, therefore, follows that the petitioners were the employees of the Respdt. Corporation.

12. Before dealing with the issue contained in the first part of the terms of reference I would like to dispose of its 2nd part because in case the termination of the concerned employees is set aside they may also be effected by the Award relating to the Unions demand for regularising their services.

13. Significantly enough there is no denial of the fact that barring Sh. Jagdev Singh S/o Kapoor Singh all the Workmen mentioned in Annexure B of the Schedule had put in more than of one year's continuous service within the meaning of section 25-B before their impunged disengagement and that neither any terminal benefit nor any advance notice was given to them by the Management. Therefore, keeping in view the ratio of the case of State Bank of India Vs. N. Sundramani (1976) 1 Supreme Court Cases 822 and Mohan Lal Vs. Bharat Electronics Ltd. (1981)-3 Supreme Court Cases 225, their terminations would be deemed to be honest.

14. That directly confronts the Tribunal with the crux of the matter as to how far the petitioners are justified in demanding the regularisation of their services after having put in more than 240 days of work in the regular scale of Casual Watchmen.

15. On behalf of the management it was strenuously argued that in the very nature of things it could not possibly regularise the services of the petitioners because its dominant activity of purchase, sale and distribution of food grains was seasonal; and that the work load always keeps on fluctuating from crop to crop. In the same sequence it was propounded that the retention of a large number of Watchmen during the non-harvesting season could have serious reprecussions on its limited financial resources.

16 Despite seeming attraction the submission failed to carry conviction with me. The pertinent point is that according to the common case of the parties the petitioners were working for the Respdt. Corporation since the year 1981, it not from an earlier stage. I do appreciate the seasonal nature of the Coropration's business but what defied logic is, as to then what for it kept on retaining them all round the year, including the lean periods when the activity of the purchase and sale of foodgrains is reduced to the minimal level ? It rather shows that the Corporation requires a large number or watchman for its multifarious assignments including distribution, upkeep and security of the stored staff.

17. One cannot loose sight of the fact that the Respdt. Corporation is miniature-incarnation of a Welfare State who was expected to behave like a model Employer rather than the proverbial Shylock. Its impunged conduct in dealing with the "Subject" may not tantamount to unfair labour practice; but was certainly not charitable to the poor employees in keeping them in suspended animation for years together. The very thought and apprehension of an unprotected termination at the sweet will of the Employer is repulsive to the philosophy of a progressive society, and that, perhaps, explains the gist of the Corporation's own Circular dated 20-7-78 in which the practice of keeping Casual labour on ad hoc and daily basis for indefinite periods was depricated and it was suggested that steps should be taken to create regular posts to the desired extent; albeit, with the approval of the competent authority

18. I, therefore, sustain the petitioners cause in its pith and substance but on taking a broad views of the situation including the administrative and financial limitation of the respondent Corporation, of course regardless of the intervening terminations as discussed in the earlier part of this Award per para No. 13, direct that all the casual Watchmen who joined its services on or before 31st March, 1982 should be regularised forthwith against available posts in accordance to their seniority. To be precise the length of service put in by a Casual Watchman under the Respdt. Corporation would be the determining factor for filling-up the post. In case the requisite number of vacancies are not aavilable to absorb all such employees' the Respdt. Corporation shall take necessary steps to create an equal number of posts at the first available opportunity i.e. at the time of preparation of the Budget for the next financial year.

19. Notwithstanding any thing contained here-in-before, it would be premissible for the Respdt. Corporation to utilise the existing vacancies at any of its depots throughout the Punjab Region for the absorption of the petitioners and in case any of them refuses to accept the offer at a particular station he would be placed at the tail of the seniority list whereas the second refusal by him would invite the penality of loosing the claim altogether.

20. Before parting with the case, I would like to record that the termination of Sh. Jagdev Singh S/o Sh. Kapoor Singh could not be faulted with because on the admitted facts he had not put in 240 days of service in his entire tenure, much less in12 calendar months so as to claim terminal benefits under section 25F; whereas no evidence was adduced to show the retention of any of his junior so as to attract the mischief of section 25-G. All the same he would be entitled for preferential treatment in the matter of re-employment as envisaged be section 25-H of the Act.

21. Award returned accordingly.

Chandigarh.
3-6-1985.

I.P. VASISHTH, Presiding Officer.

[No. L-42012/13/83-D.IV(B)/D.V]

का. आ. 3056—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7-6-1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3056.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th June, 1985.

BEFORE SHRI I.P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH.

Case No. I. D. 21/84

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India, Punjab Region—Chandigarh.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri Mangu Ram
For the Workmen—Shri P. K. Singla

INDUSTRY : Food Corporation of India. STATE : Punjab.

AWARD

Dated the 3rd of June, 1985.

The Central Govt., Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industial Disputes Act 1947, per their Order No. L-42012(47)/82-D.II.B/D.IV(B)/D.V. dated the 19th of May, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the demand of FCI Class-IV Employees Union for regularisation of the casual watchman listed in the annexure below, in the Punjab Region of FCI, drawn from the Punjab Home Guards Deptt. and who have completed more than 240 days of work, in the scale of Rs. 210—240 is justified? If so, to what relief are these workmen entitled and from what date ?"

ANNEXURE

S/Shri

1. Lal Singh S/o Kur Singh
2. Dharam Pal S/o Gurdial Singh
3. Ajaib Singh S/o Sadhu Singh
4. Paramjit Singh S|o Sewa Singh
5. Charanjit Singh S|o Daljit Singh
6. Sadhu Singh S/o Durga Ram
7. Janak Raj S/o Bhoop Ram
8. Mohinder Singh S/o Kartar Singh
9. Avtar Singh S/o Harnam Singh
10. Sitar Ram S|o Joginder Singh
11. Jai Gopal S/o Jagna Ram
12. Avtar Singh Dhillon S|o Joginder Singh
13. Jagrup Singh S|o Birbal Singh
14. Paramjit Singh S/o Naginder Singh
15. Avtar Singh S/o Arjun Singh

2. The instant reference was consolidated and tried together with reference No. L-42012(45)/82-D.II(B)/D.IV(B)/D.V. dated the 19th of May, 1984 pertaining to a similar dispute between the same Employer and a number of workmen; viz. Hakam Singh and others, since they involved common questions of fact and law. A formal order to this effect was passed by me on 10-8-84 on the recorded request of the parties; obviously to avoid any apprehension of conflict in findings, multiplicity of proceedings and undue financial strains to them.

3. The aforesaid reference of Hakam Singh and others has since been decided to day and, thus, for the reasons detailed therein, on sustaining the petitioners '(Workmen)' cause in its pith and substance I return my Award in their favour.

Chandigarh.
3-6-1985.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012/47/82-D.II(B)/D.V]

का. आ. 3057—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत खाद्य निगम के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3057.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th June, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER. CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL. CHANDIGARH

Case No. I.D. 19|84

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India-Punjab Region, Chandigarh.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Sh. Mangu Ram.

For the Workmen—Sh. P. K. Singla

INDUSTRY : Food Corporation of India STATE : Punjab

AWARD

Dated the 3rd of June, 1985

The Central Govt., Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-42012(45)|82-D.II(B)|D.IV(B)| D.V. dated the 19th of May, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

'Whether the demand of Food Corporation of India Class-IV Employees Union for regularisation of the casual watchmen listed in the annexure below, in the Punjab Region of FCI, drawn from the Punjab Home Guards Deptt. and who have completed more than 240 days of work, in the scale of Rs. 210-240 is justified ? If so, to what relief are there workmen entitled and from that date ?"

ANNEXURE

1. Sh. Hakam Singh S|o Gurcharan Singh.
2. Bhim Singh S|o Sandhi Singh.
3. Hari Singh S|o Mit Singh.
4. Bachittar Singh S|o Gurdial Singh
5. Kirpal Singh S|o Naginder Singh
6. Nachattar Singh S|o Arjun Singh
7. Kesar Singh S|o Jangir Singh
8. Darshan Singh S|o Gurdial Singh
9. Bikram Singh S|o Jora Singh
10. Bahadur Singh S|o Nahar Singh

2. Brief facts of the case, according to the petitioner-workmen are that the Respdt. Corporation was involved in the industrial activity of purchase, sale, distribution and storage of foodgrains in various parts of the State of Punjab through its district level depots and that they were employed by it as Casual-watchmen under the immediate charge of the Dist. Manager Sangrur, As a matter of fact about 4,000 Casual Watchmen were engaged on such depots under the Respdt. Corporation and out of them about 3,000 were on the regular strength whereas the remaining were being branded as 'Casuals' and because of inferior nature of their status were being denied the regular pay scales and other fringe benefits usually accorded to their colleagues working on the regular cadre strength. It was complained that even though the Corporation required a large number of regular hands yet it was deliberately keeping them on the Casual-list and discriminating against them in the content of payment of wages despite the fact that they were doing exactly the same type of job both quantity wise as well as quality wise.

3. The petitioners' Union, therefore, raised a demand on the Management of the Respdt. Corporation for regularising their services but the latter was found unresponsive inspite of intervention by the ALC(C) at the Conciliation stage and hence the Reference.

4. It may also be worthwhile to note that according to the petitioners when the Appropriate Govt. was still seized of the matter as to whether or not to seek an adjudicaion of the dispute from the Tribunal on making a regular reference,

the Management disengaged them on brazenly violating the mandatory provisions of sections 25-F; 25-G; 25-H and 25-N of the Act; moreover such as action tentamounted to an unfair labour practice.

5. Resisting the proceedings, the Management denied the relationship of master and servant between the parties. It rather avered that the petitioners were drawn on loan basis from the Punjab Home Guards to supplement the Watch and Ward Staff on Open Storage Complexes and were paid wages for the particular days they worked there in accordance to the rates approved by the Deputy Commissioners concerned. Elaborating its cause the Management contended that on liquidation of the foodgrain stocks lying in the open, some casual watchmen were repatriated to their parent Dept. i.e. Punjab Home Guards before reference by the Appropriate Government. In short, the Management pleaded the futility of the petitioners' cause.

6. Meanwhile the Central Government referred the following two similar disputes also to this Tribunal for adjudication:—

1. I.D. 21|84 Workmen Vs. F.C.I. Order No. L-42012-(47)|82-D.II.B|DIV(B)|D.V. dated the 19th of May, 1984.

2. I.D. 22|84 Workmen Vs F.C.I. Order No. L-42011-22|82-D.IV(A)|D.IV(B)|D.V. dated the 19th of May, 1984.

7. Since common questions of fact and law were involved in all these cases, therefore, at the recorded request of the parties and to avoid undue financial strains to them, besides multiplicity of proceedings and any apprehension of conflict in findings, I consolidated them all in the instant reference No. 19|84 for common adjudication per my Order dated 10-8-84. Obviously this award shall hold valid for all these references

8. In support of their respective versions both the parties adduced verbal as well as documentary evidence, which I have carefully perused and heard them. The burden of arguments raised on behalf of the Management was that there was no master-servant relationship between the parties and that otherwise also the petitioners were employed only as on a Casual basis which did not qualify them as "workmen' to claim a reference to the Tribunal.

9. The objection against the petitioners' locus-standi does not require any serious attention because the definition of "workmen" as laid down in section 2(s) of the Act ibid is wide enough to include even the Casual-work force. For my views I draw support from the observations in the cases of Pilot Pen Company (Ind.) Pvt. Ltd. Vs Presiding Officer Additional Labour Court 1971 (I) LLJ 241, and Crompton Engg. Co. Madras P. Ltd., Vs. Additional Labour Court Madras 1975 (I) LLJ 207.

10. Similarly the submission that there was any inherent lack of master-servant relationship between the parties is also devoid of force. Even though it was urged that the petitioners were employees of Punjab Home Guards and were working under the Corporation on loan or deputation yet the Management's own witness Sh. Mangu Ram, Assistant Manager (IR) conceded in his cross-examination that they did not have any rule to draw class IV employees of other departments on loan or deputation. Obviously no service conditions or terms were prescribed, and reduced into writing when the petitioners were allegedly drawn from the Punjab Home Guards.

11. Otherwise also, there are certain time honoured fundamentals to decide the proposition of somebody's working on deputation. To be precise, there has to be a parent department and borrowing Organisation who wants to utilise the services of an employee of the former for some limited purpose or period. Necessarily, it requires the consent of all the three parties, including the concerned employee whose tenure and service conditions, while working on deputation, are then settled and fixed on mutual agreement; all the same his roots keep on sticking to the parent department in the form of lieu against the original post and that is how that normally temporary employees are not sent out on deputations. Significantly enough, in the case in hand, it was not even suggested by the Management that the petitioners were consenting party to such an arrangement. Similarly their appointment letters containing the terms and conditions of the alleged deputation should have also been prepared and shown to the Tribunal. But it was not to be and the reasons are not far to seek.

12. Be that as it may, the matter has already been finally settled between the parties by this Tribunal in yet another similar dispute relating to the matter of Labh Singh and others per I.D. No. 18 of 1983 decided on 29th Sept., 1984; a certified copy thereof was filed by the petitioners as Exb| W2. The same very question again arose in yet another dispute between the Respdt. Corporation and its workmen Jai Dev and Others per I.D. No. 17 of 1983 decided on 22nd of November, 1984. Both these Awards have since been accepted by the Appropriate Government and published in the Gazette. After examining various aspects of the issue the Tribunal had concluded that there was a meaningful relationship of a Master and Servant between the parties and that the petitioners being 'workmen' wihin the province of Section 2(s) of the Act were eligible to agitate their service conditions before the Tribunal in the Reference proceedings. It was further held therein that the Punjab Home Guards had acted only as a condute in sponsoring them for recruitment as Casual Watchmen by the Respondent Corporation otherwise the former never held any control on their work or conduct and that by no strength of imagination it could over assume the powers and pedestal of their Employer.

13. Neither of these Awards has yet been avoided by the Respdt. Corporation by any legal process and hence they would be deemed to be binding on it both under the philosophy of estoppel and resiudicata. As a necessary corollary it, therefore, follows that the petitioners were the employees of the Respdt. Corporation.

14. However, the learned counsel for the Corporation submitted that since the services of the petitioners had already been terminated before the receipt of the reference from the Appropriate Govt., therefore, no worthwhile relief could be granted to them by the Tribunal in the light of section 10(4) of the Act.

15. I am not impressed with the logic because Section-10(4) can not be divorced from the concept of Section 33(1) and when both these provisions are read together for a harmonious construction, one can not possibly resist the inference that once the Conciliation Officer, after taking cognizence of a dispute; submits his failure report to the Appropriate Govt. any disruption in the status-quo much unilateral termination, before declining of the reference by the latter would be invalid in the absence of its prior permission. And it goes without saying that according to the common ground, shorn of taking such permission, the Management did not even apply for it.

16. In the same sequence it may also be worthwhile to note that by the time of their disengagement the concerned workmen had already put in more than an year's continuous service within the meaning of Section 25-B of the Act, whereas neither any terminal benefits nor any notice of the proposed termination was given to them by the Management. Therefore, keeping in view the ratio of the cases of State Bank of India Vs. N. Sundrmani (1976) Supreme Court Cases 822 and Mohan Lal Vs. Bharat Electronics Ltd. (1981) 3 Supreme Court Cases 225, their terminations would be deemed to be non-est.

17. That directly confronts the Tribunal with the crux of the matter as to how for the petitioners are justified in demanding the regularisation of their services after having put in more than 240 days of work in the regular scale of Casual Watchmen.

18. On behalf of the management it was strenuously argued that in the very nature of things it could not possibly regularise the services of the petitioners because its dominent activity of purchase, sale and distribution of food grains was seasonal; and the work load always keeps on fluctuating from crop to crop. In the same sequence it was propounded that the retention of a large number of Watchmen during the non harvesting season could have serious repercusions on its limited financial resources.

19. Despite seeming attraction the submission failed to carry conviction with me. The pertinent point is that according to the common case of the parties the petitioners were working for the Respdt. Corporation since the year 1981, if not from an earlier stage. I do appreciate the seasonal nature of the Corporation's business but what defies logic is, as to then what for it kept on retaining them all around the year, including the lean periods when the activity of the purchase and sale of food grains is reduced to the minimal level. It rather shows that the Corporation requires a large number of Watchmen for its multifarious assignments including distribution, upkeep and security of the stored stuff.

20. One can not loose sight of the fact that the Respdt. Corporation is miniature-incarnation of a Welfare State who is expected to behave like a model Employer rater than the proverbial Shylock. Its impunged conduct in dealing with the 'Subject" may not tentamount to unfair labour practice; but certainly not charitable to the poor employees in keeping them in suspended animation for years together. The very thought and apprehension of an unprotected termination at the sweet will of the Employer is repulsive to the philosophy of a progressive society, and that, perhaps, explains the gist of the Corporation's own Circular dated 20-7-78 in which the practice of keeping Casual Labour on ad-hoc and daily basis for indefinite periods was depricated and it was suggested that steps should be taken to create regular posts to the desired extent, alhert with the approval of the competent authority.

21. I, therefore, sustain the petitioners cause in its pith and substance but on taking a broad view of the situation including the administrative and financial limitation of the respondent Corporation, of course regardless of the intervening terminations as discussed in the earlier part of this Award per paras No. 15 and 16, direct that all the casual Wacthmen who joined its services on or before 31st March 1982 should be regularised forthwith against available posts in accordance to their seniority. To be precise the length of service put in by a Casual Watchman under the Respdt. Corporation would be the determing factor for filling up the post. In case the requisite number of vacancies are not available to absorb all such employees, the Respdt. Corporation shall take necessary steps to create an equal number of posts at the first available opportunity i.e. at the time of preparation of the Budget for the next financial year.

22. Notwithstanding anything contained here-in-before, it would be premissible for the Respdt. Corporation to utilise the existing vacancies at any of its depots through out the Punjab Region for the absorption of the petitioners and in case any of them refuses to accept the offer at a particular station he would be placed at the tail of the seniority list whereas the second refusal by him would invite the penalty of loosing the claim altogether.

23 Award returned accordingly.

Chandigarh.
3-6-1985

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012/45/82-D.II(B)/D.IV(B)/D.VI

नई दिल्ली, 13 जून, 1985

का. आ. 3058.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 4) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, लोडना कोलियरी मैसर्ज भारत कोकिंग कोल लि. डाक लोडना, जिला धनबाद के प्रबंध तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को ———— को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th June, 1985

S.O. 3058.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lodna Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Lodna, District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 10th June, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 15 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lodna Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Lodha, District Dhanbad

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 31st May, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(29)/83-D.IV(B) dated the 16th May, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Lodna Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Lodna, District Dhanbad in dismissing S/Shri Kesho Prasad, Electrician and Suresh Prasad Electric Helper from service with effect from 2nd August, 1982 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

Earlier an order was made by the order dated 22nd October, 1984 in a preliminary issue raised on behalf of the management that the domestic enquiry held against the concerned workmen was not fair and as such enquiry proceeding was set aside and the management was given opportunity to adduce evidence in this Tribunal to establish the charges against the concerned workmen. Accordingly this case has to be decided on the oral and documentary evidence adduced on behalf of the parties on merit.

The case of the management is that on 30th June, 1981 at about 9.45 A.M. about 15 to 20 persons headed by the concerned workmen Shri Kesho Prasad, Electrician and his brother Suresh Prasad Electric Helper, both working in the Lodna Colliery, forcibly entered into the office room of the personnel section of the Area and enquired from Shri Ramadhar Tripathy, a staff of the personnel section, about Shri Sarbajit Singh Personnel Manager, Shri Ramadhar Tripathy told that he does not know about Sarbjit Singh. Thereafter the concerned workman Kesho Prasad started scuffling with him and assaulted him on the chin. Thereafter they went out of the room closing the iron shutters saying that nobody will be allowed to go out and the mob proceeded towards the office of the General Manager. The said mob forcibly entered into the area office shouting filthy language and tried to break open the office room of the General Manager where

the General Manager, Personnel Manager and Dy. Personnel Manager (E) were discussing some official matters. The General Manager and others bolted the room from inside for fear of being assaulted by the said mob. The mob pushed the doors of the chamber of the General Manager and tried to break open the door by striking on it with the weapons they were carrying. When they failed to break open the doors of the chamber of the General Manager they got down from the first floor where the chamber of the General Manager is situated and damaged the official Car No. BHR 1390 of the General Manager which was parked in front of the General Manager's office. Thereafter they proceeded towards the main gate of the area office and forcibly occupied the school bus of the Company and forced the driver to take them to Lodna colliery and there they assaulted Ramji Mishra, Superintendent Lodna Coke Plant who was on duty. A sense of panic was created by the said mob and the lives of everybody working in the area office was in danger. Earlier on the day there was a clash between the groups of workers owing allegiance to JMS and BCKU unions during which fire arms were used and Shri Ramadhar Bhar of JMS and Suresh Gupta of BCKU were seriously injured. The mob consisting of the concerned workmen belonged to the BCKU. Shri Harkirat Singh, General Manager, Lodna Area informed the police about the incident and on the basis of his written report the police drew FIR. The management had nothing to do with the incident in which Suresh Gupta, an outsider, received injuries. The management had no bias against the concerned workmen. The two concerned workmen Shri Kesho Prasad and Suresh Prasad were chargesheeted and explanation was called for from them. Kesho Prasad submitted his reply to the chargesheet but Suresh Prasad avoided to submit any reply to the chargesheet inspite of reminders. Thereafter a departmental enquiry was ordered to be made against the concerned workmen. An officer of the management outside the Lodna Area was selected to hold the departmental enquiry in a fair and impartial manner. The concerned workmen avoided to attend the enquiry on one plea or the other and as such the enquiry was held exparte against them. The charges levelled against the concerned workmen were fully established in the said departmental enquiry and after examination of the enquiry report the concerned workmen were dismissed from service with effect from 2nd August, 1982.

The case of the workmen is that one of the concerned workmen Shri Kesho Prasad was a permanent Electrician and the other concerned workman Suresh Prasad was a permanent electrical helper at Lodna Colliery. They were working at Lodna since long with unblemished record of service. The two concerned workmen were championing the cause of the workmen before the management in the capacity of union officials. The Lodna Colliery was under the control of the goonda and mafia leader from the days of the erstwhile management. The concerned workmen for the first time dared to challenge the authority and exploitation of the management backed puppet union leaders and thereafter the workmen in general started shifting their allegiance from the puppet union and started joining BCK Union. On seeing the union activities of the concerned workmen the puppet union leaders with the connivance of the management started hatching up plan to remove the concerned workmen from service. The goondas made a murderous attack on the life of Shri Suresh Gupta an active office bearer of BCKU on 30th June, 1981 in which Shri Suresh Gupta received bullet injury and was removed to the hospital. The workmen became very much agitated on hearing the news that Shri Suresh Gupta received bullet injuries. The management in order to cover up their own misdeeds entangled the concerned workmen in false case at the instance of their puppet union leaders. The management issued chargesheet to both the concerned workmen on 30th June, 1981 alleging false and concocted charges in respect of which a criminal case had already been lodged by the General Manager. The concerned workmen replied to the chargesheet denying the charges. The management initiated a departmental enquiry against the concerned workmen with pre-plan to dismiss them from service. The concerned workmen requested the management to stop the enquiry till the finalisation of the criminal case but the management did not stop the enquiry proceeding. The management withheld the payment of subsistance allowance to the concerned workmen with an ulterior motive and fixed the venue of the enquiry at Karnik Bhawan which is at a distance of 15 K.M. from Lodna Colliery. The concerned workmen had attended the enquiry on 15th January with all witnesses but the Enquiry Officer himself was absent at the given time of enquiry. The case of the concerned workmen, further, in that they had not participated in the alleged mob on the alleged date of occurrence. On 30th June, 1981 the concerned workmen joined their duty at 7.30 A.M. and thereafter they were deputed to work in the power house. The Engineer, Shri Dubey asked both the concerned workmen at about 9.30 to 10.00 A.M. to go to Madhuband Sub-station to work. Both of them went to work at Madhuband sub-station and after completing the work at Madhuband sub-station they returned back to the power house at about 4 P.M. and asked Shri Khan to mark "Out" in the Attendance Register. But Shri Khan did not mark them "Out" in the Attendance Register as the Manager had asked him not to allow them to go. The concerned workmen denied to have gone in the mob and assaulted Ramadhar Tripathy and that they had forcibly entered inside the office of the General Manager and tried to forcibly break open the chamber of the General Manager and that they damaged the car of the General Manager and that they had taken away the school bus to Lodna. Their further case is that they have been victimised as they are the office bearers of Bihar Colliery Kamgar Union.

The point for determination in this reference is whether the dismissal of the two concerned workmen from service with effect from 2nd August, 1982 is justified.

The management have examined 11 witnesses in all to prove the charges against the concerned workmen. The two concerned workmen have also examined themselves as WW-1 and WW-2 in order to prove their case. The management has produced documents which have been marked Ext. M-1 to M-12 and the concerned workmen have produced document which have been marked Ext. W-1 to W-16.

The charges against the concerned workmen are set out in Ext. M-1 and M-2 dated 30th June, 1981. It will appear from the said chargesheet that the two concerned workmen were on duty in the first between 7.30 A.M. to 3.30 P.M. on 30th June, 1981 at power house, Lodna. But they left the place of duty without information or permission. The second charge against them is that on 30th June, 1981 at about 9.30 A.M. the two concerned workmen alongwith others went to the Area office Lodna Area with deadly lethal weapons and manhandled Shri Ramadhar Tripathy a Clerk of Personnel Section who was performing his official job and that they were enquiring about Sarbajit Singh in abusive language. Thereafter they forcibly entered in the General Manager's Office and tried to break open the doors of the General Manager's chamber where the General Manager, Personnel Manager and Deputy Personnel Manager were discussing some problems and that when they failed to break open the door, they along with others damaged Car No. BHR 1390 which was parked in front of the Area Office. They were also charged that at about 10.00 A.M. they abused Shri Ramraj Mishra, Supervisor Lodna Coke Plant and tried to assault him with iron rods and chappal etc. and also threatened him with dire consequences if he failed to leave Lodna Coke Plant within two days. The above acts of the concerned workmen constituted misconduct under para 29 sub-para 9 and 18 of the Standing Orders applicable to the employees of Lodna Colliery. We have therefore to see if the said charges have been established by the management in the evidence led before this Court as I have already stated that the enquiry proceeding was held to be vitiated.

So far the charge of abusing and assaulting Shri Ramraj Mishra is concerned, the management has adduced no evidence before this Court and as such it has to be held that the said charge against the concerned workmen for having abused Shri Ramraj Mishra and attempted to assault him has not been established. It is held that the said charge has not been established against them.

I will now deal with the charge against the concerned workmen for having manhandled Ramadhar Tripathy Clerk, Personnel Section while he was performing his official job in the Personnel Section at Lodna. Shri Ramadhar Tripathy has been examined in this reference as MW-11. He has

stated that on 30th June, 1981 he had come in the Personnel department of Lodna Area office at 9.30 A.M. and when he was working one of the concerned workmen Shri Kesho Prasad along with another person came to him in furious mood and enquired from him about Sarbajit Singh in abusive language and when MW-11 told him that he did not know the whereabout of Sarbajit Singh, Kesho Prasad started scuffing and assaulting him. He has stated that he got injury in his chin. He has further stated that they went out of the room closing the iron shutters saying that nobody will be allowed to go out and thereafter they proceeded towards the G.M. Office. He knew Kesho Prasad from before and as much he had identified Shri Kesho Prasad at the time he was assaulted by Kesho Prasad. In his cross-examination he has stated that he had not heard any hulla prior to the entry of Kesho Prasad in the office. He knew Suresh Prasad and Kesho Prasad as they used to visit his office. He has admitted that he is a member of INTUC and that the concerned workmen are the members of other union. He came out of his office at about 9.55 A.M. It will appear from his evidence that he was alone at the time when Kesho Prasad had entered the office and had assaulted him and as such we do not have witness to corroborate the evidence of MW-11. MW-5 Shri Sarbajit Singh, Personnel Manager of Lodna Area, has stated that Ramadhar Tripathy told him that Suresh Prasad and Kesho Prasad had come in his office and were searching him (Sarbajit Singh) and that when Ramadhar Tripathy did not inform his whereabouts the concerned workmen assaulted him. He had also seen injury in his chin. As Shri Sarbajit Singh was the Personnel Manager under whom MW-11 was working it was quite natural that he had informed the incidents to MW-5. The evidence of MW-11 shows that only Kesho Prasad along with another person had come to him and that Kesho Prasad alone had assaulted him. He has not stated that Suresh Prasad had gone along with Kesho Prasad and had assaulted him. It will appear that MW-11 knew both Suresh Prasad and Kesho Prasad and had Suresh Prasad entered the Office and assaulted him, MW-11 must have named Suresh Prasad as his assailant. It is clear therefore that Suresh Prasad had not assaulted MW-11 and that only Kesho Prasad had assaulted MW-11 and at that time there was another person with Kesho Prasad whom MW-11 did not identify. Thus there is no evidence that Suresh Prasad had assaulted Ramadhar Tripathy and that Suresh Prasad had entered office of the personnel manager where MW-11 was working. In the above view of the matter Suresh Prasad cannot be held guilty in any charge of assault to MW-11. However, there is clear evidence of MW-11 that Kesho Prasad had assaulted MW-11 while he was working in the office and had refused to give the whereabouts of the Personnel Manager Shri Sarbajit Singh. Nothing has been elucidated in the evidence of MW-11 that any part of the evidence of MW-11 was false. The evidence of MW-11 find corroboration by the evidence of MW-5 who had seen mark of injury in the chin of MW-11. The injury on the chin of M-11 was of a simple nature and as such we cannot expect any injury report from the doctor and in the absence of injury report the evidence of MW-11 cannot be disbelieved. The only criticism against MW-11 is that he was a member of INTUC union and the concerned workmen were the members of another union and hence MW-11 has falsely implicated them The fact that they are the members of different unions can be used to the advantage of both the parties but in view of the evidence before us it appears that MW-11 Ramadhar Tripathy was assaulted because he belonged to a different union. I see no reason to disbelieve the evidence of MW-11 and I hold that the management has been able to establish that Shri Kesho Prasad had assaulted MW-11 Ramadhar Tripathy in the Office when Ramadhar Tripathy refused to disclose the whereabouts of Sarbajit Singh, Personnel Manager. This charge therefore is established against Kesho Prasad.

It will appear from the evidence of MW-3 Sudhir Ranjan Ghosh, Foreman Incharge in Lodna Colliery that the two concerned workmen had come to the office at 7.30 A.M. on 30-6-81 to attend their duties. Ext. M-9 is the Attendance Register. It will show that both the concerned workmen had entered their attendance in the Attendance Register at 7.30 A.M MW-3 being the Foreman Incharge allotted the duties to the concerned workmen in the power house. MW-3 has stated that after deputing them to duties he went to the office of the Manager for discussion regarding the work and at about 8.30 A.M. or 9.30 A.M. he returned back to the power house and subsequently he found that the two concerned workman were not working in the power house. It appears from his cross-examination that the Engineer also disputes work men on duty. According to him the concerned workmen were deputed to work inside the power house. He has stated that when a workman is allotted work after his attendance and goes before schedule hour of his duty, time of his departure is noted in the Attendance Register. He has also stated that the attendance in the Attendance Register is marked by the Attendance Clerk Shri A. S. Khan. The said A. S. Khan has been examined in this case as MW-6, MW-6 has stated that he used to take the attendance of the Engineering Section. He has stated that on 30-6-81 the concerned workmen came for duty at 7.30 A.M. and got the time recorded in the Attendance Register but the concerned workmen did not turn up for marking them out and as such time of their departure was not mentioned in the Attendance Register of 30-6-81. On persual of the Attendance Register Ext. M-9 it will appear that only incoming of the workmen is noted but their departure by making them "out" has not been shown. He has denied that the two concerned workmen had come to the office at 3.30 P.M. and asked him to note "Out" in the Attendance Register. From the above evidence of MW3 and MW-6 it appears that the concerned workmen had attended the office for the duty at 7.30 A.M. on 30-6-81 but they had left the office and did not return back to get their departure noted in the Attendance Register. The above evidence has been led to show that the concerned workmen had left the duty and joined the mob which had gone to the office of the General Manager.

MW-3 A. M. K. Sinha, Senior Administrative Officer, Lodna Area has stated that on 30-6-81 he was coming to the Area Office on the car driven by the driver at about 10.30 to 11.00 A.M. when the driver of the Car informed him that Suresh Prasad and Kesho Prasad had damaged the car of the General Manager and that they had taken the school bus towards Lodna Office. He has stated that at about 11.00 A.M. he reached the Area Office and saw BHR-1390 with marks of damage and thereafter he had gone to the chamber of the General Manager. He had not seen as to who had damaged the car of the G.M. or that the concerned workmen had taken away the bus towards Lodna office. He was not an eye witness. So his evidence is not of much importance in order to prove the charges against the concerned persons.

MW-7 M. P. Dubey, Dy. Personnel Manager has stated that at about 9.30 A.M. on 30-6-81 he got down at Area Office from the Staff Bus to attend the office. When he was coming to his office he saw about 15 to 20 persons including the two concerned workmen running towards the main office carrying lathi, bhalla etc. shouting abusive language and thereafter he rushed to the G.M.'s office where the Personnel Manager (MW-5) was sitting along with G.M. (MW-5). He has stated that the concerned workmen were leading the mob. He told the General Manager that the mob including the concerned workmen were coming towards the General Managers's Office and while he was reporting this matter to the General Manager there was sound of some people rushing towards the Office of the General Manager on the stairs and thereafter they bolted the room from inside as the General Manager wanted the doors to be closed. He has stated that the mob tried to break open the doors when they were bolting the doors from inside. The mob started striking at the doors and were shouting. The mob went away and thereafter the door of the chamber of the General Manager was opened when they saw marks of violence on the door of the General Manager's chamber When they came down they found the G.M.'s Car No. BHR-1390 parked on the ground floor damaged. He had seen the mob retreating from a distance of about 15 to 20 feet and at that time the concerned workmen were in front of the mob. MW-7 knew the concerned workmen from before as he was working as Deputy Personnel Manager. Even WW-1 Kesho Prasad has stated in his cross-examination that they used to discuss about the problems of Lodna Colliery with the officers and it was quite possible that MW-7 had identified the concerned workmen in the mob who came shouting in front of the chamber of the General Manager and had tried to break open the door by evidence shows that the concerned workmen were identified striking with the weapons they were carrying. Thus his in the mob.

MW-4 is Harkirat Singh, General Manager of Lodna Area. He has stated that at about 9.40 on 30-6-81 he was having discussion in his chamber with his personnel Manager Sarbajit Singh (MW-5) and at that time MW-7 Shri M. P. Dube, Deputy Personnel Manager came rushing to his chamber and informed him that about 15 to 20 persons led by Shri Kesho Prasad and Suresh Prasad armed with weapons were approaching the office. He has further stated that he heard the sound of some people rushing on the first floor where his chamber is situated and with the help of two other persons who were in his chamber he closed the door of the chamber from inside. He has stated that the mob was shouting and abusing against the management and the mob tried to force open the doors of his chamber and when they were unsuccessful to break open the door the mob returned back. He found marks of violence with some sharp substance on the door of his chmaber. When he came down stairs he found his staff car damaged and its rear and right hand side glass were broken and there were also mark of some sharp substance on the boots of the car. He was informed by Shri R. P. Mishra (MW-10) Inspector C.S.F., Lodna Area informed him that the school bus was carried away to Lodna Colliery after forcing out students from the bus while MW-4 was examining his car Shri B. K. Singh Area Manager Technical (MW-9) told him that the mob including the concerned workmen had damaged the car. In the cross-examination MW-4 has stated that he had not himself seen the workmen and the mob breaking the door damaging the car and taking away the school bus. It appears on reference to his earlier examination before the criminal court in the case against the concerned workmen that he had not identified any of the members of the mob as the persons of the mob had gone away at the time he came out of the chamber. The certified copy of his evidence is marked as Ext. M-16 in this case. It is clear, therefore, that MW-4 had not seen the mob himself and had not identified the concerned workmen as members of the mob. However, his evidence shows that there was a mob which had tried to force open the door of his chamber and had tried to break open the door with some sharp substance and that the Car parked outside was also damaged. It will also appear from his evidence that the mob which came and tried to break open the door of the chamber were shouting and abusing the management.

MW-5 Sarbajit Singh, Personnel Manager had come along with MW-4 and had gone along with him for discussion in the chamber of the General Manager. He also stated that Shri M. P. Dubey, Deputy Personnel Manager came in the chamber and told him about the mob including the concerned workmen coming in a furious mood towards the G.M.'s office. He has supported what MW-4 has stated. He has not stated that he himself had identified the concerned workmen in the mob. In his cross-examination he has clearly stated that he had not actually seen the mob when they were shouting. He has further stated that he had not seen the concerned workmen damaging the car. He had not seen Shri Tripathy being assaulted. He had come out of the chamber along with MW-4 and had seen the mob going away. As he was in the chamber along with MW-4 and had come out after the mob left the place it is obvious that he had not identified either the concerned workmen or any other person in the mob. Thus he also supports about the incident of the violence committed by the mob at the door of General Manager and damage of the car. He had not identified the persons in the mob.

The next important witness in this connection is MW-9 Shri B. K. Singh, Area Manager Technical. He has stated that on 30-6-81 at about 9.30 A.M. he reached the Area Office along with the General Manager and Personnel Manager but he went to his office chamber and the General Manager and the Personnel Manager went to the chamber of the General Manager. He has stated that while he was in his chamber at about 9.45 A.M. he heard some shout and noise on the first floor and opened the door of his chamber and came out. He saw about 5 to 6 persons near the door of the General Manager who were beating the door of the General Manager with sword and iron rod. On seeing him the persons of the mob proceeded towards him and on his enquiry as to why they had come there with sword the persons in the mob replied that officers are doing Goonda gardi and Atyachar and they shouted to assault him but one of the concerned workmen Kasho Pd. who was among the mob stopped the other persons not to assault him as they were concerned only with the General Manager or the Personnel Manager. He saw them getting down stairs and thereafter he heard some sound of striking something with some hard materials down stairs and looked through glass panes and saw that the mob were hitting the car of the General Manager and thereafter proceeded towards the gate of the office. He came down and saw that the mob got into the office bus meant for transport of staff and school children. He has further stated that thereafter he came up stairs and saw the General Manager, Personnel Manager and Dy. Personnel Manager coming down stairs from the first floor and he narrated them what he had seen He has specifically stated that he had recognised Shri Kesho Pd. and Suresh Prasad out of this mob of five or six persons whom he knew from before as they are local leaders and they used to come to his office when he used to visit the mines. He has further stated that the same group of mob whom he had seen striking at the door of the General Manager were the persons who were damaging the car of the General Manager and had entered into Company's bus. In his cross-examination he has stated that BCCL has security force and that the Inspector of the Security Force was in the prmises at the time of the incident but there was no posting of Security guard at that time. His evidence has no been falsified and it appears that he had seen the members of the mob from a very close quarter and as such it was quite possible for him to identify the concerned workmen whom he knew from before.

MW-10 is Shri R. P. Mishra who was posted as Sub-Inspector in Joyrampur Area office on 30-6-81. He was on duty on that day at about 8.30 A.M. and learnt that there was some firing in Joyrampur Colliery and thereafter he went towards wireless station to inform about the incident to his higher authority. He has stated that when he was transmitting the message, he heard some shout near the area office and when he descended down stairs he met a constable who told him that some persons armed with weapons were near the office chamber of the General Manager and were pushing his door. He has further stated that when he was coming down on the first floor he found a group of persons descending stairs and he saw some of them in front of the chamber of the General Manager. He had identified the two concerned workmen in the said mob. He had seen some striking mark on the door of the chamber of the General Manager and had also heard some sound of breaking the glass down stairs and when he came down he found the glass of the door of the car broken and also saw a cut mark on the dicky of the car of the General Manager and at that time he had seen a group of persons from a distance of about 7 to 8 feet from the car and also saw the said group boarding school bus which was near the entrance. According to him one constable Kripal Dan was posted in front of the chamber of the General Manager on the day of occurrence but it appears from the evidence of the witnesses that the said constable was not actually on his duty at the time of the incident. It will appear that the name of the concerned workmen was told to him by some other persons and that he himself did not know the name of the concerned workmen. He had seen the face of the concerned workmen. He has clearly stated that it will not be possible for him to identify the concerned workmen at present. It appears therefore that his identification of the concerned workmen has not to be given weight.

I have discussed above the evidence of all the MWs which in nutshell will show that a mob consisting of the two concerned workmen and others armed with fatal weapons had first gone to the office of the Personnel Manager and that Kesho Pd. had assaulted Shri Ramadhar Tripathy and that the said mob went shouting and abusing in front of the chamber of the General Manager and that they tried to break open the door of the chamber of the General Manager and also tried to break open the door by striking sword and iron rod on it and that when the doors of the Chamber of General Manager which were bolted from inside was not opened, they came down stairs and damaged the car of the General Manager parked in the office and that thereafter they boarded the bus of the Company and went away. None of the MWs have specifically stated that the concerned workmen were seen breaking open the door of the chamber of the General Manager and trying to break open by using sword and iron rod. There is also no specific evidence that

the concerned workmen were seen damaging the car of the General Manager. The evidence is attributed to the mob consisting of the concerned workmen and other person. This fact finds corroboration even by the suggestion which has been made to MW-4 on behalf of the concerned workmen. The suggestion given on behalf of the concerned workmen to MW-4 was that he had shelter the assailant of Shri Suresh Gupta and as such he was apprehensive of assault by the mob. To further suggestion made on behalf of the concerned workmen MW-4 has stated that he was not aware of the fact that the mob had come to his chamber in his search of the assailant of Shri Suresh Gupta and returned back when they learnt that the assailant was not in his chamber. It is clear therefore that a mob of persons had come to the chamber of the General Manager in search of the assailants of Shri Suresh Gupta and that the mob returned only when they were satisfied that the assailant of Suresh Gupta were not in the chamber of the General Manager. It appears from the evidence of MWs that on the day of occurrence Shri Suresh Gupta has received gun shot injury in a fight between two rival union and that the said Suresh Gupta was a leader of Bihar Colliery Kamgar Union and the mob had become violent due to the assault on Shri Suresh Gupta. The same type of suggestion which was made to MW-4 was made to MW-5 as well and in reply MW-5 has stated that he did not learn that the mob had come insearch of the assailant of Shri Suresh Gupta and that the mob had entered inside the chamber of the G.M. when they were discussing and that the mob returned back when they did not find the assailant of Shri Suresh Gupta in the chamber of the General Manager. I have pointed out the said suggestion made on behalf of the concerned workmen only to show the truth of the evidence of MWs regarding the fact that the mob had actually come to the chamber of the General Manager.

MW-5 in his cross-examination has stated that none of the persons of the mob except the two concerned workmen were chargesheeted. Admittedly the mob consisted of more than the two concerned workmen and it will appear from the evidence that the same type of allegations are made against all the persons in the mob. The fact that the concerned workmen were alone chargesheeted shows that as they were local union leaders of Bihar Colliery Kamgar Union they were alone chargesheeted while others who also committed the same crime were not chargesheeted. The concerned workmen have been dismissed from service for the facts alleged against them in the chargesheet. As there is no specific allegation that the concerned workmen had committed specific acts of violence on the door and on the car, I do not think it proper that the concerned workmen should be punished with the severe punishment of dismissal from service. There is specific evidence of assaulted by Kesho Prasad to Ramadhar Tripathy but the said injury was of a very simple nature caused either with fist or slap and for that the punishment of dismissal appears to be very harsh and not proportionate to the act of violence committed by Kesho Prasad. The evidence against the cocerned workmen does not disclose any crime so as to award punishment of dismissal from service and I think that the punishment of dismissal of the concerned workmen from the service is very harsh punishment for the acts of violence committed by them and the said punishment requires modification. I hold therefore that the charge against the concerned workmen has been established but it does not warrant the severe punishment of their dismissal from the service and the said punishment is not proportionate to the acts of violence committed by them. In the above view of the matter order of dismissal of the concerned workmen from service is not justified and is set aside and they are to be reinstated in their job from the date of their dismissal. However as the charges have been established against the concerned workmen and they have done no work since the date of their dismissal they will not be allowed any back wages but the period from the date of their dismissal to the date of their reinstatement will be counted for the purpose of the continuity of their services.

In the result, I hold that the action of the management of Jodna Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. in dismissing the concerned workmen from service with effect from 2-8-82 is not justified, and that the concerned workmen are entitled to the relief as detailed in the aforesaid paragraph.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012(29)/83-D.IV(B)]

नई दिल्ली, 14 जून, 1985

का. आ. 3059:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत खाद्य निगम, चंडीगढ़ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 7 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 14th June, 1985

S.O. 3059.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th June, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I. D. 22/84

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India, Punjab Region—Chandigarh.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri Mangu Ram.

For the Workmen—Shri P. K. Singla.

INDUSTRY : Food Corporation of India STATE : Punjab

AWARD

Dated, the 3rd June, 1985

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, per their Order No. L-42011/22/82-D.IV(A)/D.IV(B)/D.V. dated the 19th of May, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

> "Whether the demand of FCI Class IV employees Union for regularisation of S/Shri Gurbux Singh, Amarjit Singh, Jagtar Singh, Bahadur Singh, Jang Singh, Gulzari Lal, Garibu Singh and Avtar Singh as regular Watchmen in the Punjab Region of Food Corporation of India drawn from the Punjab Home Guards' Deptt. and who have completed more than 240 days of work in the scale of Rs. 210—240 is justified ? If so, to what relief are these workmen entitled and from what date ?"

2. The instant reference was consolidated and tried together with reference No. L-42012(45)/82-D.II(B)/D.IV(B)/D.V. dated the 19th of May, 1984 pertaining to a similar dispute between the same Employer and a number of workmen; viz. Hakam Singh and others, since they involved common questions of fact and law. A formal order to this effect was passed by me on 10-8-84 on the recorded request of the parties; obviously to avoid any apprehension of conflict in findings, multiplicity of proceedings and undue financial strains to them.

3. The aforesaid reference of Hakam Singh and Others has since been decided to day and, thus, for the reasons detailed therein, on sustaining the petitioners, (Workmen) cause in its pith and substance I return my Award in their favour.

Chandigarh,
Dated : 3-6-1985.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-42011/22/82-D IV(A)/D.IV(B)/D.V.]

नई दिल्ली, 18 जून, 1985

का. आ. 3060:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, संगूर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार, को 13 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th June, 1985

S.O. 3060.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, in Distt. Sangrur and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th June, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I. D. 38/1984

PARTIES :

Employer in relation to the Management of Food Corporation of India.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer—Shri Mangu Ram.

For the Workmen—Shri Pawan Kumar Singla.

ACTIVITY : Food Corporation of India STATE : Punjab

AWARD

Dated, the 7th June, 1985

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, per their Order No. L-42012(11)/83-D.IV(B)/D.V. dated the 13th November, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Food Corporation of India is justified in refusing Casual, Earned and other Leaves to its casual workers ? If not, to what relief are they entitled to and from what date ?"

2. According to the petitioner-workmen they were working as casual Watchmen with the Respondent Corporation in district Sangrur for the last 9 to 10 years and were being paid wages on monthly basis. It was pleaded that in a dispute between the parties, per Reference No. 18/1983, this very Tribunal gave its Award dated 29th September 1984 directing the respondent Corporation to regularise their services because they had throughout been discharging the duties of the same type and nature as those working on the regular cadre strength. But, instead of implementing the Award in its letter and spirit, the management was discriminating against them in the context of Leave and Restricted/Gazetted holidays. To be precise even though such benefits were given to the regular employees yet the petitioners were being deprived of the facility.

3. Feeling aggrieved, the petitioners raised a demand through their Union on the Management for the appropriate relief but the letter was found unresponsive despite the intervention of the A.L.C. (C) at the conciliation stage and hence the Reference,

4. Resisting the proceedings on all counts the management submitted that the petitioners were working as Casual Watchmen on daily wages for the last 4 to 5 years and not 9 to 10 years as suggested by them; that they were being paid on daily-wage basis as per rates approved by concerned Deputy Commissioners and that the Tribunal's Award dated 29-9-1984 in the aforesaid Reference No. 18 of 1983 was already under challenge in a competent Court, and as such the matter was subjudice. Denying any discriminatory treatment to the petitioners the management contended that in the very nature of things there was vast difference in the service conditions of the regular and the casual watchmen and as such the latter could not be equated with the regular staff for the grant of leave and such other facilities.

5. During the pendency of the case another similar reference was received from the Appropriate Government per their Order No. L-42012(12)/83-D.IV(B)/D.V. dated the 29th November 1984 relating to a dispute between the parties on the point of gazetted and restricted holidays. The said reference was registered in this Tribunal per I. D. No. 59 of 1984, and since common questions of fact and law were involved therein, therefore, to avoid any risk of conflicting findings, multiplicity of proceedings and unnecessary financial strains to the parties both these cases were consolidated and tried together at their recorded request per my order dated 4-1-1985. All the proceedings have thus been conducted only in the instant case and this Award shall hold valid for both these references.

6. Be that as it may, in view of the omnibus nature of the terms of reference, the parties were straightaway called upon to adduce evidence in support of their respective versions without going through the drill of framing any formal issues. The petitioners examined P. K. Singla General Secretary of their Union and tendered a few documents whose authenticity was not questioned from the opposite side, where as, in its discretion, the management preferred to contest the case on the legal nicities alone, without feeling the necessity of adducing any evidence of fact.

7. On a careful scrutiny of the entire available data and hearing the parties I am inclined to sustain the petitioners' cause in its pith and substance because in its written statement the Management admitted having issued Circular No. 8-6/77/E.P. dated 6-9-77 on the subject under reference and also conceded that it was publicised in the "field" per letter No. A/23(13)/77-78/17648 dated 8/15-11-1984. An attempt was, however, made to wriggle out of its implications on the pretext that it applied only to those casual workmen who were drawing their pay and allowances on monthly basis whereas the petitioners were daily-paid casuals.

8. Copy of the aforesaid Circular is available on records as Exh. W 2 and for the obvious reasons its reproduction would be essential for the proper adjudication of the point in issue. It reads as below :—

"Recently a question arose whether casual leave is admissible to the employees of the Corporation who are appointed on part time or on contract basis. Casual leave is intended to cover Casual absence of employees for personal reasons and during this period the employees were treated as being on duty for all purposes. In view of this it has been decided that such of the employees of the Corporation who are appointed on part time or on contract

basis but draw their pay and allowances on monthly basis may also be allowed to avail of casual leave/ Restricted holidays on the terms and conditions as is admissible to the regular employees of the Corporation. These instructions will not be applicable to employees engaged on daily rate basis."

9. A cursory reading of the Circular may lend credence to the Management's view point but the effort to knock out the petitioners under its cover is based on the assumption that the petitioners were engaged on daily rate basis; a proposition which does not appear to be substantiated by any evidence; good, bad or indifferent. Rather we have the sworn testimony of the Union's General Secretary P. K. Singla that they were being paid wages on monthly basis; and significantly enough even a suggestion to the contrary was not floated to him when he was available in the witness box for cross-examination. At the risk of repetition it may also be emphasised that in its discretion the Management did not like to adduce any evidence inspite of the fact that it was possessed of the relevant record including muster rolls and payment registers. Obvious inference would therefore be that the deposition of Shri P. K. Singh was closer to truth.

10. As a necessary corrolary it follows that the petitioners were entitled for the facilities envisaged by the above mentioned Circular Ex. W-2. All the same its scope could not possibly be extended beyond the benefits of casual, restricted and gazetted holidays because of the explicit and unambiguous language used therein.

11. On behalf of the petitioners it was argued that in the light of I. Ds. No. 17 and 18 of 1983 answered by this Tribunal on 2nd November 1984 and 29th September 1984 (Ex. W-3 and Ex W-4) respectively they should be equated with the regular employees for all intents and purposes because despite projecting subjudiced nature of these Awards the Management did not adduce any evidence to show that they were under challenge any where. On the other hand the relevant notifications under section 17 of the I. D. Act (Ex. W-3/A and W-4/A) prove that they have since been published in the Gazette on acceptance by the Appropriate Government.

12. I am afraid, in their anxiety to press their point the petitioners have gone astray on the scope of Awards in I. D. No. 17 and 18 of 1983. Taken at their best, the Awards contain a direction to the management to regularise the services of such Casual Watchmen who were in its employment from a particular point of time; then, the Management was also required to take appropriate steps to create the requisite number of vacancies before issuing the orders; moreover some of the employees who failed to accept stations of their choice were to be debarred from the relief. In my considered opinion all such details called for an enquiry of fact which was not possible in the instant case both for want of necessary data as well as limited scope of the Reference. It is besides the point that acceptance of the Awards by the Appropriate Government, all by itself was not sufficient to clothe the petitioners with the status of "regulars".

13. Similarly the petitioners claim for the other type of leave benefits e.g. Earned or Medical also appears to be over ambitious because in the very nature of things casual hands are employed for a limited purpose or duration for a particular object of temporary character, more or less on contract basis.

14. Thus to sum up my aforesaid discussion on the various aspects of the issue, as emerging from the records and the limited points raised before me, on partly sustaining the petitioners cause I direct the management to forthwith equate them with the regular employees in the matter of Casual leave, and Gazetted and Restricted Holidays.

15. Award returned accordingly.

Chandigarh,
7-6-1985

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-42012(11)/83-D.IV(B)/D.V.]

नई दिल्ली, 17 जून, 1985

का० आ० 3061.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, चंडीगढ़ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th June, 1985

S.O. 3061.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th June, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER. CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 59/84

PARTIES :

Employer in relation to the Management of Food Corporation of India, Punjab-Region, Chandigarh.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer.—Shri Mangu Ram.

For the Workmen.—Shri P. K. Singla.

INDUSTRY : Food Corporation of India. STATE : Punjab

AWARD

Dated, the 7th of June, 1985

The Central Govt. Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, per their Order No. L-42012-(12)/83-D.IV (B)/D.V. dated the 29th November, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the management of Food Corporation of India Sangrur is justified in refusing paid Gazetted Holidays and Restricted Holidays to its casual workers in Distt. Sangrur? If not to what relief are these casual workers entitled to and from what date ?"

2. The instant reference was consolidated and tried together with reference No. L-42012(11)/83-D.IV(B) dated the 13th of November, 1984 pertaining to a similar dispute between the same parties, since they involved common question of fact and law. A formal order to this effect was passed by me on 4-1-85 on the recorded request of the parties; obviously to avoid any apprehension of conflict in findings, multiplicity of proceedings and undue financial strains to them.

3. The aforesaid reference dated 13-11-1984 has since been answered today and, thus, for the reason detailed therein, on sustaining the petitioners' (workmen) cause in its pith and substance I return my Award in their favour.

Chandigarh,
Dated : 7-6-1985.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer
[No. L-42012(12)/83-D.IV(B)/D.V.]

नई दिल्ली, 19 जून, 1985

का. आ. 3062.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, राजस्थान आनुशक्ति परियोजना डाकघर अनुशक्ति के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 19th June, 1985

S.O. 3062.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rajasthan Atomic Power Project, P. O. Anushakti and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th June, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 29/81

In the matter of dispute between :

Workmen of Rajasthan Atomic Power Project,
represented by the Secretary,
Rajasthan Anushakti Karamchari Union,
H-1A/71, N.T.C. Colony, RAPP,
Rawatbhatta-323305.
(Via Kota)

Versus

The Management of Rajasthan
Atomic Power Project,
through the Chief Project Engineer.
Anushakti-323303,
(Via-Kota).

APPEARANCES :

Shri P. C. Jain—for the Management.

Mrs. Nitya Ramakrishnan Adv.—for the workmen.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 22-1-1981 vide Order No. L-42011(71)/78-D.II.B. made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the demand of the workmen of Rajasthan Atomic Power Project, P.O. Anushakti, Via Kota, for grant of equal facilities and service conditions to Tradesmen (Supervisors) in Civil and Stores Sections as given to other Supervisors of the Project, is justified? If so, to what relief these Tradesmen (Supervisors) are entitled ?".

2. The Rajasthan Atomic Power Project had categories of Tradesmen in its employment including those in the Civil and Stores Sections. In the statement of claim it is pleaded that 39 Tradesman Supervisors in the Civil Section and 11 such persons in the Stores Section work as Supervisors and they are distinguished as such. After, 1974 they were given revised pay-scales under the Central Civil Service (Revised Pay) Rules, 1973.

3. There were other Supervisor-employees in the Civil Section and other sections of the Project who were classified as Scientific Assistants and given better facilities like pay-scale, leave, loans and they were regular employees of project but the tradesman-Supervisor were not so treated. The tradesman-Supervisors could not avail of transfer and if he wants to go some other unit, he has to resign his job in the Rajasthan Atomic Energy Project and then joina fresh hand whereas Scientific-Assistant could move to other project in the other Units of Department of Atomic Energy.

4. The nature of duties performed by all the Supervisors whether in the Tradesman category or Scientific Assistant category were said to be the same and on the principle of equal pay for equal work it was claimed that the R.A.P.P. Management may be ordered to put Tradesman-Supervisors on par with other Supervisors of the project and grant them equal facilities and service conditions.

5. The Management of Rajasthan Atomic Power Project Kota contested the claim and asserted that Tradesman-Supervisors were not Supervisor but were only workmen and that the work performed by these persons was explained to the Assistant Labou Commissioner (Central) Kota in the minutes dated 23-12-77. The Scientific Assistants were Supervisory personnel and were regular workmen with the approval of the Management and the workmen concerned were not Supervisors of the same nature. The duties performed by the two categories were not similar and the Management had not treated the different workmen with discrimination and there was a difference of condition of service only between the workmen and the Supervisors and not among Supervisors themselves. The designation of an employee was not conclusive in the matter. It had to be ascertained what was the nature of principal duty and a small portion of work done contrary to normal duty did not convert the nature of an employee to be Supervisor.

6. A technical plea was taken that when the workmen call themselves as Supervisors the jurisdiction of the Tribunal is posted on their own pleadings.

7. The matter in issue referred to this Tribunal has been adjudicated on the evidence led by the parties and opportunity was given to the workmen to clarify their case in respect of discrimination claimed and to make it precise by way of stating as to how they claimed to be made equal to Scientific Assistants and at what stage.

8. In the evidence led the workmen have filed certain certificates where Shri U. R. Gehlot, T/Man 'E', K. K. Choudhary, Tradesman 'D', Rama Tradesman A, and Bijendra Singh Tradesman have been given certificates of good work including supervision and have mentioned as Supervisors therein.

9. The Tradesman are categorised from categories A to G and only charge-hand, Assistant Foreman, Foreman are classified as Supervisors by the Management and the promotion from Tradesman A to G is on the basis of years of services, performance, skill and ability. The scales of Tradesman from A to G all differ and the movement from Tradesman A to G category does not depend on the existence of the vacancy but on years of service, skill and ability to do the work. The workmen have sought relief by giving alternative suggestion. The first suggestion is that those workmen who had the minimum educational qualifications and minimum of work experience including work experience in supervisory capacity should be awarded designation of post in supervisory cadre corresponding to qualifications in terms of Article 6 of the Merit Promotion Scheme and those Tradesman-Supervisors who do not possess the minimums education qualification as mentioned in Article 6 who have an abundance of work experience total as well as in Supervisory Capacity may be placed in the lowest available supervisory grade of Chargehand. The second alternative offered is that the Tradesman Supervisor be placed in the grade in accordance with length of their service experience in the Supervisory capacity. The suggested scheme is as follows :

Tradesmen with upto 10 Yrs. of supervisory experience.	To be appointed Chargehand	(Work experience in supervisory capacity prescribed in the scheme is 2 years).
Tradesman with 10-15 Yrs. of supervisory experience	To be appointed Assistant Foreman	(Work experience in supervisory capacity in the scheme is 6 years)
Tradesman with 16-20 years of Supervisory Experience.	To be appointed Foreman	(Work experience in supervisory capacity prescribed in the scheme is 10 years).
Tradesman with over 20 Yrs. of experience.	To be appointed Foremen 'B'	(Work experience in supervisory capacity in the scheme is prescribed 15 years.)

The list of such Tradesman is annexed as Annexure-III. The third alternative suggested is that an equation be arrived at on the basis of scale of pay and years of service put in and the following detail is given.

Those Tradesmen drawing basic pay between Rs. 300 to Rs. 400 and work experience upto 10 years.	To be appointed Chargehand	(whose basic pay is Rs. 425)
Those Tradesmen drawing basic pay between Rs. 401 to Rs. 500 and work experience upto 15 years.	To be appointed Asstt. Foreman	(Whose basic pay is Rs. 470.
Those Tradesman drawing a basic pay between Rs. 501 to Rs. 600 and work experience upto 20 years.	To be appointed Foreman	(Whose basic pay is Rs. 550.)
Those Tradesmen drawing basic pay between Rs. 601 to Rs. 700 and work experience above 20 years.	To be appointed Foreman 'B'	(Whose basic pay is Rs. 650)

10. It is indicated that in the case of Tradesman above the level of those drawing 425—600 as basic pay is a general parity with the Supervisory cadre above the post of Chargehand, Assistant Foreman, Foreman and Foreman 'B' at least in the pay scale.

11. The Management of the Rajasthan Atomic Power Project has countered these suggestions and have argued that the vacant post in supervisory grade are filled either by direct recruitment or by considering departmental candidates in response to circulars issued and that filling up of post of supervisory grades by promotion is a selection process and is not automatic inclusion by length of service. There must be a vacant post in supervisory grade and candidate must possess minimum education qualification and experience in supervisory grades. The more length of service or qualification was said to be not sufficient to entitle an employee to automatic promotion/redesignation to supervisory grade. Trades man (Store Supervision) and Tradesman (Civil Supervision) could not be considered as having supervisory experience merely on the ground of the designation, as the jobs do not involve supervisory functions. The Chargehand, Assistant Foreman and Foreman had supervision of a different kind than the Tradesman (Stores Supervision) and Tradesman (Civil Supervision).

12. The Affidavit of Shri N. D. Soni, Scientific Officer/Engineer Grade (SE) is on record when he has stated that the workman Sita Ram is issuing and taking back the tools and tackles from the Tool Crib/Stores in the Workshop did a routine job and kept account but did not do supervisory work and did not supervise the work or duties or other Tradesmen/workmen in the Stores Section. There was no workman under him and he merely handled tools. In regard to Tradesmen (Store Supervision), it was stated that the word supervisory has only been added to distinguish him from other trades in workshop like Fitter, Turner, Milwright, Welder, Electrician and the word Supervisor did not mean that he did the work of supervisor because the supervisory duties are performed by chargehand, Assistant Foreman, Foreman and Engineer.

13. The statements of Manubhai WW-2 and Sita Ram WW-1 do not show that they supervised other employees in the project.

14. The Scientific Assistants are all engineer Diploma Holders and the Foreman are all I.T.I. trained. The claimant do not have any of these qualifications. When there is a basic educational qualification difference which qualifications are minimum, the question of equality in emoluments does not arise and there is no discrimination involved.

15. It is to be seen that the RAPP has a unique scheme of movement of Tradesmen from category A to G depending upon years of service and skill and ability without insisting on the existence of a post in the higher category. It is only when the promotion is to the supervisory cadre of Foreman Scientific Assistant or Assistant Foreman that the existence of the vacancy is a pre-requisite for promotion either departmentally or directly.

16. It appears to me that the use of the word 'Supervisory' has created a confusion with these workmen and because Scientific Assistants, Foremen and Asstt. Foremen are also called Supervisors, this claim for parity had been made by these workmen.

17. The Management of R.A.P.P. has clearly explained that the Tradesmen A to G are workmen categories and these employees do not have other employees under them to direct and supervise and cannot be called supervisors in fact of the nature of Asstt. Foreman or Foreman and cannot be given pay scales equivalent to them.

18. I do not find sufficient reason to accept the case of these workmen and cannot find fault with R.A.P.P. scheme of merit promotion and refusal to grant status of Scientific Assistant Foreman and Asstt. Foreman to these Tradesmen simply because of the nomenclature supervisory being added to their posts. The differencia between these workmen and the essential Supervisory Officers, Charge-hand, Asstt. Foreman and Foreman and Scientific Assistant is clear and is not hairy and these workmen cannot be given relief in the manner they claimed. The action of the Management is upheld and does not call for interference.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government. for necessary action at their end.

Dated : June 10, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-42011(11)/78-D II (B)/D V]

R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 1985

का. आ. 3063.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-6-85 को प्राप्त हुआ।

New Delhi, the 11th June, 1985

S.O. 3063.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner & Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st June, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 88|80

In the matter of dispute between :

Shri S. N. Gupta, Head Cashier, c|o Shri Madanlalji, Railway Station Chaoraha, Near P.O Ramganj Mandi, District Kota.

Versus

State Bank of Bikaner & Jaipur.
(Jaipur)

APPEARANCES :

Shri A. N. Tiwari for the workman.

Shri Surya Narain and Miss Mithlesh for the Management.

AWARD

The Central Government is the Ministry of Labour vide Order No. L-12012|50|80-D.II(A) dated 16th August, 1980 made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the Management of State Bank of Bikaner & Jaipur in dismissing Shri S. N. Gupta, Head Cashier, Pipalda Branch in District Kota with effect from 6th July, 1979 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Mr. S. N. Gupta joined the State Bank of Bikaner & Jaipur as Cashier-cum-Godown Keeper on 25-8-1961 and was promoted as Head Cashier w.e.f. 25-3-1970. His services were terminated by letter No. BM|2,8|2 dated 27-6-1979 on the ground of having committed misconduct. The charges against him were as under :

"(i) You demanded and accepted various amounts as bribe from the persons as mentioned below for getting the loans sanctioned in their favour :—

1.	Shri Asraf Ali	Rs. 50.00
2.	Shri Dhanna Lal	Rs. 50.00
3.	Shri Mithu Lal	Rs. 50.00
4.	Shri Raghu Nath	Rs. 100.00
5.	Shri Mohan Lal	Rs. 350.00
6.	Shri Bapu Lal	Rs 300.00
7.	Shri Ram Singh	Rs. 350.00
8.	Shri Kanhi Ram	Rs. 350.00
9.	Shri Mangu	Rs. 375.00

(ii) You demanded and accepted Rs. 20 as bribe from Shrimati Phuli Bai, Sweepress, Sunel Branch for releasing the payment of her Bonus amount of Rs. 80 in the month of May, 1973;

(iii) You demanded and accepted bribe of Rs. 500 (Rs. 50 per month w.e.f. August 1972 to May 1973) from Shri Nemi Chand for arranging him an appointment of a temporary peon in the Sunel Branch on 5th August, 1972 ;

(iv) You had raised a loan of Rs. 1000 in the name of one Shri Pancalal by getting the same guaranteed by your brother Shri Jagdish Chandra."

3. The Departmental enquiry was conducted by S. R. Jain, Officer in the Head Office. His appeal against the orders of his removal from his service was rejected by the Appellate Authority.

4. Workman's case is that the Enquiry Officer did not deal with him fairly and was biased, and did not give him fair opportunity in the enquiry. Even his jurisdiction was challenged. His case is that none of the charges against him is established, and that he should be allowed reinstatement in service with full back-wages and continuity of service.

5. The Management of State Bank of Bikaner and Jaipur have contested this case. The dismissal, after holding the domestic enquiry against him on the charges of misconduct, is said to be valid and proper and he is said to have been given full opportunity of being heard in the departmental enquiry. The charges proved against him were said to merit dismissal and no other penalty.

6. By my Award dated April 9, 1984 I refused relief to the workman and held that the charges against the workman S. N. Gupta were clearly established in respect of acceptance of bribe of Rs. 50 each from Asraf Ali and Dhannalal for getting the loan sanctioned from the Bank of Bikaner & Jaipur and upheld punishment of dismissal imposed upon him. I did not rely on much of the other evidence produced in the enquiry on the main ground that the CBI Inspector who recorded the statements of witnesses was not allowed to be cross-examined by the workman in the enquiry proceedings by the Enquiry Officer.

7. Aggrieved by the Award of this Tribunal Mr. S. N. Gupta filed a Writ petition No. 631 of 1984 before the Judicature Rajasthan Bench, Jaipur on 4th May, 1984. The Writ petition was admitted and was decided by Hon'ble Mr. Justice K. S Sidhu by his order dated 17-1-1981 and the Award of this Tribunal was set aside and the matter remanded to this Tribunal with the following directions :

(a) The Tribunal will hear the parties on the question as to whether the domestic enquiry is defective or not.

(b) If it finds that the enquiry is valid, it will be open to it to decide the reference on the basis of the findings of the Enquiry Officer and determine if the punishment awarded is justified.

(c) If the Tribunal finds that the enquiry is defective, it shall give the employer an opportunity of producing an evidence before it in support of the charges which forms the subject matter of the domestic enquiry. The workman will also be entitled to produce the evidence in rebutted of those charges and the Tribunal will then make its award on the basis of the enquiry held by it.

8. In accordance with the directions of the High Court of Rajasthan the matter has been re-heard on the question whether the domestic enquiry is defective or not and written arguments have been filed by the parties before this Tribunal.

9. The workman challenges the enquiry proceedings on a number of counts. He alleges that the charge-sheet lacks necessary particulars. He asserts that the so-called complaints were inordinately delayed and that the statements recorded in C.B.I. enquiry would not be admissible in enquiry proceedings. The conduct of the CBI Inspector is challen-

ged in respect of the recording of those statements and the numerous discrepancies and contradictions, and the concealment of material evidence. A number of witnesses stated that their statements alleged to have been recorded by the CBI Inspector were not recorded or that they had to sign blank papers and it was the Branch Manager and the Agricultural Assistant who conspired with Nemi Chand, Temporary Peon with the help of H. C. Singh C.B.I. Inspector to concoct this case against the workman. Specific allegations made against K. S. Kachawa Manager and Agricultural Assistant Man Singh that in order to cover up his own irregularities in payments made by them especially in relation to Ram Kaniya and in case of minor Bapu Lal, photo of which was sealed by the workman in presence of internal Auditor.

10. Grievance is also made by the workman in respect of disallowance by the enquiry officer of the production of the photo of Ram Kaniya which was got sealed and kept in custody of the Branch Manager and Head Cashier.

11. The procedure adopted by the Enquiry Officer was said to be unfair and not authorised by law. The opportunity for cross-examination was said to be denied to the workman when adjournment was not allowed at his representatives request on 4th and 5th April, 1977 when material witnesses were got examined and fleed without any cross-examination.

12. Pointed reference is made to the serious lapse on the part of CBI Inspector not being allowed to be cross-examined by the enquiry officer in the domestic enquiry when statements recorded by him were made the basis of evidence against the workman while they were inadmissible and caused prejudice to the workman.

13. The assertion by the workman is that the enquiry is invalid and that proper enquiry should be conducted before a y conclusion of guilt can be made against him. Detailed arguments had been filed by the workman in respect of his innocence and the fabrication of this case against him by the Branch Manager and the Agricultural Assistant.

14. The charge-sheet contains a number of charges against the workman. It mentions receipt of bribe from 9 persons for grant of loans acceptance of Rs. 20 bribe from Sweepress Tuli Bai, demand and acceptance of Rs. 500 from Nemi Chand for getting him appointed as temporary Peon on 5-8-1972 and raising a loan of Rs. 5000 in the name of Panna Lal by getting the same guaranteed by his own brother Jagdish Chandra.

15. Each charge of bribe against workman is a separate charge and there could have been a separate domestic enquiry in respect of that charge but a joint enquiry was held in respect of all the charges.

16. In the view that I had taken of this case earlier all the charges except those relating to acceptance of bribe of Rs. 50 each from Asraf Ali and Dhanna Lal were held not proved and, therefore, it is not necessary for the enquiry to be valid in respect of all the charges against the workman. It is sufficient if the enquiry is valid only in respect of two charges that were held proved by this Tribunal and charges on which the punishment in domestic enquiry was upheld by this Tribunal.

17. In so far as the entire enquiry proceedings are concerned, on all the charges framed against the workman, it was apparent even from the Award made earlier by me that the enquiry officer was held to be in error in not allowing the CBI Inspector to be cross-examined when a number of witnesses did not owe the statements said to have been made to the CBI Inspector. The Enquiry was held to be vitiated in respect of those charges in which the witnesses did not own the statements alleged to have been made by them to the CBI Inspector, who was not allowed to be cross-examined by the workman.

18. However, the view was taken by me that the refusal to allow cross-eximnation of the C.B.I. Inspector by the workman operated to the detriment of the Management of State Bank of Bikaner and Jaipur itself, in that the charges in respect of which the witnesses did not own the statements made before the CBI Inspector could not be held proved in the enquiry, and all such charges were held not proved for enquiry officer's refusal to allow the workman to cross-examine the CBI Inspector, who recorded the statements in the CBI enquiry made earlier.

19. This was done on the view that prejudice is caused to the workman by not being allowed to cross-examine the CBI Inspector, and the statements made to the CBI Inspector could not be believed, unless he was allowed to be cross-examined by the workman. However, it was the Management which was made to suffer for that fault of the enquiry officer, because the charges in respect of which this could have effect were all ignored and were not made the basis of any action against the workman.

20. It is made plain herein that the enquiry officer was wrong in refusing to allow the CBI Inspector to be cross-examined by the workman and that this did cause prejudice to the workman in respect of charges, where the witnesses concerned did not own their statements before the Enquiry Officer, but the prejudice to the workman was completely offset by this Tribunal's declaring that all those charges would be ignored and it shall be taken as if there was no enquiry by the Management in respect of those charges, and the Management did not request this Tribunal to hold further enquiry into those charges. Even now there is no request by the Management for furthere evidence being led by the Management before this Tribunal in respect of those other charges.

21. It is settled law that the Tribunal will allow enquiry before it, only when there is prejudice caused to the workman in respect of certain charges against him. When the Tribunal decides to deal only with two charges against the workman, the question to be decided is whether the domestic enquiry in respect of those two charges is defective or not, because the enquiry in respect of other charges is just ignored and is not made the basis for any action against the workman.

22. The order of remand of the Rajasthan High Court is understood in this sense that the Tribunal will hear those charges, and the question of defective nature of the domestic enquiry, but the matter is limited to those charges which this Tribunal accepted for examination earlier but did not record a positive finding that the defects in the domestic enquiry pointed out by the workman, even in respect of these two charges, whether they existed in fact or not. The Tribunal will now deal with the precise objections raised by the workman to the domestic enquiry in respect of the two charges in respect of acceptance of bribe from Shri Asraf Ali and Dhanna Lal, and all the other charges against the workman in the charge-sheet should be simply ignored and it shall be deemed as if there was no enquiry on those charges and that no enquiry further is to be held by this Tribunal in respect of those charges.

23. The first objection by the workman is that the charge-sheet lacks necessary particulars. This plea looses all importance because the workman at his request before recording of any evidence was supplied on 1-11-1976 with copies of statements of witnesses recorded in the preliminary enquiry by the C.B.I. Inspector and all material facts were there in the statements recorded by the C.B.I. Inspector and the workman cannot be said to have been prejudiced by lack of material particulars of the charges against him.

24. The delay in the lodging of complaint by the complainants is a matter to be considered in relation to the credibility of witnesses and does not per se make the complaints incredible.

25. In so far as the non-recording of statements of witnesses in chief in extenso is concerned, this is not fatal in this enquiry because the witnesses were shown or read out their statements before the enquiry officer and they admitted them to be correct and thereafter the witnesses were made over for cross-examination. The Management has rightly relied upon the two Supreme Court rulings. It has been held in State of Haryana Vs. Rattan Singh reported in 1982(1) LLJ. 46 that strict rule of evidence do not apply to domestic enquiry and all materials which are logically probative are permissible including hear-say evidence. In other case State of U.P. Vs Om Parkash reported in AIR 1970 SC 679 it has been ruled by the Supreme Court that in Departmental enquiry statements of witnesses recorded in the absence of the delinquent employee can be used if they are made available to him thereafter and he is allowed opportunity to cross-examine the witnesses and that rules of natural justice are not violated by such procedure even though this procedure is not an ordinary one. It is, therefore, held that the manner adopted by the enquiry officer of accepting the statements recorded earlier by CBI Inspector admitted by the witnesses concerned followed by cross-examination by the employee is not improper and violative of rules of natural justice.

26. The CBI Inspector was one of the witnesses in the enquiry and he sat there but on objection raised by the workman he was removed from the place and it cannot be said that the CBI Inspector's presence interfered with the independence of the witnesses because a number of witnesses refused to own their statements alleged to have been recorded by the CBI Inspector. No prejudice is held to have been caused to the workman by the presence of the CBI Inspector in the circumstances aforesaid on certain dates of enquiry.

27. The production of photo of Ram Kaniya in the circumstances of the case was not material because in the evidence led and cross-examination of R S. Kachawa this was not put to the Manager and in the earlier reply furnished in 1976 by the workman in the charge-sheet the workman merely alleged malice and did not at all implicate the Branch Manager or the Agricultural Assistant as being in conspiracy with the complainants.

28 As regards the disallowance of the prayer of the workman for adjournment of proceedings on 5th April, 1977 the telegraphic message from S. L. Gupta employee's representative through Branch Manager Sunil was received only at 3.15 PM and by then the cross-examination of Shri Asraf Ali by Mr. Gupta had been concluded in respect of the original paper or affidavit purported to have been signed by Asraf Ali, the enquiry Officer was right in refusing the adjournment when he was not shown the original paper purported to have been signed by Asraf Ali and only a copy was made over to him. As regards the proceedings dated 6th April, 1977 about adjournment of proceedings on account of his representatives sickness the enquiry officer did not accept it the ground that considerable delay in the enquiry had taken place and he proceeded to record statements of cross-examination of Mr. Sukla and Man Singh Even if the order made by the enquiry officer disallowing adjournment of proceedings on 6th April, 1977 was indiscrete, it caused no prejudice because cross-examination of Agricultural Assistant Man Singh could be effectively done by the workman himself who knew all about what had to be asked from the Agricultural Assistant and that was done it caused no prejudice to him in the hearing that day.

29. The workman has pleaded that the documents copies were not given to him on his request. The documents had been exhibited during the enquiry and their inspection was allowed to the workman and in case of voluminous documents this was a procedure that could be adopted and the grant of copies to the workman was not obligatory to comply with rules of natural justice in the departmental enquiry.

30. I am satisfied that on the whole the enquiry was conducted by the enquiry officer properly and fairly and opportunity for defence was given to the workman and even additional witnesses's were allowed to be produced by him in addition to those whose names he had given earlier. Asking the workman to give names of defence witnesses at the earlier stage is not denial of natural Justice especially when additional witnesses were allowed to the workman at later stage.

31. As regards the jurisdiction to order dismissal from service, the workman's case is that he was appointed initially as a clerk by the then General Manager in 1961, but he was being dismissed from the post of Head Cashier and it is not his case that he was promoted as Head Cashier also by the General Manager and that he was dismissed by an Authority subordinate to the one who

promoted him as Head Cashier and that objection does not stand. The Management has filed the list of disciplinary Authorities and the Appellate Authorities and Mr. V. B. Bhalla Regional Manager appears as the disciplinary Authority and the Asstt. Regional Manager [illegible] Appellate Authority in the notice of [illegible] issued in terms of para 19.14 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 and further notice dated 16th June, 1975. The jurisdictional objections are non-meritorious.

32. The workman has strongly urged that he has been made a victim of conspiracy by two Rajputs, the Branch Manager R. S. Kachawa and Agricultural Assistant Man Singh and that they conspired with the CBI Inspector and the other witnesses and Nemi Chand Temporary peon to make false cases against him. There is little factual evidence in support of it. In reply to the charge-sheet the workman on 3-5-76 simply said that the charges were false malicious and baseless and that he would submit admitted reply to the parties after examining the documents and evidence against him. He did not allege any conspiracy by the Branch Manager and Agricultural Assistant against them.

33. In the cross-examination of Mr. R. S. Kachawa Branch Manager, he was asked about temporary appointment of Moti Lal and Mr. Kachawa explained that he was appointed temporary peon and he stated that he was removed in his absence. Whether Moti Lal passed matric or not Mr. Kachawa replied that he had not passed matric. In respect of Nemi Chands appointment Mr. Kachawa explained that Nemi Chand was appointed temporarily and about his age he replied that he had a talk with Pardit who prepared to horroscope who stated it was correct. Manager was honest in saying that the termination of service is the power of the Manager and that at the time the payments were made no complaints were made to him tha [illegible] dc were short. As regards loans to [illegible] and brother Girdhari separately the Manager replied that loan was given to Girdhari, grand-father and Bapu jointly under the craftsman scheme and after the death of Girdhari it was given to Bapu, alone and no loan was given to his brother Girdhari. Girdhari, brother of Nemi Chand was appointed as Badli even though he was not literate because only requirement was that he should be honest and the appointment was not a regular one. The cross-examination of Shri Kachawa is rather short and does not give any impression that Mr. Kachawa was in conspiracy with anyone. Same faults can always be found in the working of an officer during a period but there is little in evidence that the Branch Manager Mr. Kachawa and the Agricultural Assistant being Rajputs cospired together with other witnesses to make false charges against this workman in conspiracy with the CBI Inspector. I am of the clear opinon that the allegation of conspiracy of all these people against the workman is a figment of the workman's imagination and has no relation to facts, and the making of these allegations shows how far S. N. Gupta can travel from truth to malign those who give evidence about what they know or learn which may incidently hit him.

34. Regarding the credibility of Asraf Ali it is to be stated that he stated the truth and he was not shaken in his testimony by the cross-examination. Asraf Ali had earlier been declined a loan and when he had obtained the benefit of loan which he desparately wanted, there could not be any question of making complaint to the Manager about his having been made to pay Rs. 50 as bribe to S. N. Gupta. It is only when the CBI Inspector investigated the matter that Asraf Ali in 1975 made the statement after he had repaid the loan and had nothing to fear and S. N. Gupta was not there in the bank or at a place where Gupta could harm him. It is not possible to believe that Asraf Ali deposed falsely at the instance of anyone.

35. The circumstances of the case of Asraf Ali getting a loan on subsequent application by mentioning lower figure of income at the instance of Mr. S. N. Gupta and payment of Rs. 50 bribe to S. N. Gupta are credible because he would not have got the loan under DIRA unless S. N. Gupta suppressed the information of the first application of Asraf Ali made in November, 1972 from the Branch Manager and Mr. Gupta was made payment of Rs. 50 because the second application would be verified by the Branch Manager Mr. Kachawa and the loan sanctioned by that officer only if the discrepancy in the income of the applicant was not made known to the bank.

36. There is no difficulty whatsoever in believing Asraf Ali and the discrepancies mentioned by the workman are inconsequential. Nathu Lal kept away from the CBI enquiry and the departmental enquiry because Nathu Lal did not want to trouble himself with these matters and preferred silence. If Asraf Ali was a liar S. N. Gupta could have produced Nathu Lal in his defence and in any case the circumstances of the case make me believe Ashraf Ali as has been done by he enquiry officer. I see no danger in relying upon the swarn testimony of Asraf Ali before the enquiry Officer and reject the arguments of Mr. S. N. Gupta that Asraf Ali is a false witness giving false evidence to injure him at the instance of the Branch Manager and the Agricultural Assistant.

37. Dhanna Lal is the other person whose evidence has been accepted by the enquiry officer. The workman insists that his evidence should be rejected because there is no credibility and that he also was dropped up by the Branch Manager and Agricultural Assistant. Dhanna Lal stated that he borrowed this amount from Ram Gopal and gave Rs. 50 to S. N. Gupta that he did repay to Ram Gopal and the bank loan was granted to him which he repaid in instalments. The evidence of Dhanna Lal is that when he paid Rs. 50 to Mr. Gupta no one else was there.

38. The evidence of Dharna Lal and Ram Gopal is not discrepant and unreliable. It is correct that Ram Gopal stated that the repayment was made by not paying salary to Dhanna Lal's brother and he also stated that it was when going to hospital in the evening that money was paid.

39. Some discrepancies are bound to arise even in the evidence of truthful witnesses but it is the circumstances and the situation that must determine whether the witnesses are trumped up, false and motivated or otherwise.

40. In this case Dhanna and Ram Gopal do not have any links with the Branch Manager and the

Agricultural Assistant and have no enmity against this workman and the evidence about taking of money from Ram Gopal and making its payment by deduction from Dhanna Lal's brother salary cannot be disbelieved. The credibility of Dhanna Lal is not discounted when he stated that the payment was made and in fact the payment was deducted by non-payment of salary to Dhanna Lal's brother. There was no work for which Dhanna Lal took money from Ram Gopal except that of making bribe payment to S. N. Gupta. Dhanna Lal sincerely stated that Man Singh asked him to make a statement and it is possible that Man Singh required him to state the truth because Dhanna Lal stated that he paid the bribe and that he went to the bank a number of times and went to the Manager also to find out that the loan had been sanctioned or not and that he went to the bank whenever repayment was to be made. The Agricultural Assistant Man Singh did ask this witness about what happened and Dhanna Lal gave statement to the CBI Inspector. Dhanna Lal states that what he said was true and that he was not an agent of Man Singh, Agricultural Assistant and was not manipulated by Man Singh to depose falsely against S. N. Gupta. He appears to be an ordinary potter who wanted money for making bricks and earthern pots and got his application recorded by S. N. Gupta and paid Rs. 50 on his demand for getting the loan sanctioned. He does not appear to be a clever and motivated person and it is not possible to discard this statement and his cross-examination has not shaken his credibility. The enquiry officer could certainly rely upon his evidence and this Tribunal does not find the evidence of Dhanna Lal and Ram Gopal unreliable at all.

41. I am of the clear opinion that in the circumstances of the case the evidence of Dhanna Lal and Ashraf Ali about payment of Rs. 50 bribe each to S. N. Gupta was rightly believed by the enquiry officer and the allegations of any conspiracy between them and the Branch Manager and Agricultural Assistant were rightly rejected by him. The charges against the workman of acceptance of Rs. 50 bribe each from these two persons stand proved beyond any reasonable doubt and the defence of innocense of S. N. Gupta is not capable of acceptance.

42. Mr. S. N. Gupta is a person who would charge any and everyone giving evidence against him as a conspirator or a liar. He has been found guilty of acceptance of bribe from two poor customers of the bank who were to be given loan assistance as craftsman with little means such an employee cannot be retained in service and the punishment of dismissal awarded to him by the Management of State Bank of Bikaner and Jaipur does not call for any interference and is justified and S. N. Gupta is not entitled to any relief in the matter.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

May 29, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-12012|50|80-D IV(A)]

नई दिल्ली, 19 जून, 1985

का. आ. 3064.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-6-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 19th June, 1985

S.O. 3064.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employees in relation to the United Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th June, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 116|80

In the matter of dispute between :

Shri Sham Narain Singh s|o Shri Udrez Singh, resident of A 184, Jagatpuri, Shahdara, Delhi.

Versus

United Bank of India, New Delhi

APPEARANCES :

Shri R. C. Danwar for the workman.
Miss Geeta Sharma for the Management.

AWARD

Central Government Ministry of Labour on 10th October, 1980 vide Order No. 12012|77|80-D.II.A. made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of United Bank of India, 205-208, Ansal Bhavan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi in not promoting Shri Sham Narain Singh, Sub-staff as Head Peon with effect from 12-6-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Mr. Sham Narain Singh sub-staff originally joined the United Bank of India on 1-11-57 and Sita Ram Bari was appointed on 23-2-59. Mr. Sham Narain Singh officiated as Head Peon as and when the Head Peon Shanker Dutt at Asaf Ali branch of the bank was absent. Shanker Dutt died on 13-3-79 causing a clear vacancy but the Management in June, 1979 appointed Sita Ram Bari, Armed Guard as Head Peon in place of Sham Narain Singh. Sham Narain Singh workman claims that he was the seniormost eligible sub-staff and according to the policy then in force at the time of death of Shanker Dutt on 13-3-79 Armed Guard or Lift-Man could not be posted as Head Peon or Daftry under Management's own policy in booklet para 92 B(i) on page 11 relating to promotion|posting of sub-staff.

3. The workman's case is that the alleged amendment in the rules by Telex message in June, 79 was motivated and mala fide and intended to injure his interest when he was a Active Union Worker and the Union of workmen has taken up the case of Sham Narain Singh for relief to be given to him by posting Sham Narain Singh as Head Peon at Asaf Ali Branch of the United Bank of India from 13-3-79 alongwith other benefits accruing therefrom in addition to cost. Shri P. Chattopadhya, Regional Secretary of the Union submitted the written arguments.

4. The Management claims that the reference itself is to be looked into and the validity of the Management action vide Telex message MZ-1 making change in policy in June, 79 cannot be questioned because there is no specific adjudication required by appropriate government in respect of that promotion policy and that in fact Sita Ram joined as permanent staff on 23-2-57 whereas Sham Narain Singh joined permanently on 27-4-60. So far as increments for temporary service are concerned, they were given to both but the seniority of Sita Ram Bari was said to be unquestioned and under the amended policy of June, 79 the posting could well be given to Sita Ram and the Bank Management policy could not be challenged and Sham Narain Singh had not been victimised for any union activity.

5. The matter has been tried.

6. The main case of the Union is that the matter must be decided on the policy existing on 13-3-79 and whether it is a promotion to the post of Head Peon or its appointment to an allowance carrying post, the fairness of the Management action has to be seen and the denial of the same to the workman has to be examined by the Tribunal and in this case the Telex message was not circulated or policy change circulated to the workman and could not be the basis of any changes. In the existing policy to the detriment of the workman.

7. It is correct that Head Peon is allowance post and not a promotion post. The only question is whether Sham Narain Singh is entitled to claim the same or not.

8. Relevant in this connection are two documents MZ-2 dated 4th August, 1980 and MZ-1 Telex message from Personnel Department dated 9-6-79 as under :

UNITED BANK OF INDIA

HEAD OFFICE

NOTE NO.

DATED : AUGUST 4, 1980

SRI S NIYOGI,
ASSTT. CHIEF OFFICER,
UNITED BANK OF INDIA,
PERSONNEL DEPARTMENT,
HEAD OFFICE.

Please refer to your Note No. PD : DIR:SN:49 dated 31-7-80 concerning the issue of our not considering the seniority of Sri Shyam Narayan Singh, sub-staff, Asaf Ali Road Branch for filling up the vacancy of Head Peon, caused on account of the demise of Sri Shankar Dutta, the Ex-Head Peon, of the said Branch.

In this perspective, the relevant particulars of Sri Sita Ram Bari, Armed Guard, made Head Peon at the aforesaid death-vacancy, and Sri Shyam Narayan Singh, are exhibited below for ready reference :—

Name of sub-staff of Asaf Ali Road Branch	Date of Appointment (as per Budget)	Date of Increment
Sri Sita Ram Bari	23-2-1959	23-2-1960
Sri Shyam Narayan Singh	27-4-1962	27-4-1973

From the above, it appeared that Sri Bari was senior to Sri Singh, but the plea of Sri Singh was that he worked as temp. Godown Darwan for 4 years, five months and twenty-six days and this period should be taken into account for counting his seniority and thus his date of appointment would be (27|4|62—4 years—5 months 26 days) i.e. 1-11-1957, by which he would have been senior to Sri S. Bari.

But our relevant Circular No. PD|626|72 dated 28-3-72 (along with its annexure) in this connection was referred to (photostat copy of which is enclosed) whereby it has been embodied that in the event of considering seniority, increments benefit would be allowed and in case of promotion, total services period (excluding breakage) would have to be considered.

In this instant case, therefore, the seniority of Sri Singh, in consideration of incremental benefit allowed for two years (official approval from the then Manager, Personnel, Sri R. M. Goswami, is enclosed marked flag 'A') whereby date of appointment of Sri Singh happened to be 27-4-1960 (27-4-62—2 years) and accordingly Sri Bari was made Head Peon and was allowed the Head Peon Allowance, Sri Bari's date of appointment being 23-2-59.

Also, it has been approved that an Armed Guard may be made Head Peon against a vacancy, if justified by the criterion of seniority, and Sri Bari fell in this purview.

For your information.

Sd|- (T. K. Ray)
OFFICER
PERSONNEL DEPARTMENT".

"31-2446 UBI IN
21 7387 UBI IN
MSN NO 3121
FOR : BM NIR

FROM : COPERSONNEL DEPTT.

REFER OUR TELEX MSG NO. 3093 DATED 8-6-79 REGARDING HEAD PEON AT ASAF ALI ROAD BRANCH. DECIDED FINALLY THAT HENCEFORTH ARMED GUARD IF SENIORMOST IN THE OFFICE HAS TO BE MADE HEAD PEON IN EXISTING SUCH VACANCY

WITHOUT PREJUDICE, OUR PREVIOUS INSTRUCTION IF ANY IN THIS REGARD TO BE IGNORED, ASAF ALI ROAD BRANCH CONTACTED OVER PHONE AND ADVISED IN THE LINE SINCE NO HEAD PEON HAS YET BEEN MADE IN THE BRANCH
DT TIME 9-6-79 1.23
31 .2446 UBI IN
21 7387 UBI IN
|as|2583

9. Sham Narain Singh workman had been getting officiating chance whenever the allowance post of Head Peon at Asaf Ali Road became vacant and when Shanker Dutt expired it was he who was appointed on temporary basis as Head Peon. It appears that the amendment in the policy in June, 79 was unfair to Sham Narain Singh and was made by telex message only to deny that right and expectations of Sham Narain Singh to be Head Peon with allowances and there appears no other reason for the change vide MZ-1 and there is no demand shown to have been made for a change in policy by the workman and the Management has not given any good reason why Armed Guard should be made a Head Peon except that they wanted Sita Ram Bari in place of Sham Narain Singh.

10. The circumstances of the change and the manner in which it was brought vide MZ-1 are eloquent and clearly show that it was not a bona fide action of the Management and that Sham Narain Singh was entitled to expect confirmation as Head Peon and to the allowance attached to that sub-staff post I am not at all impressed by the argument that this Tribunal cannot examine the change vide telex message MZ-1. The Central Government has made the reference to this Tribunal to examine whether the non-promotion of Sham Narain Singh as Head Peon is valid or not and incidentally the alleged change in policy vide MZ-1 has to be examined in that context.

11. I am of the clear opinion that the change in policy vide MZ-1 Telex message in June, 79 was detrimental to Sham Narain Singh and unnecessarily favoured the Armed Guard Sita Ram and that Sham Narain Singh temporary Head Peon was wrongly denied promotion and confirmation as Head Peon. His claim is justified and the action of the Management is improper and, therefore, the Management is ordered to pay Sham Narain Singh all payments due to him on the basis that Sham Narain Singh became Head Peon w.e.f. 12-6-79 onwards The Management shall also pay Rs. 300|- as costs of this reference to the workman. Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

June 10, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-12012|77|80-D. II(A)]

का. आ. 3065.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-6-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3065.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th June, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 19/81

In the matter of dispute between :

Shri D. N. Bundela S|o Shri Chhedi Lal, resident of Sahibabad, Distt. Ghaziabad.

Versus

The Management of State Bank of Bikaner and Jaipur through their General Manager, Head Office, Jaipur.

APPEARANCES :

Miss Mithlesh and Shri Surya Narain—for the Management.

Shri Tara Chand—for the workman.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 17th February, 1981 vide Order No. L-12012/90/80-D.II-A made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur in terminating the services of Shri Devendera Nath Bundela, a temporary workman of the Bank in Delhi with effect from 4-5-75 while giving permanent employment to other lower ranking temporary workman is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Devendra Nath Bundela applied for recruitment in the State Bank of Bikaner and Jaipur in pursuance of notice dated 11-4-74 for recruitment as a clerk. He was called for written test and qualified. He also appeared in Viva Voce test in August, 1974. Thereafter he was included in the list of candidates for employment in clerical cadre. He got temporary appointments from 29-10-74 to 21-1-1975 at Krishnanagar, Delhi Branch and from 10-2-75 to 3-5-75 at Lawrence Road Branch and no appointment thereafter.

3. The workman has argued that two candidates at Sl. No. 22 and 23 of the Select Panel who similarly started as temporary employees like him were continued in employment permanently but he was denied

any further employment after 3-5-75. He asserted that the bank action was illegal and discriminatory and sought protection of section 25-G of the Industrial Disputes Act, 1947. He claims reinstatement with full backwages and continuity of service from 4-5-75 and appoinment as permanent from the date Mr. R. C. Dhuli at No. 22 was made permanent.

4. The Management of State Bank of Bikaner and Jaipur contested the claim and asserted that there were limited number of vacancies and the claimant was low in the order of merit and could not be offered regular employment in bank service. He was kept on a panel for being given temporary employment as and when temporary vacancy arose.

5. 21 candidates Sl. No. 2 to 23 were given temporary employments as and when such temporary vacancy arose. The workman did not complete one year's continuous service within section 25-B of the I. D. Act, 1947 and for that reason was not entitled to any relief under section 25-F of the I. D. Act, 1947 and for the same reason the Management did not include him among those who were to be appointed regularly later. He had become 25 years old on 4-5-75.

6. The policy in regard to absorption in permanent service of Sarva Shri R. C. Dhull and Deepak Saxena, junior to the claimant in the panel list was that they had completed 240 days temporary service in the bank before the maximum stipulated age in it of 25 years for absorption in bank service and in the light of Supreme Court decision in N. Sunderamony's case they were absorbed in bank service there was said to be no discrimination and the bank could not be faulted in the matter.

7. The matter referred to the Tribunal has been tried. Evidence of the Parties recorded and written arguments filed by the parties have been perused.

8. The main argument of the workman is that he was a retrenched employee on 4-5-75 even though he had not completed 240 days' service and was entitled to the benefit of Section 25-F of I. D. Act, 1947 and in place of Deepak Saxena candidate Sl. No. 23 he was entitled to be taken up in temporary service from 9-6-75 in place of Deepak Saxena. It is urged that it was the statutory duty of the bank under section 25-H to offer this temporary employment to workman instead of offering the same to Deepak Saxena who was not only junior to the workman on Select Panel but who was not even a retrenched workman as he had never worked in a bank at all before 9-6-75. The submission is that it is the Management who prevented the workman from completing 240 days' temporary service in 12 calendar months by not complying with section 25-H of the I. D. Act, 1947.

9. The Supreme Court of India in N. Sunderamony's case enlarged the definition of "retrenchment" under section 2(oo) of the I. D. Act, 1947 and included loss of confidence and termination by efflux of time also in the term "retrenchment" and did not confine this word to redundancy or surplus age. This was done despite the argument addressed to the Supreme Court that a person whose services were terminated for loss of confidence of the Management could not be re-employed under section 25-H of the I. D. Act, 1947.

10. Even though sections 25-F and H occur in the same chapter, the contexual enlargement of the word "retrenchment" for the purposes of section 25-F now includes within retrenchment not only termination of surplus labour but also termination of service in whatsoever way brought about except the categories expressly exclude in the definition under section 2(oo) of the I.D. Act, 1947. The natural corollary, therefore, is that the word retrenched workman in section 25-H of I. D. Act must receive contexual shrinkage and cannot be given the same meaning. It will be impossible to insist that a person whose services are terminated for loss of confidence by the Management under section 25-F of the I. D. Act, 1947 in accordance with the procedure prescribed therein, is entitled to re-employment under section 25-H of the I. D. Act, 1947 immediately on such termination of service when a vacancy arise.

11. I am of the clear opinion that section 25-F of the I. D. Act merely prescribes the procedure for retrenchment which procedure is mandatory but it does not ensure security of service and so far as section 25-H I. D. Act, 1947 is concerned, it is not applicable to all retrenched employees.

12. The Management has two conditions : one of 25 years age on a particular day and completion of 240 days service in the bank for offering regular employment and the different a so laid down by the Management cannot be said to be discriminatory or unfair and it was not necessary for the Management to refuse temporary employment to Deepak Saxena who was also on the panel and was not obligatory on the Management to offer temporary employment further to this workman from 9-6-75. The action of the Management in the circumstances aforesaid cannot be said to be violative of any statutory provision and the workman could not insist that he should be allowed to complete 240 days' service for regular emplovment in the bank when he had reached the age of 25 years already on 4-5-75.

13. The action of the Management of the Bank does not call for interference and the workman is not entitled to any relief. Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

June 10, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012/90/80-D.II (A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

का. आ. 3066.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सीमेंट उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947

का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 3 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए :

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या० एस-11017/2/81-डी-I(ए)]

New Delhi, the 12th June, 1985

S.O. 3066.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Cement Industry which are covered by entry 3 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purpose of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/2/81-D.I(A)]

का. आ. 3067.—केन्द्रीय सरकार से यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उप खंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 4723 दिनांक 13 दिसंबर, 1984 द्वारा बैंक नोट प्रेस, देवास को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जनवरी, 1985 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उप खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जुलाई, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या० एस-11017/11/81-डी-I(ए)]

S.O. 3067.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (a) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour S.O. No. 4723 dated the 13th December, 1984 the Bank Note Press, Dewas (MP) to be a public utility service for the period of six months, from the 15th January, 1985;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 15th July, 1985.

[No. S-11017/11/81-D.I(A)]

का. आ. 3068.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 4724 दिनांक 13 दिसंबर, 1984 द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 दिसंबर, 84 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 जून, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या० एस-11017/14/81-डी-I(ए)]

एस०एच०एस० अय्यर, अवर सचिव

S.O. 3068.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (a) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Goernment of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour S.O. No. 4724 dated the 13th December, 1984 the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 23rd December, 1984;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 23rd June, 1985.

[F. No. S-11017/14/81-D.I(A)]
S.H.S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

का. आ. 3068—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्ज वाज फारवर्डिंग प्राइवेट लि. के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंबई नं. 1 के पंचाट भाग-2 को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 12th June, 1985

S.O. 3069.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes Part II the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay-No. 1 as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employees in relation to the management of M|s. Vaz Forwarding Pvt. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd June, '85.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

PRESENT :

Dr. Justice R. D. Tulpule Esqr.,

Presiding Officer

Reference No. CGIT-4 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to M|s. Vaz Forwarding Private Limited, Bombay;

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employer : Mr. Shetty, Advocate.

For the workmen : Mr. Udaysingh, Advocate.

INDUSTRY : Ports & Docks STATE : Maharashtra

Bombay, the 18th day of May, 1985

AWARD PART-II

The dispute relating to bonus payable to the workmen between the workmen and the management of M|s. Vaz Forwarding Privat Limited for the year 1979-80 has been referred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, to this Court for adjudication.

2. The workmen represented by the Transport and Dock Workers' Union filed a statement of claim tracing the history of the dispute and the proceedings before the Conciliation Officer. It says the dispute was finally revived in 1982. That time the company gave the union "one copy of its unaudited balance sheet". The company's accounts so produced showed a provision for payment of bonus at 20 per cent and hence 20 per cent bonus should be paid. It said that it will submit its bonus calculations when the employers file their balance sheet.

3. The company's written statement filed on 22nd February, 1983 says that an audited copy of the profit and loss account and balance sheet has been submitted to the union and still the union has not made any submissions thereon or filed its calculations with the statement of claim. In substance it said that even with this material, the union has not made any specific challenges. According to it bonus more than the minimum was not payable and it had not shown its willingness to pay more at any stage. It prayed that the union be called upon to submit its calculations and show from the audited balance sheet furnished, how the demand is justified.

4. On 28th April 1983 the union filed an applicatin and a statement which was not a bonus calculation but raised certain disputes about certain sums not on the basis of the audited balance sheet but on the basis of the unaudited balance sheet and corresponding figures of those items in the previous year. Thus it says that less income and more expense is shown. The freight figures shown are inflated as compared to last year. It raised contentions about bonus provision and said staff was reduced, general expenses and premises rent is increased compared to previous years and contended that a loan shown as made was false. Welfare expenses and salary of three employees debited was also challenged. This was not in a proper sense a bonus calculation submitted by the union nor a specific challenge to certain items in the audited balance sheet unless the items are liberally treated and taken as challanges. In the later stage of the proceedings as I will show presently the union confined its dispute only to items mentioned in its application dated 21st February, 1985. By the application of 28th April it sought production of income tax returns of the company.

5. This case is marked with a persistent and peculiar lack of interest and responsibility on the part of the union and its representatives throughout its progress. Its attitude was more often of impeding the progress of the case then of co-operation. The application was posted for hearing on 5.9, 19.10 and 18.11 when nobody from the union was present. An exparte notice was issued when they appeared on 15-12-1983. certain directions were given to be complied with on the next date viz. 9-1-1985. The union again remained absent. One more chance was given and it was directed that the application will be treated as not pressed if the directions are not complied with. This also had no effect and the application stood rejected.

6. It continued to remain absent on more occasions. Again an exparte hearing notice was issued on 5-7-1984. From 14th August, 1984 it remained continuously absent till 20-12-1984 when an exparte award was dictated. Thereafter the union's

counsel appeared and persisted in having the award reopened. Ultimately he took the advise to file a proper regular application as contemplated by the rules. Mr. Shetty for the employer graciously consented to the ex-parte award being set aside and the matter re-heard.

7. All this history had however little chastening effect on the union which continued more or less in the same unhelpful dogged attitude. Its application in the nature of challenges to figures in the balance sheet and for action under Section 23(2) of the Payment of Bonus Act was heard on 13th March, 1985 and an order was dictated in the presence of the parties substantiably granting its request. The union however failed to act accordingly for a most irresponsible reason and sought to dictate its terms. The hearing of the reference was adjourned to 1st April, 1985. But that day also the union remained absent. An ex-parte order was passed probably for the thirteenth time against it and the matter was posted for evidence to 12th April. On that day the union advocate made an appearance. None of the workmen were present. Evidence was then recorded and the employer closed his case. For the workmen an on the spot last minute attempt was made to file imaginary set on and set off calculations. I had directed the employer during evidence to file those registers. They had never been called for by the workmen at any stage. The matter was then proceeded with and argued. Even after conclusion of the arguments the union representative sought to produce a document, being notice of an annual general meeting without giving any reasons for non-production and sought to make submissions on the ground that no prejudice is or will be caused to the employer. He had to be ultimately directed not to address on the basis of the document after being pointed out the various ways in which prejudice would be caused and his purported contentions met. However the union did not desist from fresh attempts and even after the arguments were completed made fresh applications making untrue and incorrect statements therein. That application had to be rejected.

8. Not having availed of opportunity of inspection and calling and getting clarification of the Company's accounts and not having led any evidence whatsoever oral or documentary the union was left with what was available to make good its contention. To a direct question counsel for the union stated that his case rested on the contentions raised in the application dated 21 February, 1985 and to the challenges to items raised in that application from the balance sheet.

9. Those items or figures challenged in the balance sheet are the figures of gross profit (—9871-00) or loss shown in this case. The union sought to add Rs. 1,29,961.00 by which according to it the income in the audited balance sheet was reduced, the amount of increased expenses (from the unaudited and the audited balance sheet) thus making the total gross profit of Rs. 2,18,853.00.

10. Three other challenges were also raised (1) welfare expenses, (2) salary to Kale Prabhu & Gole & lastly what it said was a disproportionate rise in the C.I.G. and road freight. It may at once be stated that there is absolutely no evidence led or on record to show that either these were not incurred or falsely inflated. Though alleged that Kale, Prabhu & Gole were not employees, there is not even a word against the employees evidence. There is no admission about Gole as alleged except in the unapproved and unreferred to correspondence produced during the conciliation proceedings. All that the union stated was nothing was spent in Bombay on welfare. The employer stated that it represented all India expenses and denied that no welfare expense was incurred. The contention about the increase in the "CIG" and "Road freight" expenses is unfathomable. Presumably what is intended and that was also what was pointed out was that in proportion to what was paid in 1979 it is high. Such a bare allegation is difficult to be accepted as evidence or proof that the expense was inflated to siphon off profits. For one thing for some inexplicable reasons schedule 16 is missing from the profit and loss and balance sheet produced by the union on which they are relying. This was what was given to the union in conciliation proceedings in May, 1982. That is the trump card of the union as it shows a net profit of Rs. 1,44,573.00 which the audited balance sheet has converted into a net loss of Rs. 9,871.

11. If we see the P & L account and balance sheets for the years 1979-80 and 1978-79 (got produced by me for varification of set off and set on register) it will be seen that these figures appear in schedule 13. The comparative figures for the previous years are also available. The heads of expenditure are slightly different. For 1979-80 they appear as C.I.G. Road freight and freight, while for 1978-79 they appear as G.I.C. (wrong for C.I.G), Transport and freight. It will be seen from that those figures are—

	1977-78	1978-79	1979-80
(1) Road freight			
(2) Freight	32,32,802	2,88,03, 3[illegible]0	5,74 58. 355
(3) Transport			

12. The employees have had no grievance for the year 1978-79 and they accepted the bonus paid to them. There is a nearly nine times increase in that figures from 77-78. It has risen only twice in 1979-80. A some what different position appears for C.I.G. expenses.

1977-78	1978-79	1979-80
75,359	37,703	6,96,779

This may be compared with the income figures (gross) for these years. They are also below—

1977-78	1978-79	1979-80
1,36,55,413	8,68,89,619	13,67,52,978

13. It will be seen that the gross income has risen in 1978-79 from 1977-78 by over 6 times and by about 1.5. times from 1978-79 in 1979-80. This discloses a near uniformity in increase so far as road-freight, freight and Transport are concerned.

14. On the other hand C.I.G. expenses have actually mysteriously gone down in 1978-79 though the business went up six times and has jumped by 20 times in 1979-80. Compared to 77-78 figure the increase is 8 times. Unfortunately the reasons for these were not explained by the employer in the box.

But not a single question was put to him in the cross-examination by the employees in this behalf. The employees, I have already pointed out failed to avail themselves of the opportunity of inspection and seeking clarifications. They also did not seek this clarification in regard to C.I.G. expenses during evidence. There can be and may be several reasons for the increases in freight and transport, and C.I.G. such as increase in the rates. For C.I.G. it may also be that arrears were required to be paid in 1979-80. It is not known what this item is made up of. The union did not ask for the break ups at any time. Its approach to the case all along appears to be ad-hoc and not well formulated. Its grievances do not seem to have been genuinely generated and therefore no effort was brought to bear upon the case.

15. In this situation and since the employers also failed to explain the evaporation of profit a bonus calculation taking some of the figures mentioned in the union's calculation of 21st February, 1985 works out as below.

COMPUTATION OF GROSS PROFITS ACCOUNTING YEAR 1980

Net profit for the year (as per Profit and Loss Attached to letter dated 20th May, 1982)	Rs.	Rs. 1,44,573
ADD :		
1. Provision for bonus	85,224	
2. Depreciation	1,59,698	2,44,922
ADD:		
1. Bonus for previous year	19,351	
2. Donations	32,469	51,820
NOTE : Items sought to be added on account of Gratuity (Rs. 5,246) and capital expenditure (Rs. 26,891) cannot be added under the bonus formula and were also not challenged in application dated 21-2-1985.		
Profit for purposes of bonus		4,41,315
LESS :		
1. Depreciation under Section 6(a)	1,35,437	
2. Direct taxes (will have to be computed on the Net Profit) 50% of 1,44,573	72,286	
3. 8.5% interest on paid-up capital	1,27,500	
4. 6% interest on reserves	1,53,920	
		4,89,143
Available surplus		47,828
Allocable surplus (@60% of available surplus)		Nil

The wage bill for the year is Rs. 16,29,384. 8.33 per cent bonus comes Rs. 62,674.

16. As regards set on and set off, the extracts of the separate register produced by the company goes to show that there was no set on available for the previous year. This is also clear upon a perusal of the profit and loss account and the balance sheet for the year 1978-79. Bonus paid actually was more than what would have been the allocable surplus on the basis of the bonus formula. In the circumstances, since bonus paid is more than the allocable surplus of 8.33 per cent, which is the minimum, it must be held that the demand is not justified.

17. Award accordingly.

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-31011/3/82-D.IV (A)]

नई दिल्ली, 17 जून, 1985

का. आ. 3070.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th June, 1985

S.O. 3070.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexture in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen, which was received by the Central Government on the 12 June, 1985.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri J. Venugopala Rao,
Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 15 of 1982.

BETWEEN

The Workmen of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam;

AND

The Management of Visakhapatnam. Port Trust, Visakhapatnam.

APPEARANCES :

Sarvasri M. Pandu Ranga Rao and B. G. Ravinder Reddy, Advocates for the Workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Hon. Secretary of A. P. Chambers' of Commerce and Industry, Hyderabad for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-34012(3)/81-D.IV(A) dated 23-3-1982 referred the following dispute under Sections 73 and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their Workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Visakhapatnam. Port Trust in fixing the seniority of Shri N. Appa Rao, Clerk

(Commercial) taking into consideration his past service as Clerk (Train) and Ward Foreman is justified ? It not, what should be the criterion to determine his seniority on appointment as Clerk (Commercial)) ?

This reference was registered as Industrial Dispute No. 15 of 1982 and notices were issued to both the parties.

2. In the claims statement it is mentioned that the fixing of seniority of Sri N. Appa Rao, Ex-Yard Foreman, as Clerk (Commercial) basing on the principle of relative seniority which is irregular, mala-fide, motivated and opposed to the rules and procedures applicable to the Visakhapatnam Port Trust (VPT). According to the worker the V.P.T. introduced scheme of conducting periodical vision tests operation and signal staff to assess periodically whether the concerned worker has that particular vision standard prescribed for the post in the interst of the Port and the worker. In case of failure of any worker in the periodical vision test, he would be provided with an alternative appointment in a post for which no such standard of vision was prescribed. The very provision for providing alternative employmentis intended to rehabilitate the worker as he could not be thrown out of employment after putting in so many years of services. In other words providing alternative employment is in the interest of the worker who is already in service in that particiular cadre which are intended to be protected. While providing alternative employment the junior most employee in the cadre should not be discharged and there should be vacancy caused due to some reason or other at the time of rehabilitation. If there is no such vacancy, a supernumerary post is to be created for the purpose. Thus it goes without saying that the seniority of such worker is to be fixed at the bottom of the existing workers as otherwise their claims for promotion etc., would be adversely affected by introducing this worker somewhere in the seniority list he V.P.T. authorities adopted a novel method of invoking the principle of relative seniority in this case only as they are interested in that individaul. Now all other cases of similar nature, the effected employees who were offered with alternative employment were place at the bottom of the list as on that date. The application of the relevant rule of the Railway Establishment Manual as contended by the Management has no relevance in this case as this port is not governed by the provisions of the Railway Establishment Manual. Infact the V.P.T. employees recruitment and seniority this Port Trust has got its own regulations, known as "Visakhapatnam Port Employees" (Recruitment and Seniority) Regulations 1964, are the regulations under which such seniority is governed between the employees. There is a conciliation proceedings when the workers raised a dispute on the subject, the management could have conceded the requests and rectified the iregularity instead of complicating the matter. But the Management tried to invite the opinion of the other Union and suddenly informed the V.P.T. Employees Union that fixation of seniority of Sri N. Appa Rao in the alternative post of Clerk (Commercial) in terms of para 2614 of the Railways Establishment Manual is in order and no revision is considered necessary. It is mentioned by the workers that the same is done by the Management unilateraly and capraciously. Thus the said fixation of seniority of Sri N. Appa Rao should be held as not justified.

3. The Management filed a counter stating that the seniority of Shri N. Appa Rao, Ex-Foreman, Clerk (Commercial) was correctly fixed taking into consideration the relevant rules governing the subject matter and the practice in vague. It is denied that the fixation o fseniority was irregular, mala fide, motivated and opposed to the rules and procedure applicable in the V.P.T. The Management stated that it would be necessary to examine and consider the working of Port Railway in which Sri N. Appa Rao was working as Yard Foreman of Port Trust under Major Port Trusts Act, 1963 was under the control and supervision and management of the Central Government. The V.P.T. was under the control and supervision and management of Ministry of Railways (Railway Board) of Central Government till 1956. At present it is under the control of Ministry of Shipping and Transport of the Central Government. The entire working of the Port Railway is on similar lines as that of Trunk Railways. The relevant rules and regulations applicable to the working of the Railways are alsoimplicitly followed in the working of the Port Raiways. There are no separate rules for the V.P.T. in connection with the working of the Port Railways and as such the Management of V.P.T is still following the Railway rules in the matter like vision tests, periodical vision tests and the absorption of medically decategorised employees in the alternative jobs in the Port Trust . In fact the Resolution No. 128|66-67 the VPT Board has resolved to adopt the railways standards for general physical examination and also periodicity of the vision tests and the standards of fitness for different categories of staff as in Annexures 1 and 2 to the Note on the said resolution and require the categories of employees as mentioned in Annexure 3 to under go such periodical tests. The Medically decategorised employees are being absorbed in the alternative appointmnts after taking into consideration the required qualifications for the post in which the employee is to be absorbed and subject to availability of post. While absorbing him in the alternative post subject to availability of the post, his seniority is fixed after taking into consideration the total length of service in the Port Trust is not correct to say that the seniority is determined taking into consideration his date of absorption in the alternative post giving a go-bye to his entire past service in determining his seniority. It is not correct to allege that while providing alternative employment the iuniormost in the cadre is discharged The principle regarding the fixation of seniority for medically decategorised employees working in the Port Railway is also governed by the rules 2614 of the Railway Establishment Manual, Government of India which is being followed by the Port Trust.

4. In the instant case the Rule 2614 refered to aabove cannot be invoked and as such the Employees Seniority list is fixed in the bottom of the particular cadre post. No similarity can be drawn to two instant cases in fixing the seniority as the circumstances of the two cases vary depending upon availability of the post. It is no doubt true that all Port employees are

governed by Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964. When these regulations are silent regarding the absorption of the medically decategorised employees, it is necessary for the Port Trust to invoke the relevant rules of the Railways Establishment Manual. During the course of concilation meeting the claim-Union itself has raised the issue of the fixation of seniority of Sri. N. Appa Rao. Hence, this subject was discussed.

5. The Workers examined W.W. 1 and marked Exs. W1 to W20. The Management examined M.W. 1 and marked Exs M1 to M3.

6. W.W. 1 is one D. K. Sharma, Secretary of the Visakhapatnam Port Employees Union He deposes that he is working as Senior Assistant in the Marine Department of Visakhapatnam Port Trust. According to him the employees of Visakhatnam Port Trust are governed by the Visakhapatnam Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations 1964. He marked the said Regulations as Ex. W1. According to him under Ex. W2 the Secretary of the Visakhapatnam Port Trust addressed to Trustees of V.P.T Board by name Sri M.V. Bhadram with its enclosures is marked as Ex. W3 extract of Chapter III of Indian Railway Establishment Manual, and marked Ex. W4 as extract Chapter III of Indian Railway Establishment Manual. According to him Ex. W3 is not approved by the Visakhapatnam Port Trust. He marked Ex. W5 as the acopy of the resolution of the Visakhapatnam Port Trust passed in its 5th meeting of the year 1966-67 on 25-8-1966 together with its annexures. He marked Ex. W6 as the copy of the resolution of Visakhapatnam Port Trust passed in the year 1980-81 held on 24-4-1980 together with its enclosures.

7. According to him Sri N. Appa Rao working as Yard Foreman and his original date of apointment was 15-9-1960. He filed Ex. W7 as the compy of the list of seniority list of Yard Foremen. According to him Sri N. Appa Rao failed in vision test prescribed to the post of Yard Foremen. On account of this failure of the above test, he was given an alternative post of Clerk (Commercial) with effect from 1-7-1971. Again he was restored by the Management to its original post of Yard Foreman from 26-4-1976. He marked Ex. W8 copy of the seniority list of Clerk (Commercial). According to him for the second time, Sri. N. Appa Rao was reverted from the post of Yard Foreman to the post of Clerk (Commercial) w.e.f. 23-12-1976. On these two occasions when he was reverted he was placed at the bottom of seniority list of Clerk (Commercial). On a represenation made by him his seniority is said to have been refixed having regard to the length of his service Challenging the refixation of the seniority Sri N. Appa Rao in the cadre of Clerks (Commercial), Union General Secretary made representation to the Chairman, Visakhapatnam Port Trust. Ex. W9 is the compy of the said representation. Ex. W10 is the copy of the reply of the Management dt. 3-4-1981. It is admitted that there is no rules and regulation fixing the seniority of medically decategorised employees. Whenever an employee fails in vision test, the practice in the Visakhapatnam Port Trust is to absorb him in the ordinary post and to keep him at the bottom of the existing employees. The following are the examples in support of the above said practice. According to him one S. Appalakonda, Karuku Appanna and others were fixed at the bottom of their respective post as shown under Exs. W11, W12, W13. According to him there is no case of fixing the seniority of an employee who is medically decaterised and absorbed in the alternative post taking his length of service into consideration. It is his case that the Railway regulations are not applicable to the employees of the Visakhapatnam Port Trust. tI is mentioned that when the seniority of N. Appa Rao was refixed by the Management giving credit to his length of his service, the effected employees were not given opportunity and in that connection he gave representation under Ex. W14 resulting in conciliation proceedings and Ex. W15 is the copy of the minutes of the conciliation proceedings. According to him Ex. W16 is the copy o fthe letter dated 14-7-1981 written by the Conciliation Officer, Central reporting the failure of conciliation proceedings. Ex W17 is the copy of the letter dated 2-6-1981 addressed by the Secretary of the V.P.T. to all Labour Unions to offer their views regarding the revision of seniority of N. Appa Rao in this connection. The workers union represented as per Ex. W18 to the Management that the Management replied to thm stating that no revision of seniority of N. Appa Rao was considered necessary. The same is marked as Ex. W19. Ex W20 is the copy of the letter written by the Union to the Government of India.

8. M.W.1 is the Personnel Officer in Visakhapatnam Port Trust According to him Sri N. Appa Rao was originally appointed as Watchman in the year 1960. Later he was appointed as Clerk (Trains) in Traffic Department in 1965. In 1967 he was promoted as Yard Foreman but the vision test conducted for the post of Yard Foreman Sri N. Appa Rao failed in 1971 and thus he was given alternative employment of Clerk (Commercial). According to him the said alternative post was given taking into consideration all his qualifications and experience. According to him the Clerk (Commercial) is an allied post to Clerk (Trainees) and Yard Foreman and its an equivalent post with the clerk (Trains) whereas the Yard Foreman is a promotional post to Clerk (Train). He maintained that he was not reverted to previous post of Clerks (Trains) as the vision test is prescribed for the post of Clerk (Trains) also. Thus while posting as Clerk (Commercial) his seniority was fixed by placing him at the bottom o fthe list of Clerks (Commercial). On his representation to the Chairman again his seniority was fixed at the top of all the then Clerks (Commercial) taking into consideration the length of service in the post of Clerks (Trains) and Yard Foreman. According to Rule 2614 of Ex. W3. He marked Ex. M1 is above said representation of Sri N. Appa Rao dated 11-8-1979. Ex. M2 is the order of the Secretary of the Port Trust dt. 14-4-1980 ordering to refix the seniority of N. Appa Rao taking his past service into consideration. According to him the medically decategorised employees are governed by rules contained in Exs. W3 and W4 and that the Visakhapaatnam Port Trust (recruitment promotion and seniority) Regulations 1964 deal with the principles of seniority and that they have nothing to do with the fixation of seniority medically decategorised employees.

9. The admitted facts are that Sri N. Appa Rao, Clerk (Commercial) was originally appointed as Watchman in the year 1960. In 1965 he was appointed as Clerk (Trains) in Traffic Department. In 1967 he was promoted as Yard Foreman. It is admitted that in the Vision Test conducted for the post of Yard Foreman, Sri N. Appa Rao failed and in 1971 he was given alternative appointment of Clerk (Commercial). According to the Management, he was given the above alternative post taking into consideration his qualification and experience in the earlier post as Chapter III and Chapter XXVI of the Indian Railway Establishment Manual marked as Exs. W4 and W3. The Managements case is that the post of Clerk (Commercial) is an allied post and equivalent post to Clerk (Trains) and the Yard Foreman is a promotional post to Clerk (Trains).

10. The record showed that till 1964 the Visakhapatnam Port Trust was administered directly by the Ministry of Shipping and Transport. From 1964 the administration of the Visakhapatnam Port is kept under the Trust Board called Visakhapantnam Port Trust under over all control of Shipping and Transport. Original the Port Trust was under the administrative control of Indian Railways. At that time the entire Indian Railway Establishment Manual was applicable to the employees of the Port. This can be seen from Regulation 4 of Ex W1. The Visakhapatnam Port were shifted from the administration of the Indian Railways to the administration of shipping and Transport. In 1962 and thereafterwards the Visakhapatnam Port was administered directly by the Ministry of Shipping and Transport till 1964. The Rules marked as Exs. W3 and W4 and the rule in Chapter X of Indian Railway Establishment Manual are made aplicable to the employees of the Port Trust in view of the Regulation 4 of the Major Port Trust (Adoption of Rules) Regulations 1964 as already marked under Ex. W1.

11. This is the only instance of a Yard Foreman posted as Clerk (Commercial) after medically decategorised Though the post of Clerk (Trains) and Clerk (Commercial) are different categories, there are no interse transfers from one category to the other. The duties of the post of Yard Foreman and Clerk (Commercial) are different though they are connected posts. Only when the duties and responsibilities of two posts are connected to each other they are called allied posts. The allied post need not be equivalent post in the matters like pay and allowances.

12. The seniority of Sri N. Appa Rao was fixed at the top of the then existing list of Clerk (Commercial) as per Ex. M1 representation but notice was not given to the effected clerks (Commercial)

13. In the instant case the Management contended that the Industrial Tribunal was governed by the reference made and cannot go beyond the reference even though some parties might have sought relief. It is the case of the Management that on the basis of the reference there is no scope for Industrial Tribunal to grant any relief to any party and when Sri N. Appa Rao has not claimed any relief or raised any industrial dispute, the question of going into fixation of seniority did not arise. Therefore it is argued that the reference should be rejected on this ground. On the other hand the counsel for the workman contended that they are not asking for the entire seniority list to be altered, they are asking for the relief as the employees are affected by seniority given to Sri N. Appa Rao. So whether Sri N. Appa Rao was satisfied with seniority given to him and whether Sri N. Appa Rao raised industrial dispute is not material, according to him the dispute arose because there was seniority list of Clerks and Sri N. Appa Rao was not a Clerk (Commercial) and he was a Yard Foreman; When he was found unfit for Yard Foreman, he was posted as Clerk (Commercial). In the seniority list Clerk (Commercial) Ex. W8 he was shown at S. No. 63 almost at the bottom treating his appointment after being found medically unfit as Yard Foreman as a fresh appointment. On a representation made by Sri Appa Rao the seniority list is changed and Sri Appa Rao is to be at the top of the list. The employees who are working as Clerk (Commercial) were aggrieved on giving seniority to Sri Appa Rao over and above them. Therefore their union took up their case. The learned counsel for the Workmen contended that, thus it is open to the Tribunal to find the fixation of seniority of Sri. N. Appa Rao as not proper and the same is in violation of principles of natural justice as it was done without hearing any of the persons affected for refixation of seniority and thus it is open to the Tribunal to say that on the consideration of the rules Sri N. Appa Rao should be shown at the bottom of the seniority list as he was originally shown. I accept this contention of union counsel. Thus the Management is not right in saying that this point is outside the reference. The workmen are not contesting the interse seniority of Clerk (Commercial) amongst themselves. They are only contesting that Sri N. Appa Rao who is medically found unfit is Yard Foreman ought to have been shown at the bottom of the seniority as was rightly shown in the beginning and the subsequent alteration placing him on the top of the list without notice to any of the persons affected was against the principles of law as well as the rights of affected persons as it involved the principles of natural justice.

14. The principles of natural justice is that the notice should be given to the concerned persons who are affected especially when their rights and their seniority are being altered. Here in the instant case originally Sri N. Appa Rao was shown in the seniority list of Clerk (Commercial) at S. No. 63 almost at the bottom treating his appointment after being medically unfit as Yard Foreman from all respects as fresh appointment. When he gave representation about his seniority he cannot be granted automatic the seniority in the ranking which is sought for by him without effecting the rights of the others. The others who are going to be affected in such a case should be given an opportunity to say why he should not be granted seniority over them or to explain how the order already passed giving him the ranking at the bottom of the seniority as shown under Ex. W8 is proper and correct. When the person concerned is originally fixed

at the bottom of Clerk (Commercial) he cannot be automatically shifted to top ranking position on his representation without hearing the effected parties in Ex. W8 who are shown seniors to him. The change in the order of seniority putting him at the top without hearing the affected parties would effect all those persons on whom Sri. N. Appa Rao is shown as senior and further it amounts to clear violation of principles of natural justice as the same was done without hearing the persons affected in refixing the seniority.

15. In the instant case Sri N. Appa Rao was working as Yard Foreman and on the ground that his eye-sight was not normal as he was disqualified in the vision test he was transferred and appointed as Traffic Goods Clerk in the first instant and after he filed the Writ Petition No. 2595|73 he was given an alternative job in the year 1973. The Management attempt that the Clerk (Commercial) is equivalent post to Clerk (Trains) whereas Yard Foreman is promotional post to Clerk (Trains) when Sri N. Appa Rao failed in Vision Test prescribed for the post of Clerk (Trains) he was posted as Clerk (Commercial) fixing his seniority at the bottom of list of Clerks. Now basing on his representation Ex. M1 dt. 11-8-79 after taking into consideration the Rule 2614 of Ex. W3. The Management thought that he should be given seniority over and above all those persons. Rule 2614 of Ex. W3 reads as follows:—

> "The medically decategorised staff absorbed in alternative posts, whether in the same or other cadres, should be allowed seniority in the grade of absorption with reference to the length of service rendered in the equivalent or corresponding grade irrespective of rate of pay fixed in grade of absorption. In the case of staff who are in grade higher than the grade of absorption at the time of medical decategorisation, total service in the equivalent and higher grade is to be taken into account. This is subject to the proviso that if a medicaly decategorised employee happens to be absorbed in the cadre from which he was originally promoted, he will not be placed above his erstwhile seniors in the grade of absorption."

Now the Management contend that having taken into consideration the length of service in the post of Clerk (Trains) and Yard Foreman applying Rule 2614 of the Railways as shown under Ex. W3 they refixed his seniority. It is no where stated even as per Rule 2614 that the total service in the equivalent and higher grade is taken into consideration for all the persons while considering the seniority of this Sri N. Appa Rao. Moreover when Sri N. Appa Rao is a medically decategorised employee when he happens to be absorbed in the other cadre he cannot be placed above his seniors in the grade of absorption. Thus applying Rules 2614 also I fail to understand how Sri N. Appa Rao could be fixed over and above the other persons shown in the list of Clerks (Commercial) on the basis of his length of service in his previous cadre. While his seniority is to be fixed in the cadre of Clerk (Commercial) which is different from the Clerk (Trains).

16. It is next contended that the Major Port Trust Act is applicable to Visakhapatnam Port Trust and under Section 28 power has given to the Port to frame regulations, and it is open to the Port Trust to frame his rules and regulations regarding the service conditions of the employees also and when they have not framed any rules and regulations and when Visakhapatnam Port Trust passed a resolution adopting rules applicable to the Railway staff absorption in alternative employment that it is open for the Port Trust to treat the Regulations made by the Railways as part of its own regulations. In fact the Management relied upon Port Trust Resolution No. 128|66-67 adopting standard of physical examination and written test of the railways and also absorption of medically incapacitated staff in alternative employment as found in the Railway Manual and therefore it is contended that the Port Trust is deemed to have adopted the said procedure by resolution relating to the said subjects. There cannot be any dispute that the Port Trust authorities have power to adopt the Railway Regulations by passing resolution adopting the same. But it cannot be said that by virtue of this resolution injustice should be done to others while they tried to refix the seniority of one person who was originally fixed at the bottom of seniority of other Clerks (Commercial). There is a bound duty for the Management to give notice to the effected parties so that they can contest the method and manner of the consideration adopted in refixing the seniority of Sri N. Appa Rao to the detriment of their seniority in their cadre. While Sri N. Appa Rao is a stranger in their cadre who was originally working as Clerk (Trains) being unfit medically decategorised and after his filing Writ was tried to be brought into equivalent cadre and when he was placed at the bottom of that new cadre of absorption if he is to be considered for higher place in the same cadre naturally the persons effected should be given an opportunity to say how the same is not in accordance with law and how such an order will effect their rights which are secured to them in the normal course. The principles of statutory interpretation relied upon as quoted from G. P. Singh at page 175 in the written arguments of the Management will not hold good to say that the effected parties should not be given any opportunity to explain their stand vis-a-vis Sri N. Appa Rao who is being shown above them on his representation behind their back. It is mandatory that before fixing Sri N. Appa Rao's seniority a fair and reasonable opportunity should be given to the persons who were effected. The services of Yard Foreman Sri N. Appa Rao are being considered for refixing his seniority without hearing the affected persons and the said service is being taken into account in refixing the seniority. It cannot be said that it is a personal matter between Sri N. Appa Rao and Port Trust. Ex. W8 would show that Sri N. Appa Rao was already fixed in seniority fairly at the bottom of the Clerk (Commercial) and he cannot be given refixing his seniority over those clerks (Commercial) who were above him without giving opportunity to them.

17. The Port Trust is given Rule making power under Section 28 though the resolution passed by the Port Trust refers to the standards of fixation with regard to the medical standards and it did not refer to any absorption medically unfit person in the ordinary employment since the authority has power to

adopt some other rules or some other provisions of the Act by way of resolution. Even if the Rule 2614 of the Railway Manual is shown under Ex. W3 is applied in the instant case it must be applied only by giving notice to the effected parties also. Sri N. Appa Rao length of service and other consideration in re-fixing his seniority should be examined with reference to the persons of the cadre in which he is being absorbed. Infact he was already fixed at the bottom of the said cadre of person present Clerk (Commercial) when he is considered as afresh by applying Rule 2614 of the Railway Manual the persons over and above whom he is going to refix should have an opportunity to explain that such a thing cannot be done Thus on a consideration of the entire matter I hold that the action of the Management of Visakhapatnam Port Trust in fixing the seniority of Sri N. Appa Rao, Clerk (Commercial) taking into consideration the above service as Clerk (Trains) and Yard Foreman without considering the merits in seniority of other Clerk (Commercial) who are shown above to him by giving them as opportunity to explain is not justified. In the normal course it would be fair to detriment his seniority on appoinment of Clerk (Commercial) when he was medically decategorised employee he should not be placed above his erstwhile seniors in the grade of absorption and the interse seniority of all the Clerks (Commercial) the service of Sri N. Appa Rao as on the date of transferring him into the cadre of Clerks (Commercial) should be taken into consideration for the purpose of seniority. In other words the refixation of seniority of Sri N. Appa Rao as shown under Ex. W7 is not proper and the same is not justified and therefore liable to be set aside. The Port Trust authorities atleast should have framed rules by now. They should follow rules as framed under Section 28 for fixing the seniority in such cases. If they are going to follow the Railway Manual Rules they should hear all the affected parties as shown in Ex. W8 and after giving them an opportunity for representation and hearing them, and then it should taken into consideration about the length of service and the seniority on appointment as Clerk (Commercial) only for the seniority purpose in the grade of absorption as Clerks (Commercial).

Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 1st day of June, 1985.

Sd|- INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence.

Witnesses Examined for the Workmen :

W. W. 1 D. K. Sharma

Witnesses Examined for the Management :

M. W.1 Y. Bhadrachalam

Documents filed by the Workmen :

Ex. W1 First regulations made by the Central Government and regulations made by the Visakhapatnam Port Trust Board under the provisions of Major Port Trust Act, 1963 at Page Nos. 15 to 21.

Ex. W2 True Copy of the letter No. AA|19|82, dt. 16-9-82 addressed by the Secretary Visakhapatnam Port Trust to M. V. Bhadram, Trustee Visakhapatnam Port Trust Board regarding the Visakhapatnam Port Trust Employees' Regulations.

Ex. W3 An extract of Chapter XXVI of the Indian Railway Establishment Manual, regarding the absorption of medically incapacitated staff in alternative Employment.

Ex W4 An extract of Chapter III of the Indian Railway Establishment Manual regarding the rules regulating seniority of Non-Gazetted Railway servants.

Ex. W5 True copy of the resolution of the Board of Trustees of Visakhapatnam Port Trust passed in 5th meeting of the year 1966-67 on 25-8-1966.

Ex. W6 True Copy of the resolution of Board of Trustees of Visakhapatnam Port Trust passed in their meeting No. 1 of 1980-81 held on 24-4-1980.

Ex. W7 True copy of the Seniority list of Yard Foremen pertaining to Traffic department as on 31-12-79.

Ex. W8 True copy of the Seniority list of clerks (Commercial) pertaining to Traffic department as on 31-12-79.

Ex. W9 True copy of the representation made by the General Secretary, Visakhapatnam Port Trust to the Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam regarding alternative employment on failure in the periodical vision tests.

Ex. W10 True copy of the Letter No. F|IPC|XVIII|62, dt. 3-1-1981 addressed by the Secretary to the General Secretary, Visakhapatnam Port Employees' Union, Visakhapatnam regarding the alternative employment on failure in the periodical vision tests.

Ex. W11 True copy of the Seniority List of Hamals pertaining to Traffic Department as on 31-12-79.

Ex. W12 True Copy of the Seniority list of tug master class II pertaining to Dy. Conservator department as on 1-1-72.

Ex. W13 True copy of the Seniority list of Messengers pertaining to Marine department as on 1-9-73.

Ex. W14 True copy of the Representation to the Assistant Labour Commissioner.

Ex. W15 True copy of the Minutes of Conciliation Proceedings held on 30-6-1981 before the Assistant Labour Commissioner (C) Visakhapatnam in the dispute between the Management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen represented by Visakhapatnam Port Employees Union over protection of Seniority of N. Appa Rao, Ex-Yard Foreman.

Ex. W16 True Copy of the letter No. 16|15|81-ALC dt. 14-7-1981 addressed by Assistant Labour Commissioner, Visakhapantam to the Secretary to Government of India, Ministry of Labour, New Delhi regarding the failure of Conciliation proceedings.

Ex. W17 True Copy of the letter No. F|IPC|XVIII|62|Pt. IV, dt. 2-6-81 addressed by the Secretary, Visakhapatnam Port Trust to three (3) Labour Unions regarding the seniority of Sri N. Appa Rao in the alternative post of Clerk (Commercial).

Ex. W18 True cop of the Letter No. TM|PV|81, dt. 12-6-81 addressed by the General Secretary to the Chairman, Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam regarding the seniority of Sri N. Appa Rao in the alternative post of Clerk (Commercial).

Ex. W19 True Copy of the letter No. F|IPC|XVIII|62|Pt. IV. dt. 18-8-81 addressed by the Secretary, Visakhapatnam Port Trust to the General Secretary. Visakhapatnam Port Employees' Union, Visakhapatnam regarding the Seniority of N. Appa Rao in the alternative post of Clerk (Commercial).

Ex. W20 True copy of the letter No. TM|PV|81, dt. 29-8-81 addressed by the General Secretary the Visakhapatnam Port Employees' Union to the Secretary, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. regarding the Industrial dispute between the Management of Visakhapatnam Port Trust and their Workmen represented by Visakhapatnam Port Employees' Union over Seniority of Sri N. Appa Rao, ex-Yard Foreman in the alternative post of Clerk (Commercial).

Documents filed by the Management :

Ex. M1 Representation dt. 11-8-79 made by N. Appa Rao to the Management with regard to alternative appointment and fixation of pay.

Ex. M2 Order of the Secretary of the Port Trust, dated 14-4-80 ordering to refix the seniority of N. Appa Rao.

Ex. M3 True copy of the Judgement in W.P. 485|78 of the By Consent High Court of Andhra Pradesh.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-34012|3|81-D IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 17 जून, 1985

का. अ. 3071 —लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 के साथ पठित लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र, गोवा दमन और दीव के लिए एक सलाहकार समिति गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्रम मंत्री, गोवा, दमन और दीव सरकार, पणजी।	—अध्यक्ष
2. कल्याण आयुक्त, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, और क्रोम अयस्क खान श्रमिक-कल्याण निधि, गोवा, दमन और दीव, पणजी।	—उपाध्यक्ष
3 क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), दूसरा तल, वेकफील्ड हाउस, स्प्राट रोड, बेलार्ड एस्टेट, फोर्ट, बम्बई।	—सदस्य
4. श्री चन्द्र कांत केरेंकर, विधान सभा सदस्य, पाले।	—सदस्य
5. श्री वी. वी. डेम्पो, डेम्पो हाउस, कंपाल, पणजी, गोवा।	—सदस्य
6 श्री एम. एस. तालौलीकर, हीरा महल, पणजी, गोवा।	माइंसओनर्स/मिनरल्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले
7. श्री प्रभाकर डोंडे, गोवा स्टेट कमेटी ऑफ मेटर, ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन्स, पोस्ट बाक्स संख्या-90, वास्को-डिगामा, गोवा।	—सदस्य —खान श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले
8. श्री वी. ए. गावास, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल माइंस वर्कर्स यूनियन, क्वेपम, गोवा।	
9. श्रीमती सुनामिता मेरगुलाह ई. ग्रेसियस, बेनोलिम, सालकोट, गोवा।	महिला प्रतिनिधि
10 कल्याण प्रशासक, लोह/मैंगनीज/क्रोम अयस्क खान, श्रमिक कल्याण निधि, गोवा दमन और दीव, पणजी।	—सचिव

2. लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि नियम, 1978 नियम 15 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय पणजी निश्चित करती है।

[यू.-19012/7/81-कल्याण II]

आर. डी. मिश्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 17th June, 1985

S.O. 3071.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act 1976 (61 of 1976) read sub-rule (1) of rule 3 of the Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Rules 1978, the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee for the Union Territory of Goa, Daman and Diu with the following as members, namely :—

1. Labour Minister, Government of Goa Daman and Diu. Panaji.	Chairman
2. Welfare Commissioner, Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund, Goa, Daman and Diu, Panaji.	Vice-Chairman
3. Regional Labour Commissioner (C) 2nd Floor, Wakefield House, Sprott Road, Ballrad Estate. Fort, Bombay.	Member
4. Shri Chandrakant Verenkar M.L.A., Pale.	Member
5. Shri V.V. Dempo, Dempo House, Campal, Panaji-Goa.	Member representing mine owners.
6. Shri M.S. Talaulikar, Hira Mahal, Panaji-Goa.	Mineral Exporters Association.
7. Shri Prachakar Dorde, Goa State Committee of Centre of India Trade Unions, Post Box No. 90, Vaso-Da-Gama, Goa.	Member representing mine workers.
8. Shri V.A Gawas, General Secretary, National Mines Workers' Union, Quepem-Goa.	Member representing mine workers.
9. Smt. Sunamites Mergulhao L. Gracias, Benaulim, Salcote-Goa.	Women representative
10. Welfare Administrator, Iron/Manganese/Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund, Goa, Daman and Diu, Panaji	Secretary

2. In pursuance of rule 16 of the Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government hereby fixes Panaji to be the headquarter of the said Advisory Committee

[U-19012/7/84-W. II]

R. D. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जून, 1985

का. आ. 3072.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप खंड (1) (i) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, नीचे अनुसूची में उल्लिखित उद्योग को उक्त उप खंड के प्रयोजनार्थ, विनिर्दिष्ट करती है। यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

अनुसूची

क. लोहस (फैरस)

(1) लौह और इस्पात (धातु)
(2) लौह और इस्पात की ढलाई तथा गढ़ाई करना।
(3) लौह और इस्पात की संरचनाएं।
(4) लौह और इस्पात की पाइपें।
(5) विशेष इस्पात।
(6) लौह और इस्पात के अन्य उत्पाद।

[सं-16011/1/83-एल. डब्ल्यू.-खंड II]

ए. के. श्रीवास्तव, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

New Delhi, the 17th June, 1985

S.O. 3072.—In pursuance of sub-clause (1) (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 (37 of 1970), the Central Government hereby specifies, for the purpose of the said sub-clause, the industry mentioned in the Schedule below. This notification shall remain into force for a period of two years from the date of publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

A. Ferrous :

(1) Iron and steel (metal).
(2) Iron and steel castings and forgings.
(3) Iron and steel structurals.
(4) Iron and steel pipes.
(5) Special steels.
(6) Other products of iron and steel.

[No. S. 16011/1/83-LW-Vol. II]

A. K. SRIVASTAVA, Director General (Labour Welfare) |Jt Secy.

नई दिल्ली, 17 जून, 1985

का. आ. 3073.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 47 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बयास डेम प्रोजेक्ट के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ ..... के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th June, 1985

S.O. 3073.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Beas Dam Project, and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd June, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL CHANDIGARH

Case No. I.D. 149|83 (Delhi) 41 of 1983 (Chandigarh).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Beas Dam Project.

AND

Their Workmen :

APPEARANCES :

For the Employers—Sh. B. S. Puri.

For the Workmen—Sh. D. S. Chohan.

ACTIVITY : Beas Dam Project STATE : Punjab

AWARD

Dated the 29th of May, 1985

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-42011(17)|81.D.II(B) dated the 9th of March, 1982 read with S.O. No. S-11025(2)|83 dated the 8th of June, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the demands of the workmen of Beas Dam Project, Talwara, that (1) The position in the seniority list of original Carbon Steel, Welders should not be changed due to merger of High Tensile Welders in the trade of Carbon Steel Welders and (2) The to what relief are the concerned workmen in the seniority list of Carbon Steel Welders after the last man of the original list of Carbon Steel Welders, are justified ? If so, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. Brief facts of the case, accordance to the petitioner workmen comprising of Grade-I Welder belonging to the trade of Carbon Steel serving under the Respondent Project, are that they were appointed against their present assignments on various dates on or before Is of November, 1975 and that, under the same very employer about 18 Grade-I Welders were separately working in the trade of High Tensile. It was alleged that with a view to favour its henchmen the Management illegally merged the two trades and formulated a joint seniority list of Carbon Steel and High Tensile Welders effective from 1-4--1977 thus prejudicing their (Petitioners), carrer-prospects flowing from the incident of seniority. The petitioners also accused the Management of violating the mandate of the Tribunal's Award in Reference no.8-C of 1973 and, raised a demand for quashing of the joint seniority list with the prayer for sticking to the old policy of having separate seniority-lists of Carbon Steel and High Tensile Welders Grade-I. However the Management turned a deafear to their logic despite the intervention of the ALC(C) at the Concialiation stage and hence the Reference.

3. Resisting the proceedings on all counts, the Management contended that there was no valid dispute which could form the subjec matter of any adjudication, that otherwise also the petitioners were estopped from the raising the issue because at one stage they had accepted the impunged seniority list and it was in view thereof that certain workmen were either retrenched or otherwise disengaged in accordance to the most equitable criterian of 'last come first go". It was further pleaded that there was only one single composite trade of Grade-I Welders, who had attained that position on promotion from the lower ranks after passing Certified Trade Test, and that the seniority was always fixed on the time honoured principle of the date of appointment in the Cadre. It was avered that there were only four Grade-I Welders working under the classification High Tensile and even their seniority was fixed below those who had joined as Grade-I Welders in the Carbon Steel at an earlier stage.

4. Elaborating its version, the Management propounded that since all the Grade-I Welders had the same working conditions including pay and perks; therefore they could be asked to work in either of the classifications of High Tensile or Carbon Steel and that they had throughout been placed in a common seniority list.

5. The parties were put to trial on the following issues framed over and above the terms of reference.

(i) Whether the Reference is legally infirm or incompetent as alleged ? O.P.R.

(ii) Whether the Workmen and their Union are estopped as alleged? O.P.R.

6. In support of their respective versions both the parties adduced verbal as well as documentary evidence which I have carefully perused and heard them. Before going into the merits of the case it may be worthwhile to note that during the pendancy of the proceedings, the Management disengaged a large number of workmen including all the incumbents of the impunged seniority list in accordance to the provisions of section 25-FFF of the Act due to part completion of the work on project, and its action was sustained by the Hon' Supreme Court per their Order dated 30-3-84. In view thereof the Management prayed for dropping the proceedings altogether, whereas the petitioners insisted for adjudication of their demand lest there should be any further complication or dispute at the time of any future re-employment.

7. For the obvious reasons, I feel inclined to accept the contention of the petitioners because it would facilitate a proper formulation of the Seniority list as required under Rule 77 read with section 25H of the Act. As such, on rejecting the Management's submission I proceed to deal with the case as per my following issuewise discussion.

ISSUE No.1

8. A bare perusal of the definition clause section 2 (k) would suffice to believe that any difference or dispute between a workman and his employer connected with the terms or conditions of employment would fall within the province of an 'industrial dispute' which in a befitting situation, may be legitmately

referred to a Tribunal or Court by the Appropriate Government under Section 10 for judicial adjudication. In the case in hand there was a serious controversy between the parties as to whether Grade-I Welders working in the classifications High Tensile and Carbon Steel formed one single cadre or as to whether they should be separated for the purpose of seniority; and it hardly requires any emphasis that such like matters have a long-range effect on one's service prospects. To put in plain words, there is a contentious point regarding the service conditions of the petitioners which requires settlement. Therefore, it would be a ludicrous proposition to throw out the Reference for want of a valid dispute. Accordingly the issue is answered against the Management.

ISSUE No. 2

9. There is no evidence; good, bad or indifferent; to show the acquiescence of the petitioners in the retrenchment or disengagement of any workman from the joint-seniority list on the basis of "last come first go" as propounded by the Management, similarly no such data was placed before the Tribunal from which it could be assumed that the petitioners had explicitely or by necessary implication ever accepted the joint seniority list, or that by their act or conduct they induced any other person or the Management to change position to its prejudice. Hence the issue is answered against the Management.

TERMS OF REFERENCE AND RELIEF

10. At the risk of repetition it may be mentioned that according to the petitioners, Grade I Welders pertaining to the classifications of High Tensile and Carbon Steel had throughout been placed in different trades with separate lists of seniority and that it was for the first time in the year 1977 that a joint seniority list was drawn. But significantly enough no evidence or material was adduced to substantiate the plea, so much so that despite specifically accusing the Management of violiting the mandate of Award in reference No. 8-C of 1973 they did not bother to produce even a copy of the same and led no evidence to cite any instance.

11. On the other hand, the Management had a simple defence based on the plea that they had a composite pool of Grade-I Welders from which they used to deploy the requisite number of workmen in the classifications of High Tensile and Steel Carbon and thus the joint seniority list was circulated on 1-4-77 also. A copy of the said list was filed as annexure C with the written statement, and on revision, as Exb.M3 during the course of trial. a Careful scrutiny thereof would leave no manner of doubt that the date of one's promotion, of course after passing of the Certified Trade Test; was adopted as the criterian for fixing up the seniority and that was how that at least six persons from the Carbon Steel enjoyed a higher position than four of their counter-parts working in the High Tensile; actually they were the only four Grade-I Welders in the High Tensile classification. And it goes without saying that according to the common case of the parties, all the Grade-I Welders, irrespective of the sub-trades or classifications etc. enjoyed the same pay and perks.

12. To crown it all, the petitioners own admissions during the course of their cross-examination before this Tribunal lend credence to the Management's view point. To precise, WW1 Atma Ram conceded that he had gradually risen from the position of a Beldar to the rank of a Grade-I Welder in the Carbon Steel and that he had attained it only after passing the Certified Welders' Trade Test which was a pre-condition. Similarly WW4 Gujjar Ram had also risen from the rank of a Junior Welder on passing the Certified Trade Test. Both these petitioners were fair enough to admit the relevant inaccuracy in their affidavits to this extent. Of course WW2 Karnail Singh and WW3 Sukhdev Singh claimed having joined straightaway as Grade-I Welders but even they could not conceal that first they qualified the aforesaid Trade Test and only then they were given the appointments per Test cards Ex. M9 and Ex. M-10, respectively. Perusal of both these documents would show that no particular classification or trade etc. was assigned to either of them, and that they were straightaway deployed in the Carbon Steel.

13. Against the above backdrop one can not possibly differ with the Managements plea that as a matter of fact they had a common pool of the Grade-I Welders from which they used to assign the requisite number of workmen to the different shops, sub-trades or classifications etc. without disturbing their composite seniority

14. Thus to cum up my aforesaid discussion on the various aspects of the issue and the limited points raised before me, on maintaining the validity of the joint Seniority List I return my Award against the workmen but direct the Management to stick to the aforesaid list fo rthe purpose of Section 25-H and Rule 77 framed thereunder because I was made to understand that some steps are being taken to divert some of the retrenched staff to a number of sister projects including BBMB.

I.P.VASISHTH, Presiding Officer

Chandigarh.
29-5-1985

[No. L-42011(17)/81-D. II(B)]

नई दिल्ली, 19 जून, 1985

का. आ. 3074.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, न्यू दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 19th June, 1985

S.O. 3074.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Public Works Department, New Delhi their workmen, which was received by the Central Government on the 14th June, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 40|83

In the matter of dispute between

Shri Shyam Babu, S|o. Shri Radhey Shyam
r|o. Block-85|297, Panchkuiya Road, New Delhi.

Versus

The Chief Engineer, C.P.W.D.
Nirman Bhawan, First Floor, Gate No. 3,
New Delhi.

The Executive Engineer (E)
Electrical Division No. III,
C.P.W.D. Nirman Bhawan,
New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Narinder Chaudhary for the Management.
Shri R. C. Verma for the workman

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 21st April, 1982 vide Order No. L-42012(36)|81-D II(B) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Central Public Works Department New Delhi in terminating the services of Shri Shyam Babu, Khalasi with effect from 30-6-1980 is legal and justified ? If not to what relief the workman is entitled ?"

2. Shyam Babu was appointed as Khalasi on 27-7-1979 in Electrical Division No. III C.P.W.D. He claimed to have worked from 27-7-1979 to 30-6-80 without any break and claims that he was dismissed on 30-6-80 without any show-cause notice or enquiry. He claimed reinstatement in service with full back wages and continuity of service.

3. The Management contested the claim and asserted that nothing was due to the workman and that the workman was employed as casual labour on muster roll and was not regular employee at all and that he did not work continuously and that his period of work was 26-7-79 to 28-9-79, 3-10-79 to 12-1-80 and 14-1-80 to 14-6-80. There was no work for him after 30-6-80 and as such he was not continued on muster roll.

4. The matter has been tried and the evidence of the parties recorded.

5. Shri A. Mazumdar, Executive Engineer, C.P.W.D. Elect Division No. III filed affidavit indicating the working days of the claimant Shyam Babu as 185 during the period 26-7-79 to 30-6-80. In addition he stated that the workman did not report for duty after 30-6-1980 and abandoned work at his own will. Mr. V. K. Jambholkar, Executive Engineer (E) Elect. Division No. III, CPWD, New Delhi also has given a similar affidavit.

6. In the cross-examination of Mr. A. Mazumdar he explained that he gave the affidavit from record and that he had no personal knowledge of the attendance of Shyam Babu and he was not conversent with the signatures of Mr. Srivastava, Assistant Engineer (Elect.) on certificate WZ-2 where it is certified that the workman worked on 27-7-79 to 30-6-80 on muster roll with the intermediate breaks and could not certify the statements of Srivastava on mark W-1 statement showing details of work on muster roll which reads as under :

Statement showing the details of Muster Roll on which Sh. Shyam Babu, Khalasi worked.

Name of the worker with father's name address and designation	S. N.	Muster Roll No.
Shri Shyam Babu s/o Sh. Radhey Shyam K-131, Clive Square DIZ area N/Delhi Khalasi	1	82/III/ED III/79-80
	2	104/III/E D III/79-80
	3	124/III/ED III/79-80
	4.	143/III/ED III/79-80
	5.	165/III/ED III/79-80
	6.	187/III/ED III/79-80
	7.	209/III/ED III/79-80
	8	226/III/ED III/79-80
	9	243/III/ED III/79-80
	10	15/III/ED III/80-81
	11.	35/III/ED III/80-81
	12	57/III/ED III/80-81

Address.-
297/85 P.K. Road Pahar Ganj, N/Delhi

Period of M R.	No. of days present
26-7-79 to 12-8-79	15 days
13-8-79 to 12-9-79	26 days
13-9-79 to 12-10-79	26 days
13-10-79 to 12-11-79	0 days
13-11-79 to 12-12-79	0 days
13-12-79 to 12-1-80	27 days
14-1-80 to 13-2-80	27 days
14-2-80 to 13-3-80	25 days
14-3-80 to 13-4-80	25 days
14-4-80 to 13-5-80	0 days
14-5-80 to 13-6-80	27 days
14-6-80 to 30-6-80	13 days
	185 days

7. The workman in his affidavit asserted that he was appointed through Employment Exchange and that he worked as casual labour on muster roll but denied that he worked only for 185 days and asserted that he worked without any break from 27-7-79 to 30-6-80.

8. In fact WZ-1 statement about days, that the workman worked with the management on muster roll was filed by Mr. R. C. Srivastava, Assistant Engineer in Conciliation and the file of the Conciliation proceedings was called by me and was examined and the original of WZ-1 was on record of the Conciliation Officer and the Management explanation is that it was prepared on spot without verification and put before Conciliation Officer and that the actual attendance in the muster roll copies now filed in this court.

9. It is impossible to accept the Management's explanation and further impossible to accept that the workman worked only for 185 days. The Management takes shifting stands. In the affidavits filed it is affirmed that the workman did not report for duty after 30-6-80 whereas in the reply to the claim statement of the workman the plea was that the workman was not employed after 30-6-80 because there was no work for him meaning thereby that the workman was there but could not be allotted work.

10. In this situation, the sworn statement of the workman coupled with the verification of actual days of work on which he worked as Khalasi in statement WZ-1 is accepted that he worked for more than 240 days during the period 26-7-79 to 30-6-80 and was clearly entitled to retrenchment compensation under section 25-F of the I.D. Act, 1967 on account of having worked for more than 240 days in a year and his service could not be terminated by refusal to give his work.

11. The workman is ordered to be reinstated in service with back wages at the rates current for casual labour as revised from time to time but no leave wages are allowed to him. He shall be continued as casual labour as before. The payment shall be made to him from 1-7-1980 onwards for working days and work shall be taken from him when he reports for duty. His regularisation and confirmation shall be in accordance with the existing rules of the CPWD but his services could not be terminated except after compliance with Section 25-F of the I.D. Act because the provisions of section 25-F of the I.D. Act, 1947 are mandatory and that section applies to casual labour as well. The Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer.

[No. L-42012(36)|81-D.II(B)]

June 11, 1985.

का. आ. 3075.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि. के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 3075.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneshwar, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Mineral Exploration Corporation Limited and their workman, which was received by the Central Government on the 3rd June, 1985.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

PRESENT :

Shri K. C. Rath, B.L.,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 7 of 1982 (Central)

Bhubaneswar, the 28th May, 1985

BETWEEN

The employers in relation to the management of Mineral Exploration Corporation Limited. First Party

AND

Their workmen Second Party

APPEARANCES :

Shri S. K. Sarkar,
Sr. Personnel & Administrative Officer. —For the first-pary

Shri R. N. Bose,
Assistant Area Secretary,
M.E.C. Employees' Union.
—For the second-party

AWARD

Dispute referred to by the Central Government for adjudication under Section 7-A and Clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Order No. L-43012|6|81-D.III(B) dated 31-5-1982 of the Ministry of Labour runs thus:—

"Whether the action of the management of Mineral Exploration Corporation Limited:—

(i) In terminating the services of Shri D. Satyanarayanan, workman of their Panohpatmali, Bauxite Project with effect from 30-12-78 and keeping him unemployed during the period 31-12-78 to 13-4-80; and

(ii) in again terminating the services of Shri D. Satyanarayanan; workman of their Bathmali Bauxite Project with effect from 19-3-1981 is justified. If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. On the date of hearing, i. e. 23-5-1985, both the parties filed a petition along with a Memorandum of Settlement praying to pass an Award in terms of the settlement. Both the parties admitted the terms of the settlement before me and stated that they had entered into the settlement amicably out of court in the interests of industrial peace and harmony. The settlement appears to be fair. Hence I pass this

Award in terms of the settlement and the Memorandum of Settlement do form part of the Award.

K. C. RATH, Presiding Officer

[No. L-43012|6|81-D.III (B)]

28-5-1985.

FORM H

NAME OF PARTIES :

Representing Employer.—Mineral Exploration Corporation Ltd., through Chief Manager (Pers. & Adm.), Shri C. H. Khisty.

Representing Workmen.—M.E.C. Employees Union through General Secretary, Shri N. K. Chhatterjee.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Shri D. Satyanarayanan was initially engaged on 3-4-1977 at Project Pottangi of Mineral Exploration Corporation Ltd. On the closure of the Project he was retrenched on 19-9-1978 after giving notice. He was also offered retrenchment compensation as admissible under the I.D. Act, 1947, but he did not collect the same. He was appointed afresh on 1-10-1978 at Camp Kakrigumma and was terminated on 30-12-78 as his services were no longer required. On a representation he was again re-engaged on 14-4-80 at Camp Baphlimali and was terminated on 19-3-81 on closure of the camp after giving notice and retrenchment compensation.

The MEC Employees Union raised dispute on 23-3-1981 before the Asstt. Labour Commissioner (Central) Nagpur. The matter could not be resolved in conciliation and the conciliation failed The ALC (C), Nagpur submitted its report to the Central Government on 24-8-1981. The Central Govt. referred the dispute to the Central Government Industrial Tribunal, Bhubaneswar vide order dated 31-5-1982. Subseqquently, the matter in the dispute was resolved amicably between the Management of MECL and the MECE Union on 6-8-1983. Shri D. Satyanarayanan was permitted to join duties on 31-10-1983 pending finalisation of past service benefits. On 12-4-1984 an agreement was signed by the parties regarding his past service benefits. The settlement dated 12-4-1984 was on ordinary paper. Since the same is required to be done in Form 'H', it is being done now.

Terms of Settlement

1. That Shri D. Satyanarayanan will be offered regular post of a store clerk within a period of 3 months from 12-4-1984.

2. That Shri D. Satyanarayana will be paid a lump-sum amount of Rs. 2500 (Rupees two thousand and five hundred only) within a period of one month from 12-4-1984 as compensation for the past service rendered by him.

3 That the dispute stands finally resolved and the Union|Workman shall have no other claim whatsoever regarding benefit of past service etc.

4. That in view of the above a joint application will be filed before the Central Government Industrial Tribunal, Bhubaneswar before whom above reference vide No. L-43012|6|81-D.II(B) dated 31st May, 1982 is pending requesting the Hon'ble Tribunal to pass a consent award in terms of above settlement.

For the Management of MECL, Nagpur

Sd-

(C. H. KHISTY)

Chief Manager (Pers. & Adm.)

Sd|-

(D. SATYANARAYANAN)

Concerned workman

For the MECE Union, Nagpur

Sd|-

(N. K. CHATTERJEE)

General Secretary

Date : 14-5-1985.

Copy to :—

1. The Asstt. Labour Commissioner (Central), Mount Road, Nagpur.

2. The Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur.

3. The Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

4. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi.

ANNEXURE A

RECORD NOTE OF DISCUSSIONS HELD WITH MECE UNION (RECOGNISED) NAGPUR ON 12-4-1984

REPRESENTING MANAGEMENT :

1. Shri C. H. Khisty,
   Chief Manager (P&A)
2. Shri K. B. Bhagwandes,
   Officer on Special Duty.

REPRESENTING UNION :

1. Shri N. K. Chatterjee,
   General Secretary.
2. Shri B. H. Thekwani,
   Jt. Secretary.

As decided in Apex Council Meeting held on 6-8-1983, Shri D. Satyanarayanan has already been permitted to join as contingent workman (Skilled A) vide Management's office order No. 22(27)|C|Pers| 81|14 dated 10-10-1983 and he has reported for duty on 21-10-1983.

Regarding his past service benefits, it has been decided as under :—

1. That Shri D. Satyanarayanan will be offered regular post of a Store Clerk within a period of 3 months from this date i.e 12-4-1984.

2 That Shri D. Satyanarayanan will be paid a lump-sum amount of Rs. 2500 (Rupees two thousand and five hundred only) within

a period of one month from this date as compensation for the past service rendered by him.

3. That the dispute stands finally resolved and the Union|workman shall have no other claim whatsoever regarding benefit of past service, etc.

4. That in view of the above a joint application will be filed before the Central Govt. Industrial Tribunal, Bhubaneswar before whom above reference vide No. L-43012|0|81-D.III(B) dated 31st May, 1982 is pending requesting the Hon'ble Tribunal to pass a consent award in terms of above settlement.

MANAGEMENT REPRESENTATIVES

Sd|-

1. (C. H. KHISTY)
Chief Manager (P&A)

Sd|-

2. (K. B. BHAGWANDAS)
Officer on Special Duty.

UNION REPRESENTATIVES

Sd|-

(N. K. CHATTERJEE)
General Secretary

Sd|-

(B. H. THAKWANI)
Joint Secretary.

Dated : Nagpur, the 12th April, 1984.

का. आ. 3076.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सिंगरैनी कोलरीज कंपनी लि., मंदारी और रामाकृष्णपुरम, जिला ऐदीलाबाद के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 जून, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 3076.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Andhra Pradesh Indusrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Ramakrishnapur, Adilabad District and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th June, 1985.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Shri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal.
Dated 28-5-1985

Industrial Dispute No. 94 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Ramakrishnapur, Adilabad District (A.P.).

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Ramakrishnapur, Adilabad District (A.P.).

APPEARANCES :

Sarvasri V. Jagannadha Rao, V. Venkata Ramana and V. Srinivas, Advocates for the workmen.

Sri K. Srinivasa Murty and Miss G. Sudha, Advocate for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-22012|38|84-D.III(B), dated 23-11-1984 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Mandamarri and Ramakrishnapur Division, Kalyani Khani P.O. District Adilabad to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the Management of Singareni Collieries Company Limited, in relation to their Ramakrishnapur 5 Incline of Ramakrishnapur II in dismissing from service Shri Gorla Ramachander, Trammer with effect from 27-6-83 is justified? If not, to what relief is the workmen concerned entitled?"

This reference was received in this Tribunal on 26-11-1984 and registered as Industrial Dispute No. 94|84 The notice dated 1-12-1984 had been issued to both parties with a direction that the workmen should file their claims statement on 31-12-84. The notice dated 1-12-1984 had been acknowledged by the workmen as well as the Management. On 31-12-84 Sarvasri V. Jagannadha Rao, V. Venkata Ramana and V. Srinivas, Advocates filed Vakalat for the workmen and prayed for extension of time for filing claims statement and time was extended for filing claims statement till 23-1-85. On 23-1-85 the claims statement was not filed and at the request of Counsel for the workmen time was again extended upto 6-2-1985. On 6-2-85 workmen and their counsel called absent and the claims statement has filed and again it was adiourned to 25-2-85 for filing claims statement by the workman. On 25-2-85 counsel for the workmen was present and no claims statement was filed and at his request the case was adjourned to 14-3-85 for claims statement. On 14-3-85 the workmen as well as their counsel was called absent and no claims statement was filed and again time was extended

till 28-3-85 for filing claims statement. On 22-3-85 the counsel for the workmen was present and no claims statement was filed and time was again extended till 8-4-85. On 8-4-85 the workmen and their counsel were called absent and no claims statement was filed and time was again extended till 25-4-85. On 25-4-85 the workmen and their counsel were called absent and no claims statement was filed and lastly time was again extended till 28-5-85 for filing claims statement by the workmen. On 28-5-85 also the workmen and their counsel were called absent and no claims statement was filed.

Moreover the Government of India Ministry of Labour, New Delhi ordered me to submit the Award within a period of three months in accordance with Sub Section (2A) of Section 10 of the I.D. Act 1947 and I have given full opportunity to the workmen to defend their case and they are not coming forward in spite of the several notices given by me. Hence the reference is terminated, holding that the workmen are not entitled to any relief.

Hence Award passed accordingly.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 28th day of May, 1985.

Sd/
Industrial Tribunal

Appendix of Evidence

NIL

31-5-85

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-22012(38)/84-D.III(B)]

HARI SINGH Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985